# छत्तीसगढ़ विधान सभा

# की

# अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा त्रयोदश सत्र

## मंगलवार, दिनांक 08 मार्च, 2022

## (फाल्गुन 17, शक सम्वत् 1943)

[अंक 02]

Web Copy

# छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 08 मार्च 2022

(फाल्गुन 17, शक सम्वत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे सम्वेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये)

श्री कुलदीप जुनेजा :- भाभीजी ने आज स्पेशल जैकेट महिला दिवस पर बनवाने के लिए खरीदे हैं ।

**<u>अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष उल्लेख</u>**

अध्यक्ष महोदय :- सम्माननीय सदस्यगण, सम्पूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश प्रत्येक वर्ष आज अर्थात 8 मार्च को “अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस” के रूप में मनाते हैं ।

हमारे लिये यह गौरव की बात है कि हमारे राज्य की राज्यपाल तथा महिला एवं बाल विकास की मंत्री भी महिला हैं, साथ ही इस विधान सभा में कुल 14 महिला सदस्य निर्वाचित होकर आयीं है, मैं आप सभी सम्माननीय महिला सदस्यों को इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें देता हूँ ।

अगर हम महिलाओं को इस विश्व की जननी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि महिलायें ही परिवार बनाती है, परिवार से घर बनता है, घर से समाज, समाज से राष्ट्र और कई राष्ट्रों के समूह से ही समूचा विश्व बनता है । इस वर्ष आज के इस अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय “Gender equality today for a sustainable tomorrow” (अर्थात सुदृण कल के लिए लैंगिक समानता) पर निर्धारित है ।

हमारा देश आदिकाल से ही नारी शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है । “यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता” की भावना से हमारी संस्कृति अनुप्राणित है । हम नारी को देवी, धैर्य एवं धन अर्थात लक्ष्मी का प्रतीक मानते ही हैं। आइये, आज इस दिवस पर हम अपनी संस्कृति को अधिक सुदृण बनाने हेतु एक बार पुन: दृण संकल्पित होंवें और नारी को पुरूष के समान ही समाज के हर क्षेत्र में समान अवसर देने का संकल्प लें और उन्हें पूर्ण सम्मान दें ।

पुन: आप सभी को अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनायें और बधाई ।

जय हिन्द, जय छत्तीसगढ़ ।

धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में थर्ड जेंडर का भी उल्लेख है ।

अध्यक्ष महोदय :- वे लोग अपने आप को नारी नहीं मानते ना ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, सदन की ओर से श्रीमती छन्नी साहू को आज बधाई देना चाहिये कि वह प्रियंका गांधी के "लड़की हूं, लड़ सकती हूँ" को चरितार्थ कर रही है । इसलिए पूरे सदन की ओर से उन्हें बधाई दी जानी चाहिये। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री बघेल लखेश्वर ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- महिलाओं को दीजिए ना ।

## तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

### कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन्य जीवों की गणना

[वन एवं जलवायु परिवर्तन]

**1. ( *क्र. 419 ) श्री बघेल लखेश्वर :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कांगेर वैली नेशनल पार्क, जिला बस्तर में गणनानुसार वर्ष 2018 की स्थिति में कौन-कौन से वन्यजीव थे तथा उनकी संख्या कितनी थी ? कृपया बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में कृपया बतावें कि वन्यजीवों की अंतिम गणना कब की गई व उस समय उनकी संख्या क्या थी ? विवरणात्मक जानकारी देंवे ? **(ग)** कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण व संवर्धन के लिए क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक कितनी राशि खर्च की गयी है ? वर्षवार जानकारी देंवे ?

**वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क)** वर्ष 2018 की स्थिति में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में वन्यप्राणियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्शाई जाती है। रिपोर्ट में प्रत्येक संरक्षित क्षेत्र में पाये जाने वाले समस्त वन्यप्राणियों की संख्या प्रकाशित नहीं होती है बल्कि Landscape के अनुसार वन्यप्राणियों की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्शायी जाती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की रिपोर्ट को Central India and Eastern Ghats landscape के रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, जंगली सूअर, भेड़िया, गीदड़, चौसिंघा, कोटरी, चीतल, लंगूर एवं बंदर की उपस्थिति कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पायी गयी है। **(ख)** वन्यजीवों की अंतिम गणना वर्ष 2018 में अखिल भारतीय बाघ आंकलन के माध्यम से की गई थी। गणना की विवरणात्मक जानकारी प्रश्नांश 'क' में दी गयी है। रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, जंगली सूअर, भेड़िया, गीदड़, चौसिंघा, कोटरी, चीतल, लंगूर एवं बंदर की उपस्थिति कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पायी गयी है। **(ग)** कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये चारागाह

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

विकास, जलस्रोत विकास लेन्टाना उन्मूलन आदि कार्य किये गये हैं। व्यय की वर्षवार जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** 1[1] में दर्शित है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न कांगेर वैली नेशनल पार्क के गणना से संबंधित था । माननीय मंत्री जी मेरे उत्तर ....(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चन्द्राकर जी का ध्यान थर्ड जेंडर की तरफ कैसे चला गया ?

श्री सत्यनारायण शर्मा :- सारी दुनिया जानती है कि चन्द्राकर जी क्या-क्या करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री लखेश्वर बघेल जी । आप जो बोल रहे हैं, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, क्या मंत्री जी सुन रहे हैं ? लखेश्वर बघेल ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप तो अभी तक अकेले में बात करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- लखेश्वर बघेल जी पूछ रहे हैं आप सुन रहे हैं क्या ?

श्री बघेल लखेश्वर :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कांगेर वैली नेशनल पार्क कब से घोषित हुआ, घोषित समय में कौन-कौन से वन्य प्राणी पाये जाते थे तथा कौन से वन्य जीवों की गणना हुई थी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य प्राणियों की संख्या Central India and Eastern Ghats landscape के रिपोर्ट के साथ प्रकाशित किया जाता है और उसमें रिपोर्ट के अनुसार तेंदुआ, लकड़बग्घा, भालू, जंगली सूअर, भेड़िया, गीदड़, चौसिंघा, कोटरी, चीतल, लंगूर एवं बंदर की उपस्थिति कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- मैंने पूछा कि कब से नेशनल पार्क घोषित हुआ ? उस समय वन्य प्राणियों की कोई गणना हुई थी क्या ? उसका जवाब दें ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्य प्राणियों की गणना होती नहीं है । लैण्डस्कैप परिदृश्य के आधार पर उसका एस्टीमेशन होता है, उसमें कई राज्य भी शामिल होते हैं । उसके एस्टीमेशन के आधार पर यह प्रकाशित किया जाता है ।

श्री बघेल लखेश्वर :- आपने कहा कि गणना नहीं होती थी, लेकिन मीडिया के पास जानकारी है कि कौन-कौन से प्राणी हैं, वह लोग कहां से गणना करते हैं?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वन्यजीवों की गणना नहीं होती। वह estimation होता है और वह परिदृश्य के आधार पर Central India and Eastern Ghats Landscape की रिपोर्ट की आधार पर इसका प्रकाशन होता है। उसी से अनुमान होता है कि यहां क्या-क्या पाया जाता है।

---

[1] परिशिष्ट -"एक"



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मीडिया के माध्यम से गण्ना हो, हम लोग स्वयं जंगल के रहने वाले हैं। आज से पहले कांकेर वैली एक डेन्स फारेस्ट होता था, उसमें शेर, बाघ और कई प्रकार के वन्य जीव होते थे, लेकिन आपने कुछ ही वन्य जीवों की जानकारी दी है। इसका मतलब यह है कि हमारे बाघ, शेर, अन्य वन्य प्राणी भी गायब हो गये। उसके रखरखाव, संरक्षण एवं संवर्धन में हमारे फारेस्ट विभाग की कमी है। आपने जो भी आंकड़ा दिये हैं, उसमें हमारे बहुत से वन्य प्राणी गायब हैं। मीडिया के माध्यम से कई प्रकार के वन्य प्राणियों की जानकारी 80 के दशक में दी गई थी। लेकिन वह सब प्राणी गायब हो गये हैं। उसमें वन विभाग के वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन में कमी होगी। यह हो सकता है कि आने वाले समय में वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं सवर्धन की कोई कार्यवाही न हो। इसके लिए विभाग हर साल करोड़ों रुपया खर्च करता है। अभी 2018 से जनवरी 2022 तक वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्धन के लिए 26 करोड़ रुपये खर्च कर चुके हैं। इसके बावजूद भी वन्य प्राणियों का सरंक्षण, संवर्धन नहीं हो पा रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार इस बात को दोहराता हूं कि वन्य प्राणियों की गणना नही होती, उनकी उपस्थिति, अनुपस्थिति दर्शाई जाती है। जहां मीडिया में प्रकाशन वाली बात है तो मीडिया के प्रकाशन को एथेंटिक नहीं माना जा सकता। विभागीय तौर पर जो जानकारी दी है, वह बिल्कुल सही है। उसके बाद भी यदि माननीय सदस्य के पास कोई स्पेसीफिक जानकारी किसी बारे में होगी तो वह जानकारी आप लायेंगे तो आप जैसा चाहेंगे, हम कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- यह आपका अंतिम प्रश्न है।

श्री बघेल लखेश्वर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सालों में वन्य प्राणियों की खाल जब्त हुई है, फारेस्ट विभाग द्वारा जब्ती के कितने प्रकरण बनाये गये हैं, यह बताने का कष्ट करें ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विषय उसमें उद्भूत नहीं होता है।

श्री बघेल लखेश्वर :- वन्य प्राणी गायब हो रहे हैं, इसलिए तो प्रश्न पूछ रहा हूं न। हो सकता है कि वन्य प्राणियों को मारकर खा जा रहे होंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- आपका जो मूल प्रश्न है वह अवैध शिकार के ऊपर नहीं है।

श्री बघेल लखेश्वर :- इसी से रिलेटेड है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्न को देखेंगे तो यह प्रश्न कांगेर घाटी के ऊपर है। इसके परिशिष्ट को भी आप देखेंगे तो लेन्टाना उन्मूलन पर सबसे ज्यादा राशि 7 बार व्यय की गई है। लेन्टाना उन्मूलन क्या चीज है ? उसमें क्या किया जाता है ? कितनी साल में कितनी बार लेन्टाना उन्मूलन किया जाता है या हर 5 साल में किया जाता है ? कांगेर घाटी में 7 बार लेन्टाना उन्मूलन किया गया है और सबसे बड़ी राशि व्यय की गई है। उसके क्या कारण हैं और उससे क्या फायदा होता है ?



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वन विभाग की प्रक्रिया है, लेन्टाना उन्मूलन होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- लेन्टाना उन्मूलन क्या है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 150 प्रकार के फूल लेन्टाना के रूप में पाया जाता है जो जंगल में बहुत विस्तारित तौर पर रहता है और उसका उन्मूलन बहुत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, वह जानना चाहते हैं, उनने पहली बार जानने की कोशिश की है कि लेन्टाना क्या है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेन्टाना 150 किस्म के छोटे-छोटे फूल होते हैं जो जंगल में पाये जाते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप परिशिष्ट को देखेंगे लेन्टाना उन्मूलन के लिए इतनी बड़ी राशि दी गई है। मैंने पूछा कि लेन्टाना उन्मूलन कितनी अवधि में चलता है, 15 दिन में, महीना भर में, साल में 4 बार, दो साल में चलवाते हैं और जो इतनी राशि व्यय की गई है वह किस आधार पर व्यय की गई है ? उसको मशीन से करते हैं, मेहनताना से करते हैं, मजदूरी से करते हैं, किस तरह से करते हैं कि जिसमें इतनी बड़ा राशि व्यय होती है ? अवधि, कारण और मेहनताना मशीन का है या आदमी का है, किस चीज का है ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विभागीय तौर पर किया जाता है। मजदूरों के द्‌वारा किया जाता है। और इसमें प्रत्येक दो वर्ष में लेन्टाना उन्मूलन किया जाना बहुत आवश्यक है। संरक्षित क्षेत्रों में लेन्टाना के प्रकोप को कम करने की दिशा में कार्य किया जाता है। इस कार्य से एक तरफ लेन्टाना को हटाने से वन्य प्राणी विचरण के लिए खुले स्थान मिलेंगे, वहीं दूसरी ओर इन खुले स्थानों में खाद्‌य घास एवं अन्य पौधों को पनपने का अवसर मिलेगा। इस कारण यह जरूरी है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बस्तर में रहने वाले, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी जंगल था लेकिन मैंने आज तक जंगल में लेंटाना उन्मूलन नहीं देखा है कि जंगल के अंदर साफ-सफाई हो रही है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपने लेंटाना देखा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- मैं वह नहीं जानता कि लेंटाना किसे कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- जब आप पहचानते नहीं हैं कि लेंटाना किसे कहते हैं तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है।

श्री अजय चंद्राकर :- तो क्या कागज में उसका उन्मूलन हो जाता है ?

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई जानवर फूल को सूंघ ले तो यह इतने विचलित क्यों हो रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- भैया, यदि आप मंत्री नहीं बन रहे हो तो मैंने वहां मनोचिकित्सालय खोला था, आप बिलासपुर में जाकर भर्ती हो। हमने अस्पताल को अच्छा बना दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, लेकिन यह जानना जरूरी है क्योंकि सबसे बड़ी राशि इसमें व्यय हुई है और बोल रहे हैं कि 2 साल में उन्मूलन होता है लेकिन आप तारीख देखिये इसमें 2 साल नहीं हुआ है। 2 साल से कम अवधि में हुआ है। आप परिशिष्ट पढ़ लीजिये। माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2 साल में होता है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं चाहूंगा कि इस बारे में आपका कोई विभागीय अधिकारी आकर मुझे लेंटाना के बारे में समझाये कि लेंटाना के सूंघने से, खाने से, छूने से क्या-क्या होता है और उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं।

प्रश्न संख्या 02 : XX XX

श्री अजय चंद्राकर :- खड़े हो जाओ। (श्री अमरजीत भगत की ओर इशारा करते हुये)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चंद्राकर जी, लेंटाना जस्ट मीन्स लंगटाना। वह बाबा लोगों का जो लंगोट रहता है, आपने कभी देखा है। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- उसके बारे में माननीय अध्यक्ष जी विस्तार से समझायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- वह लपटाना हो सकता है, लेंटाना नहीं हो सकता। (हंसी)

**<u>अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण के संबंध में</u>**

**<u>[सामान्य प्रशासन]</u>**

3. ( *क्र. 227 ) श्री धरम लाल कौशिक : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति दी गई है ? वित्तीय वर्षवार जानकारी देवें ? (ख) क्या यह सही है कि अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है ?यदि हां, तो कब व उस समिति में कौन-कौन सदस्य हैं, समिति की बैठक कब कब हुई है, समिति के द्वारा क्या अनुशंसा की गई है और समिति को कब तक अपनी रिपोर्ट देनी थी ? यदि नहीं, दी गई है तो कब तक दी जावेगी ? उक्त अनुसार कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जावेगा ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्ति की जानकारी वित्तीय वर्ष अनुसार प्रपत्र में संलग्न है।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(ख) जी हां। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 12-1/2019/1-3, दिनांक 11.12.2019 द्वारा प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार समिति गठित की गई है-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य | सदस्य विभाग |
| 2. | सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग | सदस्य सचिव |
| 3. | सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 4. | सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | सदस्य |
| 5. | सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग | सदस्य |

समिति की बैठक दिनांक 09.01.2020 को सम्पन्न हुई है। समिति द्वारा बैठक में की गई अनुशंसा निम्नानुसार है :-

(1) विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या की पूर्व उपलब्ध औरपचारिक जानकारी प्राप्त की जाये।

(2) विधि एवं विधायी कार्य विभाग का परामर्श/अभिमत प्राप्त किया जाये।

(3) पूर्व में गठित समिति द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाये।

समिति द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार विभागों तथा उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्ष कार्यालय/निगम/मंडल/आयोग/संस्था आदि में पूर्व से कार्यरत अनियमित, दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी चाही गई है।

नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से भी अभिमत प्राप्त किया जा रहा है। विधि विभाग द्वारा उक्त के संबंध में महाधिवक्ता का अभिमत चाहा गया है। विधि विभाग के टीप दिनांक 28.05.2019 में लेख किया गया है कि महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त होने पर सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जायेगा, जो अपेक्षित है।

समिति को यथाशीघ्र अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुसार अनियमित, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को कब तक नियमित किया जायेगा, समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले हमारी सभी महिला साथियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और इस विधान सभा में अधिकाधिक उनको अपनी बात रखने का अवसर मिलें और आपका संरक्षण मिलें।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- नेता जी को बोलने नहीं दोगे ?



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत दिन के बाद आपका दिन-भर का प्रश्न दिया है। आप तो अनिता योगेन्द्र शर्मा को पहले प्रश्न में ही गायब कर दिये हो। (हंसी)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आज महिला दिवस है। वह महिला दिवस के कार्यक्रम में है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपके दिन-भर का प्रश्न बहुत दिनों बाद आया है।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानकारी चाही है कि 01 जनवरी 2019 से अभी 31 जनवरी 2022 तक, यहां पर कितने लोगों के नियुक्तियां हुई है। उसमें सभी श्रेणी मिला करके 20,291 जवाब में आया है। उसमें 2018-2019 के 3333, यदि इसको छोड़ दिया जाये तो लगभग 16000 की नियुक्तियां हुई हैं। मैंने इस बात को मुख्यमंत्री जी से इसलिये पूछा कि यहां पर बड़े-बड़े होल्डिंग लगे हुये हैं और इस होल्डिंग में बताया गया है कि 4,65,000 लोगों से अधिक लोगों को नौकरी दी गयी है और जब हम बिलासपुर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ में थे तो उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को नौकरी दी गयी है। लेकिन मैंने कहा कि जवाब में 20,000 आया है तो यह जवाब का मेल नहीं हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी बतायेंगे की आपका जो आकाश में और पाताल में जो नौकरी है, उसमें जो अंतर है यह क्यों है, और आपने कितने लोगों को वास्तविक में नौकरी दी है ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो यह है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने जो प्रश्न किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि 2018-2019 को हटा दें। क्यों ? जब प्रश्न ही आपने 01 जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक का किया है तो 2018 हटाने का सवाल ही नहीं होता क्योंकि 01 जनवरी 2019 से। यह जो 3333 पद हटाने की बात कर रहे हैं वह यथावत है।

श्री धरम लाल कौशिक :- उसमें जोड़ें ।

श्री भूपेश बघेल :- जोड़ लीजिये। उसमें आपने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी व चतुर्थ श्रेणी के प्रश्न पूछा है, उसमें वर्षवार यह जानकारी दी गयी है जिसमें 20291 पदों की भर्ती की गयी। नौकरी केवल शासकीय नहीं होती, रोजगार केवल शासकीय नहीं होता।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजगार में और नौकरी में अंतर है। मुख्यमंत्री जी इसको स्पष्ट कर लें। मनरेगा में जो काम करने जाते हैं उसको भी रोजगार मिलता है लेकिन आप उसको नौकरी नहीं कह सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, नौकरी का आशय है कि जो आपके द्वारा दी गई सैलरी पर आधारित हैं और वेतन पर जो आधारित हैं। जो आपके वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृत है, ये नौकरी में है। आपने रोजगार की बात करेंगे तो उसमें लिखे होते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया तो हम वैसे ही प्रश्न करते। आपने नौकरी की बात की है तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। जो आप बताये 20 हजार हैं, आपने उसके अलावा कितनों को नौकरी दी है?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने केवल नौकरी के बारे में पूछा है तो मैंने नौकरी का उत्तर दे दिया है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो इसका मतलब यही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आपकी योजना जो मैं बोलता हूँ कि होर्डिंग्स में है या पेपर में है। उसकी जो सच्चाई है वह आज सामने आ गई कि आपने 4 लाख, 65 हजार नौकरी दे दी, यह 20 हजार के माध्यम से। अब दूसरी बात यह है कि आपने, सरकार ने जनघोषणापत्र को आत्मसात किया है। आपने जनघोषणापत्र में दिया है कि अनियमित कर्मचारियों नियमित किया जायेगा। आपने उसके लिए एक कमेटी भी बनायी है। कमेटी बनाने के बाद में उसकी एक बैठक हुई है। आपकी यह जो बैठक हुई है यह दिनांक 09.01.2020 को हुई है और उसके बाद में अभी तक उस कमेटी की बैठक नहीं हुई है। वास्तविक में यह जो प्रश्न है, एक तो मेरा यह प्रश्न है, श्री विद्यारतन भसीन जी का है और माननीय शिवरतन जी का भी है। यह तीनों  लगभग एक ही प्रश्न है। उस प्रश्न को एक साथ भी लेंगे तो चल जाएगा। जैसा आप निर्धारित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न और किनका है ?  ठीक है। हम ले लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री विद्यारतन भसीन जी का है और माननीय शिवरतन जी का भी है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 03, 08 और 09 सब एक साथ है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तीनों प्रश्न एक साथ है और लगभग वही प्रश्न है।  इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा था कि  दिनांक 09.01.2020, उसकी बैठक जनवरी को संपन्न हुई और बैठक संपन्न होने के बाद में उसमें जो अभिमत दिया गया कि जानकारी प्राप्त की जाए, अभिमत प्राप्त की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बहुत गंभीर हैं। हम लोग मानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी कर्मचारियों अधिकारियों के प्रति बहुत गंभीर हैं। लेकिन वर्ष 2020 के बाद में कोई बैठक नहीं हुई। इसकी सारी जानकारी आ गई होगी तो कुल कितने अनियमित हैं, उनको नियमित कब तक किया जायेगा? और उसकी तारीख, महिना कोई बतायेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 09.01.2020 को बैठक संपन्न हुई। जिसमें प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग और उसमें 5 लोगों की समिति बनायी गई, जिसमें प्रमुख सचिव, विधि विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन, सचिव वित्त, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, इनकी कमेटी बनायी गई और इसकी बैठक दिनांक 09.01.2020 को संपन्न हुई।  जिस प्रकार से माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसमें विभाग में उसमें जो अनुशंसा की गई, उन विभागों में पदस्थ अनियमित, दैनिक वेतनभोगी, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं पूर्व उपलब्ध औपचारिक जानकारी प्राप्त की जाए। दूसरा  विधि एवं विधायी कार्यविभाग

का परामर्श, अभिमत प्राप्त किया जाए, तीसरा पूर्व में गठित समिति द्वारा अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए। साथ ही जितने निगम, मण्डल, आयोग, संस्था में कार्यरत अनियमित, दैनिक वेतनभोगी, संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की भी जानकारी चाही गई। इस मामले में विधि विभाग द्वारा दिनांक 28.05.2019 को उन्होंने ए.जी. से अभिमत मांगा है, वह भी चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य एवं अन्य विरूद्ध उमादेवी एवं अन्य 2006/04 एन.सी.सी. के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 10.04.2006 को जो आदेश जारी हुआ, उसमें यह निर्देश है कि केवल एक बार एक समय में लिए 10 वर्ष या अधिक समय के नियमानुसार स्वीकृत पदों पर लगातार कार्यरत दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, अस्थायी कर्मचारी की अनियमित नियुक्ति को नियमित करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। इसलिए इसे विधि विभाग से भी परीक्षण कराया जा रहा है, इसमें एडव्होकेट जनरल से भी अभिमत मांगा गया है। सारे विभागों से निगम मण्डल से भी इसकी जानकारी मांगी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही यह उपलब्ध होगा, उसके आगे की कार्यवाही होगी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो विधि विभाग द्वारा अभिमत मांगा गया है, ए.जी से। यह दिनांक 28.05.2019 को मांगा है कि इसमें अभिमत प्राप्त किया जाए। अब इस सरकार की गंभीरता दिखायी दे रही है। कि यह सरकार अधिकारी, कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि आपके ए.जी. बिलासपुर में बैठते हैं, रायपुर भी आते हैं। ए.जी. को कब-कब पत्राचार हुआ है और विभाग के द्वारा पत्राचार करने के बाद में ए.जी. का क्या जवाब आया है? यह आप थोड़ा सा बतायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अभी अभिमत अपेक्षित है और कब-कब पत्र गया है उसकी जानकारी मैं अलग से दे दूंगा।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपको अलग से दे देंगे न बोल तो रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं, अलग से बैठने की नहीं है। आज जो पूरे कर्मचारी लोग हैं, आपने उसको आत्मसात किया है। आपने अपने जन घोषणा पत्र में कहा है कि हम उनको नियमित करेंगे। वर्ष 2019 में पत्र भेजने के बाद में वर्ष 2022 लग गया है। आपका वर्ष 2020, 2021 चला गया, 2022 में खड़े हैं। यदि वर्ष 2022 तक नहीं आया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उसमें समय पूछना चाहता हूं कि कितने दिन के अंदर उनका अभिमत आ जाएगा और उनको नियमित कब किए जाएंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, केवल ए.जी. का अभिमत नहीं है। मैंने कहा कि विभागों से जानकारी आएगी, अभी तक करीब 33 विभागों की जानकारी आ चूकी है, शेष विभागों की जानकारी आना अभी शेष है।

श्री धरमलाल कौशिक :- कब तक आ जाएगी ? मैं यही तो पूछ रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- जल्दी कर लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- जल्दी का क्या है ?

श्री भूपेश बघेल :- जल्दी का क्या है मतलब ?

श्री धरमलाल कौशिक :- मुख्यमंत्री जी, तीन साल का समय तो वैसे ही निकल गया है। दो साल का समय भी बाकी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- नेता जी, आप 15 साल से क्या कर रहे थे ? (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी, दो साल तो वह नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में ही है और नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में कोरोना आ गया। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने तो 15 साल में नहीं किया, कम से कम यह सरकार आई है उसमें अभिमत मांग रही है, कार्रवाई कर रही है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपका वर्ष 2019 का मामला है, वर्ष 2022 आ गया है। (व्यवधान) आप समय बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने पिछले 15 सालों में नहीं किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोगों ने 15 सालों में नहीं किया तो...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी के खड़े होने पर)

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिए। नेता जी, खड़े हुए हैं, आप क्यों खड़े हो गये ? एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी खड़े हुए हैं और खुद खड़े हो गये और हमको बोल रहे हैं कि इनको बैठाओ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए-चलिए।

श्री भूपेश बघेल :- नेता जी खड़े हुए हैं और आप खड़े हो गए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, सब लोग बैठ जाईए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता जी खड़े हैं और अजय जी खड़े होकर बता रहे हैं कि इनको बैठाओ। "पर उपदेश कुशल बहुतेरे"

श्री धरमलाल कौशिक :- ये तो तब खड़े हुए हैं जब...।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, अब नेता जी को बैठा दिए। क्या बात है? देखिए। यह परंपरा है। नेता जी बैठ गए। हमारे नेता जी कितने सरल हैं। वे (व्यवधान) बैठ गए।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- क्या विपक्ष के नेता यही लोग हैं ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- कभी अजय चंद्राकर जी बहिर्गमन करा देते हैं, कभी बृजमोहन जी बहिर्गमन करा देते हैं। ये लोग नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष नहीं मानते हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ये अभी तय नहीं कर पा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन है ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी आप इतने कमजोर हैं, मैंने इतना पहली बार देखा है। ये हुल्लड़ आप करवा रहे हैं और हमने सदन के नेता को हुल्लड़ करते पहली बार देखा है। सदन के नेता भी हुल्लड़ करवा रहे हैं, आप इतने कमजोर हैं, मैने इतना कमजोर नहीं देखा था। मैं तो मजबूत आदमी समझता था।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, मैं आपके सामने बहुत कमजोर हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- वह तो दिख गया।

श्री भूपेश बघेल :- लेकिन सत्यनारायण जी बताते हैं किस मामले में ? (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके तीनों सदस्य कहां गये हैं, नेता प्रतिपक्ष जी का बहिष्कार करके चल दिए हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- हर चीज के मामले में तो आप बहुत सशक्त हैं। बहुत सशक्त हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री शिवरतन शर्मा जी।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों में तो कोई भी बहिर्गमन करा देता है। कभी बृजमोहन जी करा देते हैं, कभी अजय चंद्राकर जी करा देते हैं। नेता प्रतिपक्ष जी बैठे रह जाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आगे वाले लोग नेता प्रतिपक्ष जी का बहिष्कार करके चले गये हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वह हंटर वाली आ करके गयी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है 20,291 लोगों को शासकीय नौकरी मिली। अगर आप अनुमति दें तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भाषण की क्लीपिंग पटल पर रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- भाषण नहीं होता।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह भाषण को पटल में रखते हैं क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने भाषण में कहा कि 2 लाख 80 हजार लोगों को शासकीय नौकरी प्रदान की गयी है और यह भाषण हुआ है उसकी क्लीपिंग मेरे पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का प्रचार-प्रसार देखते थे, गोएबल्स, उसको मात कर रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गोएबल्स को विधानसभा में तो तुम्हीं लोग मानते हो। गोएबल्स से ज्यादा झूठ बोलते हो।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- 20 हजार से ज्यादा लोगों को नौकरी देना स्वीकार कर रहे हैं और भाषणों में बोल रहे हैं कि 2 लाख 80 हजार लोगों को रोजगार दिया गया।

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए न।

श्री अमरजीत भगत :- आप डाढ़ी वाले बाबा को ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप प्रश्न करिए, प्रश्न।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हमारी सरकार तो देने का प्रयास कर रही है, आप लोगों ने तो पूरा दरवाजा बंद कर दिया था। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत प्वाईटेंड प्रश्न कर रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कहां का प्वाईंटेड प्रश्न है ? प्रश्न करते नहीं हैं, भाषण देना शुरू कर देते हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकारियों की समिति बनी है, उसकी प्रोसिडिंग का उल्लेख उत्तर में किया है। दिनांक 09.01.2020 को बैठक संपन्न हुई और उसमें 3 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गयी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 33 विभागों की प्राप्त हुई है, कुछ विभागों की जानकारी अब तब प्राप्त होना शेष है और दिनांक 28.05.2019 को महाधिवक्ता को पत्र लिखा गया लेकिन वर्ष 2019 के पत्र का महाधिवक्ता का जवाब अब तक नहीं आया । क्या कभी इस पर रिव्यू किया गया कि वर्ष 2019 में पत्र लिखा गया है और महाधिवक्ता क्यों अभिमत नहीं दे रहे हैं ? और यह जानकारी इतने दिनों तक प्राप्त क्यों नहीं हो पा रही है, दो साल से ऊपर का समय हो गया है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 15 सालों में तो कुछ कर नहीं पाये हैं । पी.एस.सी. की परीक्षा मात्र 3 बार आयोजित हुई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिये जो लोग दोषी हैं, जो समय पर जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं । महाधिवक्ता समय पर अपना अभिमत नहीं दे रहे हैं तो क्या इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके नेता की कृपा से तो नमस्ते ट्रम्प हुआ और कोरोना आया । पूरे देश के लोग कोरोना से जूझते रहे । ऑफिस बंद थे, कार्यालय बंद था, सभी घर से काम कर रहे थे और उसके बाद भी हमारी सरकार लगातार काम करती रही । हमने बताया न कि 33 विभागों की जानकारी आ गयी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कोरोना की बहानेबाजी कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप कृपया पहले बैठ तो जाईए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री जी, आप कोरोना की बहानेबाजी कर रहे हैं । लगातार दो साल से सरकार काम कर रही है । आप स्वयं कोरोना में लगातार असम और यूपी का दौरा कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- एक डेड बॉडी नहीं मिली तो आप धरने में बैठने वाले थे और अब बोलते हैं कि कोरोना का बहाना बना रहे हैं । आप स्वयं उससे प्रभावित हुए थे । आप कृपया पहले बैठिए तो । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- महाधिवक्ता समय पर अपना अभिमत नहीं दे रहे हैं । आप बोल रहे हैं कि कोरोना के चलते नहीं हुआ । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप पहले जवाब तो सुन लीजिए । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप पहले मेरी बात तो सुनिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- आप नियम-प्रक्रिया की बात कर रहे हैं न । माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने मुझे उत्तर देने के लिये कहा, मैंने उत्तर दिया और अभी मैं खड़ा हूं । जब सदन के नेता खड़े हों तो उस समय बिना अनुमति के नहीं खड़े होना चाहिए । आपसे सीनियर सदस्य हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुझे प्रश्न करने के लिये माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अनुमति दी है । मैं माननीय अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति से खड़ा हुआ हूं । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- नहीं, क्या अभी आपको माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने अनुमति दी है ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हम गलत उत्तर सुनने के लिये नहीं बैठ सकते । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप व्यवस्था नहीं दे सकते । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आप व्यवस्था भी नहीं दे सकते । व्यवस्था तो माननीय अध्यक्ष जी देंगे । (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष जी तो आपकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं । आपको कब अनुमति मिल गयी ? मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से खड़ा हूं और जब सदन के नेता खड़े हों तो बिना माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से खड़े नहीं होना चाहिए । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से आपसे प्रश्न किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न तो आपने कर लिया अब उत्तर सुन लीजिए न ।

श्री भूपेश बघेल :- आपने प्रश्न किया और मैं उत्तर दे रहा था । अब उत्तर दे रहा हूं तो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बिना आसंदी की अनुमति से फिर से खड़े हो गये तो यह तरीका ठीक नहीं है । शिवरतन जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्ते ट्रम्प के चक्कर में हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सब लोग फंसे, पूरा देश फंसा । हजारों-लाखों लोगों की जानें गयीं, पूरा प्रदेश इससे प्रभावित हुआ उसके बावजूद भी हमारी सरकार लगातार काम करती रही और जहां तक अनियमित कर्मचारियों की बात है, सरकार बिल्कुल गंभीर है और हमने जनघोषणा पत्र में शामिल किया है । निश्चित रूप से चूंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसमें कोई त्रुटि न हो जाये, उसका परीक्षण करा रहे हैं, विधि विभाग से भी, ए.जी. से भी और विभाग के अधिकारियों से भी तो जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं और उनसे भी अभिमत ले रहे हैं और जब हो जायेगा तो फिर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, प्रश्न क्रमांक-4 दलेश्वर साहू जी । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है, यह महत्वपूर्ण विषय है । (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- राज्य में किसानों की सरकार कार्य कर रही है, क्या आप लोगों ने कभी प्रधानमंत्री जी से पूछा ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश की जनता को लगातार गुमराह कर रहे हैं कि कोरोना के चलते काम नहीं हो पाया । (व्यवधान) लगातार विभाग सक्रिय है लेकिन जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाये । आप यह बताईये न कि आप जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाये या जानकारी उपलब्ध कराना नहीं चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, हो गया ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार गंभीर है और इस मामले में कमेटी भी बनायी गयी है । विभागों से जानकारी ली जा रही है और जो परिस्थिति बनेगी उसके हिसाब से निर्णय लिया जायेगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू ।

श्री सौरभ सिंह :- जब जनघोषणा पत्र में बोला गया था तो क्या कोर्ट का पता नहीं था । (व्यवधान) जनघोषणा पत्र में शामिल करने के पहले यह वर्ष 2006 का निर्णय था । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गंभीरता की बात आ रही है । वर्ष 2019 में कमेटी का गठन हुआ और वर्ष 2020 में बैठक हुई । ए.जी. की रिपोर्ट नहीं आयी, विभागों की रिपोर्ट नहीं आयी, विधि विभाग की रिपोर्ट नहीं आयी, क्या सरकार की यही गंभीरता है ? (व्यवधान) आज जब मुख्यमंत्री जी से पूछ रहे हैं कि आप इसमें समय बतायेंगे, आप तारीख मत बताईये आप महीना बताईये । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- हमारी सरकार काम कर रही है । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोग बैठ जाएं ।

श्री सौरभ सिंह :- आपने गलत जनघोषणा पत्र बनाया और छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह किया है । वर्ष 2006 का निर्णय था, अभी तक नियमितीकरण नहीं हो पाया । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जवाब से संतुष्ट नहीं हैं, हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
11:30 बजे

**बहिर्गमन**

**भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में**

(नेता प्रतिपक्ष, श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

(भारतीय जनता पार्टी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।) (व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- वे बहिर्गमन की बात कर रहें है और ये जाना नहीं चाह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- दलेश्वर साहू।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धरमलाल कौशिक जी बहिर्गमन की घोषणा करते हैं। अजय चन्द्राकर जी बोलते हैं, रूको। जाना नहीं। (हंसी) रोक रहे थे।

अध्यक्ष महोदय :- दलेश्वर साहू।

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष एक है ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष कौन हैं, यह इन लोग तय ही नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी बहिर्गमन करा लेता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी को नेता प्रतिपक्ष बना दीजिए न।

अध्यक्ष महोदय :- दलेश्वर साहू। जल्दी आओ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नकल के लिए भी अकल चाहिए, बोला।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, तो बहिष्कार करके गये हैं। आये ही नहीं हैं, इसलिए तो पूछ रहा हूं। कल से नेता प्रतिपक्ष जी का बहिष्कार करके गये हैं बृजमोहन अग्रवाल जी ।

श्री अमरजीत भगत :- चन्द्राकर जी, वाट इज लेजिसलेटिव। एवरी परसन इस बहुत जिम्मेदार आदमी है। नहीं समझे। रिस्पांसिबल (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

## राजनांदगांव जिले में ३३/११ के व्ही उपकेन्द्र की स्वीकृति

**[ऊर्जा]**

4. ( *क्र. 246 ) श्री दलेश्वर साहू : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- वर्ष 2020-2021 से दिनांक 09/02/22 तक माननीय मुख्यमंत्री की अनुशंसा से राजनांदगांव जिले में कितने 33/11 के व्ही विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है ? कितने उपकेन्द्र की स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ किया जा चुका है एवं कितने प्रकरण किस स्तर पर लंबित है? लंबित प्रकरण कब तक स्वीकृत किये जा सकेंगे? विकासखंडवार जानकारी देवें?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : प्रश्नाधीन अवधि में राजनांदगांव जिले में वर्ष 2021-22 हेतु 04 स्थानों यथा विकासखंड राजनांदगांव के ग्राम पटेवा एवं घुमका चारभांठा, विकासखंड डोंगरगांव के ग्राम अरसीटोला एवं विकासखंड छुरिया के ग्राम बम्हनीचारभांठा में नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त स्वीकृत 04 उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु मुख्य अभियंता (परियोजना), वितरण कंपनी, रायपुर कार्यालय में निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त स्वीकृत नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों को छोड़कर उल्लेखित अवधि में राजनांदगांव जिले के जनप्रतिनिधियों से अतिरिक्त नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु भी प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो संलग्न परिशिष्ट [2]में दर्शित है। तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्षों में उपरोक्त उपकेन्द्रों को शामिल किये जाने के प्रयास हैं।

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र की स्वीकृति के संबंध में है।

श्री बृहस्पत सिंह :- जब भी प्रश्न उठाते हैं तो प्यार से उसका उत्तर तो सुन लिया करो भाई।

श्री दलेश्वर साहू :- माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। राजनांदगांव जिले के जनप्रतिनिधियों से अतिरिक्त नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव हुए हैं, जो संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिसमें 7 में से 4 आपकी अनुशंसा है। डोंगरगढ़-कोठीटोला, डोंगरगढ़-आलीवारा, डोंगरगांव-आसरा, डोंगरगढ़-खुड़मुड़ी। आपके उत्तर में तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पाये जाने पर एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप आगामी वित्तीय वर्षों में उपरोक्त उपकेन्द्रों को शामिल किये जाने के प्रयास हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि प्रयास शब्दों को विलोपित करते हुए..।

---

[2] परिशिष्ट - "तीन"

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। तुम उत्तर भी दे रहे हो। प्रश्न भी पढ़ रहे हो। विलोपित भी कर रहे हो। (हंसी)

श्री दलेश्वर साहू :- साहब, मैं कह रहा हूं न। मेरा मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि प्रयास शब्दों को विलोपित करते हुए सदन में स्वीकृति का आश्वासन देंगे क्या ? यह मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत बढिया। धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- आश्वासन ही आश्वासन तो है। कमेटी बन जाही उहू मे।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- आपको बैठे-बैठे बोलने की आदत है। आप सदन में बैठे-बैठे बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए-चलिए। प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- सत्तू भैय्या, अगर किसी को गुरा हो गया है तो कैसे करेगा, बताओ।

अध्यक्ष महोदय :- भाई अमरजीत।

श्री अजय चन्द्राकर :- कमेटी-कमेटी का खेल खेल रही है सरकार। आपकी कमेटी बनी है न। आपका नाम अभी शासन में है। आप रिपार्ट दे देना । आप कोरोना के कारण रिपोर्ट नहीं दे पाये क्या?

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- भैय्या, जी.एस.टी. के पैसा ला देतीस तो जल्दी जल्दी काम होतिस।

श्री भूपेश बघेल :- राजनांदगांव जिले में जनप्रतिनिधियों से नवीन 33/11 के.व्ही. के विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना की मांग की गई। अध्यक्ष महोदय, जब जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग की जाती है तो उसमें परीक्षण किया जाता है। तकनीकी रूप से भी जो साध्य होते हैं, उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसमें माननीय सदस्य ने जैसा बताया है कि मानपुर का आया, वह तकनीकी रूप से साध्य है। मानपुर सीतागांव वासड़ी का है। उसमें भी तकनीकी रूप से साध्य है। कोठीटोला तकनीकी रूप से साध्य नहीं है और आलीवारा, वह भी तकनीकी रूप से साध्य है। बागरेकसा, यह तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। आसरा, यह भी तकनीकी रूप से साध्य नहीं है और खुड़मुड़ी तकनीकी रूप से साध्य है। यह पूरी जानकारी होगी और जब यह साध्य है तो वित्तीय स्थिति जैसी बनेगी..।

अध्यक्ष महोदय :- वे क्या शब्द विलोपित करना चाहते थे, वह कर पायेंगे क्या ?

श्री दलेश्वर साहू :- प्रयास शब्दों को विलोपित करके स्वीकृति का सदन में..।

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा-अच्छा। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- देखिए, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और वहां की स्थिति देखते हैं। जनता की मांग के हिसाब से वे लोग विभाग को पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं और उसके आधार पर परीक्षण होता है। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने परीक्षण कराया है। आप यदि किसी एक में चाहते हैं तो आप उसे बता दें। मैं फिर से परीक्षण करा लेता हूं। आप किसी एक का बता दीजिए।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री दलेश्वर साहू :- अध्यक्ष महोदय, मेरा तीन में interest है। एक तो आपने कोठीटोला को असाध्य कह दिया, वह पूरा जंगल एरिया है। केवल वन विभाग है। वन विभाग का करके वह नहीं बनेगा तो क्या उन्हें वहां बिजली की पात्रता नहीं मिलेगी? इसलिए कोठीटोला को प्रथम प्राथमिकता और खुड़मुडी और आलीवारा मेरी दूसरी प्राथमिकता है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद् ।

श्री दलेश्वर साहू :- बाकी दोनों साध्य हैं, एक ही असाध्य है ।

अध्यक्ष महोदय :- जी, जी ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर से परीक्षण करा लेता हूं और माननीय सदस्य की मंशा अनुरूप उस पर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री सन्तराम नेताम । पहली बार तो मुख्यमंत्री जी आप लोगों की पकड़ में आए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लो ना ।

**केशकाल विधानसभा क्षेत्र में नलजल योजना के कार्यो की स्थिति**

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. ( ***क्र. 82** ) **श्री सन्त राम नेताम :** क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** केशकाल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वितीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान स्थिति तक नल -जल योजना के तहत कौन-कौन से ग्रामों में पानी टंकी निर्माण, पाईप लाइन विस्तार या बोर खनन के लिए टेंडर किया गया है ? कितने ग्रामो का कार्य प्रारंभ हो चुका है, कितने ग्रामो का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है? कार्य प्रारंभ नहीं होने का क्या कारण है ? ग्राम का नाम सहित जानकारी देंवे ? **(ख)** क्या किसी ग्राम पंचायत के कार्यो का टेंडर निरस्त किया गया है? यदि हाँ तो क्यों ?

**लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : (क)** केशकाल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान स्थिति (दिनांक 20 फरवरी 2022 तक) नल-जल योजना के तहत् ग्रामों में पानी टंकी निर्माण, पाईप लाईन विस्तार एवं बोर खनन के लिए किए गए टेंडर वाले ग्रामों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ"[3] अनुसार है।** 7 ग्रामों में कार्य प्रारंभ होकर पूर्ण हो गये हैं व 34 ग्रामों में कार्य प्रारंभ हो चुका है तथा 77 ग्रामों में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। कार्य प्रारंभ नहीं होने का कारण **संलग्न प्रपत्र-"अ" में दर्शित है। (ख)** जी हां! **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" अनुसार है।**

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केशकाल विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्तमान स्थिति तक नल-जल योजना के तहत जो कार्य चल रहा है । वर्तमान स्थिति तक

[3] परिशिष्ट - "चार"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निविदा की जो प्रक्रिया अपनाई गई है । इसका प्रकाशन कौन-कौन से आख़बार में किया गया है और क्या इसकी प्रक्रिया सही ढंग से हुई है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया के तहत् ही निविदा बुलाई जाती है । कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है । जिस समिति के तहत् टेंडर को फाइनल किया जाता है और वह पेपर्स में आता रहता है । वह समिति कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी है, वहां पर वह फाइनल होता है ।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय मंत्री जी मैं यह पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन से अख़बारों में विधिवत् प्रकाशित हुआ है, उसका नाम बता दीजिए ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, मैं उपलब्ध करवा दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, यह तो सदन के सामने आना चाहिए कि किसमें प्रकाशन हुआ ? यह उपलब्ध कराने वाला सिस्टम ठीक नहीं हैं । यहां अधिकारी बैठे हैं ।

श्री सन्तराम नेताम :- यह कोई बहुत बड़ा प्रश्न थोड़े ही है । जिस अख़बार में प्रकाशित हुआ उसका नाम तो मालूम होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह जानकारी सदन में आनी चाहिए, सदन में अधिकारी मौजूद हैं कि इस-इस तारीख को इस-इस अख़बार में प्रकाशित हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- प्रश्नकर्ता को पूछ तो लेने दो भाई ।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि मेरे विधान सभा में पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या है । 2019-20 में केशकाल ब्लॉक में गौरगांव है, जामगांव है, होनहेड़ है, नेट है, माड़ागांव है, सारबेड़ा में अभी तक कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अतिशीघ्र ।

अध्यक्ष महोदय :- शीघ्रतिशीघ्र ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अतिशीघ्र ।

श्री सन्तराम नेताम :- एक अंतिम प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कहा गया है कि तकनीकी त्रुटि के कारण अभी तक उस काम को प्रारंभ नहीं किया गया है । मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूं कि यह जो कार्य प्रारंभ हुआ भी है, वह काफी धीमी गति से चल रहा है । मेरा यह प्रश्न है चूंकि गर्मी आ गई और पेयजल की समस्या है । इसलिए जो कार्य प्रारंभ हो गया है क्या उसमें तेज़गति आएगी और यह कब तक पूरा होगा ?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, तेज़गति से करिये, जल्दी करिये ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, इसके कई कारण होते हैं, टेंडर लगाया जाता है । कई बार ठेकेदार, टेंडर लेकर काम को देरी से शुरू करते हैं, इनमें से दो गांव ऐसे हैं जहां ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया है, उसके लिए हमने उसे नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय :- नोटिस दीजिए, जल्दी करवाइए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मंत्री जी नवजवान हैं, इनको पानी की व्यवस्था जल्दी करनी चाहिए ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने नेतृत्व में 2023 के अंत तक आप सबके प्रत्येक गांव में पानी उपलब्ध हो जाएगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- जिस स्पीड से आप कर रहे हो, उसमें 2028 तक भी आप पूरा नहीं कर सकते ।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- कर लेंगे, अजय जी । कर लेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह प्रमाण पत्र आपसे लेना पड़ेगा ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- काम तो सब तरफ़ चल रहा है भईया ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सत्तू भईया, गुरूजी को कुछ ज्ञान दो ना ।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- पहले अजय जी को ठीक करो, बीच-बीच में कुछ भी बोलते रहते हैं ।

श्री अरूण वोरा :- अजय जी सरासर असत्य बोल रहे हैं । आप कोई भविष्यवक्ता हैं क्या, आप कह रहे हैं कि 2028 तक सरकार में नहीं रहोगे । अरे, अभी 50 साल रहेंगे और भूपेश बघेल जी रहेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूछ लो, केबिनेट से किसने निरस्त किया ।

श्री अरूण वोरा :- किसको ?

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी बात वे समझ गए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, दूसरी बात में मत जाइए, प्रमोद कुमार को बोलने दीजिए ।

**न्यूवोको सीमेंट संयंत्र का निरीक्षण**

[आवास एवं पर्यावरण]

**6. ( *क्र. 90 ) श्री प्रमोद कुमार शर्मा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोनाडीह में संचालित न्यूवोको सीमेंट सयंत्र के पावर प्लांट से अत्यधिक मात्रा में सल्फर डाई ऑक्साइड निकलने के कारण क्षेत्र में दमा के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है ? यदि हाँ तो प्रदूषण नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही की गई है ? **(ख)** प्रश्नांश-**(क)** में उल्लेखित संयंत्र का निरीक्षण वर्ष 2019 से वर्ष 2022 में दिनांक 31 जनवरी 2022 तक किस स्तर के अधिकारी द्वारा कितनी बार कब कब किया गया है ? निरीक्षण में क्या पाया गया ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

संयंत्र पर पर्यावरण मानकों का पालन नही किये जाने पर क्या कार्यवाही की गई ? निरीक्षण कर्ता अधिकारी के नाम पदनाम सहित वर्षवार विस्तृत ब्यौरा प्रदान करें ?

**वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : (क)** बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सोनाडीह में स्थित मेसर्स न्यूवोको विस्टास कारपोरेशन लिमिटेड का कोयला पर आधारित कैप्टिव पावर प्लांट दिनांक 29.01.2021 से संचालित है। उक्त पावर प्लांट में सल्फर डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु लाइम डोजिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। पॉवर प्लांट की चिमनी में स्थापित किये गये ऑनलाईन सतत उत्सर्जन मापन व्यवस्था से प्राप्त परिणाम के अनुसार सल्फर डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा से कम पाया गया है। **(ख)** जानकारी संलग्न **परिशिष्ट**[4] पर है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न लगाया था न्यूवोको सीमेंट संयंत्र के पावर प्लांट में सल्फ़र डाई-ऑक्साइड निकलने के संबंध में । अध्यक्ष महोदय, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई । जैसे ही विधान सभा में प्रश्न लगा, वहां पावर प्लांट में कुछ विशेष प्रकार का पाऊडर डलना शुरू हो गया और यहां लिख रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- क्या चालू हो गया ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कुछ पाऊडर डालना शुरू कर दिया । यहां विधान सभा में प्रश्न लगा और वहां पाऊडर डालना शुरू हो गया और यहां लिख रहे हैं कि सब ठीक-ठाक है । चलिए मान लेते हैं कि सब ठीकठाक है तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो सल्फ़र डाई-ऑक्साइड निकल रहा है उसको किस उपयोग में लिया जा रहा है या उसको कहां फेंका जा रहा है ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सल्फर डाई ऑक्साइड के लिए Lime dosing system है और Lime dosing power plant system से उत्सर्जित फ्लू गैस में उपस्थित अम्लीय प्रकृति की गैस जैसे- सल्फर डाई ऑक्साइड को लाइम चूना के द्वारा हटाने की एक तकनीक है। इस तकनीक के अंतर्गत पावर प्लांट के बाइलर में कोयले के दहन के दौरान लाइम की dosing की जाती है जिससे दहन से उत्पन्न हुई सल्फर डाई ऑक्साइड गैस लाइम के साथ रासायनिक क्रिया कर कैल्सियम सल्फाइड एवं कैल्सियम सल्फेट का निर्माण करती है अर्थात् उसके असर को समाप्त कर देती है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है कि ऐसा कोई भी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं लगाया गया है। मैं मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या हम भौतिक निरीक्षण करने के लिए अचानक कभी भी जा सकते हैं क्या? हमारे साथ में आपके कौन से अधिकारी जायेंगे। हम लोगों को अधिकार देंगे क्या?

अध्यक्ष महोदय :- आपको अधिकार तो नहीं है, आपके अधिकारी को अधिकार है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं, अधिकारी के साथ में जाने का।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। इसमें यदि आपका अनुमति हो तो हम भी बोल ले।

---

[4] परिशिष्ट - "पॉच"

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पूरे विधान सभा क्षेत्र में सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण लोग परेशान हैं। जहां के मरीज रो रहे हैं। तो इस विधान सभा के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है, वह अधिकारी के साथ निरीक्षण के लिए क्यों नहीं जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय :- जा सकता है न, वह तो अकेले भी जा सकता है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नहीं-नहीं, मैं अधिकार के साथ में जाना चाहूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- अधिकारी के साथ?

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। यहां पर सल्फर डाई ऑक्साइड का मामला है। वह बड़े उद्योपति हैं। इनका कोई कुछ बना या बिगाड़ तो सकता नहीं। पर माननीय मंत्री जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं, उनके क्षेत्र का मामला है। वहां पर वह क्या प्रक्रिया करते हैं, उसको देखने के लिए न केवल यह बल्कि दो-चार और पांच किसी को भी ले जाना चाहे तो उनको आप विशेष रूप से या आप सदन की दो-तीन लोगों की कमेटी बना दीजिए। सिर्फ देखने के लिए, निरीक्षण के लिए तो उसमें क्या तकलीफ है? सल्फर डाई ऑक्साइड जैसे घातक तत्व को रोकने के लिए अगर वह संस्थान गंभीर नहीं है तो सदन को चिंता लेनी ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपको उस पर आदेश करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- धर्मजीत जी, मैं चिंता इसलिए कर रहा हूं कि जब वह प्रश्न किया तब तो उन्होंने पावडर डाल दिया और जब यहां से मैं आदेश करूंगा तो पता नहीं वहां क्या-क्या साफ-सफाई हो जाएगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अच्छा हो जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, यही तो चिंता की बात है। विधान सभा खत्म होने बाद में फिर वैसी ही स्थिति हो जाएगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महादेय, वह प्लांट मेरे विधान सभा से लगा हुआ है।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, वह क्या प्रक्रिया हो रही है। उसको देखने के लिए यदि दो-तीन लोग चले जायेंगे तो क्या तकलीफ है? सरकार की भी मंशा है सल्फर डाई ऑक्साइड गैस को रोकना।

अध्यक्ष महोदय :- जाये न तो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मंत्री जी जवाब दे दे।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, इसमें सदन की कमेटी बना दी जाए।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं कमेटी मत बनाईये। अध्यक्ष महोदय, आप लोकल विभाग के ही तीन लोगों को नामजद कर दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- उसी जिले के लोगों को भेज दीजिए और आपके व्यवस्था से यह आदेश हो जाए तो अच्छी बात है।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- जी, जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, Lime dosing system एक सतत् प्रक्रिया है। प्रश्न लगने के बाद Lime dosing किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन में गैस उत्सर्जन 80 mg/$m^3$ से कम होना चाहिए। वहां पर 11.29 mg/$m^3$ है जो कि एकदम कम है। तो इस प्रकार से कोई बात है ही नहीं तो फिर किस बात की जांच?

श्री कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत बात है। गैस और सॉलिड में अंतर है। माननीय सदस्य गैस की समस्या की बात कर रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी को कहीं पर भी कोई आरोपित नहीं कर रहे हैं। सरकार के ऊपर भी हमारा कोई आरोप नहीं है लेकिन इसका नियंत्रण सरकार के हाथ में है कि वहां पर क्या हो रहा है या नहीं है रहा है। उनकी चिंता से आपको भी चिंतित होना चाहिए और यदि वे किसी भी एक दिन निरीक्षण करने चले जाए और वहां की व्यवस्था से देखकर संतुष्ट होंगे तो कोई बात नहीं है और यदि व्यवस्था से असंतुष्ट है तो आपके प्रभाव से वह व्यवस्था ठीक हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई जिद्दी वाली बात नहीं है। आप केवल यह कह दीजिए कि तीन सदस्य जाकर उसको देखें, उसी जिले के लोगों को भेज दीजिए। किसी और को भेजने की जरूरत नहीं है। उसमें आपके पार्टी के भी हो तो वे चले जाए, भाजपा पार्टी के हो तो वे भी चले जाए।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मॉनिटरिंग सिस्टम में जितना गैस उत्सर्जन होना चाहिए, उससे बहुत कम है। फिर अनावश्यक रूप से जांच किस बात के लिए। इसलिए मैं सहमत नहीं हूं।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं-नहीं, जांच करने के लिए नहीं, निरीक्षण करने के लिए बोल रहा हूं। निरीक्षण करने की बात है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, जांच के लिए मांग नहीं कर रहे हैं, निरीक्षण करने के लिए कह रहे हैं। निरीक्षण बंद ना हो जाय। यदि विधानसभा बंद हो जाएगा तो निरीक्षण भी बंद हो जायेगा।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष जी, हम जांच के लिए नहीं कह रहे हैं। निरीक्षण तो करा दीजिए। हमारे ही प्रदेश के संस्थान में निरीक्षण ना कर सकें, यह तो अच्छी बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, मैंने आपकी मांग को सुन लिया है। मैं देखता हूं। मोहन मरकाम जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, प्लांट मेरी विधानसभा से लगा हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है। उस क्षेत्र के लोग दमा से पीड़ित हो रहे हैं और दमा से पीड़ित होने के कारण वहां पर यह होता है। फैक्ट्रियों के द्वारा नदियों में भी प्रदूषित जल छोड़ा जाता है और नदियां प्रदूषित हो जाती है। हमारी खारून नदी प्रदूषित हो रही है। उसके


अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लिए वे लोग वहां पर प्लांट लगाकर रखते और चालू नहीं करते हैं क्योंकि खर्चा बहुत है। वह अनावश्यक रूप से संचालित है। वहां के लोग दमा से पीड़ित हैं। उसके लिए माननीय सदस्य की मांगें बहुत गंभीर है।

अध्यक्ष महोदय :- सब जगह यही हाल है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां है तो वहां इस तरह की समस्या नहीं है। यह जहां की बात कर रहे हैं वहां पर कोई नदियां-वदियां नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके लिए वहां पर वह लोग प्लांट लगाकर रखते हैं लेकिन उसको चालू नहीं करते हैं क्योंकि उसमें खर्चा बहुत है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अनावश्यक बोलते हो, ये सनसनी खर्चा करने वाला काम करते हैं। वहां पर कुछ नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह प्लांट चालू रहे और वहां के लोग दमे से पीड़ित नहीं हो, इसके लिए माननीय सदस्य की मांग है गंभीर...।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन है मैं आपसे एक चर्चा किया था, आप ही बोले थे कि हमारी सरकार को आने दीजिए, प्रदूषण वाहक बंद कर देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- बताइये न। चलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक विधायक की चिंता के इस सदन को...।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- जो गड़बड़ करते हैं उनको हम लोग बंद करते हैं। गड़बड़ करने वालों को यह संरक्षण देते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्कुल आप बंद करा दीजिए।

श्री धर्मजीत सिंह :- बाकी सदस्यों का ही प्रश्न लगा। आप बोले थे, आपको याद होगा।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- इनको जानकारी ही नहीं है। अपनी तरफ से बोलना शुरू कर देते हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह कोई जांच के लिए थोड़ी न बोल रहे हैं सिर्फ निरीक्षण करने के लिए बोल रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- भाई साहब।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप इतना अधिकार तो उन जिलों के विधायकों को दिलवा दीजिए। मंत्री जी, आपको भी बड़ा दिन दिखाकर इनको दिखवाने के लिए दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है ? कोई निरीक्षण, इंसफेक्शन के लिए इन्क्वायरी कमेटी थोड़ी न बन रही है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदा बजार, भाठापारा जिला पूरे देश में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला है।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल।

श्री शिवरतन शर्मा :- जहां हमारे लिए गौरव की बात है वही हमारे लिए दुर्भाग्य यह है कि पूरा जिला इस उत्पादन के चलते प्रदूषण का शिकार हो रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, शर्मा जी का प्रवचन चलता रहेगा, बाकी लोगों को मोहन मरकाम जी का प्रश्न आ गया है। अनुमति दी जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- खदानें खोदी जा रही हैं। सौ-सौ फीट गहरी खदान...।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं। यह विषय से हटकर प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी का प्रश्न छोटा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। प्लीज-प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- सौ-सौ फीट गहरी खदान खुद गई है उसकी फीलिंग की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। अब इस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनको दो बार नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब आया और हमने उसको नस्तीबद्ध कर दिया। भाई, आपने अनियमितता पाई तो आपने नोटिस दी और नोटिस का जवाब आने के बाद आपने नस्तीबद्ध कर दिया। अगर आपने अनियमिता पाई, नोटिस दिये तो उसपर कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए। आपने खाली जवाब देकर नस्तीबद्ध कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह विचार कर रहे हैं न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। आपको इसपर आखिर कार्रवाई तो करनी थी। नस्तीबद्ध करने पर...।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उतने में शामिल नहीं होता। एफ.जी.डी. जो यह बोल रहे हैं न एफ.जी.डी., केंद्र सरकार का टोको कोटियो प्रोटोकोल के बाद वर्ष 2022 तक। यह तो छोटे संयंत्रों की बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सारे थर्मल पॉवर प्लांटों में एफ.जी.डी., सल्फर डी सफ्सडाइजन लगाना है। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इतने छत्तीसगढ़ के थर्मल पॉवर प्लांटों में एफ.जी.डी. फ्यूल, एफ.जी. सल्फराइजेशन को यूज। यह छोटे यूनिट की बात कर रहे हैं सारे बड़े यूनिटों में लगा है।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- सारे फैक्ट्री तो मोदी जी बेचने के लिए लगा रहे हैं। सारे फैक्ट्री तो मोदी जी बेचने के लिए लगा रहे हैं। मोदी जी सारे फैक्ट्री को बेचने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई काम है भाई।

अध्यक्ष महोदय :- अभी समय है। आप ध्यानाकर्षण ले लीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- ये सारे थर्मल प्लांट में कब तक लगेगा ?

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष  महोदय, यह थोड़ा कठिन प्रश्न है। उस गति से नहीं। बहुत कठिन प्रश्न है। उनको समझने दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- इन सारे थर्मल प्लांटों में कब तक लगेगा ? यह तो सरकार का स्पष्ट निर्देश है वर्ष 31.03.2022 तक।

श्री बृहस्पत सिंह :- केंद्र सरकार का सख्त गाईड लाइन है।

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, आप प्रश्न करें।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से...।

श्री बृहस्पत सिंह :- बेचने का है।

श्री सौरभ सिंह :- सारे थर्मल पॉवर प्लांटों में लगाना है। यह छोटे प्लांट की बात कर रहे थे, एक्सिटिंग जितने थर्मल पॉवर प्लांट हैं सब में लगाना है। जितने थर्मल पॉवर प्लांट हैं सब में लगाना है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छत्तीसगढ़ में जो बीमार हो रहे हैं उसके लिए पर्यावरण विभाग जिम्मेदार होगा।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- क्यों बृजमोहन भैय्या, आप बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष  महोदय, मंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए है। वह जवाब दे रहे हैं। उनका जवाब आ जाए।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब दे रहे हैं ?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरे छत्तीसगढ़ का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं ।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बलौदा-बाजार की जनता अभी सुन रही है। लाइव टेलीकास्ट है। आपकी तरफ भी देख रहे हैं, उधर मंत्री जी की तरफ देख रहे हैं। इधर भी देख रहे हैं। वहां जांच करने से कोई बिजली नहीं गिर जाएगी। आप सिर्फ जांच ही नहीं सिर्फ निरीक्षण करने की मैं बात कर रहा हूं। निरीक्षण करावा दीजिए। उन्हें क्या तकलीफ है देख में ?

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- नियमित निरीक्षण होता है। इनको बता दीजिए प इनको कि नियमित निरीक्षण होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के नव-निर्माण में उन लोगों का बहुत योगदान है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस एफ.जी.डी. के बारे में आप जानकारी मांग रहे हैं तो उसमें एफ.जी.डी. की व्यवस्था वर्ष 2034 तक लगाने का समय दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

**<u>ग्राम बड़बत्तर जिला कोण्डागांव में नये उप केन्द्र स्थापना</u>**

**<u>[ऊर्जा]</u>**

**7. ( *क्र. 62 ) श्री मोहन मरकाम** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) क्या जिला प्रशासन कोण्डागांव अथवा राज्य शासन को ग्राम बड़बत्तर जिला कोण्डागांव में नये उप केन्द्र स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ? यदि हां तो कब व दिनांक 15 फरवरी, 2022 तक इस पर क्या कार्यवाही की गई ? (ख) कंडिका क के अनुसार ग्राम बड़बत्तर में नये उप केन्द्र की स्थापना से किन-किन समस्याओं का निराकरण व कौन-कौन से ग्राम इस योजना से लाभान्वित होना प्रस्तावित है ?

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल)** : (क) जी हॉ। ग्राम बड़बत्तर जिला कोण्डागांव मे नये 33/11 केव्ही के उपकेन्द्र स्थापना हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य विधानसभा क्षेत्र कोण्डागांव से दिनांक 01.06.2021 को ऊर्जा विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को प्राप्त हुआ था। उक्त उपकेन्द्र के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना वर्ष 2021-22 में शामिल किये जाने पर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। दिनांक 15.02.2022 की स्थिति में उक्त उपकेन्द्र का प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है। (ख) उत्तरांश ''क' के ग्राम-बड़बत्तर में प्रस्तावित नये 33/11 केव्ही उपकेन्द्र की स्थापना से विद्युत उपभोक्ताओं के निम्नलिखित समस्याओं का निराकरण होगा:- 1. बड़ेराजपुर विकासखण्ड में अल्पवर्षा अथवा रबी फसल के दौरान कृषि पंपों का भार वृद्धि होने के कारण से क्षेत्र में लो-वोल्टेज की समस्याओं का निदान संभव होगा। 2. वर्तमान में 132/33 के0व्ही0 उपकेन्द्र मसोरा से निकलने वाले 33 के.व्ही. रांधना फीडर की लंबाई 45 किमी होने एवं अतिभारित होने के कारण विद्युत व्यवधान अत्यधिक होने की समस्याओं का निराकरण होगा। ग्राम-बड़बत्तर में 33/11 के.व्ही. का नया उपकेन्द्र स्थापित किये जाने से ग्राम बड़ेराजपुर, धामनपुरी, किवड़ा कुलदाडिही, पीडहापाल, बड़बत्तर, गम्हरी, करमरी, जोड़ेकेरा, बागबेड़ा, तितरावन, पिटिसपाल आदि ग्राम लाभान्वित होंगे।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से लो वोल्टेज की समस्या के बारे में प्रश्न किया था। माननीय मुख्यमंत्री महादेय का उत्तर आ गया है। मेरा प्रश्न है पुसापाल, कोटवेल, देव डोंगर, उलेरा, बागबेड़ा, मगेदा, भतवा, ओतेंदा, सोनाबेड़ा, बागबेड़ा, गुहागोरोड़ इतने गांवों में बहुत अच्छी खेती होती है और यहां लो वोल्टेज के कारण फसल बर्बाद हो जाता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नये उपकेंद्र 33/11 के.वी. बड़बत्तर में स्वीकृति प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर मैंने जो गांव गिनवाया, ये गांव उसमें शामिल नहीं है। क्या आप इसकी केपिसिटी बढ़ाएंगे ? या फिर इनके लिए इन गावों में नया सब स्टेशन खोलेंगे क्या, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जनना चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसमें उन्होंने लिखा है कि क्या बड़बत्तर जिला कोण्डागांव में उपकेंद्र स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ? तो निश्चित रूप से माननीय सदस्य के द्वारा ही प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रस्तावित किया गया था और उसमें परीक्षण किया गया और उसके लिए स्वीकृति दी गई। इससे जो बड़बत्तर में नया 33.11 के.वी. के जो नया उप केंद्र स्थापित किये जाने से ग्राम बड़ेराजपुर, धामनपुरी, किवड़ा, पीडहापाल, बड़बत्तर, गम्हरी, करमरी, जोड़ेकेरा, बागबेड़ा, तितरावन, पिटिसपाल आदि ग्राम लाभान्वित होंगे। अब माननीय सदस्य नया प्रस्ताव देंगे तो उसके बारे में विचार किया जाएगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो उत्तर दिया है, उसमें वर्तमान में 132/33 के0व्ही0 उपकेन्द्र मसोरा से निकलने वाले 33 के.व्ही .रांधना फीडर की लंबाई 45 किमी होने एवं अतिभारित होने के कारण विद्युत व्यवधान अत्यधिक रहता है ! इन गांवों में सबसे ज्यादा खेती करते हैं, जिसमें मक्का उत्पादन करते हैं और लो वोल्टेज की समस्या के कारण 15 गांव में फसल चौपट हो जाती है । मैंने जो गांव गिनाये हैं, वह ग्राम बड़बत्तर से लगे हुए हैं, मगर मसोरा से दूरी हो जाती है, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । क्या ग्राम बड़बत्तर में इसकी क्षमता बढ़ाएंगे, ताकि उससे लगे हुए गांव के किसानों को फायदा मिल सके या फिर इन गांव में 33/11 के0व्ही0 के अतिरिक्त उपकेन्द्र स्थापित करेंगे क्या ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के ही प्रस्ताव से ग्राम बड़बत्तर में यह उपकेन्द्र स्वीकृत हुआ है । यदि वे नया प्रस्ताव उस समय ही दे दिये होते तो अब तक उसका परीक्षण भी करा लेते, तकनीकी रूप से एग्जामिन कराकर उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, लेकिन माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव दिया है, उसका तकनीकी रूप से परीक्षण करा लेते हैं और तकनीकी रूप ये यदि वायबल हुआ तो निश्चित रूप से स्वीकृति प्रदान करके कार्यवाही की जाएगी ।

श्री मोहन मरकाम :- मुख्यमंत्री जी, धन्यवाद ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आप संतुष्ट है न ?

श्री मोहन मरकाम :- जी ।

प्रश्न संख्या : 8 XX XX

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यारतन जी ने मुझे अधिकृत किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका पत्र नहीं आया है ।

श्री धरम लाल कौशिक :- उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पत्र भेजा है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- विद्यारतन जी तो लिखकर नहीं दे हे ।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं दिए होंगे तो हम प्रश्न नहीं पूछेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- उनका पत्र नहीं आया है । सॉरी ।

श्री धरम लाल कौशिक :- कोई बात नहीं ।

अध्यक्ष महोदय :- शिवरतन जी ज्यादा खतरनाक आदमी हैं, उनको प्रश्न पूछने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, इस सदन का कोई सदस्य खतरनाक नहीं है, सभी सदस्य हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- ज्यादा खतरनाक हैं, सभी खतरनाक हैं ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, यदि आप अनुमति दें तो मैं इसमें एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- पूछिए ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- प्रश्न संख्या 8 में ?

श्री धरम लाल कौशिक :- हां ।

अध्यक्ष महोदय :- वे सीएलपी लीडर हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा करिए न । शिवरतन जी प्रश्न कर रहे हैं, उसमें आप अनुपूरक प्रश्न कर लीजिए । जब आपको प्रश्न संख्या-8 में अनुमति नहीं मिली है तो आप प्रश्न कैसे कर सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, तकनीकी दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा ।

श्री धरम लाल कौशिक :- ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, शिवतरन जी ।



अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

## वित्त विभाग द्वारा नवीन भर्ती की स्वीकृति

**[वित्त]**

**9. ( *क्र. 238 ) श्री शिवरतन शर्मा** : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2018 से दिनांक 8/02/2022 तक किन- किन विभागों को किन-किन श्रेणी के कितने-कितने पदों की भर्ती हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है?

**मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल)** : वित्त विभाग द्वारा दिनांक 18 दिसम्बर 2018 से 08/02/2022 तक प्रथम श्रेणी के 1725, द्वितीय श्रेणी के 4176, तृतीय श्रेणी के 28088 एवं चतुर्थ श्रेणी के 6046 कुल 40035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की गयी है। विभागवार जानकारी परिशिष्ट†[5] में संलग्न है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न को पूरी तरह से संशोधित कर दिया गया । मैंने प्रश्न में चार बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी और सिर्फ एक बिन्दु को शामिल किया गया, तीन बिन्दुओं को काट दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधित हमने किया है या मुख्यमंत्री जी ने किया है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो मानकर चलता हूं कि विधान सभा ने ही संशोधित किया है ।

अध्यक्ष महोदय :- हां तो उस बात को छोड़िए, आप नहीं कह सकते ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, ठीक है । जो एक बिन्दु पर जानकारी आई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि वित्त विभाग ने शासकीय सेवाओं में भर्ती हेतु 3 वर्षों में 40035 पदों हेतु स्वीकृति प्रदान की है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि कुल 20 हजार बेरोजगारों को नौकरी दी गई है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग से 40 हजार लोगों की स्वीकृति मिली है, उसमें से कितने लोगों को, किस-किस विभाग में आपने नौकरी दी और बाकी लोगों को कब तक नौकरी दे देंगे, वह प्रक्रिया कहां तक हुई है, इसकी जानकारी दे दें ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, इसका प्रश्न वैसे भी व्यापक है और अभी भी जो पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, वह इतना व्यापक है कि किस-किस विभाग में कितना पद स्वीकृत हुआ और उसकी परीक्षाएं कब हुईं, उसकी नियुक्ति कब होगी और नहीं हुआ तो कब तक होगी ? यह बहुत व्यापक प्रश्न है । आप कहेंगे तो मैं एक-एक करके बताता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप छोटा सा उत्तर दे दीजिए, जिससे शिवरतन जी संतुष्ट हो जाएं ।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरे पास हर विभाग की जानकारी है, मैं बता देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- इतने बड़े व्यापक प्रश्न को आप कैसे कर रहे हैं महाराज ।

---

†[5] परिशिष्ट-छः

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग में 2018-19 में प्रथम, द्‍वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की कोई भर्ती नहीं हुई । 2019-20 में तृतीय श्रेणी में 1425, चतुर्थ श्रेणी में 28 पदों पर कुल 1453 पदों पर भर्ती हुई है । 2020-21 में कोई भर्ती नहीं हुई, 2021-22 में प्रथम श्रेणी में 1, द्‍वितीय श्रेणी में 976, तृतीय श्रेणी में 2146, चतुर्थ श्रेणी में 7 पदों पर भर्ती हुई है । कुल योग 3,130, महायोग 4,583. अध्यक्ष महोदय जेल विभाग में कोई भर्ती नहीं हुई। वर्ष 2019-20 में परिवहन विभाग में 35 लोगों की भर्ती हुई है, योग 35 भर्ती हुई हैं। ष 2020-21 में 25, कुल योग 25 लोगों की भर्ती हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- यह सब जानकारी तो परिशिष्ट में है, वह पढ़ लेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, यही तो जानकारी मांग रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न किया है उस पर आपने परिशिष्ट में 48 विभागों की में हुई भर्तियों की जानकारी दी हैं। 40,035 पदों की स्वीकृति वित्त विभाग ने दी है।

श्री भूपेश बघेल :- जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इसमें से कितने लोगों की नौकरी लग गई और जो शेष रह गये हैं, उनको कब तक नौकरी दे देंगे ? वह प्रक्रिया कहां तक पहुंची है ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, वह तो प्रक्रिया है। शीघ्रताशीघ्र भर्ती हो जायेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रक्रिया है, कहकर टालने वाली बात है। यह प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय :- टालने वाली बात नहीं है। प्रक्रिया चल रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जन घोषणा-पत्र को आत्मसात किया है। आपने जन घोषणा-पत्र में सीधा कहा है कि ..। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या बिना प्रक्रिया के हो जायेगा क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इन लोगों ने पिछले 15 सालों में एक भी नौकरी नहीं दी है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं सीधा प्रश्न कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी, प्लीज।

श्री भूपेश बघेल :- तो क्या आप लोग ही खड़े हो सकते हैं क्या ? दूसरे लोग खड़े नहीं हो सकते हैं क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारा अधिकार है।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं तो, आप जैसा चलाना चाहो वैसा नहीं चलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विपक्ष को अधिकार है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अगर विपक्ष को अधिकार है तो सत्तापक्ष को भी उत्तर देने का अधिकार है।

श्री भूपेश बघेल :- ऐसा है, ट्रेजरी बैंच के अलावा सभी अशासकीय सदस्य हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह मंत्री जी हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न पूछा है कि भर्ती हेतु स्वीकृति दिए गए पदों में से कितने पदों पर भर्ती पूर्ण कर ली गई है तथा कितने शेष है और कब तक भर्ती कर लेंगे ? अध्यक्ष महोदय, 40,035 पदों की स्वीकृति दी गई है। कुल पदों में से 11,494 पदों की भर्ती पूर्ण कर ली गई है तथा शेष 28,541 पदों की भर्ती प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है। जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण होगी सबकी भर्ती हो जायेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 हजार पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। यह प्रक्रिया कितने दिनों में पूरा कर लेंगे ? इसकी समय सीमा बता दें ?

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, समयसीमा बताना संभव नहीं है। मान लो किसी व्यक्ति का पुलिस वेरीफिकेशन करना है, तो उसमें समय लगेगा। बहुत सारी प्रक्रिया है, जिसको करना पड़ता है। अब उसमें समयसीमा बता पाना संभव नहीं है। 40 हजार लोगों की भर्ती होना है, जिसमें से 11,494 लोगों की भर्ती हो चुकी है। शेष जो 28 हजार पदों की भर्ती है, उसकी प्रक्रिया जल्दी कर लेंगे।

श्री अमरजीत भगत :- शिवरतन जी को समझ में क्यों नहीं आता ? जब प्रक्रिया चल रही है तो उनको समझ में क्यों नहीं आता ? समझा करो। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी हो जाता है और विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक भाषण अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको छोड़िये न। कुलदीप जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण बात है। अधिसूचना जारी होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक भाषण होता है कि हमने 2 लाख 80 लोगों को रोजगार दे दिया और अभी बोल रहे हैं कि 11 हजार लोगों को रोजगार दिए हैं।

श्री भूपेश बघेल :- इनका मुंह बंद करिये। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया गया है।

श्री भूपेश बघेल :- आप बैठिये, आप बैठ जाईये। अध्यक्ष महोदय, इनको समझ में नहीं आयेगा। आप इनके समय का 15 साल का रिकार्ड निकालकर देख लीजिये कि कितनी भर्तियां हुई हैं और हमारे 3 साल का रिकार्ड देख लीजिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान्, मैं आपके कार्यकाल की बात कर रहा हूं, आप इनके समय की बात मत करो।

श्री भूपेश बघेल :- आप सुनो न भाई, आप सुनो, यह सदन आपका ही नहीं है, हम लोगों का भी है, हम लोगों को भी बोलने का अधिकार है। आप बैठ जाईये। आप बैठिये तो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, पिछले 3 साल में सर्वाधिक भर्तियां हुई हैं। इनके कार्यकाल जितनी भर्तियां हुई हैं, हमने उससे डबल भर्तियां एक-एक साल में किया है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, जहां तक रोजगार की बात है, मैं एक ही उदाहरण देता हूं कि इनके शासनकाल में केवल 15 लाख किसान खेती करते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में 22 लाख किसान धान बेचे हैं। 9 हजार लोग वापस गांव खेती करने गये हैं। क्या यह रोजगार नहीं है ? क्या यह स्थाई रोजगार नहीं है ? शासन द्वारा लगातार विभिन्न प्रकार से कार्यवाही की जा रही है, लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, नौकरियां दी गई हैं, शासकीय, अर्द्धशासकीय, स्थाई नौकरियां दी जा रही हैं।

श्री अमरजीत भगत :- हर साल नौकरी देने वालों से कभी पूछ लिया करो।

श्री भूपेश बघेल :- आप कभी उनसे पूछ लिया करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे शासनकाल में अधिक रोजगार दिया गया है और आने वाले 5 साल में 12 से 15 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ के लोग बेरोजगार पड़े रहते थे हमने रोजगार उपलब्ध कराया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके शासनकाल में 563 लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन हमारे शासनकाल में 12 हजार लोगों को हर साल रोजगार मिला है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

**(प्रश्नकाल समाप्त)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश बघेल जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अभी हो जाने दीजिए । ऐसा नहीं चलेगा । ऐसा नहीं होता है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- शून्यकाल में हमको व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- पहले यह शासकीय कार्य तो हो जाये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम उसको भी करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- करने दीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप समय क्यों खराब कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमें व्यवस्था का प्रश्न उठाने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय :- हो तो जाने दो । कर लीजिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी ...व्यवधान आते हैं । (व्यवधान) ....बात करते हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री अगर उटपटांग कमेंट करेंगे तो अच्छी बात नहीं है । मंत्रियों को अपनी सीमा में रहना चाहिये । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपकी आसंदी के रहते हुये तमीज नहीं है कि किस के साथ में क्या व्यवहार करना चाहिये । मंत्रियों को बिल्कुल तमीज नहीं है ।

एक माननीय सदस्य :- माननीय सदस्य द्वारा मंत्री जी पर ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है ।

(व्यवधान)

समय :

12:01 बजे

**<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>**

**<u>(1) वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का बजट निष्पादन (परफार्मेन्स बजट)</u>**

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं, वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट परफार्मेन्स बजट पटल पर रखता हूँ ।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

**(2) छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय, निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमंक 43 सन् 1973) की धारा 8-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा अंकेक्षित स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायत राज संस्थाओं, अनुदान प्राप्त एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूँ ।

**(3) छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22**

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 पटल पर रखता
हूँ ।

**(4) छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2018-2019**

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमंक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवंहिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2018-19 पटल पर रखता हूँ ।

**(5) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यारित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21**

सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**(6) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित अपैक्स बैंक का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक ऑडिट रिपोर्ट एवं 2020-2021**

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपैक्स बैंक) का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ ।

**(7) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21**

सहकारिता मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूँ ।

**(8) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015- 16, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 एवं 2019-2020**

सहकारिता मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015-16, 2016-2017, 2017-18, 2018-19, 2019-20 पटल पर रखता हूँ ।

**(9) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-21**

सहकारिता मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्रमांक 17 सन 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखता हूँ ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**(10) परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 13 सितम्बर, 2021**

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 पटल पर रखता हूं।

**(11) छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21**

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि अधिनियम, 2016 (क्रमांक 38 सन् 2016) की धारा 29 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

**(12) छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21**

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 पटल पर रखता हूं।

**(13) अधिसूचना क्रमांक एफ 20-1/2017/38-2 (पार्ट), दिनांक 18 सितंबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020**

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 की उपाधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 20-1/2017/38-2 (पार्ट), दिनांक 18 सितंबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (दूर-परिसर केन्द्र एवं अध्ययन केन्द्र की स्थापना) नियम, 2020 पटल पर रखता हूं।

**(14) छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

तकनीकी शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

**(15) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2019, दिनांक 4 फरवरी, 2020**

राजस्व मंत्री (श्री जय सिंह अग्रवाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 4-47/सात-1/2019, दिनांक 4 फरवरी, 2020 पटल पर रखता हूं।

**(16) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20**

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, कंपनी अधिनियम 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 पटल पर रखता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी सदन में उपस्थित हैं। आपने कहा था कि यह उदाहरण मत बने। या तो वह अनुपस्थित रहें तब बोलें और उपस्थित रहें तो न बोलें। यह मैं जानता हूं। यह व्यवस्था आपने दी थी।

श्री अमितेश शुक्ल :- वह साधु आदमी हैं, वह ध्यान में हैं।

समय :
12:07 बजे

**कार्यमंत्रणा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 7 मार्च 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिये सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

**1. वित्तीय कार्य**

(1) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थान, विचार एवं पारण मंगलवार, दिनांक 8 मार्च, 2022 का रखा जाये तथा इस इस पर चर्चा हेतु 3 घंटे का समय निर्धारित किया जाता है।



अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरी व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। इसी में मैं बोल रहा हूं। कार्यमंत्रणा समिति में हम लोग उपस्थित थे। कार्यमंत्रणा समिति में समय तय किया गया, डेट तय नहीं की गई। आप जो डेट का उल्लेख कर रहे हैं, हम यहां कार्यमंत्रणा समिति का उल्लेख नहीं करते हैं। मैं आपसे इस बात का हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि ये सदन की उच्च परंपरायें रहीं हैं, जो हमारी कार्यमंत्रणा समिति में तय होता है, आपने 3 घंटे समय तय किया था, आपने दिन तय नहीं किया था। आप जो दिन का उल्लेख कर रहे हैं, वह उचित नहीं है। अगर वह उचित नहीं है तो आप उसको विलोपित कर दें।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- दिन तो अध्यक्ष जी तय करके बताते हैं न। अध्यक्ष जी, उनको बता दीजिए कि उस पर विचार कर लिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, वह क्यों खड़े हो जाते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको समझना चाहिए न कि अध्यक्ष जी समय, तारीख तय करते हैं और आपको बता रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- कल तो आप लोगों के सामने ही बात हुई थी। इसमें 8 तारीख तो तय था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, कोई बात नहीं हुई।

अध्यक्ष महोदय :- 8 तारीख की बात हुई है। मेरी बात सुनिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, कार्यमंत्रणा समिति इस सदन की सर्वोच्च समिति है।

अध्यक्ष महोदय :- वह बात सही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कार्यमंत्रणा समिति में जो निर्णय हो उस निर्णय के बारे में यहां पर जानकारी हूबहू आये। लगभग मुझे भी इस सदन में 33 साल हो गये। कभी उसको वेरीयेशन नहीं होता है। ये वेरीयेशन होने लगता है, टंकण त्रुटि भी हो सकती है, गलती भी हो सकती है। उसको विलोपित कर दें तो ज्यादा उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी बात सुनिये। जहां तक मैं जानता हूं कि 8 तारीख की बात हुई थी, 9 तारीख के लिए आपने कहा था, 2, 3 दिन चर्चा होनी चाहिए। 9 तारीख के लिए आपने कहा था कि दो दिन चर्चा होनी चाहिए, 8 पर बात नहीं हुई थी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं आज की चर्चा। हमने आपको यह कहा था कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर 02 दिन चर्चा होनी चाहिये और यदि ऐसा होगा तो आगे


अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय में भी परिवर्तन हो सकता है। तो हमें इसके ऊपर में विचार करना पड़ेगा, हमारे पास नेता प्रतिपक्ष भी है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप मत सोचिये। आप ज्यादा दूर मत जाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय नेता प्रतिपक्ष भी है, वह भी अपनी बात रख सकते हैं कि क्या निर्णय हुआ था। हमने इस बात की मांग की थी कि राज्यपाल के अभिभाषण पर 02 दिन की चर्चा होनी चाहिये, एक दिन की नहीं होनी चाहिये।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जी प्रश्न करेंगे तब तो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने कार्य मंत्रणा समिति में इस बात का निर्णय किया कि 03 घण्टा चर्चा होगी, समय का निर्धारण हुआ था लेकिन 02 दिन का निर्धारण नहीं हुआ था।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो नेता प्रतिपक्ष को नेता प्रतिपक्ष मानते ही नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तो खड़े हो गये है। (श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य की ओर इशारा करते हुये।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कल आसंदी से कहा तो हमने कल भी इस बात को कहा था कि राज्यपाल जी के अभिभाषण के लिये नीयत दिन है इसलिये कल हमने कहा था कि यह नहीं होना चाहिये। कार्यमंत्रणा समिति में 08 तारीख को होगा यह तय नहीं हुआ था।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- तय हो गया था।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं इसमें हमारा यह आग्रह है कि पहले भी हमने जो परंपरा का उल्लेख किया था , उल्लेख करने के बाद हमने यही कहा था कि महामहिम का अभिभाषण में यह दोनों एक ही दिन में नहीं हो सकता। हमने कल भी उस बात का आग्रह किया था और इसलिये हम लोग आज भी इस बात को बोल रहे हैं कि जो 03 घण्टे का है वह 03 ही घण्टा रहेगा, उसको आप किसी भी तारीख को ले लीजिये। आज राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरू होगा और उसके बाद में आगे की कार्यवाही प्रोसिड होगी।

एक माननीय सदस्य :- यह तो भारी अन्याय वाली बात है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वर्षों से परंपरा रही है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुपूरक में भी चर्चा होती है। पहले भी हुई है, यह आज की ही परंपरा नहीं है, पहले भी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :-

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(2) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक का उपस्थापन बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022 को मध्यान्ह् 12:30 बजे किया जायेगा तथा आय व्ययक पर सामान्य चर्चा गुरूवार दिनांक 10 मार्च, 2022 को होगी। यह तो तय है ?

श्री धरम लाल कौशिक :- हां, यह तय है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने कहा था कि इसमें 02 दिन बढ़ा दिया जाये, हम उसको 10, 11 कर देते हैं, आपको आपत्ति है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- किसको बढ़ा दिया जाये ? नहीं सप्लीमेंट्री को बढ़ाया जाये, राज्यपाल के अभिभाषण को नहीं। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय :- भई, मैं बजट पर बात कर रहा हूं, क्या आज आप किसी से नाराज होकर आये हैं ? आपने कहा कि बजट पर दो दिन चर्चा के लिये चाहिये तो मैं बजट के लिये 02 दिन की बात कर रहा हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पुरंदेश्वरी जी के हंटर का असर है।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, बजट तो बुधवार को है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्य रात में बुबुआ जैसे जागते हैं और दिन में बघिया कहते हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- आगे बढ़ा दीजिये कोई दिक्कत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- उसको बढ़ा तो रहा हूं। आप लोग अचानक लगता है कि विरोध करने के मूड में आये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लीजिये। आपने अभी कहा कि 10, 11 मार्च को सामान्य अभिभाषण पर चर्चा करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में 02 दिन की चर्चा होती रही... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो राज्यपाल के अभिभाषण की बात ही नहीं कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- तो वह कब होगी, 10 एवं 11 मार्च को सामान्य बजट पर चर्चा होगी, कल बजट प्रस्तुत होगा ?

अध्यक्ष महोदय :-

(3) शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 से बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 2022 को अपरान्ह् 4:00 बजे तक वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में सम्मिलित विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी तत्पश्चात विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन किया जायेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक की अनुदान की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण होगा।

(5) वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक से संबंधित मंत्रियों के विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हेतु समय का निर्धारण किया गया , जो इस प्रकार है :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री | - | 2.30 घंटे |
| (2) | श्री टी.एस. सिंहदेव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री | - | 2 घंटे |
| (3) | श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री | - | 2 घंटे |
| (4) | श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री | - | 2 घंटे |
| (5) | डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री | - | 2 घंटे |
| (6) | श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री | - | 2 घंटे |
| (7) | श्री कवासी लखमा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री | - | 2 घंटे |
| (8) | डॉ. शिव कुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन मंत्री | - | 1 घंटे |
| (9) | श्रीमती अनिला भेंडिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री | - | 1 घंटे |
| (10) | श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री | - | 1 घंटे |
| (11) | श्री गुरू रूद्र कुमार, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री | - | 1 घंटे |
| (12) | श्री उमेश पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री | - | 1 घंटे |
| (13) | श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री | - | 1 घंटे |

**विधि विषयक कार्य**

छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर चर्चा हेतु 45 मिनट का समय निर्धारित किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे। उमेश पटेल जी आपको लिख के दिये हैं, आप बिल्कुल तैयार रहिये। आगे बैठ सकते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले व्यवस्था का प्रश्न यह करना चाहता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- करिये, मैं कहा रोक रहा हूं।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- एक ही चीज बोलते हो। (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- हमको भी तो कुछ बोलने दो। दादा-गर्दी नही चलाइये। दादा-गर्दी नहीं चलाइये।

श्री अजय चंद्राकर :- जिस समय बोलना है, उस समय बोलोगे नहीं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- बोलने के समय में मौन रहते हो और बाकी समय में सक्रिय रहते हो।

समय :
12:15 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

श्री अजय चन्द्राकर :- आप खुद बोलने के समय मौन रहते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप बोलने के समय मौन रहते हैं और बाकी समय में सक्रिय रहते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर से लाल वाला गमछा दिखायेंगे तो साण्ड जो है वह एग्रेसिव होगा ही। आप नहीं समझे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप साण्ड कौन है, यह बताईये? (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- वह साण्ड बाकी टाईम में नहीं रहता। वह बोलने के समय में साण्ड नहीं रहता। (हंसी)

श्री अमरजीत भगत :- अरे भई साण्ड की बात तो नहीं मान रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह माननीय नेता प्रतिपक्ष को कुछ बोलने देंगे या नहीं देंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ ऑर्डर है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय शिवरतन शर्मा जी का प्रश्न चल रहा था। उस प्रश्न के समय पर, उनको प्रश्न पूछने देने से रोकने के लिए 2, 3, 4 मंत्री खड़े होकर, उनके प्रश्नों को रोकने की कोशिश की। यह इस सदन की परम्परा नहीं है। मुख्यमंत्री जी स्वयं सक्षम हैं और अगर सदन में इस प्रकार से प्रश्नकाल में मंत्री बाधा उत्पन्न करेंगे तो मुझे लगता है कि सदस्यों का प्रश्न पूछना मुश्किल हो जाएगा और इसके बारे में...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े होकर उत्तर दे रहे हैं तो माननीय सदस्य को भी सलीका जानना चाहिए कि अगर माननीय सदन के नेता खड़े होकर कुछ उत्तर दे रहे हैं तो उनको बैठकर सुनना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, अब ध्यानाकर्षण को लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को हमको सलीका सीखाने की आवश्यकता नहीं है। हमें यह मालूम है। आप भी विपक्ष में रहे हैं। विपक्ष में आप लोगों का रोल कैसा

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

होता था,विपक्ष में हमको नाराज़गी, गुस्सा व्यक्त करने का अधिकार है, परंतु अगर सदन में हमको मंत्री नियंत्रित करना चाहेंगे तो यह उचित नहीं है। मैं आसंदी से इस बात का निर्णय चाहूंगा कि कम से कम प्रश्नकाल में, बाकी समय में तो हमारा वाद-विवाद चलता है क्योंकि प्रश्नकाल एक घण्टे का समय है और उस एक घण्टे में सीमित प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो। आसंदी की तरफ से इस बात का निर्णय आना चाहिए। मेरा आपसे इस बात का आग्रह है और मैं आपसे इस बात के लिए निवेदन करता हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत सारे जो सदस्य विपक्ष में हैं वह इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य रहे हैं तो सारी नियम, प्रक्रिया के बारे में सबको जानकारी है, सत्ता में भी रहे हैं और विपक्ष में भी रहे हैं। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सदस्य रहे हैं। इनकी जानकारी में सारी प्रक्रियाएं है, कोई इससे अछूता नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस स्वस्थ परम्परा की बात माननीय बृजमोहन जी कह रहे हैं, बिल्कुल उसका स्वागत है।लेकिन जिस प्रकार से यदि सदन का नेता या प्रतिपक्ष के नेता यदि खड़े हों तो अन्य सदस्यों को उस समय खड़े नहीं होना चाहिए, आसंदी की अनुमति से ही खड़े होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से इसका अवमूल्यन विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है यह बहुत तकलीफदायक है। दूसरी बात माननीय बृजमोहन जी इतने वरिष्ठ सदस्य हैं हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, वह हैं भी। उन्होंने इस सम्मान को कमाया है। लेकिन आज जिस प्रकार के शब्दों का, वैसे अमरजीत भगत से उनके बहुत अच्छे संबंध हैं लेकिन उन्होंने कहा कि आप सीमा से बाहर जा रहे हैं, तमीज नहीं है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। यदि आप, माननीय सदस्य इसमें व्यवस्था मांग रहे हैं तो इसमें भी व्यवस्था आनी चाहिए। यह मैं आसंदी से कहना चाहूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय मुख्यमंत्री जी शायद आपने नहीं सुना। उन्होंने मेरे लिए किन शब्दों का उपयोग किया है।आपने शायद नहीं सुना। हम इस सदन में कभी भी किसी व्यक्तिगत मामलों में कभी उल्लेख नहीं करते हैं, उसमें कमेंट्स नहीं करते हैं। आपके मंत्रियों ने किन शब्दों का उपयोग किया, शायद आपने नहीं सुना। मेरे मुंह से वह शब्द क्यों निकला? उसका कारण यह था कि उन्होंने मेरे व्यक्तिगत मामलों में शब्दों का उपयोग किया। इसलिए मैंने उनको यह बात कही। सामान्यत: यह सदन की परम्परा रही है कि किसी के भी व्यक्तिगत मामलों में हम इस बात की चर्चा नहीं करते हैं। मैं चाहूंगा कि सदन में अगर हम लोगों को व्यक्तिगत मामलों में चर्चा करने लगेंगे तो हमाम में कोई भी ...। वह मैं नहीं बोलना चाहता। इसलिए व्यक्तिगत मामलों में कम से कम कमेंट्स, इस सदन में न करें। हम नहीं करते, अभी आपने देखा कि मोहम्मद अकबर जी ने कवासी लखमा जी की तरफ से पढ़ा तो हमने उसको मजाक में ले लिया। हमको माननीय सदस्य की मजबूरी मालूम है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन भईया, आप तो बहुत सारी बातों को वह कर लेते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल:- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो हम अगर सदन में सदस्यों की गरिमा का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभी सम्मानीय सदस्य हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी मेरा एक निवेदन है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन जी, आप तो कभी विचलित नहीं होते थे और न किसी बात को माईंड करते थे। हंटर का असर स्पष्ट दिखायी दे रहा है। वही तो मैं बोला।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी मैं आपको बोलने का समय दूंगा, आप बैठिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य गुस्सा क्यों कर रहे थे?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन की मान्य परम्पराओं का उल्लेख किया कि सदन के नेता या नेता प्रतिपक्ष खड़े हों तो उन्हें खड़े नहीं होना चाहिए। मैं उनकी बात को स्वीकार करता हूँ। पर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जब इस सदन में नेता प्रतिपक्ष खड़े होते हैं या इधर से विपक्ष प्रश्न करता है तो आपकी तरफ से मंत्री कितना व्यवधान करने को खड़े होते हैं, आप जरा कार्रवाही निकालकर देख लीजिए। कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आपके दो मंत्री ऐसे हैं कि हमेशा खड़े हो करके कुछ न कुछ कमेंट्स करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं और जानबूझकर प्रश्नकाल को बाधित किया जाता है। आपको उसको दिखवाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए बैठिए।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे मान लीजिए कोई सदस्य खड़े हों, परंपरा क्या है, व्यवस्था क्या है ? यदि किसी सदस्य को बोलना है तो आसंदी में बैठे हैं, आपसे अनुमति मांगते हैं। अभी आप निकाल करके देख दीजिए, शिवरतन जी बैठकर ऊंगली उठा करके आपसे अनुमति नहीं मांगे। खड़ा होकर मांगे, जबकि खड़े होने की न परंपरा है न अनुमति है। आप खड़े होकर आसंदी से अनुमति मांग रहे हैं। आप कितना पालन कर रहे हैं, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, कम से कम इन सब चीजों का पालन करना चाहिए।

(श्री शिवरतन शर्मा जी के खड़े होने पर)

श्री भूपेश बघेल :- आप फिर खड़े होकर अनुमति मांगेंगे। आप बैठे-बैठे आसंदी से अनुमति मांग लीजिए। मुझसे नहीं आसंदी से अनुमति मांग लीजिए लेकिन बैठे-बैठे अनुमति मांग लीजिए। आप खड़ा होकर अनुमति मांग रहे हैं। आप अनुमति नहीं मांग रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब कोई बैठकर ऊंगली दिखाकर अनुमति मांगी जाए। खड़ा होकर अनुमति मांगी जाए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ लोगों को ऊंगली करने की ही आदत है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष में हम लोग यह देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का सम्मान विपक्ष के साथी लोग नहीं कर रहे हैं। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह :- नेता जी, एक मिनट। मैं कुल मिलाकर यह देख रहा हूं कि यहां पर किसी की कोई मंशा खराब नहीं है। कल इनके विधायक दल की बैठक का ही असर है कि ये जरा ज्यादा खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वयं सक्षम हैं, आप खड़े हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, वे जानते हैं। आप क्यों मुख्यमंत्री जी को सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए हो। मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं। यह विधायक दल का 24 घंटे असर रहता है। आज असर खत्म हो जाएगा, कल से सब नार्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कल मीटिंग हुई है न तो उसका असर रहेगा। अमितेश जी और वोरा जी खड़े नहीं होंगे तो कैसे बनेगा ? आप सी.सी.टी.व्ही. कैमरे के जद में हैं। कल की मीटिंग के बाद देख रहे हैं, सी.एम. साहब हैं करके आप लोग ज्यादा खड़े हो रहे हो। मत खड़े हो, वे पर्याप्त हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सब होने के बाद भी मैं कह सकता हूं कि बाकी राज्यों की विधानसभाओं की स्थिति देखते हैं...।

श्री अमितेश शुक्ल :- उधर भी खड़े हैं, उसका भी असर है।

श्री बृहस्पत सिंह :- उपाध्यक्ष महोदय, अभी बस्तर में मैडम पुरंदेश्वरी जी का दौरा हुआ था।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम तो खड़े हुए हैं लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष जी बोलते हैं तब सम्मानित प्रतिपक्ष के विधायक उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इस पर भी थोड़ी व्यवस्था आनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप सम्मान कर लो ना मैं खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, नेता जी, आप बोलिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- वे नहीं कर रहे हैं तो आप ही सम्मान कर लो मैं खड़ा हुआ हूं। आप बिना अनुमति के खड़े हो गये।

श्री अमरजीत भगत :- आप अगर इजाजत देंगे तो आपके सम्मान में एक शायरी बोलना चाहता हूं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप बाद में पढ़ना, अभी मत पढ़ो। शायरी को रहने दीजिए। आप अंग्रेजी में शायरी करने लगोगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- भगत जी, आप बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- "आप तो हर बात पर मुस्कुराया करते थे, ऐसा हम क्या बोले कि आप बुरा मान गए।"

श्री शिवरतन शर्मा :- वाह-वाह।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बोल रहा था कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा की जो परंपरा और गरिमा है। हम सब बना करके रखे हुए हैं और मैं अभी भी कह सकता हूं कि देश के अन्य विधानसभा को हम देखेंगे तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, बेहतर स्थिति में हैं। एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। कभी किसी न किसी बात पर इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है लेकिन हमारा कहना यह है कि जो प्रश्नकाल है सामान्यत: उधर के भी सदस्य खड़े हो जाते हैं, इधर के भी सदस्य खडे हो जाते हैं लेकिन जब मंत्री हस्तक्षेप करने लगते हैं, वहां पर दिक्कत आती है। इस विधानसभा में आप देखे होंगे कि लगातार यह बातें आ रही है लेकिन उसके बाद भी हम लोग यह मान करके चलते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। मैं उसके बाद भी कह रहा हूं कि बहुत आपत्तिजनक बात और यह स्थिति निर्मित न हो, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें। हम लोग सहजता के साथ मिल करके विधानसभा को चला रहे हैं, किसी एक की जवाबदारी नहीं है। केवल आसंदी की भूमिका नहीं है, हम लोगों की भी भूमिका है और उसमें हम सब लोगों का सहयोग भी मिले और सहयोग भी कर रहे हैं। अनावश्यक हस्तक्षेप न हो और कम से कम हो, आसंदी से इस बात की व्यवस्था आए। मुझे लगता है कि आगे कार्यवाही शुरू करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, शून्यकाल।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- हम जिस स्कूल में पढ़े हैं, आप वहां के हेडमास्टर हुआ करते थे। हम लोगों ने आपसे ही सीखा है।

(श्री कवासी लखमा जी के खड़े होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय :- दादी, मैं उसी चीज को बोल रहा हूं।

श्री अमितेश शुक्ल :- शर्मा जी, प्रतिपक्ष के नेता जी के बोलने के बाद फिर खड़े हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अमितेश जी, आप बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- सी.आर. ठीक हो रहा है।

**<u>व्यवस्था</u>**

उपाध्यक्ष महोदय :- आप सभी सदस्यों से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की अपनी एक स्वस्थ परंपरा है और किसी को भी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माननीय मंत्री और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि किसी को भी चर्चा के दौरान हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । माननीय मंत्री और सभी सदस्यों से अनुरोध है कि विधानसभा की गरिमा के अनुरूप आचरण करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, शिक्षाकर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पुलिसकर्मी



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सब सड़कों पर उतरे हुए हैं । जन घोषणापत्र में सरकार ने कहा था कि अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा और जनघोषणा पत्र को सरकार ने आत्मसात किया है परंतु उसके बाद भी पंचायत सचिव संघ, वनकर्मी संघ, पुलिसकर्मी, जिनको अनुकम्पा नियुक्ति देनी है उनको अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जा रही है और उसके कारण अधिकारी-कर्मचारी सब सड़कों पर उतरे हुए हैं । आज लगभग 1 लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी सड़कों पर हैं, हम चाहते हैं कि चूंकि हमने इसमें स्थगन दिया है, आप इसके ऊपर चर्चा करवायें कि पूरा छत्तीसगढ़, कांग्रेस ने जो जनघोषणा-पत्र जारी किया, जिसको आत्मसात किया और उसके कारण कर्मचारियों में एक विश्वास की भावना पैदा हुई । इतने बहुमत के साथ में यह सरकार जीतकर आयी है परंतु उसके बाद भी कर्मचारियों की और इस पूरे प्रदेश की व्यवस्था ठप्प हो गयी है । लगातार हमारे रायपुर शहर का बूढ़ापारा केंद्र चूंकि वहां से आने-जाने के लिये रोज बाधा उत्पन्न होती है परंतु यह सरकार इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पर चर्चा करवायें ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के जनघोषणा पत्र को वर्ष 2019 के महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार ने आत्मसात किया । अब जनघोषणा पत्र इस सदन की प्रॉपर्टी बन चुकी है और जन घोषणा पत्र में 36 बिंदु कि जनता को हम यह-यह काम करके देंगे इसके लिये आश्वासन दिया गया था और उसमें सबसे प्रमुख बिंदु था कि अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, दैनिक वेतन भोगियों को नियमित करेंगे, संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे और इस सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं अब सरकार के दानफल का पीरियड शुरू हो चुका है ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कर्जामाफी भी महत्वपूर्ण था ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति यह है कि आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि अभी तक उनके पास कितने लोगों को नियमित करना है इसकी सूची प्राप्त नहीं हुई है । कुल 33 विभागों की सूची आयी है और बाकी विभागों की सूची भी नहीं आयी है। पूरे प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मी, पुलिस विभाग के लोग स्ट्राईक में हैं और पूरा प्रशासन ठप्प पड़ा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारा स्थगन है, हम निवेदन करते हैं कि कृपया इसको ग्राह्य करके इस पर चर्चा करायें ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुख, गंभीर और लज्जा का विषय है । जब कोई राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करता है तो सरकार उसको अभिभाषण में नहीं लेती । इस सरकार ने उसको अभिभाषण में आत्मसात किया है, यह सब दिख चुका है और उसके लिये एक टीम बनायी । सामान्य प्रशासन सचिव का एक निर्देश निकला कि आपने घोषणा पत्र या जन घोषणा पत्र के विषयों में क्या-क्या कार्यवाही की है इस संबंध में आगे प्रश्न में भी आयेगा । पहला क्या कार्यवाही

की ? दूसरी बात आज नौकरी, रोजगार इन विषयों में लगातार 3 प्रश्नों में चर्चा हुई, तीनों प्रश्नों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग-अलग बात कही । इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है और कब तक होगा यह हमको मालूम नहीं । कमेटी कब तक रिपोर्ट देगी यह हमको मालूम नहीं । इस सरकार की इतनी कमेटियां हैं जिसकी रिपोर्ट ही नहीं आती है । अभी माननीय सत्यनारायण जी सो रहे हैं, उनकी कमेटी भी पूरी सो गयी है । कौन है, क्या है उसको जानते नहीं हैं तो यह जो कमेटी इधर-उधर से शासकीय कर्मचारियों के हितों का नुकसान पहुंचाया जा रहा है और घोषणा के बाद जिन लोगों ने यह काम अभी तक नहीं किया है, यह सरकार अपनी घोषणा पर खरी नहीं उतर रही है इसके लिये हमने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है इसको स्वीकार करके तत्काल चर्चा करवाने का कष्ट करें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री नारायण चंदेल जी ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय चंद्राकर जी, सत्तू भैया जागरूक हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मोर इंहा के दू कमेटी के चैयरमेन है । एक स्काईवॉक के बारे में एक साल होगे रिपोर्ट, सत्तू भैया के कतेक कीमत करथौ तुमन मन। ओला तीन साल होये के बाद भी ओमा निर्णय नहीं होथे। अभी ओहा कमेटी के चेयरमेन हे। ओखर आज तक बैठक नहीं होथे।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- एकाध दिन बैठक में आ जातो। सत्तू भैय्या बुलाथे तो।

श्री शिवरतन शर्मा :- काहे अभी सत्तू भैय्या, दो महीना शंकर बाबा के शरण में रही के आये हे वाराणसी में कि दारू बंदी बर का करना हे, एखर बर बता किहके।
तो अपन अनमोन ला सुनाही, चिंता झन कर।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- सत्तू भैय्या के सब चीज सूत गेहे। (हंसी) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे पक्ष के सदस्यों ने जिन विषयों को रखा है, पूरे राजधानी में और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार और निरंतर अधिकारियों में, कर्मचारियों में, सारे लोगों में एक तो बहुत से अधिकारियों और कर्मचारियों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिला है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्हें नियमित किया जाना है, वे सब लोग लगातार पहले मुख्यमंत्री जी से मिले। अपने क्षेत्र के विधायकों और मंत्रियों से मिले। उन्होंने उन्हें नियमित किये जाने का ज्ञापन दिया, लेकिन लगातार नियमित किये जाने की मांग को लेकर, वेतन दिये जाने की मांग को लेकर हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं, लगातार हड़ताल पर हैं। लगातार धरना-प्रदर्शन चल रहा है। आज पूरे राजधानी में एक लाख से ज्यादा कर्मचारी लोग न्याय और उचित मांग को लेकर धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। हमने इस पर स्थगन दिया है। यह अविलंबनीय लोक महत्व का विषय है। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह ।

डॉ. रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर स्थगन दिया है और पूरा प्रदेश अशांत है। पूरी तरीके से शासकीय काम ठप्प पड़े हैं। लाखों कर्मचारी अलग-अलग विषय में आंदोलनरत हैं और यह जनघोषणापत्र 2018 का है। कर्मचारी कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं। कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। जनघोषणापत्र में किये गये वादे का क्रियान्वयन हो और उस क्रियान्वयन के लिए सरकार ने जो वादा किया था, चार स्तरीय समयमान वेतन के साथ अनियिमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, इनको नियमित करने के लिए जो बात की थी, इन सभी विषयों को लेकर ये आंदोलनरत हैं और ये मुख्यमंत्री जी ने आज प्रश्न के जवाब में बताया कि 1 जनवरी, 2019 से 21 जनवरी, 2022 तक प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनायी। प्रमुख सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग। यह कमेटी बनने के बाद उनकी रिपोर्ट क्या आयी है, टोटल संख्या जब मुख्यमंत्री नहीं बता पा रहे हैं, इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए जब सारा सदन चाहता है तो किसी न किसी रूप में इसे ग्राह्य कर लिया जाये ताकि चर्चा हो और कर्मचारियों के हित के लिए शासन आने वाले समय में कुछ गंभीर कदम उठाये। इसके लिए हम लोग मांग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- रजनीश सिंह जी।

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह के छत्तीसगढ़ के सभी कर्मचारी सड़कों पर हैं, इसलिए हम लोगों ने इसमें स्थगन प्रस्ताव दिया है और इसमें अनुकंपा नियुक्ति की जो मांग है, अनुकंमा नियुक्ति को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी विभाग में बहुत निराशा का भाव है। हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, शिक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी, उनके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज किया जा रहा है। उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। लोकहित के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम लोगों ने स्थगन दिया है। आपसे आग्रह है कि इसमें स्थगन ग्राह्य करके इस पर तत्काल चर्चा करायी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियमितीकरण एक राजनीतिक विषय था और जनघोषणापत्र में नियमितीकरण को जोड़ा गया और उसका एक बिंदु माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर में उल्लेख किया कि वर्ष 2006 में एक कोर्ट की रूलिंग थी कि नियमितीकरण की क्या प्रक्रिया की जायेगी? तो क्या सरकार को जो अभी वर्तमान में सरकार है, जिन्होंने जनघोषणापत्र बनाया, वे अभी उपस्थित नहीं हैं। जब जनघोषणापत्र बनाया जा रहा था तब यह नहीं पता था क्या कि नियमितीकरण नहीं हो सकता। कानून की रूलिंग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उल्लेख किया। तो छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के लोगों को और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी थे, उन लोगों को गुमराह कर

राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए जनघोषणापत्र बनाया गया। नियमितीकरण हो ही नहीं सकता, उसका उल्लेख आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रश्न में बोल दिया है। जो वर्ष 2006 की रूलिंग है। तो यह राजनीतिकरण किया जा रहा है। जनघोषणापत्र अगर बनाया गया तो हमारा निवेदन है कि उसका पालन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश में खलबली मची हुई है । पूरा प्रदेश आज माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे की ओर देख रहा है । जब 2018 का समय था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के लिए भिन्न-भिन्न हथकंडे अपनाये । कांग्रेस ने अपना जन-घोषणा पत्र जारी किया और सरकार ने उसे आत्मसात किया । जब भी कोई सरकार आती है तो उसके घोषणा पत्र के आधार पर ही भविष्य की योजनाएं बनती हैं । लेकिन यहां पर यह हो रहा है कि इनके नेता मंच पर जाकर चिल्लाते हैं कि हमने 36 वायदे पूरे कर दिये, हमने 24 वायदे पूरे कर दिये, हमने 25 वायदे पूरे कर दिये । आज पूरे प्रदेश की यह स्थिति है कि सरकार का अभिन्न अंग, जिसे सरकार का हाथ कहें । वह प्रदेश में सड़कों पर घूम रहा है, धरना-प्रदर्शन कर रहा है, अधिकारी-कर्मचारी आज परेशान हैं, उनके धरने पर होने से आज काम रूका हुआ है, प्रशासनिक कार्य रूके हुए हैं लेकिन सरकार को ज़रा भी चिंता नहीं है कि इनकी मांग कैसे पूरी की जाए । उनका परिवार उनके साथ सड़क पर खड़ा हुआ है । आज सरकार की स्थिति यह है कि सरकार उनकी किसी भी मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है । मैं इस विषय को भी रखना चाहती हूं कि सरकार ने मितानिन बहनों से भी वायदा किया था कि हम मितानिन बहनों को सहयोग करेंगे, उन्हें मानदेय के रूप में 5000 प्रदान करेंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि 5000 तो दूर, वे मितानिन बहनों को देखकर ख़ुद ही दूर हो जाते हैं कि कहीं मितानिन बहनें आकर खड़ी न हो जाएं और अपनी मांग न करने लगें । आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें आज भी व्यथित हैं, परेशान हैं और वे बार-बार इस बात को कह रही हैं कि कलेक्टर दर पर उन्होंने जो वायदा किया था, हमारी बहनों को वह मानदेय मिलना चाहिए । लेकिन आज भी स्थिति यह है कि हमारी बहनों को कहीं पर भी कलेक्टर दर पर मानदेय नहीं दिया जा रहा है । अनुकंपा नियुक्ति की बात सरकार कहती है, उसी भी आत्मसात नहीं किया । आज स्थिति यह है कि प्रदेश में अनेक ऐसी बहनें हैं जिन्हें समय पर अनुकंपा नियुक्ति की आवश्यकता है । लेकिन उन्हें समय पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है । उपाध्यक्ष जी, आज हमने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए जनता के साथ तो बहुत सारे वायदे किये । ऐसा-ऐसा आश्वासन देकर आए हैं जिन्हें ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

हमारे अधिकारी/कर्मचारी जो शासन व्यवस्था का परिचालन करते हैं उनको भी झूठा आश्वासन दिया गया ।

श्री कवासी लखमा :- उपाध्यक्ष जी, नरेन्द्र मोदी जी ने भी 15-15 लाख देने की बात कही थी, 15 पैसा भी मिला है क्या ? उनको भी बोलो 15 लाख कहां हैं ? 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, कहां है नौकरी ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप अपने विषय में कुछ नहीं बोलते और बाकी चीज में बड़ा टनाटन बोलते हो यार और बाकी समय में आप मौनी बाबा रहते हो । उपाध्यक्ष जी, ऐसे आश्वासन देकर आए हैं, उन्होंने इनके आशवासनों पर विश्वास किया । पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे अधिकारी/कर्मचारियों विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हो रही है । इसलिए स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए और इस पर चर्चा की जाए ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 2018 में अपने घोषणा पत्र में बहुत से वायदे किये गये थे कि हम शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति करेंगे, पंचायत सचिव को देंगे, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, कर्मचारियों को प्रमोशन देंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाएंगे, मितानिन बहनों को राशि देंगे । लेकिन अभी सरकार ने भयावह स्थिति ला दी है, आज इन लोगों ने राजधानी में अपनी मांगों को लेकर अड्डा डाला हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं । इन्होंने उन अड्डों में खाने-पीने की व्यवस्था भी नहीं की है । उनमें असंतोष है और सरकार इस विषय पर चर्चा से भाग रही है, इस पर चर्चा कराई जाए ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे प्रदेश के लगभग एक लाख से ज़्यादा अनियमित कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं और इस सरकार को घुटना टेकाने के लिए वे घुटने के बल पर चलने वाले हैं । जिस पर सरकार की कथनी और करनी में अंतर है । चुनाव जीतने के लिए जन घोषणा पत्र में आश्वासन देना, लिखित में स्वीकृति प्रदान करना और सरकार आने के बाद कैसे वायदाखिलाफी करना, आज यह दिखाई देने लगा है । आज सरकार बने 3 साल से ऊपर का समय निकल गया और जब अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात आती है तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के आज जवाब आ रहे थे, दाएं-बाएं कर रहे थे। इस सरकार की गंभीरता दिख रही है कि कितनी उनके प्रति सहानुभूति है। तीन साल में आप ए.जी. (महालेखाकार) से रिपोर्ट बुलवा नहीं पाये, अभिमत प्राप्त नहीं कर सके। आपके जो विभागीय अधिकार बैठे हुए हैं। मैं एक पत्र पढ़ रहा था, जिसमें किन्हीं ने जो कि इस देश के रहने वाले नहीं है, उन्होंने स्कूल की संस्थाएं खोलने के लिए जमीन की मांग की और एक दिन के अंदर में सारे टेबल में से फाइल निकल गए और उसमें हस्ताक्षर भी हो गये। उसके बाद में उनको जमीन दे दी गई। यह तीव्र गति से चलने वाली सरकार है। जिनके बल पर वे सरकार में आयी, जिनके बल पर घोषणा किया, बड़े-बड़े सपने दिखाए, आज तीन साल में उनके कागज

एक टेबल से दूसरे टेबल पर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को यही नहीं मालूम है कि कितने अनियमित कर्मचारी हैं। वह बताने की स्थिति में नहीं है। यह सरकार की स्थिति है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की बात करते हैं। केन्द्र की सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों को 31% D.A. दिया है। यहां पर 17% में अटके हुए हैं। आज यहां के जो कर्मचारी हैं, वह मंत्रालय में धरने में बैठे हुए हैं और 31% D.A. की मांग कर रहे हैं। साड़ी की राशि के बारे आप लोगों ने देखा है कि केन्द्र सरकार ने राशि दिया और राशि देने के बाद में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हैं, हमारे मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं कि 800 रूपये साड़ी के बदले में आपने उनको 50-60 रूपये टिका दिया। इस बात को ले करके उन्होंने असंतोष जाहिर किया। आज मितानिन धरने में बैठे हुए हैं, आज आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता धरने में बैठे हुए हैं, अनियमित कर्मचारी धरने में बैठे हुए हैं और यह महत्वपूर्ण विषय में हम लोगों ने स्थगन दिया है। सारे कार्यवाही को रोक करके आज के इस स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हो और जो सारे कर्मचारी हैं, उसके साथ सरकार न्याय करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हम लोगों ने स्थगन दिया है और आप उसमें चर्चा करायेंगे, यह हम आपसे अपेक्षा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- आपके स्थगन की सूचना विचाराधीन है। इसे किसी न किसी रूप में लिया जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- उपाध्यक्ष महोदय, आज चर्चा करते तो अच्छा होता।

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद-से-बदतर हो गई है।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बोल चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं। मैं बोल चुका हूं नहीं। मैंने पहले कर्मचारियों के मामले में बात की है। आपको एक विषय पर ही तो चर्चा कराना है।

## ध्यानाकर्षण सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण की सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व के साथ ही माननीय सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके मैंने आज की कार्यसूची में चार ध्यानाकर्षण सूचनाएँ शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

मैं समझता हूँ कि सदन इससे सहमत हैं।

**(सदन के द्वारा सहमति प्रदान की गई)**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्रकार जी।

**(1) प्रदेश में ऑनलाईन ठगी के मामले में निरंतर वृद्धि होना.**

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य :- प्रदेश में ऑनलाईन ठगी के मामले में निरंतर ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आज के कार्यसूची के पद 3 के उप पद 1 के ध्यानाकर्षण सूचना में दूसरे नंबर पर माननीय सदस्या श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू का नाम है। परंपरा है कि ध्यानाकर्षण सूचना में पहले नंबर पर जिस सदस्य का नाम रहता है, उन्हीं के द्वारा ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ी जाती है। चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अत: मैं चाहूंगा कि माननीय श्री अजय चंद्राकर जी यदि सहमत हों तो श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू को ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ने का अवसर देवें।

श्री अजय चंद्राकर :- जिसने भी आपको सुझाव दिया। आपने अपने मन से किया, जो भी किया, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये। थैंक्यू अजय भाई। आप ऐसी रहे हमेशा।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना इस प्रकार है कि पूरे प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। दुनिया भर के साइबर ठग गिरोह चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो सभी छत्तीसगढ़ में कही फेसबुक में दोस्ती ऑनलाईन नौकरी लगाने या फिर गिफ्ट देने के नाम पर यहां तक कि ऑनलाईन प्रेमजाल में फांसकर प्रदेश के युवक-युवतियों से ऑनलाईन ठगी की जा रही हैं।

दिनांक 20/2/2022 को जिला रायपुर के तिलकनगर गुढ़ियारी निवासी महेश प्रसाद राय से टीडीएस मीटर की ऑनलाइन शॉपिंग का झांसा देकर 1 लाख रू. की ठगी की गयी। दिनांक 17/2/2022 को जिला रायपुर के रायपुर शहर के सरस्वती नगर निवासी रामेंद्र सिंह से क्रेडिट कार्ड में रिवार्ड देने का झांसा देकर 50 हजार रू. की ठगी की गयी। दिनांक 12/2/2022 को जिला रायपुर के माना कैंप थाना अंतर्गत एक रिटायर्ड आइएफएस अफसर अजय कुमार सिंह से केवाईसी के नाम पर 1 लाख 99 हजार रू. की ऑनलाईन ठगी किया गया। दिनांक 9/2/2022 को सीतापुर थाने अंतर्गत एक महिला सुशीला टोप्पो से ऑनलाईन ठगी की गयी। दिनांक 08/2/2022 को जिला रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत एमएसएल की रिटायर्ट संयुक्त संचालक डॉ. शेषा सक्सेना से सिम पोर्ट के नाम पर 2 बार में कुछ 99 हजार रू. की ऑनलाईन ठगी की गयी। दिनांक 4/2/2022 को जिला बिलासपुर के सरकंडा थानांतर्गत डॉ. कनुप्रिया से सोशल मीडिया पर दोस्ती का झांसा देकर 48 लाख रू. की ऑनलाईन ठगी की गई। दिनांक 3/2/2022 को जिला कोरबा अंतर्गत मानिकपुरी चौकी के एसईसीएल जय प्रकाश कालोनी में निवासरत सुदीप नंदी से केवाईसी अपडेट के नाम पर 6 लाख 50 हजार रू. की ऑनलाईन ठगी की गयी। दिनांक 25/2/2022 को जिला रायपुर के तेलीबांधा थाना अंतर्गत अवंति विहार निवासी विनोद कुमार वर्मा से



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

कंपनी बेचने के सौदा का झांसा देकर 1 करोड़ रू. की ठगी की गयी। दिनांक 22/1/2022 को जिला रायपुर अंतर्गत अवंति विहार रायपुर निवासी अर्जुनराज सूर्यवंशी से रकम दुगुना करने के नाम पर कुल 3 लाख रू. की ऑनलाईन ठगी किया गया। दिनांक 16/1/2022 को जिला बिलासपुर के पुलिस लाईन के क्वार्टर नं. ई-35 में निवासरत आरक्षक हरीश कौशिक से लकी ड्रॉ में ईनाम पाने का झांसा देकर 4.26 लाख रू. की ऑनलाईन ठगी की गयी। दिनांक 11/1/2022 को जिला जांजगीर-चांपा के चक्रधर थाना क्षेत्रअंतर्गत गोवर्धनपुर के कियोस्क शाखा में मजदूर कार्ड बनवा देने का झांसा देकर दोमनिका कुजुर से 20 हजार, रत्ना डनसेना से 1 लाख 19 हजार 300 रू. तथा अंजली के खाते से 1 लाख 44 हजार 859 रू. की जालसाजी की गयी। दिनांक 16/2/2022 को जिला रायपुर के रायपुर शहर अंतर्गत लाखेनगर निवासी टीकम चंद सोनकर से ईवी गाड़ियों की डीलरशिप देने का झांसा देकर, 12 लाख रू. की ठगी की गयी। दिनांक 19/11/2021 को जिला रायपुर के रायपुर शहर के सुंदरनगर निवासी गंगाधर राव गांवड़े, जो पेशे से शिक्षक हैं से क्रेडिट कार्ड बंद कराने एवं सीबिल अपडेट करने के नाम से 32 हजार 414 रू. की ऑनलाईन ठगी किया गया। दिनांक 28/10/2021 को जिला रायपुर में राजेन्द्र नगर में दफ्तर खोलकर लोन दिलाने तथा क्रेडिट कार्ड बनाकर विभिन्न लोगों से लगभग 4 करोड़ रूपये की ठगी की गयी। दिनांक 24/10/2021 को जिला रायपुर के श्यामनगर तेलीबांधा के निवासी अमन अग्रवाल से ईयरफोन खरीदने के नाम पर, क्यूआर स्कैन कोड के जरिये कुल 2 लाख 91 हजार रू. की ठगी की गयी। दिनांक 24/10/2021 को जिला रायपुर के रायपुर शहर के सुंदर नगर निवासी रजनी सोनी से क्रेडिट कार्ड बंद करने का झांसा देकर लगभग 1 लाख 25 हजार रू. की ऑनलाईन ठगी की गयी। दिनांक 20/10/2021 को रायपुर जिले के शिवानंद नगर निवासी एम धनंजय राव के गुम मोबाइल से ठगों ने ऑनलाईन सामान खरीदर कुल 55 हजार की ठगी की गयी। दिनांक 17/10/2021 को जिला अंबिकापुर अंतर्गत कलेक्टर बंगला रोड निवासी मनोज कुमार यादव से ओएलएक्स के जरिये गाड़ी बेचने के नाम से 95 हजार रू. की ऑनलाईन ठगी की गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, यह बहुत महत्वपूर्ण है जहां पर वह कलेक्टर है। दिनांक 4/10/2021 को जिला रायपुर के सीएसईबी के रिटायर्ड किशोर बैस से इंश्योरेंस एजेंट बनकर 9 लाख 40 रू. की ठगी की गयी। दिनांक 4.10.2021 को जिला कोरबा के एनटीपीसी के यमुना विहार में रहने वाली शिफाअली से ओएलएक्स के माध्यम से सामान खरीदने के दौरान लिंक से 75 हजार रूपये की ठगी की गई । दिनांक 4.10.2021 को जिला रायपुर की छात्रा जो बंगलूरू में एमबीए की पढ़ाई कर रही है, उससे इंटर्नशिप के नाम से प्रोडक्ट बिक्री में कमीशन के नाम पर लगभग 1 लाख, 61 हजार रूपये ऑनलाईन ठगी की गयी । दिनांक 24.9.2021 को जिला बिलासपुर के नेहरू नगर में रहने वाली छात्रा पाखी प्रकाश से ऑनलाईन टेबल टेनिस गेम में ईनाम जीतने का झांसा देकर कुल 3 लाख 25 हजार रूपये की ठगी की गयी ।

प्रदेश सरकार ने साईबर ठगों को रोकने हेतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है और न ही कोई योजना बना रही है, जिससे साईबर ठग गिरोहों का मनोबल दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है । सरकार इन साईबर ठगों को रोकने में पूर्णरूप से नाकाम हो चुकी है । पूरा सिस्टम फैल्वर हो चुका है । प्रदेश में विगत ढाई वर्षों में लाखों-करोड़ों रूपये की ऑनलाईन ठगी व ऑनलाईन ब्लेगमेलिंग की घटना घटित हो चुकी है, जिससे प्रदेश की जनता में प्रदेश सरकार के प्रति काफी रोष व आक्रोश व्याप्त है ।

गृहमंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, साईबर ठगी को लेकर पुलिस विभाग बहुत संवेदनशील है । प्राप्त शिकायतों पर विधि अनुरूप निरंतर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, आपका ध्यानाकर्षण रहता है तो आपके विभाग के सचिव सदन में उपस्थित नहीं रहते क्या ? यह नियंत्रण दिखाता है, सदन की गंभीरता बताती है । इसको कौन, कितनी गंभीरता से ले रहा है, यह पता चलता है । यहां आपके गृह विभाग के सचिव मौजूद नहीं हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सचिव के पास कई विभाग हैं, अलग-अलग विभागों का काम चलता रहता है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, पर सचिव तो एक ही हैं न । यह आप मान लीजिए कि ध्यानाकर्षण में उनका रहना जरूरी नहीं है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- डी.जी.पी. बैठे हुए हैं, पुलिस विभाग का पूरा महकमा बैठा हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, वह डी.जी.पी. कौन है, मैं जानता भी नहीं कि आपके डी.जी.पी. कौन हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- मंत्री जी जवाब देने के लिए सक्षम हैं, सचिव की आवश्यकता क्या है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे जानना भी नहीं है कि डी.जी.पी. हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, पुलिस विभाग का पूरा महकमा बैठा है, पर आपका टेलीफोन उठाते हैं या नहीं उठाते हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- उपाध्यक्ष महोदय, यही आपका नियंत्रण भी दिखाता है और आपका महत्व भी दिखाता है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपको माननीय मंत्री जी से जवाब लेना है, सचिव से जवाब थोड़ी लेना है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, सदन से बड़ी संस्था कोई दूसरी नहीं है। जब माननीय गृहमंत्री जी जैसे हमारे वरिष्ठ मंत्री जवाब दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, मैं सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूं कि विभाग के जो भी सचिव, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव को सामान्यत: उपस्थित रहना चाहिए ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो अधिकारी दीर्घा है, वह सदन का हिस्सा नहीं है, परन्तु इस सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए उनका उपस्थित रहना जरूरी है क्योंकि अगर वे बातचीत को सुनते हैं तो शासन स्तर पर निर्णय होकर आदेश जारी होते हैं क्योंकि डी.जी.पी. को भी शासन के आदेशों को मानना होता है । इसलिए मंत्री जी, यह सदन की गरिमा भी बढ़ेगी, आपकी गरिमा भी बढ़ेगी । भविष्य में अगर गृह विभाग का कोई भी मामला है और मैं सोचता हूं कि गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के बाद सबसे बड़ा विभाग होता है । इसलिए उस विभाग के महत्व को भी बढ़ाने के लिए और आपकी स्वीकारोक्ति को भी देखते हुए अधिकारी उपस्थित रहें, इस बात को आप सुनिश्चित करेंगे तो हमको भी बोलने में अच्छा लगता है कि वे सुन रहे हैं और कार्यवाही होगी तो आप इसको दिखवा लीजिए ।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आपकी बात सुनकर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव महोदय उपस्थित हो गए हैं । अभी तो बधाई दो ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, सायबर ठगी को लेकर पुलिस विभाग बहुत संवेदनशील है । प्राप्त शिकायतों पर विधि अनुरूप निरंतर कार्यवाही की जा रही है । यह कहना सही नहीं है कि सायबर ठग चाहे वह राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो, छत्तीसगढ़ में कहीं फेसबुक में दोस्ती ऑनलाईन नौकरी लगाना या गिफ्ट देने के नाम पर यहां तक की ऑनलाईन प्रेम जाल में फंसाकर प्रदेश के युवक-युवतियों से ऑनलाईन ठगी कर रहे हैं । वस्तुत: सायबर अपराधी सम्पूर्ण देश में ऐसे अपराध कर रहे हैं ।

उल्लेखित सभी 24 शिकायतों पर अपराध पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है । 7 प्रकरणों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं 02 प्रकरणों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है । यह कहना सही नहीं है कि सरकार के द्वारा सायबर ठगी को रोकने के लिए कोई  कदम नहीं उठाया गया है और न ही कोई योजना बनायी गई है । यह भी सही नहीं है कि सायबर ठग गिराहों का मनोबल बढ़ता जा रहा है । पुलिस विभाग द्वारा ऐसे अपराधों की रोकथाम हेतु व्यापक स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई ऐसे ठगी का शिकान न बनें। इसके उपरांत भी अपर्याप्त जानकारी के कारण कुछ व्यक्ति ऐसे ठगी के शिकार हो रहे हैं, जिनको पुलिस द्वारा वैधानिक मदद की जा रही है।

पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित हेल्पलाईन नंबर- 155260 के माध्यम से अभी तक कुल 2.45 करोड़ रूपये ठगों के पास पहुंचने के पहले ही होल्ड करा दिए गए हैं। राज्य के पुलिस अधिकारियों को सायबर क्राइम का विशेष प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। सायबर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत प्राप्त की जा रही है एवं ठोस कार्यवाही की जा रही है। पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तर पर सायबर थाना एवं सायबर लैब संचालित है।  सायबर अपराध में प्रभावी नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा रायपुर, दुर्ग

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

एवं बिलासपुर जिलों में एन्टी क्राइम एवं सायबर यूनिट का गठन किया गया है। सायबर अपराधों में पुलिस द्वारा की गई प्रभावी कार्यवाही से जनमानस में शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ा है।

**सदन को सूचना**

उपाध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है। भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

**सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुविधानुसार से आपका क्या आशय है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- समय-परिस्थिति के हिसाब से।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह पूछ रहे हैं कि उसके साथ सुविधा भी उपलब्ध करवा दें।

उपाध्यक्ष महोदय :- वह बाद में, बाद की बात है। अजय भाई, जब शाम को मिलेंगे तब।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप दादी को कह दें।

श्री कवासी लखमा :- मेरा और आपका घर तो बाजू में है, आ जाना, क्या है।(हंसी)

**ध्यानाकर्षण (क्रमशः)**

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपके विभाग की जानकारी में कुल कितने मामले हैं। देखिये, मेरे दो ध्यानाकर्षण लगे हैं। मेरा एक ऑनलाईन ठगी और एक आफलाईन ठगी पर ध्यानाकर्षण है। छत्तीसगढ़ के समाचार-पत्रों में, सोशल मीडिया में एक भी दिन ऐसा नहीं देखेंगे, जहां ठगी के मामले नहीं छपे हों। चाहे वह आफलाईन ठगी हो या ऑनलाईन ठगी हो। मैंने जो ध्यानाकर्षण दिया है, उसमें पूरे प्रदेश का है। मैं आपसे सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि आपको चाहे 3 साल का कहे, जो आपका गृहमंत्री का कार्यकाल है, 3 महीने का कहे, 1 महीने का कहे, जितने दिन में, आपकी जानकारी में कितनी शिकायतें आई हैं और सिर्फ 24 मामलों में क्यों कार्रवाई की गई है ? बाकी में क्यों कार्रवाई नहीं की गई है ? आपको, आपके विभाग को कितनी सूचनाओं की जानकारी हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने ध्यान आकर्षण की सूचना में जिन 24 प्रकरणों की जानकारी दी है, मैंने वहां पर उसका विस्तृत उत्तर दे दिया है। उस पर जो कार्रवाई की गई है, उसके विषय में भी जानकारी दे दी है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ठीक है, ध्यानाकर्षण में शब्दों की एक सीमा होती है। अब इसमें इस तरह के उत्तर आयेंगे, अगर इसी पर ही सीमित रहना है तो फिर जितने ठग हैं, वह आपके द्वारा संरक्षित और पोषित लोग हैं, आपके और पुलिस विभाग से संरक्षित और पोषित हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे दूसरा प्रश्न कर लेता हूं। आपने 3 स्थानों पर सायबर सेल खोला है। मैंने जिन 24 प्रकरणों का उल्लेख किया है, वह प्रदेश भर में है। आपने सायबर सेल खोला है, उनको क्या-क्या सुविधाएं दी हैं, क्या-क्या सेटअप दिये हैं और उन्होंने कब से काम करना शुरू किया है ? उसका कोई हेल्प लाईन नंबर है क्या ? क्योंकि आपके पुलिस वालों से बात करना मतलब आसमान से तारे तोड़ लाना है। तो आप यह बताने का कष्ट करें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में सायबर ठगी को रोकने के लिए जो काम किया गया है, मैंने इसमें उसकी भी जानकारी दी है और विस्तृत जानकारी भी दे सकता हूं। लेकिन अभी जिन 3 जिलों की बात है, हम लोगों ने अभी दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर में एन्टी क्राइम और एन्टी सायबर के लिए नया गठित किया है। लेकिन इनके गठित होने के पहले से ही हमारा काम चल रहा है। यदि आप कहें तो विस्तृत जानकारी दे दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप कहें तो विस्तृत जानकारी दे दूंगा, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। मैंने सीधा-सीधा पूछा है कि मेरा विधानसभा का जो ध्यानाकर्षण है, वह प्रदेश स्तर का है। आपने सायबर सेल खोला है। कब खोलें, क्या काम करते हैं, कितने कर्मचारी दिये गये हैं, क्या इक्विपमेंट दिये गये हैं, कब से कहां पर वह थाना है, जहां वह काम करते हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ उपाध्यक्ष जी । साईबर क्राइम की बेहतर विवेचना और पतासाजी के लिए उठाये गये कदम- साईबर थाना, राज्य पुलिस स्तर पर साईबर थाना संचालित है । जिलों में पंजीबद्ध साईबर अपराध का पर्यवेक्षण अलग-अलग स्त्रोत से किया जाता है, थाना स्तर पर भी किया जाता है । साईबर लैब राज्य पुलिस में साईबर अपराध प्रयुक्त होने वाले कम्प्यूटर मोबाईल, इलेक्ट्रानिक उपकरण के परीक्षण के लिए प्रशिक्षित पुलिस कर्मी द्वारा किया जाता है । विवेचकों को भी प्रशिक्षण दिया गया है । इस प्रकार की जो उसमें होती है तो विवेचना के लिए 2610 पुलिस कर्मियों को अब तक प्रशिक्षित किया गया है । साईबर पोर्टल भी गृह मंत्रालय भारत सरकार और क्राईम विवेचना में सहयोग के लिए उसमें भी किया गया है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरे प्रश्न में फिर से दोहरा देता हूँ । कब शुरू हुआ, कितना सेट अप दिया गया है, उसका मुख्यालय कहां पर है, कितने कर्मचारी काम करते हैं, मैं चार लाईन पूछा हूँ ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं बता रहा हूँ ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुझे चार लाईन में ही बताईये, मैं छः लाईन सुनना ही नहीं चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बता रहे हैं, बता रहे हैं ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री ताम्रध्वज साहू :- चार लाईन ही बता देता हूँ । उसके आगे आप पुछेंगे भी नहीं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसके आगे दूसरा प्रश्न पुछूंगा ।

एक माननीय सदस्य :- आप प्रश्न पूछे हैं तो उत्तर सुनने का हौसला तो रखिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- आपके ध्यानाकर्षण का दो प्रश्न हो गये हैं । राज्य साईबर पुलिस थाना, पुलिस मुख्यालय, यहां पर एक निरीक्षक है, एक उपनिरीक्षक है, प्रधान आरक्षक तीन है, आरक्षक 7, कुल 12 लोग हैं । क्षेत्रीय साईबर क्राईम समन्वय केन्द्र पुलिस मुख्यालय, एक अतिरिक्त उप पुलिस अधीक्षक है, एक निरीक्षक है, उपनिरीक्षक दो है, प्रधान आरक्षक एक है, आरक्षक दो, कुल 7 लोग है । आप जो डॉयल नंबर पूछ रहे हैं, 155260 यह 24 घण्टे चालू रहता है, इसमें चार आरक्षक वन बाई वन बैठते हैं । इस तरह जिला स्तरीय साईबर सेल में तीन अधिकारी हैं, 8 निरीक्षक हैं, कुल मिलाकर 260 अधिकारी-कर्मचारी सेल में काम कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह पूछा कि इसका सेट-अप आपने अलग से स्वीकृत किया है कि विभागीय अतिरिक्त से निकाला ? दूसरा आपने कहा है कि साईबर क्राईम को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, साईबर क्राइम के लिए मैंने आपसे इक्वीपमेंट पूछे हैं कि साईबर क्राईम के लिए आपके पास कौन-कौन से उपकरण हैं, आप विशेष प्रशिक्षण कितने लोगों को, कौन सी कंपनी से दिलवा रहे हैं और उसमें कितनी अवधि का प्रशिक्षण हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विस्तृत जानकारी दूंगा तो बोले कि 4 लाईन भर दो बोले । इसलिए मैं रूक गया । 20 नवीन पद आपने जो पूछा है, उसी को बताने जा रहा था । जब घटनाक्रम बढ़ते गया, हमने पुलिस बल से प्रशिक्षित करके उनको काम पर लगाया, जिसकी जानकारी 260 मैंने दिया । अभी हम लोगों ने 20 नवीन पदों का सृजन साईबर क्राईम की रोकथाम के लिए किया । साईबर लैब पुलिस मुख्यालय में 20 नवीन पद प्रकियाधीन है, जो हम लोगों ने सृजन किया । केन्द्र सरकार से योजना के लिए वृहत जनजागरूकता अधोसंरचना विकास के लिए 3 करोड़ 65 लाख रूपये की मांग भी की है । साईबर भवन हमारा बन रहा है । हम लोग पूरी दिलचस्पी लेकर पुलिस मुख्यालय परिसर में साईबर क्राईम की एकीकृत विवेचना एवं प्रशिक्षण के लिए 2 करोड़ 77 लाख रूपये की लागत से साईबर भवन का भी निर्माण हमारा हो रहा है । नवीन उपकरण जो आपने कहा है, साईबर लैब पुलिस मुख्यालय के आधुनिकीकरण और नवीन उपकरण के क्रय के लिए प्रक्रियाधीन है, हमारा पैसा स्वीकृत हो जायेगा, प्रक्रिया पूरी होगी, जो-जो साईबर क्राईम के लिए आवश्यक उपकरण है, उसे हम खरीदेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा एक प्रश्न है, फिर उनसे बोलिये । मैंने कहा कि आप प्रशिक्षण किस व्यक्ति, किस संस्था से, कितने लोगों का, कितनी अवधि का, कहां करवा रहे हैं । यह पूछा ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा कि जब हमारा सब सेट अप तैयार हो जायेगा तो उसका प्रशिक्षण जहां से करवाना होगा करवायेंगे, लेकिन वर्तमान में हमारे जो.....।

श्री अजय चन्द्राकर :- ना-ना गलत उत्तर है । इसमें लिखा है साईबर क्राईम का विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हम तो कह रहे हैं ना ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप किससे दिलवा रहे हैं । कितने दिन का कोर्स है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- हमारे अपने खुद के अधिकारी हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नाम तो बताईये, ये सेल, ये व्यक्ति, इतने लोगों का, इतने दिनों का । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप देखिये,उन्होंने कहा कि सब हो जायेगा, तब प्रशिक्षण दिलवायेंगे । विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है । किससे दिलवाया जा रहा है, व्यक्ति है, संस्था है, कितने दिनों का कोर्स है, क्या प्रशिक्षण है, यह बताने में क्या तकलीफ है, मुझे समझ में नहीं आता है । इसमें क्या गोपनीयता की बात है । न आरोप-प्रत्यारोप है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैंने गोपनीयता की बात बताई न। हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके द्वारा दी गई जो प्रारंभिक जानकारी है, उसके आधार पर वह हमारे नियमित अधिकारी, कर्मचारियों को प्रारंभिक तौर पर प्रशिक्षण देकर उस काम में लगाया गया है। जब हमारा साईबर भवन से लेकर, पूरा सेटअप तैयार हो जायेगा और राशि स्वीकृत हो जायेगी तो लैब और उसके उपकरण खरीदकर फिर उसके बाद हम उनको पूर्ण करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्री अजय चन्द्राकर : जो इच्छाशक्ति दिखा रहे हैं यानि यह सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह से उत्तर आया है, शासन में इस अपराध को रोकने के लिए कोई इच्छाशक्ति नहीं है। आप उनको संरक्षण दीजिए। मेरा ऑफलाईन वाला और आयेगा, आज आग्रह करूंगा। कब पद स्वीकृत होगा, कब पैसा आयेगा, कब equipment खरीदेंगे, कब भवन बनेगा, तब तक छत्तीसगढ़ को लूट लो। आपने चारागाह बना दिया है।

श्री ताम्रध्वज साहू :- चारागाह आप लोगों ने बनाया था। 15 साल में चारागाह बनाकर छोड़ दिया और बात करते हो।

श्री संतराम नेताम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किये हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर 15 साल लूटे नहीं होते तो आज यह 15 सीट में सिमट नहीं गये होते। आप 15 सीट में सिमट गये हैं, आप बताईये कि और कितने में सिमटना चाहते हैं?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी आपकी जान की चिंता है। यदि उत्तरप्रदेश में सरकार नहीं बनी तो आप आत्महत्या मत कर लो।

श्री अरूण वोरा :- उत्तरप्रदेश में सरकार बन रही है।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय गृह मंत्री जी की इस सरकार में क्या स्थिति है, इससे पूरा प्रदेश परिचित है। मैंने प्रश्न किया न कि माननीय मंत्री जी आपका टेलीफोन अधिकारी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं तो वह बोलते हैं कि उठाते हैं। आप अलग से बात करेंगे तो बतायेंगे कि इनकी बात एस.पी. भी नहीं सुनते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय, हमर भैया सहानुभूति के पात्र हैं, उनके ध्यानाकर्षण में गृह सचिव नहीं आये हैं। ओला का करबे। D.G.P. आपके फोन को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष जी, D.G.P. भी फोन उठाते हैं, A.C.S. भी फोन उठाते हैं और जब भी मीटिंग में बुलाता हूं वह मेरे निवास में भी आते हैं और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। पूरा पुलिस प्रशासन मेरे कंट्रोल में है।

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत बड़ी बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सब आपका फोन उठाते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय मंत्री जी, मैं आपको बधाई देता हूं। यह आपको बोलना नहीं चाहिए, यह आपका अधिकार है। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हम सरकार हैं और सरकार में बैठे हुए मंत्रियों का अगर कोई अधिकारी अपमान करे, उसका फोन नहीं उठाये, उससे बात नहीं करे तो मैं सोचता हूं कि ऐसे अधिकारी को एक मिनट भी पद पर नहीं रहने देना चाहिए। अगर सरकार में बैठे हुए लोग अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेंगे तो वह ऐसे ही हमारे सर पर चढ़कर बोलेंगे। आपसे मेरा आग्रह है कि आप अपने अधिकारों का उपयोग करिये। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जनता ने आपको चुना है, आप उसको पूरा करिये। आपका अधिकारी फोन उठाते हैं, इसके लिए आपको बधाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके लिए बहुत-बहुत बधाई।

उपाध्यक्ष महोदय :- बैठिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज तक शपथ ग्रहण से लेकर, विभाग आवंटन से लेकर, मेरे विभाग के किसी भी अधिकारी, कर्मचारी ने मेरा फोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं हुआ है। सबने पूरा सम्मान दिया है, सबने पूरे आदेश का पालन किया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बहुत बढ़िया बधाई।

श्री बृहस्पत सिंह :- जब चन्द्राकर जी मंत्री थे तो इनकी बात को लोग नहीं सुनते थे, इसी बात को याद कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- इनकी बात नहीं सुनते थे।

श्री अजय चन्द्राकर :- अपने विषय में बोल नहीं सकते, अपने विषय में बेचारा बन जाते हो। दूसरे के विषय में खड़े होना शुरू कर देते हो।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, 15 सालों में जो इनके साथ होता था, इनका फोन अधिकारी नहीं उठाते थे, उसी बात को बता रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू (धमतरी) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि साईबर ठगी को रोकने के लिए आप किस तरह का जनजागरूकता अभियान चला रहे हैं और इससे कितने लोगों को फायदा हुआ है? क्या इस ठगी में कमी आई है?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीया सदस्य जी ने साईबर क्राईम की रोकथान के लिए जो प्रश्न उठाया है। हम लोगों ने हेल्पलाईन जारी किया है, जैसा कि मैंने बताया है कि जो हेल्पलाईन 24 घंटे चालू रहती है। इसका सबसे बड़ा फायदा भी हुआ है। इस हेल्पलाईन को जारी करने के बाद जैसे कहीं ठगी हुई, जानकारी आई, संबंधित व्यक्ति ने तत्काल हमारी हेल्पलाईन में फोन करके अगर सूचना दी तो हम लोगों ने तत्काल बैंक को कहकर उसके पैसे के ट्रांसफर को रोक लगाई है। इस तरह 2 करोड़ 45 लाख रूपये अब तक राशि को रोकी है। जहां तक जागरूकता अभियान का प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ट्वीटर पर फेसबुक पर साइबर मितान अन्य अभियान के माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाने का लगातार काम कर रहे हैं। जहां फोन पर कोई जानकारी आती है तो वह आदमी एक सेकंड में बहक जाता है कि मुझको ईनाम मिलने वाला है या एक लाख रूपये मिलने वाला है तो तत्काल अपनी गोपनीय जानकारी दे देता है या और कुछ दे देता है और जितनी आधुनिक चीजें आने लगी है उसके कारण यह अपराध बढ़ने लगा है, चाहे वह मोबाईल हो या अन्य चीजें हों लेकिन इसके रोकथाम के लिये हम लोगों ने पूरी कार्रवाई शुरू कर दी है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह था कि सोशल मीडिया को छोड़कर अन्य और कौन से माध्यम से आप जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ आपने जो हेल्पलाईन नंबर जारी किया, तो हेल्पलाईन नंबर तक जब संदेश पहुंचता है तो वे कितने समय में कार्रवाई करना प्रारंभ कर देते हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने जो हेल्पलाईन नंबर दिया है, उसमें 04 नंबर दिया गया है, जो एक के बाद एक 24 घंटे उपलब्ध है। जैसे ही कोई जानकारी आती है सबसे पहले तत्काल वहां से बैंक को सूचित करते हैं ताकि उसके खाते से पैसे का ट्रांजेक्शन रूक जाये, उसका पैसा बच जाये और जैसा मैंने कहा कि 2 करोड़ 45 लाख रूपया इसमें हम लोगों ने अभी तक बचाया है। जन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जागरूकता अभियान का अभी आपने कहा उसकी मैं पूरी जानकारी दे दी। साईबर मितान है, फेसबुक है, ट्वीटर है और अन्य जो माध्यम है और पुलिस द्वारा समय-समय पर बहुत सारे शिविर भी लगाये जाते हैं, चौक-चौराहों में भी हम लोग बोर्ड लगाकर जानकारी देते रहते हैं। तो बहुत सारा काम इस पर चलाया जा रहा है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक अंतिम प्रश्न है कि विभाग के अलावा क्या कोई अन्य साईबर एक्सपर्ट जो हाते हैं, क्या उनसे प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने अलग-अलग प्रशिक्षण संस्थाएं हैं, उनके विशेषज्ञों से हम लोग प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के प्रशिक्षण हैं, अलग-अलग अपराध के हिसाब से है और हम लोग आगे भी प्रशिक्षण दिलवाते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक।

**(2) रायगढ़ जिले में कैलो परियोजना अंतर्गत किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिलना ।**

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

रायगढ़ जिला में केलो परियोजना अंतर्गत कई किसानों को सिंचाई का लाभ आज पर्यन्त तक नहीं मिल पा रहा है, जबकि केलो डेम का निर्माण कई वर्ष पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। केलो परियोजना अंतर्गत लगभग 22000 हे. कृषि भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य हैं परंतु वर्तमान में केवल 5-6 हजार हे. कृषि भूमि को ही सिंचाई का लाभ मिल रहा है। नहरों का कार्य पूर्ण नही होने के कारण कई किसानों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है। पुसौर क्षेत्र के सुकुल भठली, पडिगांव, देवलसुर्रा, इत्यादि उनेक ग्रामों में नहर निर्माण का कार्य अब तक अपूर्ण है। समय पर नहर निर्माण का कार्य पूर्ण न होने एवं किसानों को सिंचाई का लाभ न मिलने से किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केलो परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 22810 हे. (खरीफ) है। यह सही है, कि रायगढ़ जिले में स्थित केलो बांध का निर्माण वर्ष 2012-13 में पूर्ण किया जा चुका है। बांध पूर्ण हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं तथा नहर कार्य 80.50% पूर्ण किया जा चुका है। केलो मुख्य नहर तथा इसकी झारमुड़ा शाखा नहर अंतर्गत मिट्टी एवं पक्के कार्य पूर्ण हो गये हैं। वितरक नहरों में धनगांव वितरक नहर का कार्य संपूर्ण 12.36 कि.मी. में पूर्ण कर लिया गया है। तेलीपाली वितरक नहर का कार्य 11.70 कि.मी. में से 9.61 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 2.09 कि.मी. हेतु निविदा आमंत्रित है। शारदा वितरक नहर का कार्य 8.34 कि.मी. में से 6.42 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष 1.92 कि.मी. का कार्य प्रगति पर है। अमलीपाली वितरक नहर का काय कार्य 7.98 कि.मी. में से 7.23 कि.मी. पूर्ण कर लिया गया है तथा 0.75 कि.मी. भू-अर्जन के



अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

कारण शेष है। छिछोर उमरिया वितरक नहर का कार्य 10.92 कि.मी. में से 9.95 कि.मी. पूर्ण कर लिया गया है तथा 0.97 कि.मी. भू-अर्जन के कारण शेष है। कथली वितरक नहर का कार्य 8.46 कि.मी. में से 7.41 कि.मी. पूर्ण कर लिया गया है तथा 1.05 कि.मी. भू-अर्जन के कारण शेष है। टेंगापाली वितरक नहर का कार्य 13.86 कि.मी. में से 12 कि.मी. का कार्य पूर्ण हो चुका है। तथा शेष 1.86 कि.मी. कृषकों के विरोध के कारण अपूर्ण है। माईनर नहरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

परियोजना के अब तक अपूर्ण रहने का मुख्य कारण (1) भू-अर्जन अधिनियम 2013 का लागू होने के कारण भू-अर्जन प्रकरणों को नये सिरे से पुन: तैयार करने तथा इसके निराकरण में विलंब हुआ। (2) कृषकों के भूमि विवाद एवं खाता दूरूस्त न होने के कारण भू-अर्जन प्रकरणों में विलंब हुआ। (3) केलो परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति की समय-सीमा की वृद्धि की स्वीकृति के अपेक्षाकृत विलंब होने के कारण भू-अर्जन प्रकरणों के निराकरण में विलंब हुआ। (4) टेंगापाली वितरक नहर के भू-अर्जन अवार्ड पारित होने एवं एजेंसी निर्धारण होने के बावजूद ग्राम नेतनागर के कृषकों के विरोध के कारण आर.डी. 12.00 कि.मी. एवं उसके आगे दो लघु नहरों में निर्माण कार्य बाधित हुआ। (5) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के चलते भी निर्माण कार्य बाधित हुआ।

पुसौर क्षेत्र के सुकुलभठली, पड़िगांव, देवलसुर्रा में कुछ हिस्सों में कृषकों के भूमि विवाद एवं खाता दुरूस्त न होने एवं अन्य प्रकरणों से भू-अर्जन लंबित होने के कारण नहर का निर्माण अपूर्ण है। छूटे हुए भूमि का पूरक भू-अर्जन प्रकरण तैयार कर शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु समुचित प्रयास किये जा रहे हैं। भू-अर्जन समस्याओं की वजह से नहर निर्माण में विलंब हुआ, जिसके कारण परियोजना अपनी पूर्ण रूपांकित क्षमता के लक्ष्य को अब तक प्राप्त नहीं कर सकी है। यह सही है, कि वर्तमान में परियोजना से सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई का लाभ नहीं मिल रहा है और वास्तविक सिंचाई लगभग 5800 हेक्टेयर तक में ही की गई है। परंतु विगत 06 वर्षों से मुख्य नहर से कृषकों को खरीफ के दौरान ट्रायल रन के तौर पर सिंचाई हेतु पानी सुगमता पूर्वक दिया गया है एवं पानी वितरक नहरों तक पहुंचाया गया है। जो उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में है। भू-अर्जन और निर्माण कार्य पूर्ण होने पर सम्पूर्ण क्षेत्र के कृषकों को लाभ सुनिश्चित हो सकेगा। अत: कृषकों में आक्रोश जैसी स्थिति परिलक्षित होने का प्रश्न नहीं है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लगभग 58 से 60 करोड़ रूपए की मुआवजा राशि पेंडिंग है। वर्ष 2012 में बांध बनने के बाद, आज तक किसानों को पानी नहीं पहुंचने से, उनके मन में सिंचाई नहीं होने के कारण रोष व्याप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि यह जो नहर, केनाल है आप यह कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने बताया कि वर्ष 2011-12 से यह काम चल रहा है और बीच में भू-अर्जन का जो रूल चेंज हुआ उसके कारण से भी भू-अर्जन के प्रकरण



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लंबित हैं। यह बात सही है और हमने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि इसमें भू-अर्जन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करें।

श्री सौरभ सिंह :- काकर क्षेत्र में कतका-कतका नहर हे?तुंहर दूनो के क्षेत्र लगे-लगे हे, हो सकत हे मंत्री जी, तुंहरे क्षेत्र के कुछ नहर नई बने हे। करवाव देव घोषणा तुंहरे क्षेत्र में हो ही।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी समय-सीमा जानना चाहूंगा?

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी समय-सीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि इसमें खातों के विवाद भी हैं। कई जगह जब तक वह विवादपूर्ण तरीके से रिजॉल्ड नहीं होंगे तब तक भू-अर्जन की प्रक्रिया भी लंबित हो सकती है। इसलिए हमने विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी पूर्ण कर सकें, हम करेंगे।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम सवाल है कि इन नहरों के केनालों को पूर्ण करने की अवधि कब तक थी?

श्री उमेश पटेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल्कुल यह  बात सही है कि प्रक्रिया, यह प्रक्रिया काफी सालों से प्रक्रियाधीन है। यह बात सही है लेकिन कोई ऐसी समय-सीमा इसमें निर्धारित नहीं है और मैं आपको यही आश्वस्त करूंगा कि जो भी लंबित प्रकरण हैं जिसके कारण से यह बांध पूर्ण होने में जो समस्या आ रही है उसके कारण जो देरी हो रही है, उसको हम पूर्ण कर जाएंगे। वैसे इसको वर्ष 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। हम उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए तैयारी कर रहे हैं।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद्।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री बृजमोहन अग्रवाल जी।

समय :
1:20 बजे

**(3) प्रदेश में हिन्दी माध्यम स्कूलों को स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यक्ष विद्यालय में बदला जाना।**

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है :-

शिक्षा में उपलब्ध अधिकतम संसाधन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी विद्यालय को सौंपकर सरकार हिन्दी माध्यम स्कूलों के लाखों बच्चों के साथ अन्याय व अत्याचार कर रही है। हिंदी के स्कूलों को षड़यंत्रपूर्वक बंद किया जा रहा है। सरकार ने प्रदेश में चल रहे सैकड़ों हिंदी माध्यम स्कूलों, जिसमें लाखों की संख्या में छात्र अध्ययन थे, इन्हीं स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रांरभ किया है। अनेकोनेक मदों की राशि इन स्कूलों में खर्च कर अनियमितता की गयी है। विभागीय बजट में इन स्कूलों के लिए



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

शिक्षक एवं अन्य स्टॉफ के लिए नियमित स्वीकृति नहीं दी गई है। हिंदी माध्यम स्कूल जो महापुरूषों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रेरणादायी लोगों के नाम पर थे, उसे रातों रात बदल दिया गया। हिंदी विद्यालय में अध्यापन के लिए व कार्यालयीन कार्यों में लगे स्टॉफ को एक-एक कर वहां से हटाया जा रहा है, जिससे हिंदी माध्यम के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो, बच्चें मजबूरी में स्कूल छोड़ दें। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार का तांडव मचाया गया है। बिलासपुर संभाग में तो संविदा भर्ती न कर पैसा ले कर सुदूर क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को पूरे प्रदेश से संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है। जिन हिंदी स्कूल को बंद किया जा रहा है वहां पर 5-5 कि.मी. दूर कोई हिंदी मीडियम स्कूल नहीं है, आखिर इन क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का क्या होगा ? स्कूलों को सरकार द्वारा चलाने के बजाय सोसायटी गठित कर चलवाया जा रहा है। इसमें नियुक्त स्टॉफ को नियमित वेतन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है। प्रदेश के लाखों छात्रों के मन में शासन एवं प्रशासन के प्रति भारी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी स्वयं शिक्षा मंत्री रहे हैं। आप लोगों ने 15 साल में जो नहीं कर पाया, वह हम लोग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- बताते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पहले जवाब पढ़ लें।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप जवाब पढ़ लो फिर आपको बताते हैं कि क्यों तकलीफ हो रही है।

श्री शैलेश पाण्डे :- अब हमारे मंत्री जी को कुछ नहीं बोलोगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्यों तकलीफ हो रही हैं बोले हैं, क्यों तकलीफ हो रही है बताते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बृहस्पत सिंह जी बैठे हैं। आप सोच समझकर बोलिए। (व्यवधान) जो गड़बड़ करेगा उसको ठीक करेंगे बोले हैं। आपके ऊपर तो पैसे के लेन-देन का आरोप लगाया है। जो मंत्री गलत करेगा उसको बृहस्पत सिंह जी। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- हमने चंद्राकर जी को कहा है कि ठीक से बोलिए नहीं तो...। (व्यवधान)

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बृहस्पत सिंह जी बैठे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, क्या बोलना है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, हो गया बैठिए।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चंद्राकर जी, सोया हुआ शेर को मत जगाओ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शेर के दांत तोड़ दिए गए थे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप निश्चिंत होकर, निर्भय होकर बोलिए। आप उनसे घबराईये मत।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- किससे भय है ?



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- बृहस्पत सिंह जी से।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- वह तो आपको है। (हंसी)

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, चलिए, वक्तव्य दीजिए।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना गलत है कि शिक्षा में उपलब्ध अधिकतम संसाधन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय को सौंपकर सरकार हिंदी माध्यम के स्कूलों के लाखों बच्चों के साथ अन्याय व अत्याचार कर रही है। सत्य यह है कि सरकार हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यमों में बच्चों की पढ़ाई की उत्कृष्ट व्यवस्था कर रही है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के माध्यम से राज्य सरकार ने प्रदेश के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ाई एवं रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया है। यह कहना गलत है कि हिंदी के स्कूलों को षड़यंत्रपूर्वक बंद किया जा रहा है। सत्य यह है कि प्रदेश में स्थापित 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में 51,851 बच्चों की पढ़ाई हिंदी माध्यम में 74,734 बच्चों की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम से कराई जा रही है। यह सत्य है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पूर्व संचालित विद्यालयों में प्रारंभ किये गये हैं, परंतु यह भी सत्य है कि इन पूर्व से संचालित विद्यालयों में हिंदी माध्यम में पढ़ने चाहने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई हिंदी माध्यम से कराई जा रही है, साथ ही साथ इन विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना भी प्रारंभ किया गया है। जहां कहीं आवश्यक है वहां हिंदी व अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग-अलग पालियों में संचालित की जा रही है। यह कहना गलत है कि अनेकानेक मदों की राशि इन स्कूलों में खर्च कर अनियमितता की गई है। सच यह है कि इन स्कूलों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, कम्प्यूटर, स्मार्ट क्लास रूम आदि के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न मदों से अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है। यह कहना गलत है कि विभागीय बजट में इन स्कूलों के लिए शिक्षक एवं अन्य स्टॉफ के लिए नियमित स्वीकृत नहीं दी गई है, बल्कि सत्य यह है कि शिक्षा विभाग के बजट में नवीन मद के रूप में इन स्कूलों के लिए प्रावधान किया गया है। यह भी सत्य नहीं है कि हिंदी माध्यम स्कूल जो महापुरूषों/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व प्रेरणादायी लोगों के नाम पर थे, उन्हें रातों-रात बदल दिया गया । सच यह है कि शासन के पत्र क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 30.09.2020 में यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जहां कहीं स्कूल का नामकरण पूर्व में दिया जा चुका है वहां स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना अंतर्गत (विद्यालय का पूर्व में नामकरण किया गया नाम) शासकीय इंग्लिश स्कूल रखा जाये । विद्यालयों तथा कार्यालयीन कार्य में लगे सटॉफ का स्थानांतरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जो समय-समय पर आवश्यकता के अनुरूप किया जाता है । राज्य सरकार के द्वारा हिंदी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की गई है । हिंदी माध्यम के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने

या मजबूरी में बच्चों के स्कूल छोडने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में संविदा भर्ती के नाम पर भ्रष्टाचार का ताण्डव मचाने की बात पूर्णत: गलत है । सच यह है कि इन स्कूलों में राज्य शासन के संविदा भर्ती नियम का पालन करते हुए पूरी पारदर्शिता से योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है । यह कहना गलत है कि बिलासपुर संभाग में तो संविदा भर्ती न कर पैसा लेकर सुदूर क्षेत्र में पदस्थ शिक्षकों को पूरे प्रदेश से संलग्न/प्रतिनियुक्ति पर लाया गया है । सच यह है कि राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत योग्य व्यक्तियों का पूरी पारदर्शिता से चयन कर प्रतिनियुक्ति पर उनकी पदस्थापना की गई है । चूंकि किसी हिंदी माध्यम सकूल को बंद नहीं किया जा रहा है इसलिए इन क्षेत्रों में हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था में कोई समस्या नहीं है । यह सच है कि इन स्कूलों को संचालित करने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में सोसायटी गठित की गई है, जिससे स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप इन स्कूलों का बेहतर संचालन किया जा सके । यह कहना गलत है कि इनमें नियुक्ति स्टॉफ के नियमित वेतन की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है । सच है कि इन स्कूलों में वेतन हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था विभाग के बजट में की गई है । आगामी शिक्षा सत्र से प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय भी संचालित करने का प्रस्ताव है । प्रदेश में किसी भी प्रकार का रोष व्याप्त नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2018 में संविधान के अनुच्छेद- 345 के तहत् छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने क्या सर्वसम्मति से ऐसा कोई प्रस्ताव पारित किया था कि छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी होगी और यहां के बच्चों को उसी में शिक्षा दी जायेगी और हमारे संविधान के अनुच्छेद- 350 और 351 में क्या इस बात का उल्लेख है कि प्राथमिक शिक्षा मात्रभाषा में दी जाये । इस प्रदेश की मात्रभाषा हिंदी और बच्चों की मात्रभाषा छत्तीसगढ़ी है तो उसके बाद शिक्षाविद और सबने जो वर्ष 2021 की जो शिक्षा नीति है उसमें भी इस बात का उल्लेख है तो उसके बाद भी आपने यह परिवर्तन क्यों किया ? हमारे संविधान में 350-351 और इस विधानसभा का संकल्प है उसके बाद भी आपने यह परिवर्तन क्यों किया ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि सभी भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए लेकिन आपने भी तो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किये थे उसका क्या हुआ ? आखिर आपने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का संचालन किया था और आपने उसमें किसको रखा था ? उसमें आपने हिंदी पढ़ाने वालों को रखा था और उसका हश्र क्या हुआ ? आज हर कोई यही चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें और उसको अब हम शुरू कर रहे हैं और 171 की अभी उसमें शुरूआत की गयी है, उसकी इतनी लोकप्रियता है कि आज हर कोई वहां बच्चों को पढ़ाना चाहता है । जहां तक मात्रभाषा छत्तीसगढ़ी की बात है तो हम लोगों ने प्राईमरी स्कूलों में छत्तीसगढ़ी भाषा की जितनी भी हमारे यहां बोलियां हैं, चाहे गोंड़ी हो, भरथरी हो, कुडूक हो और भी हैं, सबको हम उसमें पढ़ा रहे हैं ।

अरपा पइरी के धार जो कि हमारा राजगीत है उसको हमने हर स्कूल में रखा है तो छत्तीसगढ़ी का भी उल्लेख उसमें किया गया है और अंग्रेजी माध्यम को आप लोगों ने ही शुरू किया था लेकिन उसमें आप लोगों ने यह गलती की थी कि उसमें आपने हिंदी के शिक्षकों को रखा था । हमने जो शुरू किया है वह उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल हैं स्वामी आत्मानंद के नाम से जो खोल रहे हैं उसमें जो शिक्षक रखे जा रहे हैं, उसमें थ्रू आउट अंग्रेजी माध्यम का जो पढ़ा हुआ जो टीचर होगा, उसे उसमें रखा गया है ताकि पूरा परिवेश अंग्रेजी माध्यम से हो और वहां बोलचाल भी उसमें हो ताकि पूरी तरह से उसे पढ़ सके। तो यह हम लोगों ने शुरूआत की है और उसकी लोकप्रियता है और इसीलिए कई जगह भी मांग की जा रही है कि वहां पर और भी स्कूल खोला जाये। तो जितने हमारे संसाधन हैं इसके लिए हमने बजट में प्रावधान किया है तब कहीं जाकर हमने खोला है। हमने प्रत्येक विकासखण्ड में खोलने का प्रयास किया है और इसकी लोकप्रियता है। यहां नहीं पूरे हिन्दुस्तान में कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल का संचालन हो रहा है, यह अच्छा है और लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। यह हमारी सोच है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, जरा आप मुझे यह बता दें स्वामी आत्मानंद जी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए बहुत सम्माननीय रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 13 हजार गांवों में स्वामी आत्मानंद वाचनालय खोले गये थे। जरा स्वामी आत्मानंद जी के नाम से उनकी आत्मा इसके लिए प्रसन्न नहीं होगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्कूल है।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह वाचनालय अभी भी चल रहा है या नहीं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चल रहा है। रायगढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से स्कूल है। रायगढ़ में राजा नटवर सिंह के नाम से स्कूल है। रायपुर में बुलाकी दास पुजारी के नाम से स्कूल है। रायपुर में ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम से स्कूल है। बिन्नी बाई के नाम से स्कूल है। जो राष्ट्रीय नेताओं के नाम से जितने स्कूल थे, उन स्कूलों को बंद करके। वहां पर रायगढ़ में आज भी धरना चल रहा है। आज भी प्रदर्शन चल रहा है। वहां से नाम मिटा दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 100 साल पुराना स्कूल है। मेरे पास फोटोग्राफ्स आये हैं। वर्ष 1910 का स्कूल है। उसका शिलान्यास है। अंग्रेज के कमिश्नर का नाम लिखा हुआ है। माननीय मंत्री जी, आप अंग्रेजी स्कूल खोल रहे हैं, उसमें हमारा कहीं कोई विरोध नहीं है, परंतु अंग्रेजी स्कूल को आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर नयी जगह चालू करके, उसके लिए पैसे की व्यवस्था करके आप खोलें। पूरे प्रदेश में क्यों आंदोलन हो रहा है ? आप बोल रहे हैं। आपने उत्तर पढ़ा है। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इन 171 स्कूलों के लिए स्वयं जवाब दिया है कि 171 स्कूलों में 50 हजार से ज्यादा बच्चे हिन्दी स्कूलों में थे और 171 स्कूलों में 71 हजार से ज्यादा बच्चे हैं। तो आप जरा यह बता दें कि उन 51 हजार बच्चों के लिए 171

स्कूलों में कितने शिक्षक थे और वर्तमान में 171 स्कूलों में कितने शिक्षकों की भर्ती हो गई है ? वहां पर वर्तमान में कितने शिक्षक हैं ? हिन्दी स्कूलों में जरा आप यह बता दें। देखिए, किसी योजना को लागू करने के लिए आप तुगलकशाही करें, यह ठीक नहीं है। मेरे विधान सभा में भाटागांव स्कूल है। हिन्दी स्कूल में 1200 बच्चे हैं। वहां के 23 टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया। अभी मेरे पास सूची है। तुगलकशाही चल रही है।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- कैसे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जरा यह बता दें कि क्या किसी कलेक्टर को दूसरे जिलों से हिन्दी मीडियम स्कूलों से शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का अधिकार है ? मेरे पास ऑर्डर की कॉपियां हैं। यहां चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में कौन से नियम चल रहे हैं ?

समय :

1.33 बजे **(सभापति महोदय (श्री सत्यनारायण शर्मा) पीठासीन हुए)**

उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है, उन्हें प्रतिनियुक्ति दे दी गई। जिन्हें 6 महीने पोस्टिंग नहीं हुई है। उन्हें प्रतिनियुक्ति दे दी गई। यह ऑर्डर है और ट्राइबल जिलों से।..।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, प्रश्न करिए। आप प्रश्न करिए, भाषण नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया है और यह बहुत बड़ा मामला है। आप भी इससे पीड़ित होंगे। आज बिलासपुर में यह ऑर्डर है। कितने लोगों का है, 28 लोगों का। दिनांक 10/08/2021.
मेरे पास ऑर्डर है। इसके बाद में ऑर्डर है।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी, कृपया आप प्रश्न करिए।

श्री कवासी लखमा :- यहां पर नेतागिरी कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां पर नेतागिरी करने आये हैं। यहां घास छिलने नहीं आये हैं।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन जी प्रश्न कर लीजिए, ध्यानाकर्षण में भाषण देने की परम्परा नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 23 लोगों को, ये बिलासपुर के कलेक्टर ने कार्यालय अध्यक्ष उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय संचालन समिति बिलासपुर ।

सभापति महोदय :- आपको अनेक अवसर मिलेंगे, आप प्रश्न कर लें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं प्रश्न कर रहा हूं क्या कलेक्टर को यह अधिकार है कि जशपुर से, चांपा से, रायगढ़ से, कोरिया से, मुंगेली से, बलौदाबाजार से, रायगढ़ से, गरियाबंद से, मतलब जो टीचर अपने गृह जिलों में जाना चाहते हैं, वे मोटी रकम देकर अपने गृह ज़िले पहुंच गए ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, आप तो भाषण दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, यह पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य का सवाल है ।

सभापति महोदय :- यह सदन नियम, प्रक्रिया से चलता है । आप कृपा करके प्रश्न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने प्रश्न पूछा है कि क्या 171 स्कूलों में 50 हज़ार बच्चों के लिए पूर्व में कितने शिक्षक थे और वर्तमान में कितने शिक्षक हैं ? 171 अंग्रेज़ी स्कूलों में कितने शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और कितने शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे ज़िलों से ले आया गया है । बिलासपुर में क्या कलेक्टर को यह अधिकार था कि वह प्रतिनियुक्ति में जशपुर से, जगदलपुर से, मुंगेली से, अंबिकापुर से शिक्षकों को ला सके । क्या अनुसूचित क्षेत्रों में बच्चे नहीं पढ़ते हैं ? उन्होंने किस अधिकार के तहत् शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया ? क्या अनुसूचित क्षेत्रों से बिना एवजीदार के किसी शिक्षक को बुलाने का अधिकार है ? एक कलेक्टर को दूसरे जिले के शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का अधिकार है क्या?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, पहले तो आपने यह कहा कि स्कूलों का नाम बदल दिया गया है । किसी भी स्कूल का नाम परिवर्तन नहीं किया गया है, जिनके नाम पर स्कूल था, उन्हीं के नाम पर अंग्रेज़ी माध्यम उत्कृष्ट स्कूल की जो योजना है और उसी के तहत् किया गया है । रही प्रतिनियुक्ति की बात, तो प्रतिनियुक्ति राज्य शासन के अधिकार में है और राज्य शासन ने उसको किया है और हमने संबंधित शिक्षक की सहमति से प्रतिनियुक्ति की है । हमने जो प्राचार्य प्रतिनियुक्ति पर भेजा है उसके लिए यहां समिति बनी थी, समिति ने पूरा स्क्रीन किया है, उनके साक्षात्कार लिये गये हैं, अगर किसी भी संस्था का प्रमुख अच्छा रहेगा तो वह संस्था अच्छा काम करेगी । विभाग के जिन लोगों को प्राचार्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा, यहां उनकी स्क्रीनिंग हुई, उनसे बात करके उनकी सहमति लेकर प्रशासनिक अकादमी में उनकी ट्रेनिंग कराई गई । इसलिए इसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने बिलासपुर के 3 आदेशों का उल्लेख किया है । मेरे पास मुंगेली जिले के जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश है कि प्रतिनियुक्ति के संबंध में इस कार्यालय से कोई सहमति नहीं ली गई, यह जिला शिक्षा अधिकारी लिखकर भेज रहा है । जहां पर वह शिक्षक नियुक्त है, क्या वहां के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता है या नहीं ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- प्रतिनियुक्ति कलेक्टर ने नहीं की है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मुख्यमंत्री जी आपने एक अच्छे उद्देश्य से स्वामी आत्मानंद जी के नाम से स्कूल खोला है, परंतु आदिवासी इलाकों के पदस्थ शिक्षक पैसा देकर अपने गृह जिले के अंग्रेजी स्कूलों में पदस्थ हो रहे हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कम से कम स्वामी आत्मानंद

जी के नाम से यह नहीं होना चाहिए । माननीय मंत्री जी, आपकी जानकारी में नहीं है, आप मुझे प्रतिनियुक्ति आदेश बता दें ।

सभापति महोदय :- चलिए, केशव चंद्रा जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, मेरा प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- बड़ा लम्बा हो गया, बृजमोहन जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 171 स्कूलों में 50 हजार बच्चों के लिए कितने हिंदी माध्यम के शिक्षक थे और वर्तमान में कितने शिक्षक हैं ? अंग्रेज़ी स्कूलों के लिए उनका एक-एक स्कूल के लिए सेटअप क्या है, कितने लोगों की भर्ती की गई है और कितने लोगों को प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है और जो प्रतिनियुक्ति के लिए कलेक्टर बिलासपुर ने आदेश जारी किये हैं क्या वह नियमानुसार है ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, वे वहां पर हिंदी माध्यम से पढ़ेंगे, उनके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है । जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, वे अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ेंगे। जहां तक प्रतिनियुक्ति की बात है तो प्रतिनियुक्ति राज्य शासन का अधिकार है । जो टीचर जिस स्कूल में जाना चाहते हैं, उनकी सहमति पर जाएगा और उसके बाद वहां जो कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, उसमें कलेक्टर हैं, जिला पंचायत के सी.ई.ओ. हैं, वहां के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, सहायक आयुक्त ट्रायबल हैं, वे उनका साक्षात्कार लेंगे, उसके बाद प्रतिनियुक्ति दी जाएगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं particular पूछना चहता हूं। अगर आप अनुमति देंगे तो मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। बिलासपुर के कलेक्टर ने 100 से ज्यादा लोगों को प्रतिनियुक्ति पर बिना शासकीय आदेश के अनुसूचित जिलों से सीधा अपने यहां को बुला लिया। इसमें करोड़ों का लेन-देन हुआ है। मेरे पास में मोबाइल टेप है। आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुना दूं। समाचार पत्रों में छपा है। माननीय मंत्री जी मैं आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहा हूं। जो स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर deputation में आने के लिए लोग अपने गृह जिले में आने के लिए लाखों रूपये खर्च कर रहे हैं। हमारे अनुसूचित क्षेत्र खाली होते जा रहे हैं। उनकी जो खरीदी हो रही है, वह खरीदी में जितना बड़ा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। स्वामी आत्मानंद जी के नाम से कम-से-कम ऐसा नहीं हो। हम लोगों ने स्वामी आत्मानंद जी को अपना आदर्श माना है, उनको पूजा है। वे स्वामी विवेकापंद जी के अनुयायी थे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं...।

सभापति महोदय :- चलिए। बृजमोहन जी, प्रश्न करिए न। आप प्रश्न तो नहीं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। भाषण देने की परंपरा नहीं है। प्रश्न करिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, अब इसमें क्या हुआ कि इसी मुद्दे पर बिलासपुर में दो लोग जेल में हैं। यह आदेश कलेक्टर के आदेश से हुआ है। कलेक्टर के खिलाफ में आपने क्या

कार्रवाई की? क्या कलेक्टर को आदेश करने का अधिकार था? आप अनुमति दे तो मैं सदन के पटल पर रख देता हूं। आप मुझे बता दे कि कितने शिक्षकों की कमी है? और भविष्य में किसी भी हिंदी स्कूल के टीचर को जब तक वहां पर की एवजीदार की व्यवस्था नहीं हो तब तक जिनको आपने बुलाया है, वहां अंग्रेजी स्कूल नहीं बने हैं। वह अभी भी हिंदी स्कूल है और वह deputation पर अंग्रेजी स्कूल में आ गये और वह हिंदी स्कूल खाली पड़े हुए हैं। वहां पर बच्चे नहीं है। मेरा जो मूल प्रश्न है, उसके बारे में मैं आपसे यह चाहता हूं कि स्वामी आत्मानंद जी के नाम से खोली गई अंग्रेजी स्कूलों के नाम पर हिंदी स्कूलों की बर्बादी न हो, हिंदी स्कूलों के बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो, इसके बारे में मैंने दो-तीन प्रश्न किए हैं, मंत्री जी आप यह जानकारी दे दे।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय सभापति महोदय, हमारा जो अंग्रेजी माध्यम को लेकर स्कूल खोलने का आशय है, वह वहां पर उत्कृष्ट हो। वहां पर उसकी गुणवत्ता रहे। जहां तक आप कलेक्टर बिलासपुर की बात कर रहे हैं तो कलेक्टर को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अधिकार नहीं है। प्रतिनियुक्ति पर भेजने का अधिकार राज्य सरकार को है और राज्य शासन ने उसमें अनुमति प्रदान किए हैं तो वहां प्रतिनियुक्ति पर गए हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्य शासन के आदेश की कापी मुझे उपलब्ध करवा दे। जिस-जिस दिनांक का आदेश है, वह आपने बाद में जारी किया है। पहले कलेक्टर और बहुतायत अधिकारी ये 100 लोगों से 10 करोड़ रूपये खाये हैं। (शेम-शम की आवाज) ये समाचार पत्रों में आप ही लोगों का दिया हुआ है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, यह गलत है। आपका आरोप गलत है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- सभापति महोदय, बृजमोहन जी कुछ भी बोलते रहते हैं। अनावश्यक रूप से कुछ भी बात करते रहते हैं।

श्री देवेन्द्र यादव :- सभापति महोदय, वे निराधार आरोप लगा रहे हैं।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- सभापति महोदय, वे आरोप लगा रहे हैं, यह गलत बात है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, सदन की कमेटी से जांच कराई जाये। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- शर्मा जी, बैठिये।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, वे ऐसे कैसे आरोप लगा सकते हैं। यह निराधार है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- पूर्व मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। (व्यवधान) मैं उन्होंने क्या कहा था कि (व्यवधान)। हम लोगों ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है और ना ही करने देंगे इसमें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने सरकार में बैठे हुए किसी के ऊपर भी आरोप नहीं लगाया है। मैंने इस सदन में बैठे हुए किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- तुमन तो जानते नई हव (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- नहीं, मंत्री जी के ऊपर आरोप लगाये हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं-नहीं, मंत्री जी उसको जेल में क्यों भेजना पड़ा, यह पता लगवायें? जिला शिक्षा अधिकारी के यहां से (व्यवधान) पता लगवायें?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नेता जी, उसमें जांच हुई और कार्रवाई भी हो रहा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- जेल गये ना?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हां, जायेगा।

श्री धरम लाल कौशिक :- हां, बस। आप उसको स्वीकार करिए न।

श्री सौरभ सिंह :- और बाकी लोग बचा थोड़ी है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आप लोग 15 साल से भ्रष्टाचार यही करते आये हो, इसलिए तो जनता ने हटा दिया है।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, आप लोग क्या चाहते हैं? जो काम आप लोग नहीं कर, वह काम हम लोग कर रहे हैं, वह काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, हम यह चाहते हैं कि स्वामी आत्मानंद के नाम से खोली गई स्कूलों के संचालन करने के लिए इस देश की राष्ट्रभाषा, छत्तीसगढ़ की मातृभाषा, छत्तीसगढ़ी और हिंदी की स्कूलों के साथ भी सम्मान किया जाए। कोई भी हिंदी माध्यम स्कूल बंद न की जाए। वहां के शिक्षकों का ट्रांसफर न किया जाए। अनुसूचित क्षेत्रों में जो लोग पदस्थ हैं, उनको यहां पर बुलाकर डेपोटेशन पर...।

सभापति महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप सुन रहे हैं न। मेरी बात मान लीजिए, मेरा ध्यानाकर्षया जवाब आने दीजिए न। उन क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्रों से कोई भी शिक्षक को डेपोटेशन पर न बुलाया जाए और सीधी भर्ती बिलासपुर से...।

सभापति महोदय :- माननीय चंद्रा जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, आप सुन नहीं रहे हैं। आपने बिलासपुर में सीधी भर्ती क्यों नहीं की ? बिलासपुर में डेपोटेशन से क्यों बुलाया ?
बिलासपुर के जो नौजवान बच्चे हैं, वह आपको मिल जाते। आपको जिला के स्तर पर भर्ती करना है तो बिलासपुर के...।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय सभापति जी, सदस्य प्रश्न पूछ चुके होंगे। (व्यवधान)



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने प्रश्न पूछा है, मेरे प्रश्न का जवाब आ जाए।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय सभापति महोदय, इनके कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवसायीकरण-व्यावसायीकरण।

सभापति महोदय :- चंद्रा जी, चलिये बहुत लंबा हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, बिलासपुर में आपने क्यों नहीं बुलाया ? (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- आपने तो कहा डीआर. को कहा था...।

सभापति महोदय :- बस हो गया। माननीय चंद्रा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय सभापति महोदय...।

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- आपने यह भी कहा कि बहुत ही अच्छा आदमी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर में जहां पर पढ़े-लिखे बच्चे हैं जहां पर 3-3 विश्वविद्यालय हैं वहां पर सीधी भर्ती करने की बजाय वहां पर...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति महोदय, इन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा का बाजारीकरण बढ़ाया है। व्यवसायीकरण बढ़ाया है। आज जब गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा मिल रही है तो इनको यह बात रास नहीं आ रही है। इनका कार्यकाल याद कर लें। लोग धरना-प्रदर्शन, आंदोलन करते रहे।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- शिक्षा देने का विरोध भी सुनते हैं।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मेरा भी सदन में...। (व्यवधान)

स्कूल शिक्षा मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- आप जवाब दीजिए न।

श्री देवेन्द्र यादव :- आप नो प्रोफिट नो लॉस की बात करते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति जी से...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, बिलासपुर में आपने सीधी भर्ती क्यों नहीं की ? बिलासपुर में 3-3 विश्वविद्यालय हैं बिलासपुर में 2200 कॉलेज हैं बिलासपुर जिले में, बिलासपुर संभाग में। आपने वहां डेपोटेशन में क्यों बुलवाया ?
क्या वहां पर नौजवानों की कमी थी ?

सभापति महोदय :- चलिये, बृजमोहन जी।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं, विभाग में जो टीचर हैं। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- सबसे बड़ी बात कम पूछते नहीं है। आपका भाषण बहुत लंबा हो गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे प्रश्न पूछना है। मेरा जवाब आने दीजिए। मेरे एक भी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। मेरे प्रश्न का जवाब तो आ जाए।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्रा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दिया कि जहां आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम विद्यालय खुला है तो वहां हिंदी मीडियम की स्कूल बंद नहीं की जाएगी और उन्होंने जवाब में यह भी कहा कि यह विद्यालय तथा कार्यालयीन कार्य में लगे स्टाफ का स्थानांतरण एक प्रशासकीय प्रक्रिया है लेकिन जितने भी हिंदी स्कूल थे, पूरे के पूरे स्टाफ का ट्रांसफर कर दिया गया। शासकीय आदर्श और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (सक्ती) में जनवरी, 2022 को आठ था, आपने आठ के आठ को ट्रांसफर कर दिया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्मिक विद्यालय (जैजैपुर) में 17 स्टाफ थे, आपने 17 का स्थानांतरण कर दिया। शासकीय कन्या हाई स्कूल (चंद्रपुर) में जनवरी, 2022 में 8 स्टाफ थे, आपने 8 के 8 स्टाफ का स्थानांतरण कर दिया। शासकीय उच्चतर माध्मिक विद्यालय (डभरा) में 27 थे, आपने 27 का स्थानांतरण कर दिया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (मालखउदा) में 20 थे, 20 के 20 का आपने स्थानांतरण कर दिया। अब वहां बच्चे लोग बिना शिक्षक के कैसे पढ़ेगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा हाथी चर दीस ओला।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उन हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं ? अगर बंद नहीं करना चाहते हैं तो वहां शिक्षक की व्यवस्था कैसे करेंगे ? आपने तो उनका स्थानांतरण कर दिया। बच्चे लोग आंदोलनरत हैं, सड़क पर बैठे हैं। आप बच्चे लोगों से क्यों राजनीति करवा रहे हैं ? बिना शिक्षक के बच्चे लोग कैसे पढ़ेंगे ?
इसलिए कृपया बताये कि आप कैसे स्कूल संचालित करेंगे और शिक्षक की व्यवस्था कैसे करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- ठीक है। माननीय सभापति जी, पहली बात तो यह है कि किसी भी हिंदी माध्यम के जो स्कूल हैं, उसको हम बंद नहीं किये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके सामने नाम लिये हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं बंद नहीं किये हैं। वहां पर दो पालियों में अंग्रेजी की भी पढ़ाई हो सकती है और हिंदी की भी पढ़ाई हो सकती है। हिंदी की पढ़ाई के लिए वहां पर टीचर की व्यवस्था है और अभी हम लोगों ने आदेश दिया है कि यदि किसी भी टीचर को जिनका ट्रांसफर हुआ है वह उसको रिलीफ न किया जाए। अभी परीक्षाएं चल रही हैं तो उनको अभी रोका गया है। चाहे बोर्ड की परीक्षा हो



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

या स्थानीय परीक्षा हो, वह लोग तब तक वहां रहेंगे और हिंदी की पढ़ाई वहां पर हो, उसके लिए हम वहां टीचरों की व्यवस्था करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप स्कूल का नाम बता रहे हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- नहीं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं, आपके पास जो शिक्षक हैं उनका आपने ट्रांसफर कर दिया। अब आप कहां से व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- स्कूल का नाम बताये हैं।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- अभी कोई रिलीफ नहीं हुए हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति जी, इनके रिकार्ड में है रिलीफ हो गये, ज्वाइनिंग कर लिये। डी.ई.ओ. ने एक आदेश दिया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे भइगे, ते कथरी ओढ़ के घी पियत हस भैय्या।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप कहां से व्यवस्था करेंगे ?

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि वहां अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो और हिन्दी माध्यम से भी पढ़ाई हो । विद्यार्थियों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी, इस बात को मैं विश्वास के साथ कहता हूं ।

सभापति महोदय :- चलिए, बहुत लंबी चर्चा हो गयी । माननीय सदस्य शैलेश पांडे जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- सभापति जी, वहां के बच्चे लोग आन्दोलनरत् हैं । वहां दिक्कत आ रही हैं, बच्चे लोग आन्दोलनरत् हैं, बच्चे लोग सड़कों पर बैठे हैं । वहां शिक्षक पदस्थ थे, उनको ट्रांसफर क्यों किया गया ? 171 शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं ।

सभापति महोदय :- शैलेश पांडे जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरा एक अंतिम प्रश्न है ।

सभापति महोदय :- अब तो गाड़ी आगे निकल गई ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, तिल्दा-नेवरा में एक स्कूल को आप जबरदस्ती बंद कर रहे हैं । वहां की बच्चियां धरने में बैठी थीं, यह तीन दिन पहले की बात है, आप रिकार्ड देख लीजिए । तिल्दा-नेवरा में हिन्दी माध्यम की स्कूल को आप लोग जबरदस्ती बंद कर रहे हैं, इससे 50 छात्राएं ये लिखकर दे रही हैं ।

सभापति महोदय :- ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है, आप बैठिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति जी, मुझे एक प्रश्न करने दीजिए ।

सभापति महोदय :- प्रमोद जी, आप बैठिए ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, मंत्री जी को मालूम ही नहीं है, जाने दो । (हंसी)

सभापति महोदय :- प्रमोद जी, इस ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है। आप बैठिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरा अंतिम प्रश्न है । रायपुर शहर की आर.डी. तिवारी स्कूल, रायपुर की डी.पी. पुजारी स्कूल, रायपुर की शहीद स्मारक स्कूल, इन तीनों स्कूलों में हिन्दी माध्यम की स्कूलें बंद कर दी गई हैं क्या उसको प्रारंभ किया जाएगा और बिन्नी बाई सोनकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटागांव के सभी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया है । क्या उनको वापिस लाया जाएगा, मेरा एक प्रश्न है, उसका जवाब दे दें ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- सभापति महोदय, जो बच्चे हिन्दी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम शिक्षकों की व्यवस्था वहां पर करेंगे और किसी प्रकार का नाम परिवर्तन नहीं किया जाएगा । चाहे वह आर.डी. तिवारी स्कूल की बात हो, चाहे बिन्नी बाई स्कूल की बात हो (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, यह सराकर गलत है । हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से असंतुष्ट हैं, हम सदन से बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
1:53 बजे

**बहिर्गमन**

**भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में**

(श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नारे लगाते हुए सदन से बहिर्गमन किया गया)

सभापति महोदय :- शैलेश पांडे जी अपने ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ें ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, एक प्रश्न पूछने की अनुमति दीजिए ।

सभापति महोदय :- इस ध्यानाकर्षण में आपका नाम नहीं है । आप बैठ जाईए, प्लीज़ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

**ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)**

**(4) बिलासपुर जिले में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया लंबित रखी जाये**

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण की सूचना का विषय इस प्रकार है :- बिलासपुर जिले के अंतर्गत खाद्य विभाग द्वारा विभिन्न हितग्राहियों का बड़ी संख्या में राशन कार्ड बनाया गया है, परन्तु वर्तमान में लोगों के द्वारा आवेदन पत्र जमा करने के बाद भी संबंधित अधिकारियों के द्वारा अनावश्यक रूप से राशन कार्ड बनाने एवं नाम जोड़ने व काटने की प्रक्रिया लंबित रखी जा रही है । शासन की महत्वपूर्ण योजना खूबचंद बघेल एवं मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना अंतर्गत नि:शुल्क ईलाज में राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है । विभाग एवं जिला अधिकारियों के रवैया एवं आवेदन लंबित रखने के कारण लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिससे जनता में अत्यधिक रोष व्याप्त है ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक कुल 30283 नवीन राशनकार्ड जारी किए गए हैं तथा पूर्व से प्रचलित राशनकार्डों में 48544 नवीन सदस्यों के नाम जोड़े गए हैं । जिले में फरवरी 2022 में 2885 नवीन राशनकार्ड जारी किए गए तथा 4911 नवीन सदस्यों के नाम जोड़े गए तथा 3591 सदस्यों के नाम राशनकार्ड के हटाये गए हैं । बिलासपुर जिले में वर्ष 2021-22 में माह फरवरी 2022 तक नवीन राशनकार्ड हेतु 30492 आवेदन तथा राशनकार्डों में सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए 49109 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से नवीन राशनकार्ड के 30283 आवेदन तथा राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु 48579 आवेदन निराकृत किये जा चुके हैं तथा नवीन राशनकार्ड के 209 आवेदन तथा राशनकार्ड में सदस्यों के नाम जोड़ने हेतु 530 आवेदन परीक्षण हेतु विचाराधीन हैं । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशनकार्ड जारी किया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के अन्तर्गत राशनकार्ड हेतु आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षण उपरान्त पात्र पाये जाने पर हितग्राहियों को 30 दिवस के भीतर राशनकार्ड जारी किये जाने का प्रावधान है। जिले में उपरोक्तानुसार नवीन राशनकार्ड जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। अत: यह कहना सही नहीं है कि बिलासपुर जिले में राशनकार्ड के आवेदन को लंबित रखा जा रहा है।

बिलासपुर जिले में वर्ष 2021-22 में माह अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के अन्तर्गत 34,036 व्यक्तियों द्वारा नि:शुल्क ईलाज की सुविधा प्राप्त की गई है। अत: यह कहना सही नहीं है कि जिले में राशनकार्ड के आवेदन

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

लंबित होने के कारण लोगों को नि:शुल्क चिकित्सा में परेशानी हो रही है। जिले में नवीन राशनकार्ड जारी करने के सम्बन्ध में जनता में कोई रोष व्याप्त नहीं है।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, तुंहर ए.पी.एल. वाला राशनकार्ड बने हे या बने हे , तेला पहली बतावा।

श्री शैलेश पांडे :- मेरा राशनकार्ड बना है।

श्री सौरभ सिंह :- बने हे ना।

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, मैं पहले माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी को यह जानकारी नहीं है कि उनके विभाग के अधिकारी आम जनता का फोन नहीं उठाते हैं, विधायकों का भी फोन नहीं उठाते हैं। मैं मंत्रालय में सचिव महोदय फोन करता हूं तो वह भी फोन नहीं उठाते हैं।

समय :
1.57 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, माननीय मंत्री जी मैं आपको डाटा देता हूं कि 1 दिसम्बर, 2021 को खाद्य नियंत्रक को पत्र लिखा था और साथ में सूची भी भेजी थी कि इन-इन लोगों के आवेदन राशनकार्ड बनाने हेतु आपके पास आये हुए हैं, हमारे पास भी आवेदन है, इनका राशन कार्ड बनाईये। राशनकार्ड बनाने की प्रक्रिया यह है कि नगर निगम से वेरीफिकेशन होता है, उसके बाद खाद्य विभाग में जाता है। अभी तक यही प्रक्रिया थी। अब समस्या यह आ गई है कि खाद्य नियंत्रक बोलते हैं कि श्रम विभाग से अनुमोदित कराकर लाईये। यह कौन सी प्रक्रिया आ गई ? प्रश्न यह है कि श्रम विभाग बीच में कहां से आ गया, जबकि खाद्य विभाग राशनकार्ड बनायेगा, आप इस बात का निराकरण कर दीजिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि मेरी जानकारी के अनुसार बिलासपुर में 241 राशनकार्ड बनाने हेतु सूची भेजी थी, जो अभी लंबित है। मैं उसमें से एक नाजरा बेगम का नाम बताना चाहता हूं। नाजरा बेगम का पति बीमार था, उसके पास ईलाज के लिए पैसे नहीं थे। मैंने कहा कि इसका राशनकार्ड बना दीजिये, लेकिन उसका राशनकार्ड नहीं बनाया गया। आप लोग सेवा गारन्टी की बात कर रहे हैं, यह अच्छी बात है, अच्छा काम है। लेकिन 90 दिन होने के बाद भी नाजरा बेगम का राशनकार्ड नहीं बना है। मेरे पास ऑनलाईन आवेदन और आफलाईन का डाटा है। तो ऐसे जो लंबित राशनकार्ड हैं, इसके लिए जो अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं क्या आप उसकी जांच करवायेंगे ? दूसरी बात यह है कि ऐसे राशनकार्ड कब तक बन जायेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राशनकार्ड बनाना सतत प्रक्रिया है और राशनकार्ड बनाने में कहीं भी रोक नहीं है। माननीय सदस्य के द्वारा जिस अवधि का पूछा गया है, उस

अवधि में कुल 30,283 राशनकार्ड जारी किए गए हैं। यदि आप इसका डिटेल पूछेंगे तो मैं आपको बता सकता हूं। अप्रैल माह में 1,763 राशन कार्ड, मई में 338 राशनकार्ड जारी किए गए हैं।

श्री शैलेश पांडे :- आप दिसम्बर, 2021 से अभी तक बता दीजिये।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिस अवधि का प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर आयेगा। इसलिए आपने जिस अवधि का पूछा है, उस अवधि में 30,283 राशनकार्ड बने हैं। यदि आप पूछेंगे कि किस-किस श्रेणी के राशनकार्ड बने हैं तो उसको भी बता दूंगा। यदि लंबित राशनकार्डों के बारे में पूछेंगे तो उसको भी बता दूंगा। यदि आप लंबित राशनकार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्हा में 75 आोवदन लंबित है, उसमें 5 आवेदन सदस्यों के नाम जुड़ने हेतु लंबित है। तखतपुर में 20 आवेदन, कोटा में 42 आवेदन, मस्तुरी में 49 आवेदन, बिल्हा में 23 आवेदन, कुल 209 आवेदन लंबित है । उसमें 530 सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए आये हैं । इसमें नाम जोड़ना है। आपने जो अवधि पूछा है, उसमें 30 हजार 283 राशन कार्ड बना दिये गये हैं । यह माह अप्रैल से फरवरी तक है ।

श्री शैलेष पाण्डे :- श्रम विभाग का है ।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें श्रम विभाग का कोई रोल नहीं है ।

श्री शैलेष पाण्डे :- आपके अधिकारी बोलते हैं, मैं तो खुद बात किया हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- आप प्रक्रिया से थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए । राशन कार्ड बनाने के लिए कहीं भी श्रम विभाग से किसी प्रकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग ध्यानाकर्षण पर चर्चा कर रहे हैं या आपसी चर्चा कर रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, वह संवाद चल रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग आपस में बातें कर रहे हो ।

श्री अमरजीत भगत :-प्रश्न पूछ रहे हैं तो जानकारी तो देनी होगी ।

अध्यक्ष महोदय:- ऐसा नहीं हो सकता । ध्यानाकर्षण का जवाब दीजिए, आपसी चर्चा करने की जरूरत नहीं है ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपने समय दिया । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद खाद्य नियंत्रक जी को फोन किया । मेरे कार्यालय से उनके पास कागज गया । उसके बाद उन्होंने नहीं किया । जब नहीं किया तो मैंने उनको फोन किया । उन्होंने मुझे बताया कि अनुमोदन करने के लिए मैंने श्रम विभाग में भेजा है । उन्होंने मुझसे कहा इसलिए मैं यहां पर सत्य भाषण दे रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय:- आपकी सत्यता को देखते हुये मैंने स्वीकार किया है, अब समझ में आ गया कि अधिकारी गलत है, उसको ठीक करेंगे ।

श्री शैलेष पाण्डेय :- मैं यही जानना चाहता हूँ कि शहर के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं मिल पा रहा है । यह मेरी परेशानी है । माननीय मंत्री जी इसका निराकरण करें ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

समय :
2.02 बजे

**नियम 267 क के अधीन शून्यकाल की सूचनाऐं**

अध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्य की शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इसके उत्तर के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया जायेगा ।

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
3. श्री नारायण चंदेल
4. श्री सौरभ सिंह
5. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

समय :
2.03 बजे

**वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परम्परानुसार सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत की जाती है । उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाहूंगा कि वे सभी मांगों को एक साथ प्रस्तुत कर दे । मैं समझता हूँ कि इससे सदन सहमत है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 31 मार्च 2022 समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 3, 6, 8, 11, 19, 21, 30, 41, 46, 64, 65, एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार सौ बानबे करोड़, तैंतीस लाख, बहत्तर हजार, तीन सौ अनठानबे रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कल भी बात की थी, आज भी बात की है । राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होना है, एक दिन का समय रखा है । मुझे लगता है कि शायद हम लोगों के साथ में जो विश्वास का आधार होना चाहिये, वह नहीं है । आपने अनुपूरक बजट को पहले रख दिया है । राज्यपाल जी के भाषण को बाद में रखा । यह राज्यपाल जी का अपमान है । इसलिए हम मुख्यमंत्री जी के सप्लीमेंट्री बजट का ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- सुन तो रहा हूँ ।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आप हमारे नियम प्रक्रिया को पढ़ लें । परम्पराओं को भी यदि ध्यान में रख लें । आज तक कभी भी जो हम करने जा रहे हैं, वह हुआ नही है ।

डॉ.शिव डहरिया :- वर्ष 2010 में इसी सदन में हुआ है । कुछ पढ़ लिखकर आया करो ना । बिना पढ़े लिखे मत आया करो । अध्यक्ष जी, वर्ष 2010 में इसी सदन में हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- नकल के लिए भी अकल चाहिये ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं यह जो बात बोल रहा हूँ, कोल एण्ड शकधर के छोटे स्वरूप में है । जो हमारे नियम प्रक्रिया में है ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें कोरोना का जिक्र है क्या ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह प्रस्ताव किये जाने पर अभिभाषण पर चर्चा अध्यक्ष द्वारा नियत किये जाने के बाद किसी दिन के लिए स्थगित किया जाये । उस अभिभाषण पर चर्चा शासकीय विधेयक अन्य किसी शासकीय कार्य के पक्ष में विलंबित की जा सकती है । यदि शासकीय कार्य में आपको विलंबित करना है, वह उसी दिन नहीं हो सकता । आप पांच दिन बाद चर्चा करवा लीजिए, सरकार का दूसरा बिजनेस ले लीजिए ।

डॉ.शिव डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय करते हैं वहीं होता है । इतना तो ध्यान रखा करो ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग सब शासकीय बिजनेस को करने के लिए तैयार है । परन्तु कम से कम नियम, परम्पराओं का ध्यान रखा जाना चाहिये । हम पहले दिन से इसबात का आग्रह कर रहे हैं । हमें इस बात का खेद है कि आप हमारी बातों के ऊपर में जितना ध्यान देकर परम्पराओं का निर्वहन होना चाहिये, वह नहीं हो रहा है । यह जो हो रहा है कि माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर चर्चा बाद में होगी, इस पर चर्चा पहले होगी। यह उचित नहीं है। एक ही दिन में दोनों बिजिनेश को निपटाना मुझे लगता है कि यह परंपराओं के विपरित है। अगर आप इसके ऊपर में निर्णय करें तो अच्छी बात है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप इस पर चर्चा करिये न, चर्चा में भाग लीजिए। आप चर्चा में भाग लेते नहीं हैं, आप लोग चर्चा से भाग जाते हैं। आप दोनों नेता जी को तो बोलने ही नहीं देते।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जिस प्रणाली को स्वीकार कर रहे हैं, जो Great Britain Parliamentary है, नियम प्रक्रियाओं से ज्यादा उसके convention की बात होती है। ..(व्यवधान).. मैं चाहता हूं कि अभिभाषण के मामले में नियम प्रक्रियाओं का पालन किया जाये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चन्द्राकर जी, जिस किताब और नियमावली का हवाला दे रहे हैं, उनको उसकी पूरी जानकारी नहीं है कि उसके ऊपर भी माननीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार होता है, किसी भी विषय में चर्चा करा सकते हैं।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, यदि नियमों में आपको चलना है तो फिर आप जब तक पूरे शासकीय कार्य न हो जायें तब तक टाईप के लिए डाल दीजिए। आप इसको convention के आधार पर इसको कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है। छत्तीसगढ़ में अजीब स्थिति निर्मित हो रही है। आपसे बार-बार आग्रह है। हम पारित करने के विरोध में नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी, विधानसभा में साल में एक बार आते हैं, सप्लीमेंटी बजट साल में चार बार आता है, बजट आता है, शासकीय काम होते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग राज्यपाल महोदया जी का कितना सम्मान करते हैं? यही लोग राज्यपाल जी के अभिभाषण में टोका-टाकी कर रहे थे। आप लोग कर रहे थे या नहीं कर रहे थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राज्यपाल जी के अभिभाषण को विधानसभा में प्रायरटी देना चाहिए, विधानसभा का सत्र भी उनके द्वारा आहूत किया जाता है। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव के ऊपर में चर्चा पहले चर्चा करने की बजाय, पूरा समय देने की बजाय आप शासकीय काम को ज्यादा महत्व दें तो मुझे लगता है कि यह शायद सदन की अवमानना होगी, राज्यपाल जी की अवमानना होगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई अवमानना नहीं होगी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी जानकारी में और शायद इस सदन में भी अभी तक की जो हमारी प्रचलित परंपरा रही है, हमारी प्राथमिकता में सबसे पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा रही है और चर्चा के बाद में अन्य शासकीय बिजिनेश होते हैं। शासकीय बिजिनेश के बाद में जो बाकी हमारे सब विषय आते रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि एक तो हमारी परंपरा टूट रही है कि दो दिन की जगह में एक दिन पहली बार हुआ। आपने इसका कारण कोरोना बताया। अब तो कोरोना नहीं है और दूसरी बात मैंने कहा कि चुनाव भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी हो करके आ गये हैं। उत्तरप्रदेश में खूब गुल खिलाये हैं। परसों 10 तारीख को उसका परिणाम भी आ जायेगा। इस स्थिति में अब सत्र की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

श्री अमरजीत भगत :- क्या आप ऐसा बोल करके भयभीत कर रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- भयभीत नहीं कर रहे हैं। उत्तरप्रदेश वाले आपकी क्या दुर्गति करेंगे, आपको देखना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह परंपरा कभी नहीं रही है कि एक दिन में माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा हो और उसी दिन सप्लीमेंट्री पर चर्चा हो। यह कभी नहीं हुआ है। लेकिन हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे, आप आसंदी पर बैठे हुए हैं। यदि बन रही हैं तो कोई नई परंपरायें बनें। यहां की गरिमा बढ़े और परंपराओं को तोड़ने का काम न करें। इसलिए सरकार जो चाहती है, वह सब संभव है, ऐसा नहीं है। आसंदी को इस पर विचार करना चाहिए और विचार करके एक दिन

में दोनों चर्चा नहीं होगी। आप तृतीय अनुपूरक की चर्चा किसी भी दिन करा लीजिए, हम लोग उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। पहले माननीय राज्यपाल महोदय जी के अभिभाषण पर चर्चा होगी और उस पर चर्चा होने के बाद में तृतीय अनुपूरक पर चर्चा होगी। हम उसके लिए आपसे निवेदन करते हैं और इस परंपरा का पालन होना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि शासन पक्ष को किसी तरह की जिद ही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करवा दीजिए और अनुपूरक बजट लेकर फिर से एक सूची निकाल दीजिए, हम लोग आज ही शासकीय काम करेंगे। आप धवनिमत से बिना बहस के प्रस्ताव पारित करवा दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अध्यक्ष महोदय को आर्डर कर रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- यह परंपरा ठीक नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आपने अभी लोकसभा में देखा होगा माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर 7 दिन चर्चा हुई है और 7 दिन की चर्चा के बाद में प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कृषि बिल में कितने दिन चर्चा करवाये थे, उसको तो बताओ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर एक दिन चर्चा करवा रहे हैं, यह उचित नहीं है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- लोकसभा में कृषि बिल में कितने दिन चर्चा करवाये थे ? कृषि बिल को बिना चर्चा के पारित कर दिये थे।

श्री अमरजीत भगत :- कृषि बिल जब लोकसभा में लाया गया था तो बिना चर्चा के पारित कर दिया था। आप दिल्ली का उदाहरण न ही दें तो ज्यादा अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय :- अब मैं बोलू कि आप ही लोग बोलते रहेंगे ?

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, आप बोलिये।

एक मिनट, डहरिया जी को पूरा बोलवा दीजिये।

**अध्यक्षीय व्यवस्था**

अध्यक्ष महोदय :- कल आप लोगों ने यह कहा कि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में संशोधन देने के लिये कुछ समय बढ़ाया जाये। कल सायं 5 बजे का समय निर्धारित था, आपने अगले दिन पूर्वाह्न 11 बजे करा लिया। अब उसमें हमको टाईप करने और यहां व्यवस्थाएं देने में कुछ समय तो लगेगा। जो खाली समय था उसमें चर्चा करा लिया, इसमें क्या आपत्ति है और अभिभाषण पर चर्चा से पूर्व अन्य कार्य



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

न लिये जाने संबंधी आपके व्यवस्था के प्रश्न को मैंने सुना। संसदीय पद्धति एवं प्रक्रिया पुस्तक कॉल संदर्भ के पृष्ठ 228 में यह उल्लेख है कि अभिभाषण पर चर्चा, अभिभाषण किये जाने के कुछ दिनों के बाद प्रारंभ होती है और इस बीच समय में अन्य सरकारी काम किया जाता है।

अभिभाषण किये जाने के बाद और उस पर चर्चा प्रारंभ होने के बीच के समय में अन्य सरकारी काम किया जा सकता है। अत: आपके व्यवस्था के प्रश्न को मैं अग्राह्य करता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- एक दिन में कभी-भी नहीं है। सेम डे में कभी-भी नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गलत है। आप कल करवा लीजिये, आप राज्यपाल के अभिभाषण पर कल चर्चा करवा लीजिये। आप आज क्यों करवा रहे हैं ? कल करवा लीजिये। अगर आप आज ही अनुपूरक बजट और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हैं तो हम अनुपूरक बजट का बहिष्कार करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में हम सम्मिलित होंगे।

अध्यक्ष महोदय :- जी धन्यवाद।

समय :
2.12 बजे

**बहिष्कार**

**भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा अनुपूरक बजट में चर्चा कराये जाने के विरोध में**

(श्री बृजमोहन अग्रवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा अनुपूरक बजट में चर्चा कराये जाने के विरोध में सदन से बहिष्कार किया गया।)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- नेता प्रतिपक्ष कौन है ? चर्चा से भागे के परंपरा चालू हो गे हे। चर्चा से भाग रहे हो, आओ न चर्चा तो करो।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- चर्चा में नहीं शामिल (व्यवधान) । व्यवधान उत्पन्न कर रहे थे और आप बहुत राज्यपाल जी के अभिभाषण के प्रति अपनी संवेदना दिखा रहे हो।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये बोलिये।

**वित्तीय वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा**

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी के दिनांक 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाली वित्तीय वर्ष की अनुदान संख्या 3,6,8,11,19,21,30,41,46,64,65 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय की निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर 492 करोड़ 33 लाख 72 हजार 398 रूपये की अनुपूरक राशि दी जाने की मांग रखी गयी है जिसके समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- बोलिये, लेकिन संक्षिप्त में बोलिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है। जो पूरे देश में और दुनिया में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां चांवल से अधिक धान बिकता है। छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीणों की वजह से आर्थिक व्यवस्था काफी सुधरी है। जिन क्षेत्रों में 10 ट्रेक्टर बिकते थे, उसमें 25 ट्रेक्टर बिकते हैं। गांव की हालत और बहुत अच्छी और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरी है। कृषि भूमिहीन मजदूरों के लिये सरकार ने 6 हजार रूपये प्रति वर्ष देने का जो नियम तय किया है उससे भी काफी बेहतर स्थिति किसानों की हुई है और हमारे कृषि मजदूरों की भी स्थिति अच्छी हुई है। गोधन न्याय योजना से गौ पालकों को आर्थिक लाभ हुआ है, गूगल में सर्च करके देख लीजिये। देश और दुनिया में कहीं भी गोबर की खरीदी नहीं होती है, छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां गोबर की खरीदी होती है। जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद, गौठान के समूहों के समितियों को लाभ देने के लिये खरीदा जाता है और वह खाद सीधे किसानों को मिलता है। इस खाद के पीछे बहुत बड़ा मकसद है, हमारे भारत देश के सबसे पहला राज्य पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं। जहां सबसे पहले रासायनिक खादों का कीटनाशक दवाइयों के रूप में उपयोग किया गया और इतना ज्यादा उपयोग हुआ कि वहां इतनी ज्यादा बीमारी बढ़ने लगी कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी वहां के लोगों को होने लगी। वहां की सरकारों को टाटा मेमोरियल अस्पताल ले जाने के लिये स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती है। उसको देखते हुये छत्तीसगढ़ की सरकार ने बहुत गंभीरता से दूरगामी परिणाम देखते हुये यह वर्मी कंपोस्ट खाद की शुरूआत की है ताकि रासायनिक खाद से बचें। हमारे किसान स्वावलंबी हों, निरोग हों, स्वच्छ रहें। हमारे छत्तीसगढ़वासियों को आने वाले भविष्य में आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ होगा।इतना ही नहीं, आज हमारे बलरामपुर जिले के गौ-गौठानों में जो गोबर, गोबरा बसेरा है वहां पर सी.एफ.एल. बल्व बनने लगा है। वहां पर सी.एफ.एल. बल्व 100 रूपये का तीन देते हैं। हम अभी तक सुनते थे कि यह बड़े शहरों में बनता था, माननीय अध्यक्ष जी, आपके आर्शीवाद से वहां पर गौ-गौठानों की महिला समूहों ने सी.एफ.एल. बल्व बनाने लगे हैं और वह 3 महीने की गारण्टी देते हैं और 100 रूपये में तीन सी.एफ.एल. बल्व देते हैं। यह छत्तीसगढ़ सरकार और मुख्यमंत्री जी की गौधन न्याय योजना बहुत ही बड़ी देन है।

समय :
2.16 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुए)**

माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी मितान क्लब के माध्यम से 18 से 40 साल के उम्र के लोगों को इस क्लब से जोड़ने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। हर तीन महीने में उनको 25 हजार रूपये देने का भी काम करने जा रही है। इससे लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आयी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी तक छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक नौकरियां दीं गईं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय रेट फिक्स हुआ करता था। अगर किसी को चपरासी बनना है तो 2 लाख रूपये, सब इंस्पेक्टर बनना है तो 50 लाख रूपये, डिप्टी कलेक्टर बनना है तो 75 लाख रूपये, सभी नौकरियों का ऐसा रेट होता था। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, अभी तक चपरासी, चतुर्थ वर्ग से लेकर क्लास 2, डिप्टी कलेक्टर तक में लगभग 5 लाख लोगों की नौकरियां लगीं, लेकिन किसी पद की भर्ती में कहीं कोई बातें सामने नहीं आईं। किसी ने एक रूपये देने का सबूत नहीं बताया, जो गरीब से गरीब प्रतिभा है, वह अपने आप उन पदों को धारित कर रहे हैं। यह पहली बार ऐसा मौका आया है जो बिना, एक तरह से कोई रिश्वत के नौकरी मिल रही है। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य ही ऐसा है। हिन्दुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां नियमित पदों पर भर्ती करते हों, बल्कि पहले से जो नौकरियां थीं, वह खतरे में हैं। उनको निकाला जा रहा है। जो संविदा में कार्यरत हैं उनको हटाया जा रहा है। जो सरकार कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह के लाले पड़ रहे हैं, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ ही ऐसा राज्य है हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है। 5 लाख से अधिक वर्ग-4 से डिप्टी कलेक्टर, असिस्टेंट प्रोफेसर, सब इंस्पेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आर.आई, पटवारी, डी.एस.पी. टी.आई. एस.आई. प्रधान आरक्षक, आरक्षक, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्याख्याता, शिक्षकों की लगातार भर्ती कर रही है। यह हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का पूरे देश में एक नाम है और जिसकी दूसरे राज्य भी सराहना कर रहे हैं। पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नहीं किया, हमने इन 3 सालों में छत्तीसगढ़ में दुगुनी नौकरी देने का काम किया है, यह भूपेश बघेल जी की सरकार, नौकरी देने वाली सबसे अच्छी सरकार रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि जिनको सुनना और सुनाना था, वह सदन में बातें लेकर आते हैं। वह सदन में बात कहने के लिए आते हैं और फिर भाग जाते हैं इसलिए आपसे ज्यादा नहीं कहते हुए, एक ही बात कहूंगा कि वनोपज की खरीदी भी ज्यादा से ज्यादा प्रजातियों की हो रही है और ज्यादा से ज्यादा दरों पर हो रहा है। मैंने बचपन में देखा है कि हम लोगों ने भी पढ़ा है । हम लोग देखते थे कि बड़े घराने के बच्चे टाई, कोर्ट पैंट पहनकर जाते थे, वह अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने जाते थे और वह अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते थे और हम लोग देखकर, तरसते थे और आज भी पूरा छत्तीसगढ़ तरसता था। 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन कभी यह बात नहीं याद आयी। मैं भूपेश बघेल जी की सरकार और उनके मंत्रिमण्डल को धन्यवाद् देता हूँ कि गरीब से गरीब, ऑटो, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, दूसरे के खेत में काम करने वाला बच्चा भी आज अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में पढ़ रहा है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ और आपको धन्यवाद् देता हूँ।

सभापति महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, इनकी सरकार में डी.एम.एफ. की राशि का ऐसा बंदरबांट होता था, स्विमिंग पूल बनते थे..।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय सभापति महोदय, आपका भाषण खत्म हो गया, मेरा नंबर आ गया बता रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, नहीं। मेरा नंबर कट तो हो जाने दीजिए।

सभापति महोदय :- ठीक है। आप अपनी बात जल्दी पूरी कर लें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, 15 साल की सरकार डी.एम.एफ. की राशि से स्विमिंग पूल बनाती थी, बड़े-बड़े भवन बनाते थे और डी.एम.एफ. की राशि से छत्तीसगढ़ के जो दूरांचल जिले जो सरगुजा, बस्तर, बलरामपुर हैं आज भी वहां की हालत जाकर देख लीजिए, वहां मेडिकल कॉलेज से बेहतर सुविधा मिलने लगी है। वहां सारे विशेषज्ञ डॉक्टर हो गये हैं, वहां सारे ऑपरेशन होने लगे हैं, महिला रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, सर्जरी रोग विशेषज्ञ और वहां आपके सभी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होने लगे हैं जो रायपुर में ऑपरेशन में 50 हजार लगते हैं, हमारे बलरामपुर जिले में 500 रूपये नहीं लगता है। हमारी सरकार ने उनकी रहने की व्यवस्था भी की है। यह डी.एम.एफ का सदुपयोग कहा जाता है। इन्होंने 15 सालों में नहीं किया उसको बिना कोई बजट में प्रावधान किए यह सारी व्यवस्था सी.टी. स्कैन मशीनें, डायलिसिस की मशीनें, यह सारी मशीनें हमारे बलरामपुर, सुकमा जैसे जिले और अंतिम छोर में बसे जिलों के लिए किया जा रहा है। कुपोषण की कितनी बड़ी महामारी थी, मैंने देखा है, हर जिला अस्पताल के सामने उसके सुपोषण करने के लिए एक कैंप खोले गये हैं, जो गरीब बच्चों को लाकर परीक्षण करके बेहतर सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। यह सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इसी तरह से चलता रहा तो ये लगातार 25 सालों तक भागते रहेंगे और 25 सालों तक कांग्रेस सरकार चलाती रहेगी, यह सदन में बात लेकर आएंगे और सदन से भागने का काम करते रहेंगे। इनको भागने का मुबारक हो। धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रमोद कुमा शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय सभापति महोदय, मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक अनुमान बजट का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी माननीय बृहस्पत सिंह जी सरकार के बारे में धारा प्रवाह की तरह बोल रहे थे। वे रेट भी बता रहे थे कि सब इंस्पेक्टर के लिए कितना होता था, एस.पी. के लिए कितना होता था ? माननीय सभापति महोदय, अंतर यह है कि रेट थोड़ा सा बढ़ गया है। पहले 15 सालों में आज तक ऐसा नहीं हुआ...।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
2:22 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठसीन हुए)**

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरे प्रदेश की नियुक्ति में एकात नाम बता दीजिए कि फलाने ने फलाने को इतना पैसा दिया। एकात नाम बता दीजिए। सदन में आरोप लगाना मिथ्या आरोप लगाना गलत बात है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप बोलेंगे तो बता भी दूंगा। मैं माननीय बृहस्पत सिंह जी को बताना चाहूंगा कि 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी एस.पी. कलेक्टर को पैकेज में भेजने का काम नहीं किया है जो आज छत्तीसगढ़ सरकार में चल रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- कहीं नहीं हुआ है, आप एकात नाम बता दीजिए।

श्री देवेन्द्र यादव :- सम्मानीय सदस्य आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाईन कर ली है, लग रहा है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आज पैकेज में चल रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप नाम बता दीजिए कि कहां ऐसा हुआ है। एकात नाम बताईए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सदन में मंत्री जी का एक जवाब मांग रहा था जिसके लिए मैंने शायद तक अनुमति नहीं ली थी। जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल के बारे में चर्चा चल रही थी। मंत्री जी का कहना था कि जो बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहेंगे और जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहेंगे, वह पूरी छूट है। अध्यक्ष महोदय, अभी चार दिन पहले की बात है। अभी तिल्दा नेवरा में 200 बच्चियां हड़ताल, चक्काजाम की थी। उन लोगों का यह कहना है कि हम लोग इसी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं उनको जबर्दस्ती उस स्कूल से हटाया जा रहा है। यह झूठ का पुलिंदा है जो यहां पेश किया जाता है। अधिकारी क्या लिखकर देते हैं, क्या बोलते हैं नहीं मालूम लेकिन आप वास्तविक ग्राऊंड में जाकर देखिए कि क्या स्थिति है ? यह सिर्फ दिखावा, यह झूठ का दिखावा है। सिर्फ किसानों की सरकार, हमारी सरकार, छत्तीसगढ़िया सरकार, यह सब दिखावा की सरकार है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है।

श्री संतराम नेताम :- आप एक भी भ्रष्टाचार का मामला बता दीजिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- कौन से विभाग में भ्रष्टाचार नहीं है ?

श्री संतराम नेताम :- आप सदन में एक उदाहरण दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सदस्य, आरोप लगाने की बजाए तथ्यों पर बात कीजिए। वह भाषण देने की जगह नहीं थी। यह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। (व्यवधान) आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर कोई बात है तो तथ्यों पर बात कीजिए।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, उनको खत्म करने दीजिए। वे खत्म कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं अकेला हूं, मेरे को बोलने के लिए ज्यादा समय दीजिए। मैं इसलिए बैठा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, आप खत्म करिए। सब लोग चले गये हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- विपक्ष में कोई नहीं है, मैं ही अकेला बोलने वाला हूं तो कम से कम मुझे आधा घंटे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप यहां रूके हैं, इसका मतलब पक्ष में बोलेंगे। विपक्ष में बोलने वाला थोड़ी रूकेगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं विपक्ष में हूं, थोड़ा समय तो बोलने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- विपक्ष में बोलने वाले लोग तो बहिर्गमन कर दिए हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूं। अभी सरकार के द्वारा इतना भ्रष्टाचार, अत्याचार किया जा रहा है कि सरकार में बैठे कुछ चुनिंदा लोग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन इनके आजू बाजू वाले लोग होंगे वे जैसा चाह रहे हैं सरकार चला रहे हैं। अभी निको सीमेंट प्लांट बलौदाबाजार में जन सुनवाई का आयोजन हुआ था।

श्री बृहस्पत सिंह :- भाई, मुख्यमंत्री जी सरकार नहीं चलायेंगे तो क्या विपक्ष सरकार चलायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आप बैठिए न मेरे को बोलने दीजिए। इतना गुणगान किये हो तो मेरे को थोड़ा सा आलोचना करने दो।

अध्यक्ष महोदय :- बोलने दीजिए। चलिए, बोलिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ज्यादा तानाशाह है कि जनसुनवाई में 17 गांव के सरपंच, 14 जनपद सदस्य, 1 विधायक, जनपद का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वहां विरोध करने के लिए गए थे। वहां बोलने नहीं दिया गया, पता नहीं कहां से आदेश था ? किसी को कोई बोलना नहीं है, हम लोगों ने विरोध किया तो हम लोगों के ऊपर Non-bailable धारा लगाया गया। यह स्थिति है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो यह स्थिति है। हमारी सिर्फ यही मांग थी कि नये यूनिट का आप विस्तार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ यह मांग कर रहे थे कि आप लिखित में दें कि 90 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देंगे। सिर्फ यही मांग थी। क्या हम लोगों की मांग गलत थी ? सिर्फ लिखित में मांग कर रहे थे कि आप जो भी प्लांट लगा रहे हैं लगाईये लेकिन 90 प्रतिशत आरक्षण वहां के लोकल युवाओं को दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार के द्वारा हम लोगों को दमनकारी नीति के कारण दबाया गया। हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और नॉनविलेबल धारा लगायी गयी ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

कोई दिक्कत नहीं है, हम युवाओं के लिये लड़ते रहेंगे और इस सरकार के द्वारा चाहे हमें जेल में डाल दें या फांसी दे दें, हम इसका विरोध करते रहेंगे । मैं पुन: विरोध करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़ा सा और बोलने दीजिए । मन की भड़ास निकल जायेगी तो थोड़ा ठंडा हो जाउंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिए न । मैंने समझा कि आप पूर्णविराम लगा रहे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- भड़ास निकालने का यह मतलब नहीं है कि आप असत्य कथन करें । आप असत्य कथन मत करिये न ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं असत्य नहीं सत्य ही बोल रहा हूं । यहां बोलने से कुछ होगा नहीं, यहां बोलने से कुछ फर्क तो पड़ता ही नहीं है ।

श्री अरूण वोरा :- सदन बहुत पवित्र है और यहां सत्य बात बोलने के लिये हम लोग आते हैं । असत्य बात बोलने के लिये नहीं आते हैं । यहां हम अपनी भड़ास निकालने के लिये नहीं आते हैं ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैंने कहा कि बोलकर ही मन को संतुष्ट कर लें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि यह चर्चा करने की जगह है, भड़ास निकालने की जगह नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो भड़ास ही निकाल सकते हैं बाकी तो आपकी पूरी संख्या बहुत ज्यादा है । पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम चल रहा है, मैं और ज्यादा कड़ी भाषा में बोल रहा हूं । अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ट्रांसफर के लिये बता रहे थे तो ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन...|

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, दादी के विभाग की उपस्थिति उधर दिख रही है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं और विपक्ष का सदस्य होने के नाते मैं अनुशंसा करता हूं कि इस सरकार को एक रूपये भी न दिया जाये । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 3, 6, 8, 11, 19, 21, 30, 41, 46, 64, 65 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के लिये जो अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से भाई बृहस्पत जी और भाई प्रमोद जी के द्वारा बोला गया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी हमेशा की तरह पलायन का रास्ता ढूंढ़ती रहती है, आज भी वे चर्चा में भाग लेते । आसंदी से उन्हें पूरा अवसर मिला, सत्तापक्ष भी पूरा सहयोग कर रही है लेकिन ये कैसे यहां से पलायन करें उसका वह रास्ता ढूंढ़ते रहते हैं । पिछले सत्र में भी आपने देखा और आज इसकी शुरूआत हो गई है । आज ही शुरूआत हो गई और उसके बाद पता नहीं ये 13 बैठकों में बैठ भी पायेंगे या नहीं बैठ पायेंगे । अब उनके साथ दिक्कत भी है, माननीय बृजमोहन जी, माननीय अजय जी, श्री शिवरतन जी ये तीन ही हैं जो खेलते रहते हैं, सौरभ एक्स्ट्रा प्लेयर है । माननीय कौशिक जी की ये लोग सुनते नहीं हैं, कल भी आपने देखा कि कौशिक जी और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी दोनों बैठे हुए थे और बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहिर्गमन करा दिया । अब जायें, न जायें इस संकोच में थे। आज जब माननीय धरमलाल कौशिक जी ने बहिर्गमन की बात की तो अजय चंद्राकर जी को आपत्ति हो रही थी तो यह हालत है लेकिन दिक्कत यह है कि जब हंटर वाले का हंटर पड़ता है तो मजबूरी में सरकार के खिलाफ बोलना पड़ता है, वैसे इनके पास कुछ है नहीं । इनके पास कोई तथ्य ही नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है । महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने शुभकामनाएं दीं, मैं भी सभी मिहलाओं को बधाई देता हूं । इस सदन के माध्यम से सभी माताओं, बहनों, बेटियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं और बधाई । (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे संतोष है कि मेरी सरकार महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन के लिये लगातार काम कर रही है। बेटियों के जन्म से लेकर विवाह कार्यक्रम में सहयोग तक के हमारी सरकार ने नयी-नयी योजनाओं की शुरूआत की है । परिवार में दूसरी पुत्री के जन्म पर भी 5 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिये कौशल्या मात्रत्व सहायता योजना प्रारंभ की गयी । (मेजों की थपथपाहट) केंद्र सरकार ने तो इसको बंद कर दिया लेकिन हमने इसको शुरू किया । दूसरी पुत्री पर भी 5 हजार रूपये, पहली पुत्री में तो मिलता है लेकिन दूसरी पुत्री पर भी। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार से जो सीमित परिवार हैं, बेटियों के विवाह सहायता, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की गई। इसके तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राही के प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में 20-20 हजार रूपया जमा किये जायेंगे। यह पूरे देश में पहली योजना है, जिसकी शुरूआत हमने छत्तीसगढ़ में की है। (मेजों की थपथपाहट) अध्यक्ष महोदय, तीजा-पोरा के समय हमारी बहनें आयी थीं। उस समय उन्होंने कहा कि हमारे पुराने स्वसहायता समूहों के ऋण हैं, वह हम लोग नहीं पटा पा रहे हैं और उसके कारण से हम नया काम शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लोन नहीं मिल पा रहा है तो उस दिन हमने घोषणा की थी और इस प्रकार से हमारी सरकार ने महिला स्वसहायता समूहों के पुराने बकाया 12 करोड़ 77 लाख रूपये के ऋण माफ किये। (मेजों की थपथपाहट) हमने केवल किसानों के ऋण माफ नहीं किये। जलकर ही माफ नहीं किये, बल्कि महिलाओं के भी जो स्वसहायता

समूहों के जो ऋण हैं, उसे भी हमने माफ करने का काम किया और वहीं तक नहीं रूके, बल्कि अब वे जो लोन लेंगे तो पहले जो लोन लेते थे, उसे दोगुना कर दिया। (मेजों की थपथपाहट) हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी में पढ़ने के बाद हमारी जो बच्चियां हैं, वे कॉलेज दूर होने के कारण से नहीं पढ़ पाते थे। उनकी पढ़ाई छूट जाती थी। अध्यक्ष महोदय, हमने 25 जिला मुख्यालयों में पृथक से कन्या महाविद्यालय की स्थापना की है और इसमें प्राथमिकता दी। चाहे वह सुकमा हो, कोण्डागांव हो, बीजापुर हो, नारायणपुर हो जैसे दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य जिला मुख्यालय पर हमने कन्या महाविद्यालय की स्थापना की और इसका संचालन इस वर्ष से प्रारंभ हो गया। अध्यक्ष महोदय, खेती-किसानी को बढ़ावा देने के लिए किसान लगातार चाहे वह धान बेचने के लिए हो, चाहे खाद खरीदने के लिए हो, उसे दूर जाना पड़ता था। पिछले समय आपने देखा कि सरकार की अव्यवस्था के चलते अदूरदर्शिता के कारण किसान रात-रात भर जागते थे और अपनी धान की फसल ले जाकर खड़े रहते थे। 60 लाख मीट्रिक टन खरीदने में उनका पसीना छूट जाता था। इस साल हम लोगों ने लगभग 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा। (मेजों की थपथपाहट) और एक जगह भी किसान के धान बिकने में कहीं कोई शिकायत नहीं आयी। कोई किसान लाइन में नहीं लगा। न धान लाने में, न तौलाई में, न विक्रय करने में और न पेमेंट में। 3 दिन के भीतर में सारे किसानों का भुगतान किया गया और कारण यह कि हमने जो धान खरीदी केन्द्र है, उसकी संख्या में वृद्धि कर दी। वह बढ़कर 2300-2400 हो गया और साथ ही जो सहकारी समितियां हैं, वह केवल 1300 के आसपास थे, उसमें हमने 700 नई सहकारी समितियों का गठन किया है और इसके कारण से किसानों को भुगतान में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आयी। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो किया, उसका लाभ उसी प्रकार से हुआ। धर्मजीत जी आ गये हैं। वह रहते तो कुछ समर्थन में बात करते। कुछ सुझाव भी देते। कुछ आलोचनाएं भी होतीं। आज प्रमोद जी बिल्कुल एंग्री यंग मैन की तरह आये और एकदम पैकेज चल रहा है, ऐसा हो रहा है। बाबू ऐसा है कि एक ही एफ.आई.आर. में इतना तिलमिला गये हो। हम लोगों पर पता नहीं कितने एफ.आई.आर. हुए हैं।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- 12 मुकदमे मेरे खिलाफ चल रहे थे।

श्री भूपेश बघेल :- बस इतने में। बाबू, हम लोग बहुत झेले हैं। समझ गये न। इतना तिलमिलाना नहीं चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- सर, गलत है।

श्री भूपेश बघेल :- गलत। देखिए, ऐसा है कि जनसुनवाई हुई और वह किसी प्लांट के किसी खदान की अनुमति के लिए। उसमें सरकार का क्या है? सरकार तो जनसुनवाई कर रही है। अब सरकार क्यों नहीं सुनेगी? जनसुनवाई करना है, उसमें उद्योग लगना है, नहीं लगना है। खदान खुलना है, नहीं खुलना है, इसके लिए जनसुनवाई हो। है न। अब उसमें सरकार कहां से आ गई? अब आप जाकर तोड़-फोड़ करोगे, गलत करोगे तो शिकायत होगी तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. होगी, जांच होगी। कार्रवाई



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

होगी। यदि नहीं है तो नहीं होगी। लेकिन इतना तिलमिलाना नहीं चाहिए कि कलेक्टर, एस.पी. पैकैज । मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लेन-देन पिछली सरकार में होता था और कैसे होता था, यह सब जानते हैं । चौबे जी से लेकर सब, इस सरकार में इस प्रकार का काम नहीं होता । अधिकारी, ख़ासकर एस.पी., कलेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता कि कोई भ्रष्टाचार हुआ हो । यदि कोई प्रमाणित कर दे तो जो बोलिए। इसलिए इस प्रकार की बात बोलने के पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वहां जाके कुर्सी ला पटकत रिहिस हे, ते पाइके एफ.आई.आर. होए हे ।

श्री भूपेश बघेल :- अब आप एकदम से विरोध में आ गए । आसंदी से कहा भी गया, जो विरोध करने वाले थे वे बाहर चले गए, लेकिन आप किधर हैं ? अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत जी आ गए हैं । मुझे याद है पिछले सत्र में धर्मजीत भईया के साथ हमारे पक्ष के विधायकों ने भी कहा कि कनेक्शन की बहुत शिकायत है । हमने उस समय 35 हज़ार कनेक्शन्स की स्वीकृति प्रदान की और कोरोनाकाल के बाद भी हमारे विद्युत मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों ने 90 प्रतिशत कनेक्शन पूरे कर लिए और हमारी कोशिश होगी कि 31 मार्च तक वह भी पूरा हो गए और सभी किसानों को कनेक्शन मिल जाए । किसानों के प्रति हमारा यह कमिटमेंट है (मेजो की थपथपाहट)।

गोधन न्याय योजना के बारे में तो बता ही दिया । उसके बारे में बहुत ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, उसकी चर्चा तो प्रधानमंत्री जी भी करने लगे हैं । केन्द्रीय कमेटी भी आ गई है, अब जब कृषि विभाग की चर्चा होगी तो इस पर बात भी होगी। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा काम जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में किया है, पिछली सरकार ने जो हमें विरासत में दिया है, वह 40 प्रतिशत लोग ग़रीबी रेखा के नीचे हैं। यदि पूरे देश में आप देखेंगे तो ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग कम मिलेंगे । शायद ही कोई प्रदेश हमारे मुक़ाबले में आए, यह हमें विरासत में मिला है । हम लोगों के जीवन को ऊपर उठाना चाह रहे हैं । चूंकि 44 प्रतिशत जंगल है, उनके जीवन को उठाने के लिए लघु वनोपजों की ख़रीदी भी हमें करना है । हमारे आदिवासी हों या वहां परम्परागत रूप से निवास करने वाले हों, उसी से उनका जीवन चलता है । इसको ध्यान में रखते हुए हमने 2500 से बढ़ाकर सीधे 4000 रूपए प्रति मानक बोरा किया (मेजो की थपथपाहट) ताकि उन आदिवासियों की जेबों में पैसे जाएं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पूरे देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज केवल छत्तीसगढ़ से ख़रीदा जा रहा है (मेजो की थपथपाहट) । भारत सरकार से 11-11 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, केन्द्रीय मंत्री इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ख़ुद छत्तीसगढ़ आकर पुरस्कार दिया । इससे ज्यादा प्रसन्नता दूसरी नहीं हो सकती । केवल वहीं तक नहीं रूके, उन लघु वनोपजों का वेल्यू एडीशन करने का काम हमारी सरकार कर रही है, उस वेल्यू एडीशन में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है । आज महिला दिवस है इसलिए विशेष रूप से महिलाओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए । चाहे आप काजू प्रसंस्करण की बात कर लीजिए, चाहे इमली कैंडी बनाने का, चाहे तिखुर का शेक बनाने का, चाहे झाड़ू बनाने का काम

कर लीजिए, अभी मिलेट मिशन चल रहा है, उसमें सारी महिलाएं काम कर रही है और लगभग गौठान में और ये सारे मिशन मिलाकर 70 हजार से 1 लाख तक महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है, वे काम कर रही हैं और हम लगातार इस काम को बढ़ाते जा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात जो कह रहा था । एक तरफ हमारा प्रयास है कि जंगलों में रहने वालों की आय में कैसे वृद्धि हो । उसका सबसे बड़ा प्रमाण, जो आदिवासी ज़िले से आते हैं, मैं एक ही उदाहरण देता हूं और फिर से कहूंगा कि बीजापुर हमारा सबसे आख़िरी और सबसे ज़्यादा नक्सल प्रभावित में अब रह गया है, सुकमा भी, दंतेवाड़ा भी अब लगभग ख़ाली हो गया है । अबूझमाड़ को छोड़ दीजिए तो कोंडागांव का कुछ हिस्सा और कांकेर में भी अब बहुत कम रह गए है, नक्सलियों को पीछे धकेलने में हमें सफलता इसलिए भी मिली कि लोगों की जेब में पैसा आना शुरू हो गया, हमने उन्हें रोजगार देने का काम किया । हमारी जो नीति है, चाहे वह ऋण माफी हो, चाहे 2500 रूपए क्विंटल में धान खरीदी करने का हो, लघु वनोपजों की न केवल समर्थन मूल्य में खरीदी बल्कि वेल्यु एडीशन करने का काम, पहले 7 लघु वनोपज थे, उसे बढ़ाकर 61 किया गया, इससे वहां के लोगों की जेब में पैसा आया तो बीजापुर जैसे जिले में, इन तीन वर्षों में 5 हज़ार मोटर साइकिल बिकी और 500 ट्रैक्टर बिके (मेजो की थपथपाहट) । ये पैमाना है, अब यदि कांकेर, जगदलपुर, बस्तर का निकालेंगे तो आंकड़े बहुत हो जाएंगे । सबसे अंतिम छोर और नक्सल प्रभावित होने के बाद भी वहां लोगों के पास पैसा है, तभी तो वे ट्रैक्टर खरीदे हैं, तभी तो मोटर-सायकल खरीदे हैं। तो यह प्रमाण है। उसके बाद भी जिनके पास कोई जमीन नहीं है। यदि शासकीय योजना है तो उनके लिए भी है। चाहे राशन देने की बात हो, बिजली बिल हाफ देने की बात हो। उसके बाद उन गरीब लोगों के पास जो भूमिहीन श्रमिक हैं, उनको भी छः हजार रूपये प्रति वर्ष देने का फैसला किया है जो कि तीन लाख से अधिक परिवारों को मिला चुका है। (मेजों की थपथपाहट) नौजवानों के लिए अभी बेरोजगार सिविल इंजीनियर उसके लिए "ई" श्रेणी पंजीयन की व्यवस्था लागू किये हैं, उसमें 8 हजार स्थानीय निर्माणाधीन कार्यों में भागीदारी तय की है और उसमें विकासखण्ड स्तर पर 225 करोड़ के कार्य "ई" श्रेणी में पंजीकृत युवाओं को आवंटित किया गया है। यह संख्या और बढ़ेगा। इसके साथ-साथ प्रदेश में अधिकतम गांवों के आवागमन के बेहतर सुविधा देने के लिए हमने लगभग 24 हजार करोड़ रूपये की लागत से सड़क एवं पुल निर्माण के लिए योजना तैयार कर कार्य प्रारंभ किया है। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में अभी तक हमारी सरकार ने 18 करोड़ 41 लाख मानव दिवस रोजगार सृजित किए हैं। जिसमें 7 लाख 88 हजार परिवारों को 100 मानव दिवस के रोजगार दिया जाना बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, अब इनकी सरकार चली गयी। लेकिन इन्हीं के कार्यकाल में चिटफंड कंपनी खूब पनपा। माननीय भीमा मण्डावी जी हमारे उपाध्यक्ष जी के खिलाफ ही कैंडिडेट खड़ा हो गये थे, चिटफंड कंपनी वाले लोगों का इतना साहस कि वे राजनीति भी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करने लगे। वे खूब फले-फूले। लेकिन हमारी सरकार ने आकर सभी जिलों में उनके खिलाफ न केवल एफ.आई.आर. दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया और जो बाहर थे उनको भी लॉक इट किया। उसके बाद हमारा उद्देश्य केवल गिरफ्तारी करना ही नहीं है बल्कि उन हितग्राहियों को, उन निवेशकों को जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा चिटफंड कंपनी में निवेश किए हैं, वह उनके पास पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम लोगों ने 17 करोड़ रूपये चिटफंड कंपनियों से 16 करोड़ की संपत्तियां निलामी किए हैं। 15 प्रकरणों की निलामी की कार्यवाही अभी प्रक्रियाधीन है। मैं समझता हूं कि देश के किसी भी राज्य में चिटफंड कंपनी और भारत सरकार ने भी जो लोढ़ा कमेटी बनाई है वह आज तक किसी का भी पैसा वापस नहीं करा पाए हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो निवेशकों को पैसा दिलवाने की शुरूआत किये। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, वनाधिकार का मामला है जो 4 लाख 46 हजार के लगभग पहुंच चुका है। हाट बाजार क्लिनिक योजना बड़ी सफलता है। उसी तरह से मोबाइल मेडिकल यूनिट बड़ी सफलता है, शहरी स्लम योजना की सफलता, श्री धनवंतरी योजना की सफलता और उसके साथ-साथ तीन नये मेडिकल कॉलेज के साथ दो जिला अस्पताल, 85 उप-स्वास्थ्य केन्द्र और 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी बनाने की भी स्वीकृति हुई है। अध्यक्ष महोदय, इनकी देश-भक्ति तो हम जानते हैं। आजादी की लड़ाई में इनकी भूमिका क्या थी, वह सभी जानते हैं। अंग्रेजों की मुखबिरी कौन करता था, वह पूरा देश जानता है। कितने बार कौन माफी मांगा, इसको भी पूरा देश जानता है। लेकिन 50 साल पहले इंदिरा गाधी जी के समय जो अमर जवान ज्योति जलाया गया था, उसको भी इन्होंने बुझाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो अमर जवान ज्योति जलाने का फैसला किया है। (मेजों की थपथपाहट) जिसका शिलान्यास आपकी उपस्थिति में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने किया और उसके लिए भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महादेय, मैं आपसे निवेदन करना चाहत हूं कि अनुपूरक बजट में नवीन अंशदायी पेंशन योजना में शासन का अंशदान न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप आकस्मिक रूप से भुगतान की जाने वाली डिक्री धन का भुगतान भारत सरकार से प्राप्त राशियों से विमुक्त के लिए प्रावधान बढ़ाने के लिए कुल 492 करोड़ 43 लाख का प्रस्ताव सम्मिलित किया गया है। हमेशा यह कहते थे कि अनुपूरक बजट बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं। तो यह हमारी तीन साल की मितव्ययिता का असर जो आप कहते थे कि बहुत ज्यादा अनुपूरक का पैसा लेते हैं। यह पहला अनुपूरक बजट है जो केवल 492 करोड़ 43 लाख का है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से यह मांग चाहता हूं कि सदन तृततीय अनुपूरक की अनुदान मागों को सर्वसम्मति से पारित करने अनुरोध मैं सदन से करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। प्रश्न यह है कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 3, 6, 8, 11, 19, 21, 30, 41, 46, 64, 65 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार सौ बानबे करोड़, तैंसीस लाख, बहत्तर हजार, तीन सौ अनठानबे रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

**अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश बघेल जी।

<u>**छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022)**</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ कहना चाहेंगे?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पास किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पर विचार किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा। प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 2,3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।**

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

**खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह खुद भाषण देकर भग रहे थे। ये छिपकर इधर भाग कर आये हैं। (अजय चन्द्राकर जी से)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्य यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने

**पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।**

अध्यक्ष महोदय :- भूपेश जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पारित किया जाए।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2022 (क्रमांक 2 सन् 2022) पारित किया जाए।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक पारित हुआ।**

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- श्री संतराम नेताम, सदस्य माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करेंगे।

समय :

02:48

**माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा**

**"माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए छत्तीसगढ़ विधान सभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं।"**

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदया को और हमारे सदन की सभी बहनों को और प्रदेश के सभी हमारे माता-बहनों को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। शुभकामनाएं देता हूं। आपने मुझे अनुमति दी है और मैं शुरूआत करता हूं, आप हमारे प्रदेश में जो किसान के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उसके नेतृत्व में हमारे गांव के गरीब और किसानों के लिए बड़ी ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जिसका परिणाम आज प्रदेश में नहीं पूरे देश में इसकी चर्चा है और छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में आज हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के ये जो चल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं चूंकि वह किसान के दर्द को समझते हैं किसान के लिए वह बेहतर हमारे...।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा):- इसलिए मैं कहता हूं कि प्रतिपक्ष का नेता जो है...।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- संतराम जी, माननीय बंधु हा किसान के दर्द, सबके दर्द ला समझ जथे, तोर भर नहीं समझे।

श्री संतराम नेताम :- वह पूरा समझ रहे हैं। मैं खुश हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी किसानों के दर्द को समझकर हमारे विधानसभा में इस साल सबसे ज्यादा उन्होंने नवीन उपार्जन धान खरीदी केंद्र खोले हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे केशकाल विधान सभा क्षेत्र में, कोण्डागांव जिले में धान खरीदी में कोई भी अव्यवस्था नहीं हुई, न धान बेचने के लिए किसी किसान



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

को लाईन लगाना पड़ा, न किसी किसान वहां पर रात में जाकर सोना पड़ा । इसका मतलब मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश में यह स्थिति रही है कि कोई भी किसान परेशान नहीं हुए हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, आप कोण्डागांव जिले की बात कर रहे हो । वहां रकबा काटने के कारण एक किसान ने आत्महत्या की थी, ऐसा लगता है कि आप उसको भूल गए ।

श्री संतराम नेताम :- वह खबर झूठी थी, आप लोगों ने अफवाह फैलाया था ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके कार्यकाल में 15 हजार किसानों ने आत्महत्या की थी, उसको भूल गए हो ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर वह खबर झूठी थी तो एक बार जांच करा लो ।

श्री संतराम नेताम :- उस घटना को आप लोगों ने मनगढंगत बनाया था । वह क्षेत्र मेरे गांव के करीब है, वास्तव में उसका लड़का खतम हुआ था, वह मानसिक रूप से परेशान था । मैं जिम्मेदारी से बात करता हूं । वहां केवल और केवल राजनीतिकरण हुआ है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कोई भी कार्यक्रम से लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त ही हो रहे हैं ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया की सोच है । आप लोगों ने पिछले 15 साल में किसानों को प्रताड़ित किया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, उस श्रेणी में आपके मंत्री भी शामिल हैं, उस श्रेणी में जयसिंह अग्रवाल जी भी शामिल हैं ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को लूटने का काम किया, किसानों को बरबाद करने का काम किया । समय पर फसल का पैसा नहीं दिया, जिसके कारण हमारे प्रदेश के किसान आत्महत्या करते थे । हम लोगों ने भी प्रश्न लगाया, जवाब दिया गया कि हमारे किसान अधिक कर्ज से लदने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं । माननीय भूपेश बघेल जी यहीं पर बैठते थे (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) । मैं हमेशा बैठकर सुना करता था । उन्होंने किसानों के दर्द के बारे में हमेशा आवाज उठायी । वे कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम जरूर मदद करेंगे । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब हमारी सरकार बनी तो हमने किसानों का धान 25 सौ रूपये में खरीदा । हम लोगों ने घोषणा की थी कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ करेंगे । मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के दर्द को समझने वाली हमारी सरकार है । अध्यक्ष महोदय, हम भी किसान हैं, हमारे पिताजी भी किसान हैं । तपती धूप में, कड़ाके की ठंड में और बरसते पानी में किसान कैसे फसल उपजाते हैं, कैसे तकलीफ और पीड़ा से उबरते हैं । उसके लिए हमारी सरकार किसानों को 25 सौ रूपये धान का मूल्य दे रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 25 सौ रूपये प्रति क्विंटल दे रहे हैं। आज पूरे गांव में पता कर लीजिए, वे किसान खुश हैं । मेरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

गांव में ही कई किसान कर्जमाफ करने से आर्थिक रूप से मजबूत हो गए, कई किसान बोर खनन कराये हैं । हमारे कई किसानों ने अपने बेटियों की शादी कर रहे हैं । कई किसान शर्म के कारण बैंक नहीं जा रहे थे क्योंकि उनका कर्ज पटा नहीं है, हम कैसे वहां पर जाएंगे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों के दर्द को समझकर उनको राहत दी है ।

समय :
2:53 बजे **(सभापति महोदय(श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने 2013 में घोषणा की थी कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों का एक-एक दाना धान खरीदेंगे, उस समय मैं भी सदन में था । आपकी घोषणा-पत्र में था कि हम 21 सौ रूपये धान की कीमत देंगे, 300 रूपये बोनस देंगे । आपने तीन साल बोनस दिया, बाकी दो साल आपने बोनस नहीं दिया । हम लोग पूछते थे तो आप लोग बोलते थे कि हमने तो किसानों से वायदा नहीं किया था, हमने तो तीन साल बोनस दिया है । इस प्रकार से धोखा देने वाले आप लोग थे, भाजपा की सरकार थी । हमारी सरकार ने जो वादा किया, उसको पूरा किया ।

सभापति महोदय, मैं गोधन न्याय योजना के बारे में कहना चाहता हूं, जिस योजना को हमारे प्रदेश की सरकार चला रही है । इस योजना की चर्चा पूरा देश कर रहा है । उत्तरप्रदेश की एक सभा में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना चल रही है, वह पूरे उत्तरप्रदेश में भी लागू होगा । इस प्रकार से गोधन योजना की चर्चा पूरे देश में चल रही है । इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रदेश में एक अच्छी सोच को लेकर, किसानों को लेकर, गरीबों को लेकर और हमारे गांव के अंतिम व्यक्ति को लेकर सरकार अच्छा काम कर रही है, सारे लोग खुश हैं, पूरे देश में इसकी चर्चा है और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का नाम एक सर्वे में आया है । कहीं न कहीं गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के लिए काम करने वाला हमारी सरकार पहली सरकार है । जिस प्रकार से आपने 15 सालों में छत्तीसगढ़ के लोगों को लूटने का काम किया, तेंदूपत्ता तोड़ने वालों के लिए बोनस के नाम पर लूटने का काम आप लोगों ने किया है, हमारी सरकार ने सीधा-सीधा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4,000 रूपया कर दिया। सभापति महोदय, इसका मतलब किसानों को आगे बढ़ाना होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- तेन्दूपत्ता कितने दिन खरीदा गया, आप यह भी जरा बता देना ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय सभापति महोदय, हर विधानसभा में तेन्दूपत्ता तोड़ने वाले को पहले से डबल रूपये का भुगतान हुआ है। मेरे स्वयं के विधानसभा क्षेत्र के खल्लारी का आकड़ा बता सकता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमारे गांव के लोग तेन्दूपत्ता तोड़ने जाते हैं। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि तेन्दूपत्ता तोड़ने वाले भाई-बहन जानते हैं कि जब जंगल में तेन्दूपत्ता तोड़ने जाते हैं तो उनको कैसे तकलीफ होती है। कांटा-खूंटी गड़ता है और खून-पसीना बहाते हैं और उसके बदले में कितना रूपया मिलता है ? 2500 रूपया मिलता है। मैं पिछली सरकार, आपकी सरकार को कहना चाहता हूं कि मैं इसी सदन में था जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह धनोरा गये थे और वहां जूता और चप्पल बांटकर आये थे। तो मैं धनोरा के एक दीदी से पूछा कि तेन्दूपत्ता के बदले में आपको सरकार ने क्या दिया तो वह बताई कि हमको चप्पल बांटा गया है। मैंने पूछा कि दीदी आपको कैसे चप्पल मिला तो वह यह भी बताई कि मैं का बताव भैय्या, एक ठन 6 नंबर के हे अउ एक ठन 9 नंबर के हे, इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया गया था। वे यही सोचते थे कि यदि वह चप्पल खरीदेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, लेकिन अब हमारी सरकार राशि उनके खाते में डाल रही है। यह सरकार की सोच है, यह सरकार की नीयत है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनना सरल है, लेकिन जनता की सेवा करना, जनता को ऊपर उठाने का काम करना, जनता को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करना, यह हमारी सरकार की सोच है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी इसी साल, वर्ष 2021-22 में हमारी सरकार ने 97.98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है। इससे यह साबित होता है कि सरकार की सोच क्या है? इतनी अधिक बम्फर धान खरीदी के बाद भी कोई अव्यवस्था नहीं हुई है। प्रदेश में इन लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है कि हम किस प्रकार का मुद्दा बनाये। अभी इनकी प्रभारी आईं थी (xx)[6] सभापति महोदय, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल धर्मान्तरण की बात को लेकर...।

आदरणीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो कर्ज माफी हुआ है, उससे हमारे किसान काफी मजबूत हुए हैं और आपकी भी सोच ऐसी होनी चाहिए थी। आप किसानों के लिए काम करते। किसान यहां के मुखिया हैं। हमारा प्रदेश किसान का प्रदेश है। आपको यहां के लोगों को समझना है, आप अच्छे से काम करिये। आप विपक्ष में आये हैं तो आपको यहां रहकर सदन में बात करनी चाहिए। यदि आप हर चीज में बहिर्गमन करेंगे, भागेंगे तो ये मीडिया देख रही है, मीडिया के माध्यम से प्रदेश के लगभग 3 करोड़ जनता देख रही है। यहां की 3 करोड़ जनता सोच रही है कि आपको यहां क्या करने के लिए भेजे हैं और आप क्या कर रहे हैं। आपको यहां बैठकर चर्चा करना चाहिए। आप लोगों ने पिछले बजट सत्र में भी कम समय में यहां से नौ-दो-ग्यारह हो गये थे। आपको इसका परिणाम नगर पालिका में मिला। पूरे प्रदेश में आपका सुपड़ा साफ हो गया। अब यह स्थिति आ गई है कि आप 14 से 4 सीट पर आ सकते हैं। आप यहां पर काम करिये। आप यहां जनता की आवाज उठाईये। हम लोग पिछली बार

---

[6] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रदेश की जनता के लिए आवाज उठाये थे, हम 39 सदस्य होकर भी यहां पर पूरे समय रहते थे। सभापति जी, पिछले समय आप भी थे, किसानों के लिए लड़ाई, बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़े थे। यह सरकार बेराजगारों की सरकार नहीं थी। मैं पिछले बार की बात कहना चाहता हूं। पिछली बार हमारे बस्तर के बहुत से बेरोजगार लोग तामिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक क्यों गये ? वे इसलिए गये क्योंकि उनको वहां रोजगार मिल जायेगा। आप लोगों में एक व्यक्ति को भी नौकरी देने की ताकत नहीं थी। आज आप पूरे प्रदेश में पता कर लीजिये- स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है, शिक्षा विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है, पुलिस विभाग में भर्ती के लिए विज्ञापन निकला है। पूर विभागों में बम्फर भर्तियां हो रही है। यहां के बेरोजगार, पढ़ने-लिखने वाले यह सोच रहे हैं कि हम किस विभाग की वेकेन्सी में आवेदन भरें, यह हमारी सरकार की सोच है। आपकी सरकार, जिसने हमारे बस्तर के लोगों को रोजगार नहीं दिया। आज कई बेरोजगार तामिलनाडु में फंसे हुए हैं। आज भी मेरे गृह ग्राम के बांसकोट्टा, सकराम-मरकाम आज भी तामिलनाडु के जेल में बंद हैं। तो आपको रोजगार देना चाहिए था, आपको लोगों के हाथों में काम देना चाहिए था। आपको तो हमारे प्रदेश की जनता ने 15 साल मौका दिया था, आप क्यों काम नहीं किए ? अभी नौकरी नहीं दे रहे हैं, कहकर आंकड़ें पर बात करते हैं। हमारी सरकार लगातार बेरोजगारों के लिए काम कर रही है। हमारे यहां के भाई-बहन आदिवासियों के लिये काम कर रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बड़ी सोच से बम्पर भर्ती कर रहे हैं । पुलिस में एक जिले में 300 भर्ती हो रही है । अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर संभाग की बात करूं तो बस्तर फाईटर के नाम से वहां पर 2100 भर्ती हो रही है । यह हमारे लिये बहुत बड़ी उपलब्धि है । अध्यक्ष महोदय, मैं संस्कृति की बात करूं, जब से हमारे मुख्यमंत्री जी आये हैं, छत्तीसगढ़ की भावना को समझा है । छत्तीसगढ़ के लोग यह समझ लिये थे कि हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परम्परा, दिनों दिन विलुप्त हो जायेगी, समाप्त होते जा रहा था, खो जाने का मन में भावना था । माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से उन्होंने जो परम्परा, रीति-रिवाज जो यहां हरियाली से शुरूआत होती है, इसकी शुरूआत हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है । गेड़ी जिसके बारे में कई बार मजाक किया गया, हमारी परम्पराओं का एक प्रकार से तौहीन किया गया, इस प्रकार से कहा गया कि गेड़ी में नाच रहे हैं, कितना नाचेंगे, रहटुली चला रहे हैं, तमाम आरोप जो विपक्ष के साथी ने लगाये, जगदलपुर में जब इनकी बैठक हुई, शिवरतन भईया और अजय चन्द्राकर जी भी ठुमका लगा रहे थे, हमारे चंदेल साहब भी ठुमका लगा रहे थे । बढ़िया मधुर गीत में नाच रहे थे, आखिर आपको यहां की जनता ने नचाया, यहां की संस्कृति...।

श्री कवासी लखमा :- ए.सी. में नाच रहे थे । धूप में नाचना है क्या ।

श्री अमरजीत भगत :- सबसे अच्छा नंदकुमार साय जी ढ़ोल बजा रहे थे, वह दिख रहा था ।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, बैठिये ।

श्री संतराम नेताम :- अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति मजाक हो रही थी । हमारी संस्कृति की धज्जी उड़ाई जा रही थी । जनता ने एक दिन ऐसा सबक सिखाया कि जगदलपुर में जाकर सारे बड़े-बड़े नेता, यहां तक कि रमन सिंह जी भी ताली मारकर डांस कर रहे थे । हमारी परम्परा है, हमारी रीति-रिवाज है, हम सब कर सकते हैं, आप उसको करिये, आप हर क्षेत्र में आगे रहेंगे । सभापति महोदय, बस्तर की संस्कृति विलुप्त होते जा रही थी, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आदिवासी राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया । मैं भी इस उसमें इस साल लद्दाख गया था । आदरणीय सभापति महोदय, हमारी संस्कृति को देश और दुनिया के लोग देख रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार आदिवासियों की संस्कृति, बस्तर की हमारी संस्कृति को बरकरार रखा है । यहां पर पिछली बार वर्ष 2012 में जब विधायक बनकर आया, वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा था, वहां पर बड़े-बड़े दूसरे प्रदेशों के कलाकारों को लाये थे, मुझे पता है, मुझे याद है, मैं भी गया था, सलमान खान को लाये थे, टाटा कर दिये, हमारी करीना कपूर आई, कमर को मटका दी उसके लिए 50 लाख रूपये, हमारे राज्य के पैसे को दूसरे राज्य के कलाकारों को दिया जा रहा था । आज हमारे प्रदेश के आदिवासियों को पिछड़े वर्ग के यहां के कलाकारों को, लोक कलाकारों को, पैसा दिया जा रहा है । कहीं न कहीं हमारी प्रतिभा जग रही है । हमारे प्रदेश के छोटे-छोटे कलाकारों को महत्व मिल रहा है । एक नया मंच मिल रहा है । जिस प्रकार से नगरी में एक लड़की है, जिनका नाम आरू साहू है, कितनी अच्छी कलाकार है, इन कलाकारों को वहां पर मंच मिलता है और उसकी प्रतिभा दिनों दिन निखरती जा रही है । सभापति महोदय, यह हमारी सरकार की सोच है । आप पैसा खर्च कर दीजिए, प्रदेश को लुटा दीजिए, प्रदेश का पैसा यहीं रहना चाहिये । सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारी सुआ नृत्य रहुटुली वाला चलता है, कई बार मजाक उड़ाते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी पुन्नी नहाने जाते हैं, मुख्यमंत्री जी हमारी संस्कृति को जीवित करने का काम कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी इस साल पुन्नी क्यों नहीं नहाये । दो साल नहाये, फोटो खिंचवाये, इस साल क्यों नहीं नहाये, इस बात को बताओ जब उदाहरण दे रहे हो तो । इस साल क्यों नहीं नहाये संतराम जी, इसको बताओ ।

एक माननीय सदस्य :- पुन्नी नहाय बर एक झन ढ़ेबर काबर जाथे, अऊ कोनो नई जाय तेला बता गा ।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ । मैं उत्साहित नहीं कर रहा हूं । मेरा यह कहना है कि आप जो काम करिये, संस्कृति को भी बचाकर रखिये । जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी ने संस्कृति और परम्परा को लाया है, पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़िया सरकार है । ये छत्तीसगढ़ के लोग हैं । हमारे माननीय



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भूपेश बघेल जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो छत्तीसगढ़िया की भाषा में बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में नृत्य करते हैं। हमारे आदिवासी त्यौहार में एक दिन की छुट्टी देते हैं।

श्री अरूण वोरा :- चन्द्राकर जी, 1971 से अमर जवान ज्योति दिल्ली में चालू थी, उसे बंद क्यों कर दिया गया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसा है कि आप पूरी जानकारी रख लीजिए।

श्री अरूण वोरा :- मैं तो पूरी जानकारी से ही बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह दिल्ली का विषय है। के.टी.एस. तुलसी जी, राज्यसभा सदस्य कोष्टक में छत्तीसगढिया लिख देना। आप बहुत छत्तीसगढ़िया की बात कर रहे हैं, के.टी.एस. तुलसी जी को बताईये कि वह संसद में छत्तीसगढिया की बात उठायें।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमर जवान ज्योति की मशाल 1971 में जलाई गई, उसका कांसेप्ट क्या था, यह बता दो।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति जी, मजाक करना अलग चीज है। अगर कोई हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री जी को पसंद कर रहे हैं कि यह हमारी अच्छी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, पूरा देश जानता है कि "छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया" की पहचान को पूरे देश में कायम कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने आदिवासियों के साथ जो किया, 15 साल में आदिवासियों को, उनकी जमीन को लूटने का काम किया, इसलिए आप 15 सीट में सिमट गये। सभापति महोदय, आप भी बस्तर के रहने वाले हैं। आप और हम खुद देखे हैं कि इनकी सरकार ने लोहण्डीगुड़ा के कई किसानों की जमीन को अधिग्रहण किया था। जब अधिग्रहण होता है तो नियम है कि अगर उस जमीन में 10 साल तक उद्योग नहीं लगायेंगे तो वह जमीन उनको वापिस की जायेगी।

सभापति महोदय :- चलिये, जल्दी समाप्त करिये।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत जल्दी समाप्त करूंगा। वहां के किसान यह सोचकर अपनी जमीन दिये थे कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। उद्योग लगेगा तो हमारे बच्चों की जेब में पैसा आयेगा। वहां के किसान 10 साल तक अपनी आंख को टकटकी लगाकर देखते रहे, पर उनको उनकी जमीन वापिस नहीं मिली। अंत में हम लोग भी इसी सदन में मांग किये कि जब वहां उद्योग नहीं लगा रहे हो तो किसानों की जमीन वापिस करो। पर यह सरकार ने कभी हमारी बात को नहीं सुनी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आदिवासी के दर्द और पीड़ा को समझने वाला, आदिवासियों के बारे में सोचने वाला, आज ऐसा कौन मुख्यमंत्री है जो बस्तर में जाकर एक हफ्ते तक ऐसे जिले बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा जहां नक्सलगढ़ है, ऐसे जगहों पर जाकर रात्रि विश्राम करने का मतलब आदिवासियों को जानने का प्रयास, आदिवासियों के दर्द को



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पहचानने का प्रयास होता है कि वह कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, हम उनको कैसे आर्थिक रूप से मजबूत करें, उनकी परंपरा और रीति-रिवाज को हम कैसे शामिल करें और प्रदेश में उसको कैसे एक नई पहचान दें। यह हमारी सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। लोग अब जान गये हैं कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई अच्छा काम करता है तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। वह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह इसके पहले भी किसान रहे हैं, किसानों के दर्द को समझते हैं। माननीय सभापति महोदय आप भी जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में तारलागुड़ा से भोपालपट्टनम तक उन्होंने लगातार दौरा किया था। उन्होंने अध्यक्ष के कार्यकाल में भी दौरा किया था, उनको वहां के आदिवासी क्षेत्रों के दर्द के बारे में मालूम है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, दो-तीन घंटा जितनी देर तक बोलें, उनको बोलने दीजिए। हम लोग पूरा सुनेंगे।

श्री संतराम नेताम :- धन्यवाद। माननीय चन्द्राकर जी, आप ही से सीखते हैं। मैं निश्चित तौर पर चन्द्राकर जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं यहां उनको बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है, वह अच्छा पढ़ते भी हैं और विद्वान भी हैं। पर मैं एक चीज माननीय चन्द्राकर जी को कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि अगर किसानों का कर्ज माफ होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन वह आज तक इस्तीफा नहीं दिये। मैं पूछना चाहता हूं वह क्यों इस्तीफा नहीं दिये ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा नाम ले रहे हैं इसलिए मैं बोल देता हूं। माननीय सहकारिता मंत्री जी किसानों का कौन सा कर्ज माफ हुआ है, अल्पकालिक ऋण, आपके घोषणा पत्र में यह लिखा है कि अल्पकालिक ऋण माफ होंगे, किसानों के ऋण माफ होंगे, यह नहीं लिखा है।

सहकारिता मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- चन्द्राकर जी, यह हुआ है या नहीं हुआ है ? अल्पकालिक कर्ज माफ हुआ है या नहीं हुआ है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जिस दिन आप पूरा कर्ज माफ कर दिये होते, मैं इस्तीफा दे दिया होता।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- हॉं, कर्ज माफ हो तो गया है। कर्ज माफी हुई, आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया ?

श्री अजय चन्द्राकर :- संतराम जी, आप पूरा कर्ज माफ हो गया हो तो बताओ।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह घोषणा पत्र में लिखा है कि 10 दिनों के अंदर पूरा कर्ज माफ होगा। सभापति जी, हमारे माननीय संतराम जी, असत्य कथन कर रहे हैं।

सभापति महोदय :- शर्मा जी बैठिये। आप बोलिये।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति जी, हमारे शर्मा जी बहुत विद्वान हैं, हम दोनों अलग से कमरे में बैठकर बात कर लेंगे। सभापति महोदय, मैं छोटी सी अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- तुमको कुछ नहीं बनायेंगे, चाहे लाख बोल लो। समर्थन व्यक्त करना है, एक शब्द और है।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, वह तो मैं वैसे भी संतुष्ट हूं। आपने देखा है कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष हुआ करते थे। आज हमारे मुख्यमंत्री जी को देखिये, मैं तो दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदिवासियों को बस्तर के पूरे विकास की गाथा को आपके ऊपर दिया है। आदिवासियों को सौंपा है, मुझे उपाध्यक्ष बनाया है और आप देखिये कि यहां सरगुजा में भी हमारे खेलसाय सिंह जी को अध्यक्ष बनाया है और मध्य प्राधिकरण में भी आदिवासियों को बनाये हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने पूरे पावर को सिर्फ अपने पास रख लिया था। हम बस्तर के विधायक हैं, हमको बस्तर के लोगों ने चुना है। बस्तर में क्या चाहिये, पुलिया चाहिये, सड़क चाहिये, रंगमंच चाहिये, वहां के जितने भी विकास कार्य हैं वह हम लोग तय करेंगे। आज मुखिया ने पकड़ के रखा था, पिछली बार हम लोग भी थे, हमारे साथ जिस प्रकार का भेद-भाव किया गया, जिस प्रकार से बस्तर के विकास में बाधक बनने का कार्य किया गया, यह इनकी सरकार की सोच है। मैं आपको कहना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी जो बस्तर में गये थे तो वहां पर वहां के लोगों ने और हम लोगों ने मांग रखी कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था गुड़ी है। हम गुड़ी बनायेंगे हमारी शीतला माता, हमारे जिम्मेदार लोग वहां रहते हैं, उसके लिये आपको राशि देनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री जी ने पूरे पंचायत में 5 लाख के गुड़ी के लिये घोषणा की है और हमारी जो आदिवासी संस्कृति की परंपरा है, जहां हम घोटुल में रहकर वहां लया-लोर लोग मिलकर, रात में रहकर वहां पर हमारी संस्कृति की जो व्यवस्था है, जो हमारी वहां की संस्कृति की एकरूपता है, उसको बनाये रखने के लिये, जो यह जर्जर स्थिति थी, उसके लिये भी उन्होंने 10 लाख रूपये देने की घोषणा की है। इस प्रकार से आदिवासियों के लिये काम करने वाले मुख्यमंत्री, हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों के लिये सोचने वाले, सरगुजा के पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई-बहनों के लिये सोचने वाले हमारे मुखिया को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी जब बस्तर गये थे तब हम लोग उनसे 10 लाख रूपये मांगते थे परंतु एक रूपया हमें नहीं मिलता था। बस 10 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, केवल 2 पेज और है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- संतराम जी अगर आपके मुख्यमंत्री इतना कल्याण करते तो भगवान भी प्रकट होकर आशीर्वाद दे देते।

सभापति महोदय :- चलिये, हो गया खत्म करिये। बोलने वाले बहुत लोग हैं, प्लीज।

श्री संतराम नेताम :- हमारे मुख्यमंत्री जी, बस्तर के लोगों के लिये चाहे वह साहू समाज, कलार समाज, आदिवासी समाज, उन सब के लिये कम से कम 20-20 लाख रूपया...। सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे ? बस 10 मिनट में खत्म कर दूंगा।

सभापति महोदय :- नहीं, प्लीज। हो गया खत्म करिये।

श्री संतराम नेताम :- अभी तो बहुत बाकी है।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, सत्तारूढ़ दल के प्रथम वक्ता है, जो बोलना चाहते हैं, बोलने दीजिये।

सभापति महोदय :- नहीं, समय बहुत ज्यादा हो गया है।

माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्तावच में 17 माननीय सदस्य के संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है। संशोधन बहुत ही विस्तृत हैं, मैं पूरे संशोधन को नहीं पढ़ूंगा। केवल संशोधन प्रस्तुतकर्ता के नाम तथा संशोधन की संख्या ही पढ़ूंगा। जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे उनके ही संशोधन प्रस्तुत हुए माने जायेंगे :-

| **क्र.** | **सदस्य का नाम** | **संशोधनों की संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य | 99 |
| 2 | श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य | 66 |
| 3 | श्री अजय चंद्राकर, सदस्य | 76 |
| 4 | श्री नारायण चंदेल, सदस्य | 43 |
| 5 | श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य | 126 |
| 6 | डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य | 34 |
| 7 | श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य | 122 |
| 8 | श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य | 37 |
| 9 | श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य | 48 |
| 10 | श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य | 02 |

अत: अब माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर श्री संतराम नेताम, सदस्य, द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर एवं उस पर प्रस्तुत संशोधनों पर चर्चा होगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। आज सदन नियम परम्पराओं में तो चल नहीं रहा है, दूसरे तरीके से चल रहा है। नियमों में यह बात भी है कि मैं जो संशोधन दिया हूं, उनके अनुसार चर्चा हो सकती है तो एक बार इसका भी ट्रायल कर लेना की मैंने जितने संशोधन दिये हैं, उसके हिसाब से चर्चा करने की अनुमति दे दीजिए। संशोधनवार चर्चा करने की व्यवस्था नियमों में है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय चन्द्राकर जी सदन पूरी नियम और परम्पराओं से चल रहा है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यह नियमों में है। आप आप मुझे मेरे संशोधनों में संशोधनवाईस चर्चा करने के लिए अनुमति दे दीजिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

सभापति महोदय :- आपको यह जरूर दूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संतराम जी इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनका भाषण पूरा हो जाने दीजिए।

सभापति महोदय :- उनका भाषण पूरा हो गया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय संतराम जी का भाषण पूरा हो जाने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय संतराम जी आप बोलिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभी उनका भाषण बचा है।

सभापति महोदय :- उनका भाषण पूरा हो गया।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- नहीं, आप बोलिए।

सभापति महोदय :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, अभी चन्द्राकर कह रहे थे कि यह सदन नियम और परम्पराओं से नहीं चल रहा है। आप तो खुद नियमों के अच्छे जानकार हैं। कॉल एण्ड शकधर के अनुसार..।

सभापति महोदय :- माननीय वोरा जी, आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मेरे संशोधनवाईस चर्चा के लिए अनुमति दिलवा दीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ। माननीय अकबर भईया, नियमों में यह प्रावधान है कि हम संशोधनवाईस या कटौती प्रस्ताववाईस भी चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे एक बार संशोधनवाईस चर्चा की अनुमति दे दें। आज तो कुछ भी चल रहा है। आप ही थोड़ा आग्रह कर दीजिए।

सभापति महोदय :- ठीक है।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप क्यों बार-बार छेड़ते हैं भाई।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, कुछ भी नहीं चल रहा है, यह सदन चल रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो समझ में नहीं आया, उसमें खड़े नहीं होना चाहिए।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप पीछे वाले की बात मत सुनना।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, हम आज दो घण्टे बोलेंगे।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, आप समझ की बात करते हैं। यह बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। यह अनुभव के हैं।

सभापति महोदय :- माननीय वोरा जी, आप बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, इसीलिए आपको उत्तेजना आती है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, आप उत्तेजित क्यों हो जाते हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, आपको उत्तेजना होती है या नहीं होती है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय,उनके बाल सफेद हो गये हैं।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, देखिए, बाल सफेद होने के बाद उत्तेजना खत्म नहीं होती।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, अब आपको उत्तेजना नहीं आती ?

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, आप क्या बात कर रहे हो ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय सभापति महोदय, कौन कहता है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- चलिए, आपको तो उत्तेजना आती है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, यह कौन कहता है ? कि बूढ़े ईश्क नहीं किया करते, ईश्क करने की उम्र यही है और इसमें कोई शक नहीं किया करते।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी आपत्ति है कि आप मुझे बुजुर्ग कैसे बना रहे हैं ? मैं तो अभी जवान हूँ।

सभापति महोदय :- आप बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय भगत जी, ईश्क की कोई उम्र नहीं होती।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, हां, यह सही है।

श्री अमरजीत भगत :- हां, यह सही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, यदि यह सही है तो आप अभी ईश्क फरमा रहे हो ?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय चन्द्राकर जी, आप मेरी बात सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, एक तहसीलदार को डांटते हुए, इन्होंने ऐसे शब्द का उपयोग किया। अब उसको पूछना है और जानना है। अभी वह चर्चा में आएगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- अरे, सुन तो यार। ते अकेला बोलथस। हम मन ला बोलन नई देथस, ये कोई अच्छा आदत हे का?

श्री बृजमोहन अग्रवाल(रायपुर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, तें बोल।

श्री अमरजीत भगत :- मय तो बृजमोहन भईया के संग बोलत हों। एक मिनट, मैं बृजमोहन भईया को सुना रहा था। यह अरूण भईया के लिए था कि अरूण भईया की जो उम्र है वह ईश्क करने की ही उम्र है क्योंकि इसमें केवल ईश्क होता है और कुछ नहीं होता है। (हंसी)

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, मेरी उम्र बता देता हूँ मेरी उम्र 58 साल है। आप मुझे ज्यादा बुजुर्ग मत समझना।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पर उसका जवाब दीजिए। वह बोल रहे हैं कि वही होता है बाकी कुछ नहीं होता है। आप उसका जवाब दीजिए।

श्री अरूण वोरा :- मैं उससे सहमत हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- वह उससे सहमत हैं। आज दो घण्टे बोलना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय,आज इस सदन में हम बहुत भारी मन से, बहुत दु:खी मन से खड़े हुए हैं और माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर चर्चा है, वह संवैधानिक प्रमुख हैं और साल में एक बार माननीय राज्यपाल महोदया का अभिभाषण होता है इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि हम माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में भाग लेंगे। आज जब हम माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में भाग ले रहे हैं तो इस सदन की सभी मर्यादाएं टूटी हैं, सभी वर्जनाएं टूटी हैं । इस सदन की सभी परम्पराएं टूटी हैं, सभी नियम, कानून कायदे टूटे हैं। यह दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ का सदन उच्च परम्पराओं से चलता रहा है। हमें यह मालूम है कि अध्यक्ष जी को अधिकार है कि वह नियम को शिथिल करके दूसरा बिजनेस ले सकते हैं, परन्तु सदन में आज अनुपूरक बजट होना था तो अनुपूरक बजट में विपक्ष भी भाग ले। दूसरे दिन माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण पर चर्चा हो जाए । इसके ऊपर में क्या बाध्यता थी कि यह नहीं हो सकती ? हमारे विद्वान मंत्री अकबर जी बैठे हैं और सर्वज्ञ ज्ञाता कवासी लखमा जी बैठे हैं। जरा मुझे बताईए न कि क्या राज्यपाल जी के अभिभाषण पर इस छत्तीसगढ़ की विधानसभा में आज तक दो दिन से कम कभी चर्चा नहीं हुई है। कोरोनाकाल समाप्त हो गया। विधानसभा की कार्यसूची विधानसभा प्रांरभ होने के पहले दिन जारी होती है। यह क्यों नहीं हो सकता था ? अगर मुख्यमंत्री जी को आज ही सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत करना था तो राज्यपाल के अभिभाषण पर कल चर्चा हो जाती। हमारे संतराम नेताम जी विद्वान सदस्य हैं, पुराने सदस्य हैं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य जितनी संजीदगी के साथ माननीय राज्यपाल महोदया महामहिम के लिए अपनी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे

हैं, कल जब राज्यपाल महोदया का भाषण चल रहा था तो इनकी भावना एकदम प्रदर्शित हो रही थी। उनको भाषण नहीं देने दे रहे थे। आज नियम और सिद्धांत की बात कर रहे हैं। आपका सिद्धांत कहां चला गया था ? एक महिला महामहिम को आप लोग भाषण नहीं देने दे रहे थे। माननीय क्या यह सम्मान होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, राज्यपाल, राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल महिला नहीं होती, राज्यपाल पुरूष नहीं होता। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। यह सरकार मजबूर करती है। सामान्यत: हम लोग राज्यपाल जी के अभिभाषण में कभी व्यवधान नहीं करते हैं। दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है जरा देख लीजिए। क्योंकि यह सरकार राज्यपाल जी से पूरी तरह असत्य कथन करा रही थी। एक भी बिंदु सच नहीं था। मेरे पास मुख्यमंत्री जी का आज का जवाब है। उन्होंने कहा है कि 36 में से 17 वादे पूरे किए हैं 19 वादे पूरे नहीं किए हैं। आज के प्रश्न में देख लीजिए। टोटल 254 वादे हैं। उन्हीं वादों के फेहरिस्त विधानसभा में राज्यपाल से गिनवाई जा रही थी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय राज्यपाल महोदया ने अपनी भाषण में कही कि पूरे हिन्दुस्तान में अगर किसानों को सबसे ज्यादा उनकी उपज का दाम मिल रहा है तो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। यहां की योजना पूरे हिंदुस्तान में चर्चित है। एक माडल के रूप में है तो माननीय उन्होंने क्या गलत कहा ?

सभापति महोदय :- माननीय, अमरजीत जी, बार-बार टोका टाकी न करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मेरी जानकारी गलत नहीं है तो वे चौथी बार विधायक हैं। उनको भी यह जानकारी है कि राज्यपाल जी अपना कुछ नहीं बोलती हैं, उनको जो सरकार लिखकर देती है, उसको वह पढ़ती हैं। हम भी चार बार मंत्री रहे हैं, परंतु उसमें कुछ तो सत्यता होनी चाहिए। क्या आप उनसे झूठ का पुलिंदा बुलवा दोगे। उनके भाषण में जितने प्वाईंट्स हैं।

श्री नारायण चंदेल :- श्री अमरजीत भगत को मेरू दंड बताया जाए। अध्यक्ष का जो दंड रहता है उनको उसको बताया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब अध्यक्ष के पास दंड है कि नहीं यह तो पूछो। माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ में पिछले तीन सालों में संविधान को कुचला जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमारी जो प्रजातांत्रिक संसदीय लोकतंत्र है उसकी हत्या हो रही है। विधानसभा के सत्र छोटे हो रहे हैं। चर्चाओं से भाग रहे हैं। इस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम पत्रकारों का सुरक्षा कानून लायेंगे। जो पत्रकार भाटगिरी नहीं कर रहे हैं, उन पत्रकारों को जेलों में डाला जा रहा है। उनको हथकड़ी पहनकर घुमाया जा रहा है। उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। कहां के नियम कायदे कानून हैं ? आप बोलोगे तो मैं पत्रकारों के नाम पढ़ दूंगा। वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला, पत्रकार जितेंद्र जायसवाल, पत्रकार नीलेश शर्मा इनकी थानों में पिटाई होती है । क्या यही पत्रकार सुरक्षा कानून है ? यह तो हमने कभी नहीं देखा था, पत्रकार स्वतंत्र होता है, पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा होती है, सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट ने



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इनमें निर्णय दिये हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर सरकार के खिलाफ में, सरकार के चहेतों के खिलाफ में अगर कोई समाचार छापेगा, अगर कोई सोशल मीडिया पर लिखेगा तो उसको जेलों में डाला जायेगा और एक दृष्टि से हम कहें तो छत्तीसगढ़ में प्रेस के ऊपर में अघोषित आपातकाल लागू है । क्या सरकार के पास कोई जवाब है ? (शेम-शेम की आवाज) जिस प्रदेश में वहां के पत्रकारों का सम्मान नहीं होगा, लिखने वालों का सम्मान नहीं होगा, जहां पर समाचार सेंसर किये जायेंगे । चूंकि हम लोग भी सरकार के विरूद्ध में समाचार भेजते हैं, जब रात को हम फोन करके पूछते हैं कि क्यों इसको जारी क्यों नहीं किया तो कहा जाता है कि सर, हमारे पास फोन आ गया था ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं तो पूरे हिंदुस्तान में प्रेस के ऊपर इमरजेंसी तो आपकी सरकार ने लगाकर रखा है, मोदी जी ने जिस प्रकार से हाईजेक किया है, दूसरे का न्यूज ही नहीं आने देते हैं ।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बार-बार टोका-टाकी न करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार झूठ से बनी है, फरेब से चल रही है । यह अविश्वास की सरकार है ।

श्री अमरजीत भगत :- क्या किसानों के लिये काम करना झूठ है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, ढ़ाई-ढ़ाई साल के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है ।

श्री अमरजीत भगत :- यह तो आप लोगों की उपज है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, इस मामले को लेकर पूरे देश में, पूरे छत्तीसगढ़ में जो अस्थिरता पैदा हुई है । अधिकारियों को लगता है कि पता नहीं कब मुख्यमंत्री बदल जायेगा, कब यहां का निजाम बदल जायेगा, हमारा क्या होगा, कहीं हमारे पैसे तो नहीं डूब जायेंगे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बटोर लो ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, जिस पर चर्चा हो रही है क्या यह संशोधन का विषय है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- बृजमोहन जी, यह दुष्प्रचार भी तो हो सकता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, राज्यपाल जी ने कहा है कि हमारी सरकार अच्छी सरकार है । (व्यवधान)

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- पैसे वाला मामला तो आपकी सरकार में होता था, हमारी सरकार में नहीं होता है । (व्यवधान)



अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय सभापति महोदय, जिस बिंदु पर संशोधन दिया है चर्चा वहीं तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मुख्यमंत्रियों का मंत्रियों पर विश्वास नहीं है, मंत्रियों का अधिकारियों पर विश्वास नहीं है, विधायकों का मंत्री पर और अधिकारियों पर विश्वास नहीं है । कुल मिलाकर यह सरकार चूं-चूं का मुरब्बा है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यह चूं-चूं क्या होता है ?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आपने अच्छी चीज पूछ ली कि चूं-चूं का मुरब्बा क्या है ? किसी को समझ में नहीं आयेगा ? आप लोग पूछिए कि यह चूं-चूं का मुरब्बा क्या है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन में साबित कर देता हूं कि चूं-चूं का मुरब्बा कैसे है ।

सभापति महोदय :- बृजमोहन जी, विषय में आईये ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- साबित करिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, चूं-चूं का मुरब्बा कोई असंसदीय शब्द नहीं है ।

श्री अरूण वोरा :- आप बहुत सीनियर हैं और आप काफी लंबे समय से विधायक हैं लेकिन आप छत्तीसगढ़ की चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली की चर्चा कर रहे हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- हम पूरी दुनिया की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री अरूण वोरा :- आप लोग केंद्र सरकार की चर्चा मत करिये ।

श्री कवासी लखमा :- चूं-चूं का मुरब्बा क्या है, वह बताईए ।

श्री अरूण वोरा :- वे कक्ष में समझायेंगे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, सत्तादल के एक विधायक प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री पर आरोप लगाते हैं कि वे मेरी हत्या करवा सकते हैं, यह क्या है, क्या हो रहा है ? सत्ताधारी दल की एक विधायक अपने पति के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा किये गये अत्याचार को लेकर जिन्होंने अपनी सुरक्षा वापिस कर दी । 150 किलोमीटर स्कूटी में चलकर यहां विधानसभा आती है, यह क्या है? नक्सली एरिया के विधायक हैं। इस सदन में अगर विधायकों के सम्मान की, विधायकों के हितों की, अधिकारों की रक्षा नहीं की जायेगी तो कहां की जायेगी? सत्ताधारी दल के एक दर्जन विधायक जो अभी सदन में बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कहा जाता है..।

श्री अमरजीत भगत :- क्या यह आपके संशोधन का विषय है ? आदरणीय क्या यह आपके संशोधन का विषय है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उनके द्वारा कहा जाता है कि खुलेआम एक मंत्री के घर जाकर हंगामा किया जाता है कि ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो मुख्यमंत्री बोल रहे थे, वह बजट के विषय थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वहां 10-12 विधायक जाते हैं और हंगामा करते हैं। वे बोलते हैं कि हमारे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। पूरे ट्रांसफर लेन-देन के आधार पर हो रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है। खुलेआम अखबारों में बयानबाजी करते हैं और मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद उनके निजी सचिव को हटाया जाता है। क्या ऐसे सरकार चलती है ? ऐसे जनता में संदेश दोगे ? क्या जनता ने आपको इसलिए बहुमत दिया है कि सरकार इसी में उलझी रहेगी।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या है बृजमोहन जी, उस मंत्री के तो निजी सचिव को हटा दिया गया। अब अमरजीत जी भी इतने डर में रहते हैं कि मैं कुछ कहूंगा तो मेरे को ही न हटा दें। इसलिए चुपचाप रहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि अमरजीत जी जिस दिन बाबा के यहां ढोल बजाना बंद कर देंगे, तो यहां से उन्हें हटा दिया जायेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- इनका मंत्रालय तो धमतरी से चलता है।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोगों की मनगढ़ंत और भ्रांति है।

सभापति महोदय :- ज्यादा टोका-टाकी न करें।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका मंत्रालय तो धमतरी से चल रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- आपकी सरकार में भी हम लोगों ने देखा है।

श्री कवासी लखमा :- इनके मंत्री जी तो किसी की नहीं सुनते थे। बृजमोहन अग्रवाल पहले वक्ता हैं, उन्हीं को डिस्टर्ब करने में लगे हुए हैं। किस प्रकार से टोका-टाकी चल रही है। यहीं कुश्ती लड़नी है। बाहर लड़ो भाई या तो ठीक-ठाक रहो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका विभाग धमतरी से संचालित हो रहा है या नहीं, यह बताओ। आपका विभाग धमतरी से संचालित हो रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- किस प्रकार से पिछली सरकार में आप लोगों का अवमूल्यन किया जा रहा था। मालूम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, प्रदेश के एक मंत्री खुलेआम बयान देते हैं कि उनके जिले के कलेक्टर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते। वह भ्रष्टाचार मचा रखा है और पूर्व के जिलों में भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह इस सरकार के मंत्री कह रहे हैं। माननीय सभापति जी, हमें उस दिन बहुत बड़ा कष्ट हुआ, जब इस छत्तीसगढ़ की सबसे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बड़ी पंचायत के अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे जिले में बाकी प्रदूषण तो है पर प्रशासनिक प्रदूषण भी है। अगर इस पंचायत के सबसे बड़े अध्यक्ष दुखी हों तो वह सरकार चू-चू का मुरब्बा है या नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सभापति महोदय, आप कितने खुश हैं ? सभापति जी, बस्तर में क्या चल रहा है ?

श्री कवासी लखमा :- चू-चू का नाम क्यों लेते हो ? उसका मतलब क्या है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है, बहुत सारी चीजें पर्दे में ही रहने दो। पर्दा न उठाओ। पर्दा जो खुल गया तो होश उड़ जायेंगे। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- होश किसके उड़ जायेंगे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस प्रदेश में सब कुछ तय है। सब चीजों के रेट तय हैं। सब नियम-कायदे-कानून कानून से ऊपर बने हुए सब तय हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- महोदय, रेट तो आपकी सरकार बढ़ा रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस प्रदेश में सब कुछ तय है, का नारा चल रहा है। रेट के प्रति ट्रक के पीछे सब कुछ तय है। कोयला के प्रति, क्विंटल के प्रति सब कुछ तय है। शराब के प्रति बॉटल के पीछे सब कुछ तय है। सीमेंट के प्रति बोरी के पीछे सब कुछ तय है। शासकीय भर्ती में प्रति पद में भर्ती के पीछे सब कुछ तय है। अवैध प्लॉटिंग के पीछे सब कुछ तय है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल तक भी तय था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सप्लाई में प्रति नग के पीछे सब कुछ तय है। ठेका टेंडर में कितना प्रतिशत होगा, यह भी तय है। जंगल कटाई कौन करेगा, यह भी तय है। लोहे का रेट कौन तय करेगा, यह भी तय है। हां, यह भी तय है कि प्रति क्विंटल चावल की कस्टम मिलिंग के पीछे कितना पैसा मिलेगा यह भी तय है।

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा सुनिए तो..।

श्री शिवरतन शर्मा :- और धान के आर.ओ. का कितना रूपये लगेगा, यह भी तय है।

श्री अमरजीत भगत :- रायगढ़ में एक अधिवेशन हुआ था । उसमें रमन सिंह जी ने सबको कहा था कि एक साल कमीशन लेना बंद कर दो तो सरकार आ जाएगी लेकिन इन लोगों ने माना नहीं और इनका क्या हाल है, सबके सामने है । अब उस दर्द को ये लोग रह-रह कर महसूस कर रहे हैं तो हम क्या करें ?

श्री नारायण चंदेल :- अमरजीत जी, अगले चुनाव में इस सरकार का जाना भी तय है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसमें यह भी तय है कि आप कितने हाथियों को मारकर उसके अंग निकालकर लाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, इसका भी रेट तय है । एस.पी. की पोस्टिंग का भी रेट तय है, कलेक्टर की पोस्टिंग का भी रेट तय है, कस्टम मिलिंग के आर.ओ. के ठेके का रेट भी तय है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- परम्परा बन गई है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अमरजीत भगत जी, अगर मैं यह पढ़ने लगूंगा तो मालूम नहीं मुझे कितने दिन लगेंगे । माननीय अध्यक्ष जी ने समय नहीं दिया । लोगों के जीवन का मोल, किसानों की फसल का मोल, लोगों के रोजगार का मोल, महिलाओं की सुरक्षा का मोल, मरीजों के स्वास्थ्य का मोल, ये तय नहीं है । परंतु कहां कहां आना है, उसके लिए सब कुछ तय है । माननीय सभापति जी, छत्तीसगढ़ मॉडल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कैसे चल रहा है । एक्ज़िट पोल सामने आ रहे हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- परसों वह भी तय हो जाएगा । छत्तीसगढ़ मॉडल को उत्तर प्रदेश के लोगों ने पसंद किया या नहीं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब गुजरात मॉडल नहीं चलेगा, अब छत्तीसगढ़ मॉडल चलेगा । पहले आसाम में चल गया, अब यू.पी. में चलेगा, वाह रे आइडियोलॉजी ।

श्री अमरजीत भगत :- पड़ोसी के यहां बच्चा पैदा हुआ तो आपको कितनी खुशी हो रही है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दिल्ली की बात क्यों कर रहे हो यहां पर ?

श्री अमरजीत भगत :- दिल्ली ने ऐसा हश्र किया है, दिल्ली ने खून के आंसू रूलाया है ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर और ये दोनों ज्ञानी आदमी हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अमरजीत जी, पड़ोस में बच्चा पैदा होता है तो गाने का काम आजकल आप लोग करते हो ।

सभापति महोदय :- 20 मिनट हो गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 20 मिनट में से 10 मिनट तो इंटरप्शन में गया ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अग्रवाल जी, हम यू.पी. गए थे तो सब लोग छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा कर रहे थे । छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ कर रहे थे और योगी सरकार ने तो कुछ किया नहीं है, ऐसा कह रहे थे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल पर वोट नहीं मिलने वाला है ।

श्री अमरजीत भगत :- केवल यू.पी. ही नहीं, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की मांग हो रही थी कि उसको लागू किया जाए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, बैठिये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी यू.पी. में कांग्रेस की जितनी सीट आएगी उससे डबल बच्चे तो हमारे पुन्नूलाल मोहले जी के हैं ।

श्री कवासी लखमा :- बच्चे वाला नहीं बोल रहा है, आप कैसे जानते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कितने बच्चे हैं, यह तो जानते हैं भाई ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कवासी जी, आपकी कितनी पत्नियां हैं, यह हमको नहीं मालूम, लेकिन पुन्नू लाल जी के कितने बच्चे हैं, यह हमको मालूम है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- भाजपा के लोग परिवार नियोजन के कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपके लिए लड़ता हूं तो आप भड़क जाते हो । पेंशन पाकर खुद बैठे हो, पूरी तनख्वाह मिल ही नहीं रही है । वह भी वहां तय है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी, अतना जान ले, राज्यपाल तुम्हर बात ला सुनत हे, अउ तुम्हर मन के नाम से परेशान हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- कवासी लखमा जी को पूरी तनख्वाह मिले, उन्हें केवल पेंशन मिल रही है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- चंद्राकर जी, राज्यपाल जी आपके भाषण को सुन रहे हैं और अब आपका राजभवन जाना भी बंद होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सबसे सीनियर हो, 1980 से चुनकर आ रहे हो, लेकिन आपका ओ.एस.डी., मुख्यमंत्री तय करते हैं और पुराने ओ.एस.डी. के पास बहुत लोगों के एडवांस डूब गए हैं । उसको वापस लाकर जमा करवाओ ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- आपसे पूछकर तय करेंगे क्या ?

समय :
3.34 बजे

**(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मंडावी) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, इस प्रदेश के सबसे बड़े आइडियोलॉजी विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश की एक सभा में बोलते हैं कि हर ज़िले में फूड पार्क की स्थापना हो गई है । छत्तीसगढ़ का किसान टमाटर फूड पार्क के अंदर जाता है और उचित पैसा मिलता है, टमाटर रखता है और पैसा लेकर तुरंत बाहर आ जाता है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जैसे आलू डालकर सोना लाता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष जी, मैं, मेरे कार्यकर्ता, छत्तीसगढ़ की जनता टॉर्च लेकर, लालटेन लेकर, मोमबत्ती लेकर, चिमनी लेकर, दिया लेकर के और हम तो चाहेंगे कि हम माननीय मंत्रियों के साथ चलने को तैयार हैं।

श्री कवासी लखमा :- कब जायेंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो तारीख आप लोग दे देंगे तब चल देंगे। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में फूडपार्क लगा है? इनके घोषणा-पत्र में जो कहा गया है ..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ के सभी जिले में जहां गौठान बना है, वहां फूड प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गोबर को खाना है क्या? गोबर खाना है?

श्री अमरजीत भगत :- वहां पर फूड प्रोसेसिंग वर्क चल रहा है। आप जिस गोबर के बारे में criticize कर रहे हैं, वह गोबर भी पैसा दे रहा है, उससे भी लोगों को रोजगार मिल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- गोबर से मिठाई का बनाने का नया कारखाना चल रहा है। अमरजीत जी, वही फूडपार्क है क्या?

श्री अमरजीत भगत :- फूडपार्क प्रोसेसिंग सब जगह चल रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कहां चल रहा है? चलिए एकाध जगह दिखाइये।

श्री अमरजीत भगत :- जाकर देखा करो न। आप जाते कहां हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- चालिए न, हम आपके साथ देखने चलते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- अनुमति ले लीजिए, सीफ सेक्रेटरी जी नहीं हैं। चरोदा चलते हैं न, सब लोग देखकर आते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- चंद्राकर जी, चश्मा बदलिये।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो बोलने दीजिए।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अमरजीत भगत जी, चंदखुरी के लिए जहां मुड़ते हैं, उसके पहले नेशनल हाईवे में वहां पर एक गोठान बना हुआ है। उसकी क्या हालत है, आप जरा उसे देखकर आइयेगा। नेशनल हाईवे में है, मैं अंदर गांव की बात नहीं करूंगा।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार एथेनॉल निर्माण की अनुमति नहीं दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे किसान की धान को एथेनॉल निर्माण के बाद 3000 से 3500 रूपये में खरीदने को तैयार है। लेकिन यह हुई तो किसान के हित में आप लोग उसको भूलने के लिए तैयार नहीं है।

श्री राम कुमार यादव :- उपाध्यक्ष जी, कइ बार तो हमन फांदा म फंस जाथन। जइसे छत्तीसगढ़ी म एक कहावत हावय कि गुण खाय चाटा अउ पिठान खाय छरिया। ऐ मन घोषणा करे रहीन कि जरसी गाय देबो कइके, गेरवा ल धरके हमी मन ल धर दारत हावय।

श्री नारायण चंदेल :- रामकुमार कका, तैं चुप बइठ जा। पूरा चोचोबोरा कर दारत हावस। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा देश बड़ा आश्चर्यचकित है कि छत्तीसगढ़ का किसान टमाटर ले करके लातो है, पैसा लेकर आता है लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मालूम है। कहां टमाटर बिक रहा है, कहां फूडपार्क लगा है। छत्तीसगढ़ के विधायकों, मंत्रियों को नहीं मालूम है, हम लोगों को नहीं मालूम है। अरे भैया, सरकार में बैठे हुए वरिष्ठ लोगों कम-से-कम ...।

श्री कवासी लखमा :- वरिष्ठ मंत्री और वरिष्ठ विधायक बृजमोहन साहब जी, इस पर आप बड़ा-बड़ा भाषण दे रहे थे गाड़ी से नहीं लंदन से नहीं मिलेगा बाड़ी से डीजल। कहां मिल रहा है? मिलेगा क्या? यही तो 15 साल तक आप लोगों ने भी बड़ा-बड़ा भाषण दिया था कि गाड़ी से नहीं लंदन से नहीं मिलेगा बाड़ी से डीजल।

श्री राम कुमार यादव :- रायपुर में आड़ा-बाड़ा बना दे हावा। न ओमा आदमी रेंगथे, न गरवा बछरू रेंगथे, न कुकुर-बिलाई रेंगथे, त ये तुंहर आड़ा-बाड़ा के का मतलब हावय?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज बड़ी-बड़ी बातें, बड़े-बड़े अपने नेताओं तक को गुमराह कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता जो पूरे देश में अपनी सरकारों का गुणगान करते हैं, कम-से-कम उनको तो गलत बातें नहीं बतानी चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता को भी अगर अपने नेता को जो गुमराह कर सकता है, उसको छत्तीसगढ़ की जनता के साथ विश्वासघात करने में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर जी कोई स्पेशल कमेंट आ रहा है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- एक मिनट। माननीय लखमा जी ने जो डीजल के बारे में जो कहा है कि डीजल नहीं है खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से, यह नारा था। मैंने विधानसभा में कहा था कि डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाये खाड़ी में। तो माननीय रमन सिंह जी ने कहा था कि आप व्यंग्य कर रहे हैं। मैं आपके समय का एक विज्ञापन दिखाया था, उस विज्ञापन में पेड़ से पाइप लगाकर सीधे डिब्बे में भरते हुए दिखाया गया था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- पेड़ से निकालने वाला।

श्री शिवरतन शर्मा (भाठापारा) :- ताड़ी है ताड़। पेड़ से ताड़ी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ताड़ी है वह ताड़ी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर दक्षिण) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में...।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- वह ताड़ी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कभी बस्तर चलेंगे तो पेड़ में लटका हुआ आपको सीधा भरते हुए दिखा देंगे। आप सेवन करना चाहोगे तो संतराम जी आपको सेवन भी करा देंगे।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- पेड़ से पाइप लगाकर सीधे बायो डीजल का पूरे विश्व में कहीं कोई तकनीक आज तक हमने देखा ही नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- मैं आपका धैर्य...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- उससे आदमी चलेगा, गाड़ी नहीं चलेगा। (हंसी)



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके धैर्य, यह गलत आदमी है। आपके सामने शराब का उल्लेख कर दिया। आपके लिए शराब सुनना भी हराम है और वह आदमी के पास आपका बैठना भी उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, बैठिये-बैठिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैंने कहां शराब का उल्लेख किया? मैंने यह कहा कि पेड़ से टपकते हुए, भरते हुए दिखा देंगे। संतराम जी दिखा देंगे। आप बोलेंगे तो मोहन मरकाम जी दिखा देंगे। कवासी लखमा जी का क्षेत्र तो उसके लिए प्रसिद्ध है।

श्री कवासी लखमा :- क्या दिखा देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय :- पूरा बस्तर प्रसिद्ध है। चलिये-चलिये।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- तुहर समय में नून देवो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पूरे छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बद्तर हो रही है। पूरा छत्तीसगढ़ अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- हमको तो आप पीला चुके हैं। सुकमा में पीला चुके हो। हम पीये भी हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तरप्रदेश और बिहार से भी ज्यादा खराब स्थिति कानून-व्यवस्था की कहीं पर है तो...।

श्री कवासी लखमा :- तो उत्तरप्रदेश में हैं। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको उत्तरप्रदेश की आबादी कितनी है मालूम है? छत्तीसगढ़ से 10 गुनी ज्यादा आबादी है। बिहार की आबादी छत्तीसगढ़ से 4 गुना ज्यादा है। उसके बाद भी सरकार आने के बाद 1 हजार से अधिक हत्या, 35,00 से अधिक बलात्कार, 9000 से अधिक चोरी, 100 से अधिक डकैती, लूट-पाट के 800 से ज्यादा प्रकरण, आत्महत्या के 15,000 से ज्यादा प्रकरण, आगजनी के 500 से ज्यादा प्रकरण, बलवा के 1300 से ज्यादा प्रकरण है। यू.पी. और बिहार में नहीं है। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- यह कहां का आंकड़ा है?

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- यह कहां का आंकड़ा ले आये हों? यह 15 साल पहले का आंकड़ा है।

श्री कवासी लखमा :- यह 15 साल पहले का आंकड़ा है। यह पुराना आंकड़ा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अभी मैं बताता हूं। राज्यपाल जी से जो अभिभाषण पढ़वाये न, उसमें आधे आंकड़े 15 साल के थे। 4 लाख वन भूमि के पट्टे हमने दिये हैं और इन्होंने बता दिया कि अभी तक 4 लाख, 45 हजार पट्टे दे दिये...।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- शिवरतन शर्मा जी हा फर्जी किसान ला मर जही कीथे। सब ए मन फर्जी हे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो भैय्या 15 साल के कितने थे? आपके कितने हैं? जरा अलग से बताते। आधे आंकड़े पिछले 20 सालों के छत्तीसगढ़ बनने के बाद अभी तक के हैं, उन आंकड़ों को राज्यपाल जी से पढ़वा दिया।

श्री शिवरतन शर्मा :- सरकार का जवाब है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बड़ा अजीब है।

श्री कवासी लखमा :- तुम लोग भी नहीं दिये थे भैय्या।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं-नहीं, मेरे पास सरकार का जवाब है। विधानसभा का जवाब है। उस जवाब से मैं यह आंकड़े बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य :- अब आप मंत्री नहीं हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुझे मालूम है कि मैं मंत्री नहीं हूं। आंकड़े आ लोग देते हैं। आप लोग जवाब देते हैं। आपके मंत्री जवाब देते हैं उन आंकड़ों को हम उपयोग करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आंकड़े हम कोई आसमान से नहीं लाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अब आप कितना समय लेंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- अभी तो शुरू हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय :- 25 मिनट ज्यादा हो गया है। 25, 26, 27 मिनट हो गया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे को 25-27 मिनट में 20 मिनट तो इन लोगों ने टोका-टाकी में खत्म किया। मैं 7 मिनट बोल पाया। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप सीधा-सीधा बोलेंगे तो कोई टोका-टाकी नहीं होगी। उल्टा क्यों बोलते हैं?

श्री अमरजीत भगत :- आपका तो पुराना आदत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट देखे तो वर्ष 2020 में 1210 दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज हुए। औसतन प्रतिदिन 3 दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज हो रहे हैं। औसरत रोज 3 प्रकरण। सन् 1919 की रिपोर्ट के अनुसार 1036 दुकर्ष्म के रिपोर्ट।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके समय में 16 करोड़ ऐसा-ऐसा हो रहा था। उसको हम बताएंगे। आपके समय कितना हुआ? उसको बताइये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाएं। आज महिला दिवस है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- एक मिनट, भैय्या, जरा बोलने तो दीजिए। आप ही लोग इतना बोलने लगते हो तो सामने वाला क्या बोलेगा? बताओ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह उल्टा-उल्टा बोलते हैं न।

श्री अमरजीत भगत :- शब्दश: नहीं बोलते हैं न।

श्री धर्मजीत त सिंह :- आपसे भी, आपसे भी, आपसे भी तीनों से हाथ जोड़कर विनती है कि बोलने दें।

श्री कवासी लखमा :- हमें बोलते हो। यह उल्टा ही बोलते हैं। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- भाई, बोलने तो दो यार। बोलने तो दो।

श्री अजय चन्द्राकर :- देखिये, उधर एक ही समझदार आदमी हैं जो चुप बैठकर सुनता है। माननीय अकबर जी और यह जो हमारे आरंग के नरेश हैं। रविन्द्र चौबे जी नहीं है तो उनकी आत्मा उनके अंदर आप ही आप प्रवेश कर जाती है। (हंसी) उनको सदन चलाना होता है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज हम महिला दिवस मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हम भी प्रदेश की सभी महिलाओं को बधाई देते हैं। परंतु हम भगवान से कामना करते हैं इस सरकार से नहीं कर सकते

कि महिलाओं का जीवन सुरक्षित हो। हमारी लड़कियों की आबरू बची रहे। लड़कियों के साथ में दुराचार न हो। क्या आंकड़े हैं, मैं आपको आंकडे बताऊं। 2 साल में 2246 दुष्कर्म के मामले छत्तीसगढ़ में हुए। यह तीसरे साल का नहीं है। यह क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट है । आप लोग भी रायपुर में रहते हो, रोज पेपर पढ़ते होगे । रायपुर में क्या हो रहा है ? चाकूबाजी कि कितनी घटनाएं हो रही हैं, रोज गली-गली में चाकूबाजी हो रही है । सरकार की धमक होती है, पुलिस के जूते की धमक होती है, जब ठेके पर पोस्टिंग करोगे तो फिर वह पूछ हिलाने लगता है, वह काटता नहीं है । सरकार की धमक होनी चाहिए । अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं । सिटी कोतवाली के पास, पंडरी पुलिस थाने के पास, शादी-समारोह में भीड़ के बीच में चाकू मारना, सी.एम. हाऊस के सामने चाकू मारना रोज की घटना हो गई है । सरकार का कोई वजूद है या नहीं, कोई सरकार की बुलंदगी है या नहीं, कोई शासन-प्रशासन है या नहीं, कोई सुरक्षा के लोग हैं या नहीं ? राजधानी में यह हालत हो रही है । कभी-कभी तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा नहीं, आजकल गांजे का कटोरा हो गया है, आजकल शराब का कटोरा हो गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- आदरणीय बृजमोहन जी, आप कुछ बात बिल्कुल कहें, आप विपक्ष में हैं, आप आरोप लगाएं, वह ठीक है । कोई बात जस्टिफाई होना चाहिए। आंकड़ा और जो आरोप लगा रहे हैं, वह तथ्यपरक होनी चाहिए । जितनी भी शराब आ रही हैं, वह यह हरियाणा, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश से आ रही है तो इन प्रदेशों में किसकी सरकार है ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, गली-गली में गांजा पकड़ा जा रहा है, ट्रक में गांजा आ रहा है । मोहम्मद अकबर जी ने इस सदन में बैरियर लगाने के ऊपर में स्पष्टीकरण दिया था कि हम बैरियर क्यों लगा रहे हैं ? अपराधियों को रोकेंगे, तस्करी को रोकेंगे, अवैध व्यापार को रोकेंगे । वह चेक पोस्ट वसूली का अड्डा बन गए हैं, वहां से जो पैसा देकर निकलता है, कूपन दिखा देता है, वह छत्तीसगढ़ को पार करके कहीं भी देश में जा सकता है । बैरियर क्यों बने हैं ? हमारी सरकार ने बैरियर समाप्त कर दिये थे, आपने बैरियर खोले हैं । अभी दो दिन पहले एक नया काम और हुआ है । आपने तीन जिलों में क्राईम ब्रांच बना दी । हमारी सरकार की सभी क्राईम ब्रांचों को भंग कर दिया था । एक वसूली का नया काम हुआ है ।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- जिस समय बैरियर बंद किया गया था, आपके समय का राजस्व 13 करोड़ रूपए था । बैरियर स्थापति करने के बाद यहां प्रतिवर्ष 110 करोड़ रूपए का राजस्व है ।

श्री रामकुमार यादव :- तुहर समय के ना । आपरेशन कराने वाला डर्रा थे आंखी के आपरेशन कराए बर ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, अफीस, चरस, स्मैक, हीरोईन, डोडा, नशीली इंजेक्शन, नशीली सीरप, नशे की सामग्री छत्तीसगढ़ के नौजवानों का भविष्य बरबाद हो रहा है । छत्तीसगढ़ के स्कूलों में, कॉलेजों में अफीम, चरस, स्मैक आसानी से मिल रही है । कभी छत्तीसगढ़ में हमने सोचा नहीं था कि पैसा कमाने की हवस, पैसा कमाने की भूख पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य को बरबाद कर रही है । जरा सोचो, जरा सोचो, पैसा सब कुछ नहीं है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी परिवार है । जब हमारे बच्चे को ड्रग की आदत हो जाएगी, जब वह चरस लेने लगेगा, अफीम लेने लगेगा, वह स्मैक लेने लगेगा, वह छोटी-छोटी पुड़िया खाने लगेगा तो हम उसका जीवन नहीं बचा पाएंगे । वह तो मरेगा, हम भी तड़प-तड़प कर मर जाएंगे । मैंने बहुत बार सूचना दी है । छोटे-छोटे बाजार लगते हैं । उन बाजारों में इसको बेचने वाले ढूंढते हैं । मैंने विदेशों में देखा था ।

श्री अमरजीत भगत :- एक मिनट । माननीय वरिष्ठ सदस्य अच्छा भाषण दे रहे हैं, सबकुछ ठीक है । लेकिन जिस प्रकार से भारत सरकार ने निजी क्षेत्रों को सामने रखा है, चाहे वह एयरपोर्ट हो, चाहे समुद्री मार्ग हो, आये दिन हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितने हजार करोड़ की हीरोईन पकड़ी गई । यह किसका है ? अडानी का है, अंबानी का है, देश में इसी का तो विरोध हो रहा है और आप लोग उस बात को नहीं समझते। जहां ये सब व्यवस्था निजी हाथों में देंगे तो देश में इसी प्रकार की घटना घटेगी। जितनी भी नशीली पदार्थ आ रहे हैं, इन्हीं मार्गों से आ रहे हैं। उसको बंद किया जाये।

श्री सौरभ सिंह :- अडानी वाली कोल माईंस के लिए गहलोत जी और मुख्यमंत्री जी की बैठक हो गई है क्या ? जिसके लिए गहलोत जी दो बार चिट्ठी लिख चुके हैं।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी, राज्यसभा का चुनाव आ रहा है, आप वहां जाकर दिल्ली की बात करियेगा। आप यहां लगातार दिल्ली की बात कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बात से दुखी हूं , मैं परेशान भी हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लीकर का सरकारीकरण किसने किया, यह बताईये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सदस्यों को जगाना भी चाहता हूं, मैं आम सी बात कर रहा हूं। भगत जी, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मैं आपसे माफी भी मांगता हूं कि मैं जिस बात को कह रहा हूं, आप उसको गंभीरता से लीजिये। मुझे मालूम है, मेरे नजदीक के कुछ लोग हैं, जिनके बच्चे ये शुरू कर दिए हैं और आज उनके मॉ-बाप परेशान हैं। उनको नशामुक्ति केन्द्र में ले जा रहे हैं, उनका ईलाज करवा रहे हैं। जब बच्चे ऐसी आदतों में पड़ जाते हैं तो मां-बाप क पैसों को बर्बाद कर देते हैं, मां प्रेमवश चेक पर दस्तखत करके दे देती है, वे पूरे पैसों को ठिकाने लगा देते हैं, बाप को मालूम नहीं होता है। जिस दिन बात को मालूम होता है, उस दिन उसके सामने फांसी लगाकर आत्महत्या करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। क्या हम पैसा कमाने के लिए छत्तीसगढ़ की पीढ़ी को बर्बाद करना चाहते हैं ? क्या यह यही छत्तीसगढ़ियावाद है ? क्या यही छत्तीसगढ़ है?क्या यही छत्तीसगढ़ बढ़ता छत्तीसगढ़ है ? क्या यही उगता छत्तीसगढ़ है ? छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है ? बड़ी-बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। आप 2500 रूपया किसान को दे दोगे और अगर उसका बच्चा इन आदतों में पड़ गया तो उस किसान के पास  कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। आज किसानों के 50 प्रतिशत बच्चें शहरों में पढ़ने आ रहे हैं। चाहे अम्बिकापुर में हो, चाहे रायगढ़ में हो, चाहे भिलाई में हो, चाहे दुर्ग में हो, राजनांदगांव या रायपुर में हो, यदि ये सब चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाये तो बच्चों के बिगड़ने के लिए खुला मैदान है। क्या यह छत्तीसगढ़ कारीडोर बन गया है ? क्या छत्तीसगढ़ हब बन गया है ? यहां कहां-कहां की दारू पकड़ में आती है- उड़ीसा, आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, झारखण्ड, क्यों भैय्या ? आपके लोग बार्डर पर क्या कर रहे हैं ? आपके बैरियर क्या कर रहे हैं ? आपकी पुलिस क्या कर रही है ?

श्री अमरजीत भगत :- इसमें पकड़ में आ रहे हैं तब तो पता चल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- पकड़ में क्यों आ रहा है ?

श्री अमरजीत भगत :- आप वहां से सप्लाई बंद करवाईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यहां तक कैसे पहुंच जाते हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- आप वहां से सप्लाई बंद करवाईये। जब यहां पकड़ा जा  रहा है तब तो पता चल रहा है। आपके समय में तो नहीं पकड़ा जाता था, हमारे समय में पकड़ा जा रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भैय्या, हमारे समय में किसी की ताकत नहीं थी जो यहां तस्करी करके लाये। कोचियों को घर में बैठा दिया था। कोचियां की यू-यू (हाथ से ईशारा) होती थी। मंत्री जी, कोचियों की यू-यू होती थी।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी, डिस्टलरी से बिना होलोग्राम के कितना माल निकल रहा है ?

श्री रामकुमार यादव :- हमर सरकार हे तब तो पकडत हे। देश के चौकीदार हा का करत हे ? चौकीदार मन सब्बो ला बुलका डारत हे।

श्री अमरजीत भगत :- मुझे मालूम है कि आपने टेस्ट के बारे में बोला था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, आज यह हालत हो गई है कि, माननीय मंत्री कवासी लखमा जी, आपको मालूम है कि गांवों में क्या हो रहा है ? पान डिब्बों में बच्चों को कप में शराब पिलाकर उनकी आदत डाली जा रही है।

श्री कवासी लखमा :- यह तो असत्य है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलो दिखा देता हूं।

श्री कवासी लखमा :- यह गलत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मन्दिर हसौद में आ जाओ। मन्दिर हसौद की महिलाएं आपको बता देंगी।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय सभापति जी, बिना तथ्यों के अनर्गल आरोप लगाये जा रहे हैं। लगातार आपत्तिजनक बातें की जा रही हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पाऊच में दारू बेचने की आदत किसने डाली ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :-माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भी बोल रहे हैं। इनका [XX][7] करवाईये।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसका [XX] कराओगे ? आप किसका [XX] कराने की बात कर रहे हो ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुछ भी बोले जा रहे हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, नहीं किसका [XX] कराने की बात कर रहे हो ? आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी का [XX] करा सको।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गलत बात है।

श्री सौरभ सिंह :- प्रजातन्त्र में हम सब जीतकर आये हैं। कोई किसी का [XX] नहीं करा सकता।

श्री शिवरतन शर्मा :- किसकी [XX] कराने की बात आप कर रहे हो । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गलत बात है । (व्यवधान)

---

[7] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।



अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री सौरभ सिंह :- प्रजातंत्र में हम सब जीत कर आये हैं । किसी का कोई [XX][8] नहीं करा सकता । व्यवधान आप [XX] नहीं करा सकते । जो सदस्य यहां जीतकर आये हैं उन्हें बोलने का अधिकार है । आप किसी का [XX] नहीं करा सकते । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी घ्रुव :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, पाउच की शुरूआत किसने की ?

श्री सौरभ सिंह :- कैसे [XX] करा सकते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांत रहियेगा । शर्मा जी । (व्यवधान) अजय भाई । व्यवधान आप लोग शांत बैठियेगा । मंत्री जी आप भी बैठिये । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] कराने वाली बात है । आप कैसे [XX] करा सकते हो । हम सदन में जीतकर आये हैं ।

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी धुव :- सभी को बोलने का मौका मिलना चाहिये । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- [XX] करा दोगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माफी मांगे । तुरन्त माफी मांगे । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने ...(व्यवधान) पाऊच में देने का काम किया ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मैडम आप चुप रहिये ।

श्री सौरभ सिंह :- बोलने की हिम्मत है तो बताओ ।

उपाध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी आप चुप रहिये । उस शब्द को कार्यवाही से विलोपित की जाती है ।

श्री सौरभ सिंह :- किसी की हिम्मत है तो रोक लो । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- सौरभ भाई, शब्द विलोपित कर दिया गया है ।

श्री सौरभ सिंह :- जनता ने बोलने के लिए भेजा है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- असत्य कथन न करे । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :-शब्द विलोपित कर दिया गया है ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नाराज होने की जरूरत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य :- यह क्या व्यवहार है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- सुनिये, पहली बात तो आप लोग हस्तक्षेप मत करिये । इसी का परिणाम है, यह सारी चीजें हो रही है । माननीय सदस्य से निवेदन है कि पांच मिनट बोलकर समाप्त करें । (व्यवधान) विलोपित कर दिया गया है । उसके बाद आप लोग सारी चीजें कह रहे हैं, क्या मतलब ?

[8] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरे [XX][9] करवाने की बात की है । मैं अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, अजीत जोगी जी, मोतीलाल वोरा जी, श्यामाचरण शुक्ला जी, इन सबके कार्यकाल में मैं विधायक रहा हूँ और अभी तक किसी ने [XX] करवाने की बात नहीं की और न वो [XX] करवा पाये । मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, [XX] नहीं करवा पायेगा । माननीय मंत्री जी ने अगर कुछ कहा है । आपने विलोपित कर दिया, वह अगर माफी नहीं मांगते हैं तो तो यह उनके विवेक पर छोड़ दीजिए । अगर उचित लगता है तो अपनी बात वापस ले लेंगे । माननीय उपाध्यक्ष जी ने उसको विलोपित कर दिया है । (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बृजमोहन जी की बात ..(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये बैठिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे विधान सभा क्षेत्र में भाटागांव में, जमोलाभाटा में, मठपुरैना में, संतोषी नगर में, राजेन्द्र नगर में, पान डिब्बों में शराब बिक रही है, अगर आपकी ताकत है तो उसको रोक दो । मैं पुलिस को खबर करता हूँ । मैं उनको बताता हूँ, मैं बेचवा रहा हूँ । मेरे खिलाफ कार्यवाही करो, मैं बेचवा रहा हूँ । सरकार आपकी है । मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्कूल के बच्चों कों चाय के कप में पिलाया जा रहा है। माननीय सदस्यगण यह सबके क्षेत्र में हो रहा है। अवैध दारू बेचने वाले लोग अपनी शराब खपाने के लिए..।

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इनकी पूरी बात को निकाल दीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी।

श्री कवासी लखमा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय वरिष्ठ सदस्य का हम सम्मान करते हैं। अभी मध्यप्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है। कोई भी असत्य बात को एक बार बोलना चाहिए, उसको 10 बार बोलते रहेंगे।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- तैंहा, बोलत के टाइम में बोलत नई हस, अलकरहा आदमी हस तैं।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पहली बार बोल रहा हूं। थोड़ा दो मिनट सुन लीजिए। यह हर बात में आपकी सरकार में ऐसा हुआ, मध्यप्रदेश में वैसा हुआ। अगर मध्यप्रदेश में नंगा नाच हो रहा है तो क्या आप भी नंगा नाच करोगे। वह वही कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में नंगा नाच मत होने दो। छत्तीसगढ़ में यह गलत काम मत होने दो। उसमें बुरा लगने की क्या बात है? वह आपको फिगर फैक्ट नाम सहित बता रहे हैं। आपका नैतिक धर्म है कि अभी आप सदन के बाहर जाईये और वहां से मोबाईल में अपने अफसरों को बोलिये रेड करें।

---

[9] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल जी के अलावा अन्य किसी भी सदस्य का भाषण रिकार्ड नहीं किया जायेगा। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी को 5 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX][10]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कवासी जी, मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप कोई चीज समझेंगे। यह व्यवस्था है।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आज आप मंत्री हो, कल मैं मंत्री था।

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री धर्मजीत सिंह :- [XX]

श्री अमरजीत भगत :- [XX]

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जरा हमको छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य..

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ मेरा ठेका है। मेरा ठेका है। अगर आप ठेका नहीं लोगे तो मैं ठेका लूंगा। मुझे सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो मैं सड़कों पर उतरूंगा। मैं आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करूंगा। माननीय कवासी जी, जिस दिन ये विधायक सरकारी दुकानों में जाकर शराब का स्टाक चेक कर लेंगे, उस दिन सरकार बेनकाब हो जायेगी, कितनी एक नंबर की दारू बिक रही है, कितना दो नंबर की बिक रही है। कुछ परंपरायें हैं।

श्री अमरजीत भगत :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, कोई भी सरकार हो, अर्जुन सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, श्यामाचरण शुक्ल जी, मोतीलाल वोरा जी, अजीत जोगी जी भी हमारी बात सुनते थे। रमन सिंह जी भी सुनते थे। जो लोग समझदार लोग हैं

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- [XX]

---

10 [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अरूण वोरा :- [XX] [11]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो समझदार लोग हैं, उन्होंने हमेशा हमारी बातों को सुना है। हमने ऐसी संसदीय परंपराओं में काम किया है।

श्री देवेन्द्र यादव :- [XX]

श्री कवासी लखमा :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है कि हम लोगों ने मध्यप्रदेश की विधान सभा में ऐसी परंपराओं में काम किया है कि ऐसे आमने-सामने बैठते थे और एक-दूसरे से इस्तीफे की चैलेंज होती थी। एक दूसरे के खिलाफ तीखे भाषण होते थे और उसके बाद सदन खत्म होने के बाद गले में हाथ डालकर मुख्यमंत्री बोलते थे कि बृजमोहन पैसा कमाने के लिये भ्रष्टाचार करना जरूरी नहीं है। मैं उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा, ऐसे संबंध होते थे। कभी वहां की विधान सभा में, आप भी देखिये 15 साल हम मंत्री रहे हैं, आप लोगों ने तीखे हमले किये हैं, क्या हमने कभी बुरा माना ? क्योंकि विधान सभा के अंदर जो कुछ होता है वह पद के विरूद्ध होता है, व्यक्ति के विरूद्ध नहीं होता। हर स्थिति में कभी किसी को, कभी मंत्री को विपक्ष के लोगों के द्वारा कही गयी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिये। यद पद के कारण है, कवासी लखमा जी आज आप मंत्री हो, तो हम बोल रहे हैं, मोहम्मद अकबर जी मंत्री है, तो हम बोल रहे हैं।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- [xx]

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल जी समाप्त करिये। हो गया 5 मिनट में समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जी, आपका आग्रह है तो मैं 5 मिनट में समाप्त कर देता हूं। नहीं, बहुत सारी बातें यहां पर...

उपाध्यक्ष महोदय :- जी, अब इधर से उधर, ठीक है बोलिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज छत्तीसगढ़ के नौजवानों को बड़े-बड़े सपने दिखाये कि हम 10 लाख लोगों को किसी न किसी प्रकार प्रतिवर्ष रोजगार में लगायेंगे और नहीं तो हम उनको 2500 रूपये प्रतिमाह भत्ता देंगे। अभी आज के ही प्रश्नों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि 20 हजार लोगों को रोजगार मिला है, वह 20 हजार में से भी 4 हजार लोग 2018-2019 की भर्ती के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 3 साल में सिर्फ 13 हजार लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। बड़ी-बड़ी बातें करने से नहीं होगा।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- [xx]

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो अब ठीक है।

---

[11] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, हां मैं तैयार हूं] आपने रोजगार दिया है, नौजवानों को गोबर बिनने का, लोगों को शराब बेचने का, लोगों को अफीम बेचने का, लोगों को गांजा बेचने का, (शेम-शेम की आवाज) चाकू मारने का।

श्री अमरजीत भगत :- [xx] [12]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप ही ने पूछा न कि कैसे रोजगार दिया। मैं आपको बता रहा हूं।

श्री अमरजीत भगत :- [xx]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। आपने लूट करने का रोजगार दिया है और क्या शायद इन्हीं आंकड़ों को आप रोजगार बोल रहे हैं ? आप इन्हीं को रोजगार बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का नौजवान इन कामों में लगे। हमने पहले कहावत सुनी थी कि रेत में से तेल निकलता है पर आज हमने साक्षात देख लिया कि रेत में से तेल कैसे निकलता है।

श्री अजय चंद्राकर :- [xx]

श्री अमरजीत भगत :- [xx]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्यों, रेत माफिया खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या मैं करवा रहा हूं ?

श्री अमरजीत भगत :- [xx]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- धमतरी जिले में जिला पंचायत प्रतिनिधि को पीटा गया, मैंने पीटा ? महासमुंद जिले में कलेक्ट्रेट में घुसकर खनिज अधिकारी के कक्ष में गाली-गलौच, मार-पीट की गयी, मैंने की ? बालोद में अवैध रेत उत्खनन को रोकने गये पुलिस वालों को चाकू मारा गया, वह मैंने किया ? तहसीलदार को चाकू लेकर दौड़ाया, वह मैंने किया ?

श्री अजय चंद्राकर :- [xx]

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- [xx]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारी विधायक जी का पति, अवैध रेत की ट्रक को रोकता है तो उस विधायक के पति के ऊपर में मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसको जेल जाना पड़ता है और एस्ट्रोसिटी एक्ट लगती है।(शेम-शेम की आवाज) अवैध का उत्खनन रोकने के लिये मुख्यमंत्री जी ने फरमान जारी किया, वह फरमान जारी होने के बाद क्या हुआ ? जरा बताओ न, क्या एक भी रेत की खदान में छापा मारा गया, एक भी, एक भी, एक भी ? रेत की खदान कौन चला रहा है, वहां पर पास क्यों नहीं कट रहे हैं, वहां पर लोड़िंग का क्या लिया जा रहा है, वहां पर लॉयल्टी का क्या लिया जा रहा है ? वहां पर रायल्टी का क्या लिया जा रहा है?ट्रांसपोर्टिंग वाले ट्रक वाले को पकड़े रहे हो, क्यों भईया? आप यह बताईये। आप खदानों में छापे क्यों नहीं मार रहे हो?

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

---

[12] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- [XX] [13]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जो रेत खनन कर रहे हैं, वह कौन लोग हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी, समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि मैं अपनी बात 5 मिनट में समाप्त कर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- 5 मिनट हो गया। मैं घड़ी देख रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस है। 20 हजार महिला स्वसहायता समूहों को रेडी टू ईट का अधिकार छिनकर 5 हजार करोड़ रूपये का काम बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। ऐसे ही महिला दिवस मना रहे हैं। ऐसे ही महिला दिवस की बधाई दे रहे हैं क्यों भईया, क्यों महिलाओं का रोजगार छिन रहे हो? यह कौन से नियम, कायदे, कानून में है ? क्या ऐसे ही महिला दिवस मनाओगे। ऐसे ही महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करोगे? बीस हजार परिवार मतलब एक लाख लोगों का जीवनयापन रेडी टू ईट के माध्यम से होता है। क्यों? हर चीज में यह चाहिए।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इसे जो देगा, उसी को काम मिलेगा। बाकी को काम नहीं मिलेगा। मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। अगर मैं उन मुद्दों पर बोलूंगा तो शायद आप रातभर भी बैठेंगे तो यह पूरा नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अंत में कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के आवास का क्या हुआ? इस प्रदेश में क्यों लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं? गरीबों की छत छिनने के लिए कौन दोषी है? आपने राज्यपाल महोदया जी से कहलवा दिया। लगभग 18 लाख लोगों के आवास की स्वीकृति बंद हो गई है। लगभग 5 लाख लोगों के आवास अधूरे पड़े हुए हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा?यह पहली बार हुआ है कि प्रदेश की हजारों नगर पंचायत, नगर पालिकाओं के बिजली के कनेक्शन काट दिये गये। 20 सालों में यह कभी नहीं हुआ। स्कूल, शासकीय अस्पतालों में बिजली के कनेक्शन काट दिये गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सरकार है अगर मैं दूसरी भाषा में कहूं तो यह पलटू सरकार है। यह पलटू सरकार है। इन्होंने बैरियर का विरोध किया, बेरियर खोल दिया। रिटायर्ड कर्मचारियों को संविदा नहीं दी जायेगी, उनको संविदा देना शुरू कर दिया।

श्री रामकुमार यादव :- [XX]

[13] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित किया गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, प्लेसमेंट में नौकरी नहीं दी जायेगी, एक लाख लोग प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं। रेत खदान निगम चलायेगा, अब प्राईवेट ठेकेदार को दे दिया। यह सरकार जो है, इन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे, पर इस प्रदेश में रखना शुरू हो गया। तो यह पलटू सरकार है यह अपने वायदों से पलट रही है। यह किसी भी वायदों को पूरा नहीं कर रही है। मैं अंत में कहना चाहूंगा कि यह सरकार वनवासी विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, अभी सोसायटियों के चुनाव हुए, उन चुनावों में आदिवासियों को सोसायटियों का डायरेक्टर बनना था, 212 सोसायटियों में सामान्य वर्ग के लोगों को डायरेक्टर बना दिया गया। यह अपने आपको छत्तीसगढ़िया सरकार बोलती है। यह अपने आप को आदिवासी की सरकार बोलती है। चुनाव अधिकारियों ने उनको जीतने का सर्टीफिकेट जारी कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा। क्या हो रहा है वनवासियों के अधिकार को मारने वाली सरकार, नौजवानों को नशों में डूबोने वाली यह सरकार, किसानों को लूटने वाली सरकार, महिलाओं की आबरू ईज्जत को बचाने में असफल होने वाली सरकार, ऐसी सरकार को एक मिनट भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदया के मुंह से जो गलत बातें कहलवायी गईं हैं, हम उसका विरोध करते हैं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के लिए है आगे दिन पाछे गये गुरू से न किये भेद, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 15 साल में कुछ नई करव, अब पछतावव।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवद देता हूं। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी...।

श्री अजय चंद्राकर :- आपको बोलने के लिए कौन-कौन से विभाग का डाटा मिला है, यह बताईए। कौन-कौन से विभाग का कागज मिला है या अपने मन से बोलोगे।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देखिए किस तरह से सम्मानित सदस्य को बोलने नहीं दे रहे हैं और इसके बाद बोलते हैं कि नियम कायदे कानून का पालन किया जाए।

श्री अरूण वोरा :- माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, बहुत ही वरिष्ठतम सदस्य हैं, मुझे मध्यप्रदेश की विधानसभा में इनके साथ काम करने का मौका मिला लेकिन मैंने कभी नहीं देखा है कि बृजमोहन अग्रवाल जी इतने उत्तेजित हुए और उन्होंने इतना असत्य कथन कहा। आज वे नहीं कह रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल की आवाज हो सकती है लेकिन मेरे को लगता है कि इसके पीछे अजय चंद्राकर जी हैं। आपकी कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। बृजमोहन अग्रवाल जी ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दोनों झन के सांट-गांठ हे।

श्री अरूण वोरा :- मै सांट-गांठ नहीं मानता, वे सीधे सज्जन आदमी हैं। उनको 15 साल पहले मुख्यमंत्री बनना था। आपने कितना असत्य कहा, यह आपकी अंतर्आत्मा जानती है और आपने कितना झूठ का पुलिंदा प्रस्तुत किया, इसको प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। अजय चंद्राकर जी लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 15 साल के शासन को समाप्त कर प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास व्यक्त किया और कांग्रेस में सत्ता की बागडोर भूपेश बघेल जी के हाथ में आई। आप लोगों ने जो जो काम 15 साल तक नहीं किया उस काम को उन्होंने मात्र 3 घंटे में करके दिखलाया है। मैं भी उस विधानसभा में था और मैं रोज सुनता था, मुझे बोलने का अवसर आता था तो बोलता भी था कि प्रतिदिन मुख्यमंत्री के क्षेत्र में आपके क्षेत्र में किसान कर्ज के कारण और धान का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा करके आत्महत्या कर रहे थे। धर्मजीत भाई, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने और शपथ लेने के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में यह पहला अवसर है कि कोई भी मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद मंत्रालय गए, उन्होंने किसानों के बारे में चिंता की और उसमें हस्ताक्षर किए। आज किसान कितने खुश हैं, खुशहाल हैं। इसका अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं लग सकता जो योजनाएं कागजों में चल रही थी वह अब धरातल में चल रही है।

श्री धर्मजीत सिंह :- हम लोग तो किसान है ही नहीं तो हम लोगों को अंदाजा कहां से लगेगा ?

श्री अरूण वोरा :- आप यहां पर किसानों की तो बात करते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप सुन लीजिए, किसान सिर्फ भाजपा वाले हैं, उसमें जो लिस्ट जारी किया है, कांग्रेस वाले किसान नहीं हैं । आपने जो लिस्ट जारी की है उसमें भाजपा वालों का नाम है। हम लोग धान बेचे हैं, इन लोग जो बैठे हुए हैं, एक भी किसान नहीं हैं।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भाई, बहुत सीनियर हैं, वे किसान भी हैं, लेकिन किसानों के बहुत बड़े हितैशी हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय उपाध्यक्ष जी, इधर देखकर मत बोलिए, आसंदी की तरफ देखकर बोलिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- रामकुमार जी, धान नई बेचय, खाली गोबर बेचत हे।

श्री अरूण वोरा :- धर्मजीत भाई, आप तो काफी सीनियर हैं। आप किसान नहीं हैं लेकिन किसानों के जबर्दस्त हितैशी हैं। आप किसानों के हित में बोलते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- रामकुमार हा गोबर नई बेचत हे यूरिया बेचत हे।

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं किसान हूं और सिर्फ किसान हूं। बाकी मेरे पास कुछ नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- मोला गर्व हे। मैं तुहर मन असन ठगवा गौंटिया नइ हव। मैं गरीब हव मैं छाती ठोक के कथव मैं गरीब हव।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर इन्होंने 15 सालों में कुछ काम किया होता तो 15 सीट में क्यों सिमट गये होते। कागजों में कार्य दिखा है। आपने पूरा कांक्रीट का जंगल बना दिया। प्रदेश की जनता को ठग दिया। आपने केवल ठगने का काम किया है। बृजमोहन अग्रवाल जी अभी पलटू सरकार बोल रहे थे।

श्री अजय चंद्राकर :- आप वाईसेप फ्लाईओवर में नहीं चलते हैं।

श्री अरूण वोरा :- मैं चलता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आरोप है, आप बार बार छेड़िए मत।

श्री अरूण वोरा :- उपाध्यक्ष महोदय, जन आकांक्षाओं की कसौटी में हमारी सरकार खरा उतर रही है। माननीय राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया वह बिल्कुल सत्य है और वहीं योजनाएं पूरे प्रदेश में कारगर हो रही है और क्रियान्वित हो रही है। आपने योजनाएं तो बनाई लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं किया। हमारी सरकार क्रियान्वयन कर रही है। आपको इसको समझना चाहिए। हर बात में आलोचना कर रहे हैं। आप राज्यपाल जी का कितना सम्मान करते हैं, राज्यपाल जी के अभिभाषण में दिख गया। आपने इतनी टोका टाकी की...।

उपाध्यक्ष महोदय :- वोरा जी, इधर देखकर बात करिए।

श्री अरूण वोरा :- जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जितनी टोका टाकी की है उतनी हमने कभी मध्यप्रदेश में देखी है न छत्तीसगढ़ में देखी है। सबसे बड़ी बात संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। 1971 में जो शहीदों के नाम से दिल्ली में जो अमर ज्योति जल रही थी उसको बुझाने का काम किया है । आप यह नहीं जानते हैं कि देशवासी आपकी सरकार को ही बुझा देंगे । अमर शहीदों के कितने परिवारों को आपने दुख पहुंचाया है इसका अंदाजा आपको नहीं है और वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहां नये रायपुर में अमर ज्योति जिसका माननीय राहूल गांधी जी के माध्यम से शिलान्यास करवाया ।

श्री अजय चंद्राकर :- बहुत सुंदर ।

श्री अरूण वोरा :- केवल सुंदर नहीं इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा । सुंदर बोल देने से सुंदर नहीं होता, आपकी हकीकत को जनता अच्छी तरह से जान गई है और अभी आप बोल रहे थे कि किसने लिखकर दिया है तो लिखकर नहीं दिया है । माननीय राज्यपाल जी ने जो कहा है उसी को मैं कहना चाहता हूं कि तीन साल में हमारी सरकार ने जनहितैषी निर्णय लिये हैं, कल्याणकारी कार्य किये हैं । जो कार्य आपने 5 सालों में नहीं किया, भाजपा के शीर्ष नेता, आपके नरेंद्र मोदी जी भी छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ कर रहे हैं । आप बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल आयेगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा हो रही है और आप

उत्तरप्रदेश की बात करते हैं । मैं भी उत्तरप्रदेश गया था और मैंने इस बात को महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी से अब पूरी तरह से लोगों का मोह भंग हो चुका है । आप यह मानकर चलिये कि... ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- आपने अभी जो पढ़ा वह क्या चीज है, आप थोड़ा सा स्पष्ट बता देते तो हम लोगों को समझ में आ जाता ।

श्री अरूण वोरा :- मैं छत्तीसगढ़ मॉडल के बारे में कह रहा हूं । क्या आपने माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को नहीं सुना है ? आपको सुनना चाहिए। आप जब सदन में आते हैं तो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण को सुनिये ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- वह तो झूठ का पुलिंदा था ।

श्री नारायण चंदेल :- वोरा जी, आप मन छत्तीसगढ़ के मॉडल ला थोड़ा बगराओ न ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मॉडल को बगराता हूं । क्या आपने कभी किसानों के बारे में सोचा, क्या आपने कभी युवाओं और महिलाओं के बारे में सोचा ? हमारी सरकार ने सबसे पहले किसानों के बारे में सोचा । राजीव गांधी किसान न्याय योजना इसका कितना लाभ किसानों को मिल रहा है ? गौधन न्याय योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना ऐसी महती अनेक मॉडल योजनाएं हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप बजट को पढ़ रहे हैं तो रहने दीजिए ।

श्री अरूण वोरा :- देखिए, अब आपको भी सीख लेनी चाहिए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में एक-तरफ जहां किसान परेशान है, वहां हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सर्वाधिक धान की खरीदी कर अन्नदाताओं के हित का ध्यान रख रही है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही 61 वनोपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी कर सुदूर क्षेत्रों के आदिवासी क्षेत्रों के निवासियों को आर्थिक रूप से सशक्तीकरण करने में एक नयी दिशा दे रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, न केवल धान की खरीदी बल्कि गन्ना-मक्का समेत 14 फसलों के किसानों को सरकार सीधे आर्थिक मदद देने हेतु प्रतिबद्ध है । गौठानों में अब खाद, गोबर के दिये एवं कण्डों का उत्पादन प्रारंभहोने से हमारे गौठानों में भी लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने इस बात को कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में 1735 करोड़ की चिराग योजना भी आने वाले समय में अन्य राज्यों के आदिवासी उत्थान के लिये एक मॉडल बनेगा तो आप जो पूछ रहे थे न कि क्या मॉडल है तो छत्तीसगढ़ का मॉडल यही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि अभी माननीय राहूल गांधी जी आये थे, भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 6000 की घोषणा कर प्रथम किस्त समस्त हितग्राहियों को प्रदान करते हुए गरीबों के प्रति अपनी संवेदना सरकार ने स्पष्ट कर दी है ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की परंपरा व संस्कृति के संवर्धन के साथ ही आदिवासी नृत्य महोत्सव चौमासा कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान को भी कायम करने का कार्य राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है । कोरोना काल में जहां केंद्र की सरकार ने किसी भी तरीके से मदद देने से इंकार कर दिया था वहीं हमारी सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, माननीय भूपेश बघेल जी ने सभी विधायकों से एक बात कही कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के लिये पैसा देने के लिये मना कर दिया है । क्या आप विधायक लोग अपनी 2 करोड़ की राशि उसमें देंगे ? केवल भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी कांग्रेस के विधायकों ने कहा कि हम 2 करोड़ रूपये की राशि अपनी विधायक निधि वैक्सीन के लिये देंगे और उसी राशि से वैक्सीन की खरीदी की गयी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- क्या यह बात सत्य है ?

श्री अरूण वोरा :- एकदम सत्य है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- असत्य है । कोरोना काल में कितना-कितना बजट दिये हो, जरा उसका उल्लेख कर लीजिए । कितना बजट दिये हैं, जरा बता दीजिये ।

श्री अरूण वोरा :- भाजपा के सदस्यों ने उसका इंकार किया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है यह हर कोई जानता है ।

उपाध्यक्ष महोदय :- डॉ. साहब आप बैठिए । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इन लोगों ने छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं दिया । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अभी 14 सदस्यों को और बोलना है, आप लोग बैठिए । चलिये, वोरा जी आप समाप्त करियेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, अभी तो वोरा जी शुरू किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- इसके बाद अब सबको 10 मिनट दिया जायेगा।

श्री अरूण वोरा :- मैंने तो एक बात एकदम सार में कह दी है कि अगर आप कुछ किये होते तो आज वहां नहीं होते। 15 में नहीं आते। आप आने वाला समय देखिए। आने वाले समय में आप 10 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पायेंगे। यह आपके जो क्रियाकलाप हैं, वह बतलाते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- थैंक यू। शिवरतन शर्मा जी। 10 मिनट।

श्री कवासी लखमा :- जितना ये बोले हैं उतना ही टाइम इनको भी देना है। इतना लंबा मत बोलो।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के पश्चात् वर्ष 2019 में राज्यपाल का पहला अभिभाषण इस सदन में हुआ था और अभिभाषण के पांचवें

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पैरे में इस बात का उल्लेख था कि वर्ष 2018 के जनघोषणापत्र को सरकार आत्मसात् करती है। वर्ष 2019 का अभिभाषण पहला अभिभाषण था और वर्ष 2022 का माननीय राज्यपाल महोदय का चौथा अभिभाषण है। अब इस सरकार के पीरियड में एक अभिभाषण और होगा। मैं आज आपके सामने आप सबको चुनौती देते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि आपने जनघोषणापत्र को आत्मसात किया।

श्री कवासी लखमा :- क्या चुनौती भाई ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके प्रदेश के अध्यक्ष जो इस सदन के सदस्य भी हैं, आपकी सरकार के मंत्री बाहर भाषण देने जाते हैं तो बोलते हैं कि हमने जनघोषणापत्र के 36 वादों में 24 को पूरा कर दिया।

श्री अरूण वोरा :- 28

श्री शिवरतन शर्मा :- अब अरूण वोरा जी 28 बोल रहे हैं और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का इसी सदन में प्रश्न लगा है और उस प्रश्न में इनका कहना है कि हमने 36 में 17 को पूरा किया। तो पहला तो यह सरकार ही confuse है कि 17 पूरे हुए या 24 पूरे हुए या 28 पूरे हुए। पर मैं आपके माध्यम से सरकार के सारे मंत्रियों को चुनौती देता हूं कि कहीं भी वह चर्चा कर लें, इनने 36 में एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जनघोषणापत्र में जो बातें कही गई थीं, उसको एक भी पूरा नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता को छलने का, छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम इन्होंने किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं सीधा जनघोषणापत्र के ऊपर ही अपनी बात रख रहा हूं, जिसे इन्होंने आत्मसात किया है। बार-बार एक बात आती है। आज भी सदन में कहा गया कि अजय चन्द्राकर को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या किसान का पूरा कर्ज माफ हो गया। इस सदन में मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि 96 हजार किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो किसान अल्पकालीन ऋण लेते हैं, उन किसानों का 40 प्रतिशत कर्ज माफ हुआ। 60 प्रतिशत कर्ज किसानों को पटाना पड़ रहा है। कुछ किसानों को तो राष्ट्रीयकृत बैंक के किसानों को कर्ज माफी की सूचना आ गई और दूसरे साल ब्याज सहित उन्हें कर्ज पटाना पड़ा। मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण जो किसान लेता है, उसकी तो कहीं कर्ज माफी हुई नहीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा विषय..।

श्री द्वारिकाद्वीश यादव (खल्लारी) :- शिवरतन भैया, आपकी चुनौती में एक बात और शामिल कीजिए। 15 साल में आपकी सरकार में कितने किसानों का और कितनी राशि की कर्ज माफ हुई और हमारी सरकार में दो घंटे में कितने हजार करोड़ कर्जामाफी की प्रक्रिया की शुरूआत हुई, इसे भी आप सदन में बताइए न। ज्यादा अच्छा हुआ और फायदा हुआ। दो घंटे में कर्जा माफ हुई।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- यादव जी, किसानों के साथ ऐसा झूठ बोले हो, उसे बताइए। सिम्पल बात, साधारण बात है। आप चुनौती को स्वीकार करो। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- मैं चुनौती देवत हों। जावव जंगल के भीतरी में, जरसी गाय दूहू कहे रहव, जरसी गाय अउ सांड वाले मन खोजत हे तुमन ला। (व्यवधान)

शिवरतन शर्मा :- आप इनका समय जोडिए। ये डिस्टर्ब कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं, मैं गिन रहा हूं कि 10 मिनट कब हो रहा है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप 10 मिनट गिनिए मत। ये जो बोल रहे हैं, उसे भी आप देखते रहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, किसानों के कर्ज माफ के नाम पर किसानों के साथ धोखा।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- शर्मा जी, असत्य बोलने की ट्रेनिंग आप कहां से लिये थे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- उपाध्यक्ष जी, इनके पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी जी का आपके ज़िले में ही भाषण हुआ था । यदि आप कहेंगे तो उसकी क्लिपिंग सदन में रखने को तैयार हूं । किसान का एक-एक दाना धान खरीदेंगे । 15 क्विंटल की सीमा समाप्त करेंगे । क्या आपने 15 क्विंटल की सीमा समाप्त कर दी ? क्या आप किसान का पूरा धान खरीद रहे हैं ? जन घोषणा पत्र की तीसरी बात ।

श्री रामकुमार यादव :- महाराज छत्तीसगढ़ मा परम्परा हे कि हमन जम्मो धान न नइ बेचन, कुछु खाए गर कोठी मा घलो राखथन ।

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- क्या 15 लाख रूपए सबके खाते में आए हैं, क्या अच्छे दिए आए हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या सबका बिजली बिल आधा हो गया । सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि हमने 40 लाख लोगों का बिजली बिल आधा किया है, जबकि इस प्रदेश में 70 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन हैं । 30 लाख लोगों का बिजली बिल आधा नहीं हुआ । घर-घर रोज़गार, हर-घर रोज़गार, 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे । ढाई हज़ार रूपए बेरोज़गारी भत्ता देंगे । आज मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 3 वर्षों में वित्त विभाग ने 40,035 पदों पर भर्ती की स्वीकृति प्रदान की है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उसके विरूद्ध 11 हज़ार लोगों की भर्ती हुई है । 3 साल में पूर्व में वित्त विभाग में स्वीकृति के आधार पर कुल 20 हजार लोगों को नौकरी दी गई है । दूसरी ओर मुख्यमंत्री जी का सार्वजनिक भाषण होता है । 2 लाख, 80 हजार लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं । झूठ बोलने में महारत, पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हो और केवल प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं कर रहे हो, अपने नेताओं को भी गुमराह कर रहे हो । उपाध्यक्ष जी, मैं जो बात बोल रहा हूं वह ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं ।

श्री कवासी लखमा :- मोदी साहब ने तो 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही थी, 2 लोगों को भी मिली है क्या ।

श्री बृहस्पत सिंह :- असत्य बोलने में मोदी जी की नकल कर रहे हैं, ऐसा लगता है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- इतना असत्य मत बोलिए, मुख्यमंत्री कभी झूठ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी की बात पूरे प्रदेश में जाती है, मुख्यमंत्री जी की बात कानून होती है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ का कहना है, कका है तो भरोसा है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- खाद्य सुरक्षा का अधिकार । अमीर हो, ग़रीब हो, प्रत्येक परिवार को 35 किलो चावल, 1 रूपए से देंगे । यह योजना कहीं चल रही है, जहां प्रत्येक परिवार का राशन कार्ड बन रहा है, वह केवल कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है । वह कवर्धा विधान सभा क्षेत्र में बन रहा है तो उसका श्रेय अकबर साहब को कम है और उसका श्रेय विजय शर्मा को है जिसने खाद्य अधिकारी का घेराव किया और उसके चलते उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन बाकी 89 विधान सभा क्षेत्रों में 1 रूपए वाले राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं । एपीएल के राशन कार्ड बन रहे हैं, आप स्वयं खाद्य मंत्री हैं, आपने ही प्रश्न के उत्तर में स्वीकार किया है कि 12 लाख से ज़्यादा एपीएल के कार्ड हैं । मतलब, जब आपने अपने घोषणा पत्र में कहा कि प्रत्येक परिवार को चावल देंगे तो उनका कार्ड क्यों नहीं बना ?

श्री अमरजीत भगत :- यहां तो यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लागू है । केवल गरीबों को ही नहीं, बल्कि जो मांगेगा उसको देंगे तो इसमें आपको क्यों दिक्कत है ? आप भी कार्ड बनवाओ ।

श्री रामकुमार यादव :- आपकी सरकार में चुनाव के पहिली बनत रहिस हे । याद करौ वो समय ला ।

श्री शिवरतन शर्मा :- हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी विदेश गए थे । यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लेकर आएंगे । सवा तीन साल बीत गया, कहां है वह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम। स्वास्थ्य के अधिकार के अंतर्गत कितने लोगों को उपचार मिला । आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो उपचार होता था, आप उसको भी रोक रहे हैं । क्या हुआ आपके जन घोषणा पत्र का । शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार आपकी देन नहीं है । शिक्षा के अधिकार पर बड़ी बहस हुई है ।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- शर्मा जी, मैं आपको धन्यवाद् देना चाहूंगा कि आप कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं। 15 सालों में आपने कभी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र पढ़ा था (मेजो की थपथपाहट)।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप एक काम करो ना, 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल पर चर्चा करने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने के लिए आवेदन दे दो, पूरी चर्चा कर लेंगे ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 15 सालों में कितने स्कूल खुले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल बने (व्यवधान) ।

श्री शिवरतन शर्मा :- शिक्षा के अधिकार की क्या स्थिति है ? शिक्षा विभाग में क्या करप्शन हो रहा है ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी को लोग भूल चुके हैं । अब वह इतिहास में चली गई है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी की ध्यानाकर्षण में एक भी प्रश्न का उत्तर देने में माननीय मंत्री जी सक्षम नहीं थे। ग्रामीण और शहरी आवास का एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया है। मैंने भाषण नहीं दिया है। सभी प्रश्न का उत्तर दिया हूं। आपने सिर्फ भाषण ही किया है, प्रश्न नहीं किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। ग्रामीण और शहरी आवास का अधिकार और उसमें तो यह बातें और कहीं गई थी कि पांच सदस्यीय परिवार को घर एवं बाड़ी हेतु भूमि प्रदान की जायेगी। आप जरा बता दीजिए कि कितने लोगों को घर दिया गया, कितने लोगों को बाड़ी दी गई? देना तो कुछ और बात है। जो प्रधानमंत्री आवास की राशि केन्द्र की सरकार ने दी, उसका आपका राज्यांश नहीं दे सके और उसका राज्यांश नहीं देने के कारण सात लाख लोग आवास से वंचित हो गये हैं। अभी स्थिति यह है कि न ग्रामीण में रोजगार है न शहरी में आवास। शहरी आवास की क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, बंद करियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी तो मैंने शुरू किया है। शहरी आवास की क्या स्थिति है?

उपाध्यक्ष महोदय :- 11 मिनट हो गये हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- शहरी आवास की स्थिति यह है कि कांग्रेस का पार्षद जगदलपुर में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के लिए 25 हजार रूपये रिश्वत लेता है, 40 लोग एफीडेविट के साथ शिकायत करते हैं। वहां के जनप्रतिनिधि, वहां के पार्षद लगातार 20 दिनों तक धरने में बैठते हैं। जगदलपुर नगरबंद का आयोजन होता है। उसके बाद में कोई कर्रवाई नहीं। जब नगरबंद के बाद 400 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देते हैं तब जाकर राज्यपाल के हस्तक्षेप से मामला कायम होता है, गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तार करते है और उसको कोरोना पॉजिटीव दिखाकर हॉस्पीटलाइज कर देते हैं। यह आपके ग्रामीण और शहरी आवास का रिकार्ड है। माननीय मंत्री जी महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रतिबद्धता का एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूं कि महिला सुरक्षा के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। अनुसूचित जनजाति नाबालिक बच्चों के बलात्कार में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। अनुसूचित जाति बच्चों के बलात्कार में पूरे देश में छत्तीसगढ़ का स्थान पांचवा है और बलात्कार में छत्तीसगढ़ का स्थान छठवां है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं

महिलाओं की सुरक्षा का एक उदाहरण बता रहा हूं। और उससे शर्मनाक बात तो यह है कि मंत्री जी चले गये बीच में तो खूब खड़े होते हैं। हाथरस की घटना घटती है।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, अब समाप्त करिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- उसमें प्रेस-कांफ्रेंस लेते हैं और जब प्रेस वाले छत्तीसगढ़ में घटित कोण्डागांव और बलरामपुर की घटना का जिक्र करते हैं, वहां हुई बलात्कार की घटना की बात करते हैं तो मंत्री जी का जवाब रहता है कि कोण्डागांव और बलरामपुर की घटना छोटी है, हाथरस की घटना बड़ी है। बलात्कार तो बलात्कार होता है, इसमें छोटा और बड़ा किस बात का। पर आपके सरकार, आपके मंत्री की संवेदनशीलता कितनी है, यह पता चलता है। शासकीय कर्मचारियों को सम्मान, उनको चार स्तरीय वेतनमान दिया जायेगा। आज छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी, लाखों की संख्या में रायपुर में बैठे हैं। आपने क्या किया है? पुरूष कर्मियों को छुट्टी देने वाले थे, हो गई छुट्टी? उनके लिए आवास की व्यवस्था करने वाले थे, हो गई आवास की व्यवस्था? आवास और छुट्टी तो नहीं मिली। चौक-चौराहों में आपके पार्टी के नेता सार्वजनिक रूप से गाली-गलौज कर रहे हैं, वीडियो क्लिपिंग बनाकर उसको जारी कर रहे हैं और उनको कितना सम्मान मिला उसका एक उदाहरण ले लो कि क्राइम की जो रिपोर्ट है, वह यह कि पुलिस कर्मियों की हत्या की मामले में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। यह सम्मान आप शासकीय कर्मचारियों को दे रहे हो। दैनिक वेतन भोगी, अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, उन सबको आप नियमित करने वाले थे न? शासकीय सेवक के रूप में रखने वाले थे? बता दीजिए कि आपने कितने लोगों को शासकीय सेवक बनाया? दुर्भाग्य की बात तो यह है कि समिति बनती है, उसकी दिनांक 05.09.2020 को बैठक होती है और पौने दो साल में उसके बाद कोई बैठक नहीं होती। बैठक में तीन बिंदु तय होते हैं । विधि विभाग एडव्होकेट जनरल से रिपोर्ट मांगने के लिए लिखता है। डेढ़ साल में एडव्होकेट जनरल की रिपोर्ट नहीं आती है और जब आज बात होती है तो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। वर्ष 2006 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। क्यों जिस दिन जन घोषणा पत्र बना रहे थे, उस दिन क्या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की जानकारी नही थी? आज जब काम नहीं करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन याद आ रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, वृद्धावस्था पेंशन सर्व वृद्ध पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 1 हजार रूपये प्रतिमाह। 75 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 1500 रूपये प्रतिमाह और सर्व विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 1000 रूपये प्रतिमाह।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- अभी दो साल बचा है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- समाज कल्याण मंत्री हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- समाज कल्याण मंत्री जी बैठी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी, बंद कीजिए। समाप्त करियेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने बढ़ा दिया क्या? साढ़े तीन सौ रूपये को एक हजार रूपये कर दिया क्या? आपने 600 रूपये को 1500 रूपये कर दिया क्या? और इसके अतिरिक्त आप यह 1500 रूपये करने के बजाय यह जो विधवा महिलाएं, जिनको डॉ. रमन की सरकार ने बी.पी.एल. के इससे मुक्ति दी थी कि अगर कोई विधवा हो गयी तो सूखत सहारा में बी.पी.एल. में नाम नहीं होगा, तो भी उनको पेंशन दिया जाएगा। वह पेंशन नहीं दिया जा रहा है। स्थिति यह बन गई है कि अब तो धर्मगुरू भी, धार्मिक स्थान भी इस सरकार से अवैध कब्जे से वंचित नहीं हैं। हम सबके लिए गौरव की बात है कि कबीर पंत का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय छत्तीसगढ़ में हैं और दामाखेड़ा उसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है। रायपुर में नेता जी होटल के पीछे कबीर पंत का आश्रम है। कबीर पंत का मुख्यालय...।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, बंद कीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट रख रहा हूं। कबीर पंत के आश्रम के पीछे 8 फीट की रोड, कांग्रेस के एक बड़े नेता बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। अपने भाई की पत्नी के नाम पर। अपने भाई की पत्नी के नाम पर बिल्डिंग बनाना शुरू करते हैं। जो नक्शा पास होता है उसमें इस बात का उल्लेख होता है कि उस बिल्डिंग में चारों तरफ 5 मीटर की सड़क छोड़ी जाएगी। पर 5 मीटर की सड़क छोड़ना तो दूर की बात है इस ढंग से बिल्डिंग बनता है कि कबीर पंत के आश्रम के कीचन के ऊपर उनका स्लेब आ जाता है। जब वहां के आदमी विरोध करते हैं तो उनके साथ दादागिरी होती है गाली-गलोच होती है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- यह संशोधन का विषय है।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां इसका उल्लेख संशोधन में है और उनके साथ गाली-गलोच होती है। जब यह कबीर पंत के अनुयायी विरोध करते हैं हम लोग इस स्पॉट में जाते हैं तो खाली वह गली का कब्जा छोड़ा जाता है। माननीय अकबर साहब के पास लेकर के गये थे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, शैलेष पाण्डेय जी।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब यहां नगर का मुखिया बेजा कब्जा करने लगे।

श्री अमरजीत भगत :- यह संशोधन का विषय है। विषय पर आइये।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। जब नगर के मुखिया कब्जा करने लगे, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता बेजा कब्जा करने लगे और धार्मिक स्थान भी उससे न बचे तो उसकी रक्षा कौन करेगा? कोई कार्रवाई नहीं और यह स्थिति सिर्फ वहां नहीं है। यह स्थिति बहुत से स्थानों में बताना चाहता हूं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने महिला स्व-सहायत समूह का 12 करोड़ रूपये का कर्जा माफ कर दिया। आपसे मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी बैठी हैं महिला स्व-सहायता समूह का कुल कर्ज कितना है?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- पुराना कर्ज का है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर पूरा कर्जा जोड़ोगे तो महिला स्व-सहायता समूह का कर्जा 1200 से 1400 करोड़ रूपये हैं और आपने माफ किया है और आपने कहा है महिला स्व-सहायता समूह का कर्जा माफ किया जाएगा।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- जम्मो ला कर्जा करके भाग गेहो। अभी नहीं छूटाही भई।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने यह कहा है कि महिला स्व-सहायता समूह का कर्जा माफ किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, अब बंद कीजिए। दो मिनट से ज्यादा हो गया न। आपने दो मिनट का समय लिया था।

श्री शिवरतन शर्मा :- 10 मिनट में खत्म कर देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- अरे। बंद कीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, बस-बस। अभी तो बोलना ही शुरू किया हूं सर।

उपाध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, अब 20 मिनट से ज्यादा हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- अब दोनों मंत्री नहीं हैं। 5 साल में...।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- दोनों नहीं हैं बोलो न, काहे चिंता कर रहे हो?

श्री शिवरतन शर्मा :- तोर में अकल कहां हे, ता ते जवाब देबे।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर तो कुछ अकल ए नइ हे न।

श्री शिवरतन शर्मा :- तोर में कुछ नइ हे। ते बइठ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय उपाध्यक्ष जी, जल संसाधन के लिए कहा गया कि सिंचाई का रकबा हम डबल करेंगे। डबल करना तो दूर की बात है जो पुराना रकबा था उसको भी यह सरकार मेंटेन नहीं कर पा रही है। बोधघाट परियोजना 5 साल में पूरी करने की बात थी, आज तक बोधघाट परियोजना का सवा 3 साल में सर्वे तक नहीं हो पाया। फूड पार्क का उल्लेख माननीय बृजमोहन जी ने किया है । अमेठी की सभा में माननीय राहुल गांधी जी का भाषण हुआ । उन्होंने कहा कि मेरे सपनों को पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ की सरकार । अकबर भैया, आप तो बड़े समझदार मंत्री हैं । हम तो आपको विद्वान मानते हैं, आपसे ही निवेदन करते हैं कि चलो, एकाध जिले का फूड पार्क हमको दिखा दो, हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा । फूड पार्क के नाम पर सवा तीन साल में कुछ नहीं कर पाये । लोकपाल विधेयक का क्या हुआ, नक्सल समस्या की क्या स्थिति है ? शराब के मंत्री बैठे हैं । आपके घोषणा-पत्र में शराब बंदी का उल्लेख है । मेरा अशासकीय संकल्प था और जिस दिन उस अशासकीय संकल्प पर चर्चा हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने कभी गंगा जल उठाकर कसम नहीं खाई । जब मैंने

कहा कि आपने यह घोषणा-पत्र प्रकाशित किया है तो उन्होंने स्वीकार किया । सवा तीन साल में शराब बंदी के लिए सिर्फ समिति बनी है, उस समिति के लिए कितनी बैठक हुई, उस समिति ने क्या प्रतिवेदन दिया, शराब बंदी कब की जाएगी ? आप ही बता दीजिए । पंजाब के बारे में कहावत थी कि वह उड़ता पंजाब है । बृजमोहन जी ने नशे के बारे में बहुत विस्तार से बात की है । उड़ता छत्तीसगढ़ बना रहे हैं । माननीय कवासी लखमा जी, घर-घर में शराब बिक रही है । आपने लोगों को 16 पाव का ऑनलाईन परमिशन दे दिया है, उसमें आपने घर-घर कोचिया पैदा करने का काम किया है । शराब सभी जगह बिक रही है, आपके संरक्षण में बिक रही है । आपके पास आबकारी विभाग है इसलिए इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, पत्रकारों के लिए विशेष सुरक्षा कानून । यह विशेष सुरक्षा कानून बन गया क्या ? यह बता दीजिए न । आपके जन घोषणा-पत्र में यह था । आप पत्रकारों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हो । ग्राम सड़क योजना में आप बता दीजिए कि तीन साल में कितने मुख्यमंत्री सड़क योजना स्वीकृत की, आपने कितनी प्रधानमंत्री सड़क योजना स्वीकृत की ? । जल ग्रहण योजना का क्या हाल है, यह आप बता दीजिए । माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इनके जन घोषणा-पत्र की बात कर रहा हूं । आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने किसानों के लिए 35 हजार विद्युत कनेक्शन दिया है । माननीय अकबर भैया, मैं आज चुनौती दे रहा हूं । इस सदन में पिछले बजट भाषण में हमारे निवेदन पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि स्थायी कनेक्शन के 36 हजार आवेदन स्वीकृत हैं, उनको कनेक्शन देंगे । उनको स्थायी कनेक्शन देने के लिए 100 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान था । सभी लोगों को कनेक्शन देने के लिए लगभग 360 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान करना पड़ता । 31 जनवरी, 2021 के बाद जितने लोगों का पैसा पटा है, किसी के विद्युत कनेक्शन का वर्क आर्डर नहीं हुआ है, एक भी किसान को विद्युत का स्थायी कनेक्शन नहीं मिला है । पूरे प्रदेश के किसानों को धोखा देने का काम यह सरकार कर रही है । खाली आप एक झुनझुना 25 सौ रूपये में धान खरीद रहे हैं । अगर किसान हिसाब लगायेगा तो किसान को 22 सौ रूपये से ऊपर धान की कीमत नहीं मिलती । खाली सरकार उसी काम को करती है, जिस काम में सरकार के लोगों को पैसा मिले और उसका एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं । नगरीय निकाय में सारे जगह विद्युत के कनेक्शन कट गए हैं और नगरीय निकाय के कनेक्शन क्यों कटे ? क्योंकि पैसा नहीं पटा और पैसा क्यों नहीं पटा ? क्योंकि उसमें 3 प्रतिशत विद्युत विभाग को पैसा जाता तो विभाग को पैसा नहीं मिलता । वह 3 प्रतिशत मिल जाता तो विद्युत कनेक्शन जुड़ जाता, समय पर पैसा पट जाता । पर इनको गांधी जी की गुलाबी फोटो से प्रेम है और जब तक गांधी जी की गुलाबी फोटो का 3 प्रतिशत, 5 प्रतिशत नहीं मिलेगा, तब तक नगरीय निकाय से आवंटन जारी नहीं होगा । इसके लिए नगरीय निकाय के सारे विकास के काम रूके हुए हैं । सारे भागीरथ प्रयत्न के बाद विद्युत कनेक्शन कट रहे हैं । अब इस व्यवस्था को आप कैसे

ठीक कर सकते हो । यह गुलाबी रंग के गांधी जी के प्रेम को कैसे कम कर सकते हो । जरा आप विचार कर लीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी को बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब यह थोड़ी है कि झूठ का पुलिंदा बोलेंगे । सत्यता की बात करनी चाहिए । आप क्या बात कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय :- भगत जी, आप बैठिए । शर्मा जी, आप बैठ जाईए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर आपकी पार्टी को गुलाबी गांधी से प्रेम है, मैं सार्वजनिक बोल रहा हूं । 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का खेल नहीं है तो आप बता दो, खुले रूप से बोल रहा हूं, सदन के अंदर बोल रहा हूं, सदन के अंदर बोल रहा हूं, जवाबदारी के साथ बोल रहा हूं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि बिना 3 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के आवंटन जारी नहीं होता है। ये आपके पार्टी के अध्यक्ष बोलते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम कर रही है, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय कर रही है। छत्तीसगढ़िया के नाम पर छत्तीसगढ़ियों को लूटने का काम यह सरकार कर रही है। इसलिए इस अभिभाषण का विरोध करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

## सदन को सूचना

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम पर की गई है। कृपया सुविधानुसार स्वल्पाहार ग्रहण करने का कष्ट करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप रात का इंतजाम करा दीजिये, हम रात भर बैठेंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- कौन सा वाला इंतजाम, आपके लिए कौन सा वाला इंतजाम करना है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रात भर बैठने वाला, बहिर्गमन करके काबर भागथस ? बहिर्गमन करके काबर भागथस ? ओ जगह जा के गांधी जी ला परेशान करथस।

श्री केशव चन्द्रा :- पाण्डेय जी, एक ठन बात ला बताहा। आपके सरकार बनही तो हमन खुशहाल रहबो न ? आपके सरकार बनही तो हमन ला खुशहाल राखिहा भाई।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- पांडे जी, जो आपके मन में है, वह आज दिल से बोलियेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांडे जी, पुलिस विभाग के बारे में क्या दर-वर बोले थे, उसको यहां सदन में बोल दीजियेगा।

श्री अरूण कुमार वोरा :- फूट डालो राज करो की नीति बंद करो ना भाई, अब बहुत हो गया।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अंग्रेज लोग भी इतना नहीं किए हैं।

श्री अरूण कुमार वोरा :- जितना अंग्रेज लोग नहीं किए उतना तो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। ये बेचारा सीधा-साधा आदमी है।

श्री धर्मजीत सिंह :- लेकिन, इसमें दो मत नहीं है कि शैलेश पांडे बहुत बहादुर विधायक हैं। वह ऐलानिया बोलते हैं।

श्री अरूण कुमार वोरा :- वह कट्टर कांग्रेसी है।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- पर ये नेता प्रतिपक्ष जी की बात सुनते नहीं हैं, इसलिए सामने के दोनों चले गये हैं। कौन नेता प्रतिपक्ष है, मानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, देखो, वह दोनों सामने से गायब हैं।

समय :
4:57 बजे **(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए)**

**मानमीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (क्रमशः)**

श्री शैलेश पांडे (बिलासपुर) :- आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा जो अभिभाषण इस सदन में दिया गया है, मैं उन बातों, उन तथ्यों का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज सदन में गजब का एक्टिंग किया गया। हमारे सम्मानीय विपक्ष के साथियों द्वारा यहां जो असत्य बोलने का,परफारमेंस किया गया है, मैं उसकी दाग देता हूं। मैं सदन से आदरणीया पुरंदेश्वरी जी को निवेदन करता हूं कि वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाये। (मेंजों की थपथपाहट) मैंने इतनी गजब की एक्टिंग कहीं नहीं देखी, जितना आज यहां सदन में परफार्मेंस हुआ।

आदरणीय सभापति महोदय, इस देश का आम आदमी इस देश का राष्ट्र निर्माता होता है । इस देश का करदाता होता है, इस देश का आयकर दाता होता है। जिससे हमारी राज्य की सरकार, जिससे हमारे केन्द्र की सरकार, हमारी दोनों सरकार चलती है। सरकार अपनी जगह पर होती है। सरकारें आती-जाती हैं, कभी आपको मौका मिलता है, कभी कांग्रेस को मौका मिलता है। कभी केन्द्र में मौका मिलता है, कभी राज्य में मौका मिलता है। आपको भी पूरा 15 वर्षों का मौका मिला। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 साल में इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता के साथ हुआ, यह पूरा विश्व जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, हम सब उन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। कितनी

तकलीफ और कितना असर हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पांडे जी, आप ऐसा भाषण दें कि अरूण वोरा जी की नींद खुल जाये।

श्री अरूण कुमार वोरा :- मैं जग रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहां जग रहे हो ? अभी तो सो रहे थे।

श्री शैलेश पांडे :- सत्यम दुर्व्यामी, प्रियम दुर्व्यामी, दुर्व्यामी सत्यम प्रियम। आप निंश्चत रहिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुछ समझ में आया ?

श्री शैलेश पांडे :- माननीय सभापति महोदय, यह मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप मेरी बातें सुन रहे हैं। मैं और भी ध्यान से इस बात को बोलूंगा। पिछले 2 वर्षों तक कोरोना काल रहा, उस कोरोना काल में इस देश की सरकार ने हमारे प्रदेश की जनता को क्या दिया ? यह सोचने का विषय है। हमारे देश में मुगलो ने शासन किया, हमारे देश में अंग्रेजों ने भी शासन किया। हमारा देश वर्षों में गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा, हमारे देश में चुनी हुई सरकार वर्तमान में केन्द्र में है । मुगल और अंग्रेज कोई चुनकर नहीं आये थे, वे कोई चुनकर नहीं आये थे, वे अत्याचार से आये थे, कूटनीति से आये थे, आक्रामण करके आये थे और उन्होंने हम पर कब्जा किया । लेकिन जिस देश की जनता ने केन्द्र की सरकार को चुना, चुना ही नहीं विशाल बहुमत से चुना, कल निजाम कह रहे थे ना कि सुल्ताने हिंद हैं हमारे आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, उन्होंने दो साल में क्या दिया ? जब छत्तीसगढ़ की जनता मर रही थी, जब छत्तीसगढ़ के लोग मर रहे थे, जब छत्तीसगढ़ के लोग कोरोना से संघर्ष कर रहे थे, जब खाने के लाले पड़े हुये थे, तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने या उनकी सरकार ने हमको क्या दिया, यह बताईये ? धारावाहिक चलाई है । सात दिनों तक 20 लाख करोड़ पैकेज की बात की गई, लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप बताईये कि छत्तीसगढ़ को क्या मिला ? छत्तीसगढ़ को क्या दिया गया ? आपने वेंटिलेटर दी है । आधे से ज्यादा सर्विसिंग सेंटर में पड़े हुये हैं, वेंटिलेटर्स की यह हालत है । सरकारें कैसे चलती है, किस प्रकार चलती है, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं । आप भी 15 वर्ष सरकार में रहे हैं । मैं बिल्कुल बुराई नहीं करता । विपक्ष आलोचना करता है, हमको शिक्षा लेनी चाहिये । हमारे विपक्ष के जितने बड़े साथी हैं, आलोचना करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, जो कहते हैं उसको आत्मसात करना चाहिये । मैं उनका सम्मान करता हूँ । एक-एक चीज को सुनता हूँ । इस सदन में हम लोग नये विधायक के रूप में आये हैं, हम मानते थे कि इस पवित्र सदन में जनता ने हमको भेजा है, हम लोग बहुत कुछ सीखकर जायेंगे और सीखते भी हैं विपक्ष के साथियों से । ज्यादा सीखते हैं और बहुत सम्मान करते हैं । वास्तविकता तो यही है कि हमारे देश में कोरोना के काल में हमारे प्रदेश को क्या मिला, प्रदेश की जनता को क्या मिला ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- शैलेश जी इन्होंने महंगाई तो दिये हैं । ऐसा मत कहो कि कुछ नहीं दिये हैं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रजनीश कुमार सिंह :- शैलेष जी, ठीक है आप डिफेंड करिये । कोरोना में बोलिये ठीक है । बताईये हमारे मंत्री जी जो हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिये काम किया है । वह समझ में आ रहा है कि कोरोना पर ही क्यों बोल रहे हैं । ठीक है, अच्छी बात है ।

एक माननीय सदस्य :- ऐसा बोलकर चमका रहे हो क्या ?

श्री शैलेश पाण्डेय :- ठीक है, कोरोना की ही बात करिये । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस नशे की बात हमारे आदरणीय बृजमोहन भईया कह रहे थे, जिस नशे की बात आप हमसे कह रहे थे, आपने जो सदन में बातें की, आप अपने कार्यकाल को याद कीजिए, आपके कार्यकाल में जब 15 साल तक क्या-क्या नहीं बिकता रहा, क्या शराब नहीं बिकती रही, आप ईमानदार थे तो ठेका पद्धति में आपने क्यों बदला शराब का कानून ? आपने व्यवस्था क्यों बदली ? आप यह बताईये । आप हम पर शराब बंद करने के लिए कहते हैं, हमने घोषणा की थी कि बंद करेंगे यानी बंद करेंगे ।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, उस समय तो सरकारी शराब की दुकान खुल गई थी ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आपको तो बंद करने का मौका मिला था ना । आपने क्यों बंद नहीं किया ? आपने क्यों शराब बेचने मजबूर किया ? क्या इसके पीछे यह रिजन था, मैंने तो सुना है कि करोड़ो रूपये मांगे गये थे...।

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- पाऊच में बेचा ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- सभापति महोदय, यहां ठेकेदारों का राज था, ठेकेदार लोग सरकार चलाते थे, सरकार राज नहीं चलाती थी । शराब के ठेकेदार सरकार चलाते थे, इसलिए आपको ठेकेदार से शराब बंद करना पड़ा और सरकार शराब बेचने में मजबूर हुई । इस बात को विपक्ष में बैठे हुये लोग अच्छे से जानते हैं । सभापति महोदय, यह बहुत दु:ख की बात है ।

सभापति महोदय :- मैं पाण्डे जी का भाषण बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ भाई ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- आदरणीय सभापति महोदय, आप भगवान श्री कृष्ण की भांति वहां बैठे रहे, मेरा ध्यान आपके ऊपर केन्द्रित है । आपको केन्द्रित रखते हुये मैं भाषण दे रहा हूँ ।

श्री अरूण वोरा :- सुदर्शन चक्र तो कांग्रेस ही चलायेगी ।

एक माननीय सदस्य :- बाकी तो कोई सुन नहीं रहा है तो अच्छा है, ठीक है ।

श्री शैलेश पाण्डेय :- रजनीश जी बड़े भाई हैं । बेलतरा विधान सभा से नेतृत्व करते हैं । वह खुद जानते हैं कि बिलासपुर में क्या-क्या होता है, वह यहां पर बोल नहीं सकते, मैं यहां पर जानता हूँ । यह उनकी मर्यादा है । मैं जानता हूँ कि मन में क्या-क्या पीड़ा है । 15 वर्षों तक शराब ठेकेदार, शराब बेचते थे, वही ठेकेदार शराब चलाते थे, यह आप भी जानते हैं । हमारी सरकार ने अगर कहा कि आप मुझे बताईये कि क्या 15 वर्षों से हुक्काबार नहीं चल रहे थे? आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी बड़े भाई हैं, मैं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समझता हूं कि हमारे बहुत बड़े भाई हैं। वह इस बात को समझते हैं कि इस प्रदेश के 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के लड़के और लड़कियॉ सब हुक्का बार में बैठते थे। आप यह व्ही.आई.पी. रोड में बड़े-बड़े होटलों में चले जाईये, वहां पर शराब भी परोसी जाती है, हुक्का भी परोसा जाता है। वहां स्कूल के बेटे और बेटियॉ आकर शराब, हुक्का पीते हैं। क्या यह पिछले 10-15 सालों से नहीं हो रहा था? यह हो रहा था। हमने बंद किया। यह घोर अत्याचार हो रहा था। क्या यहां 15 सालों में इसके खिलाफ आवाज उठाई गई? एक विधायक ने आवाज नहीं उठाई। क्यों आवाज नहीं उठाई? क्या उन्हें अपनी जनता से लगाव नहीं था। क्या उन्हें बेटे और बेटियों से लगाव नहीं था?

मानननीय सभापति जी, मैं इस बात को आपको बताता हूं कि मैंने हुक्का बार बंद करने के लिए क्यों आवाज उठाई? मैं आज बात को सदन में सब साथियों के सामने बताता हूं। मैं विधायक बना। मेरी बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब मैं नया विधायक बना था, उसने एक दिन मुझसे आकर कहा कि पापा मेरी क्लास में बच्चे हुक्का बार जाते हैं। इस बात को मैं आज सदन के सामने कहता हूं। मेरी बेटी ने मुझसे कहा, वह इतने बड़े नामी स्कूल में 10वीं क्लास में पढ़ती थी। मैं उस नामी स्कूल का नाम कोड नहीं करूंगा। मैं एक पिता था, मेरे मन में क्या पीड़ा होगी कि मेरी बेटी कह रही है कि पापा मेरे क्लास के बच्चे लोग हुक्का बार जाते हैं। सबके पापा तो विधायक नहीं होते हैं। उन पिताओं की क्या स्थिति होगी जो बच्चों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं, जरा आप सोचिये। पैसा देते हैं, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी स्थिति के बारे में सोचिये। आदरणीय मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपनी आंखों से एक दिन देखने गया। होटल में असत्य बोल कर खाना खाने गया। मैंने देखा की होटल में बढ़िया शराब परोसी जा रही थी। एक महिला आई, उसकी उम्र 30-35 साल के भीतर होगी। उसके साथ ढाई-तीन साल की बड़ी सुंदर बेटी थी। वह हाथ पकड़कर आई, वह सामने वाले कोने में बैठी। उसके बाद दो आदमी आये, उन्होंने हुक्का रखा और वह महिला हुक्का पी रही थी। सर, यह मैं रायपुर की घटना बात रहा हूं। विधानसभा सत्र चल रहा था। असत्य नहीं कह रहा हूं। आपने कहा था न कि असत्य नहीं बोलना। मैं एक बात भी असत्य नहीं बोलूंगा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- माननीय विधायक महोदय, जितने विधायक लोग हैं, बहुत सारे बच्चो लोग अपने-अपने पिताजी से मांग रहे हैं कि दारू बंद करो, उसकी भी सुन लो न।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं हुक्का बार इस प्रदेश में केवल बिलासपुर, रायपुर की समस्या नहीं है, यह पूरे छत्तीसगढ़ की समस्या थी। हजारों हुक्का बार लोगों से लाखों रुपये लूटकर उसमें न जाने क्या-कया नशे की दवाईयॉ मिलाकर वह बच्चों को गुमराह कर रहे थे। भविष्य की नस्लें खराब हो रही थीं। एक आदमी ने आवाज नहीं उठाई। अगर उसको बंद किया है तो हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बंद किया है। यह कड़ा निर्णय हमने लिया। हमने नशे को बंद करने की कोशिश की। हमने एक सफल कदम उठाया। आपके समय में गांजा,

अफीम,..।

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त में कर लीजिए। आपको बोलते हुए 13 मिनट हो गये हैं, 10 मिनट का समय निर्धारित हुआ है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नशा बंद करने की बात कर रहे हो तो हुक्का तो छोटा नशा है, दारू को सीधा बंद करवाओ न।

श्री शैलेश पाण्डे :- वह भी बंद होगी।

श्री सौरभ सिंह :- महाराज, दारू पिकअप नहीं ले रहा है।

सभापति महोदय :- कृपया दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मैं अब मेन बात में आना चाहता हूं।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 99 दुकानें बंद कर दिये हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति जी, मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखता हूं और मेन बात में आता हूं। बहुत सारी बातें हो रही हैं। छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल, छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है ? मैं अभी उत्तराखंड गया, उत्तराखंड में चुनाव प्रचार किया, उसके बाद वहां से लौटकर आया और फिर उत्तरप्रदेश गया। वहां भी छत्तीसगढ़ मॉडल की बात हो रही थी। जितने पत्रकार आते हैं, वह कांग्रेस के नेताओं से छत्तीसगढ़ मॉडल की बातें पूछते हैं। वास्तव में यह बात सही है कि छत्तीसगढ़ मॉडल लोकप्रिय तो हो गया है। यह सही बात है। और क्यों हो गया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। उसका कारण क्या है ? सरकार में 15 साल आप भी थे, हमको तो अभी 03 साल ही हुए हैं। हम लोग 15 साल के बाद आये हैं, अगर 3 साल में छत्तीसगढ़ मॉडल की बात होने लगी है, चर्चा में आ गया है तो इसके पीछे का कारण क्या है, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। आज हमारे प्रदेश की 75% जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 25% जनता शहरी क्षेत्र में रहती है, यह मैं आपको एक मोटा-मोटा आंकड़ा बता रहा हूं। यह आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं मैं तो आपसे बहुत जुनियर हूं। आज जो यह प्रदेश है, यह किसानों का प्रदेश है और किसानों की बाहुत्यता का प्रदेश है। तो आज वास्तव में प्रदेश की जनता को क्या चाहिये था, आपको याद होगा कि जब आप सत्ता में थे तो आपने किसानों से क्या-क्या वायदे किये, आपने किससे क्या-क्या वायदे किये, यह आप जानते हैं। लेकिन उन वायदों को पूरा नहीं किया। उन सभी बातों को हम कांग्रेस के लोग 15 वर्षों में विपक्ष में रहकर छत्तीसगढ़ की जनता की जो वास्तविक आवश्यकता थी, उस वास्तविक आवश्यकता को हमने समझा और उसे समझकर हमने घोषणा-पत्र में डाला।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- पाण्डे जी 15 साल में क्या-क्या नहीं हुआ, 3-4 कार्य को बता दीजिये जो पूरा नहीं हुआ।

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने बिलासपुर में 9 साल में ब्रिज बनाये थे, हमने 3 साल में उससे बड़ा ब्रिज बना कर दिखा दिया।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- रतन-जोत फेल हो गया।

डॉ. विनय जायसवाल :- आपने सिवाय भू-माफियाओं को संरक्षण देने के, इनकी सरकार में जमीनें उड़ रही थी। (व्यवधान)

श्री रजनीश कुमार सिंह :- घोषणा में ऐसा क्या काम था जो नहीं हुआ , घोषणा पत्र में ऐसे 4 काम गिना दीजिये जो नहीं हुआ।(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बोनस एवं समर्थन मूल्य कुछ भी नहीं दिया, न ही आपने जर्सी गाय दी, न ही समर्थन मूल्य दिया।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह बैल देने की बात किये थे, गाय देने की बात किये थे, बाड़ी देने के...(व्यवधान) आपने कौन-कौन सा वायदा पूरा किया है, आप उसको बताइये ? कि आपकी सरकार ने 15 साल में कौन-कौन से वायदे किये थे और पूरे किये हैं। क्या मैं उसको गिनाऊ।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- हां, हां गिनाओ।

श्री विनय जायसवाल :- लंबा लिस्ट है जी। आप लोगों ने कहा था कि हर आदिवासी परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, क्या आपने दिया ? आपने बोला था कि गाय और बैल देंगे, क्या आपने दिया ? 15 साल में आपने क्या किया ? आज जो हमारी सरकार है, आज किसानों का 9 हजार करोड़ से ज्यादा कर्जा माफ किया, पूरे देश में ऐसा किसी की सरकार ने नहीं किया है, हमारी सरकार उदाहरण है।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब बैठिये, पाण्डे जी आप बोलिये।

श्री रामकुमार यादव :- यहां तक की वह बासी...(व्यवधान) तुमन।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप दिल्ली बार-बार जाते हैं, वहां से उत्तरप्रदेश जाते हैं, उत्तरप्रदेश में चुनाव जीताते हैं। दिल्ली जायेंगे तो क्या करेंगे, बताइये।

सभापति महोदय :- पाण्डे जी, 2 मिनट में समाप्त करिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- दिल्ली से ही तो छत्तीसगढ़ मॉडल बनना है।

श्री सौरभ सिंह :- पाण्डे जी हर एक चीज में दिल्ली जाते हैं।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- दिल्ली सरकार, छत्तीसगढ़ मॉडल को...।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- दिल्ली सरकार खर्च कर रही है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, उसे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी उसके मुरीद हुये हैं। अभी उत्तरप्रदेश के चुनाव में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को बोला है कि जो छुट्टा जानवर का प्राब्लम है, मैं उसको 10 मार्च



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

के बाद ठीक करूंगा। सीधे-सीधे प्रधानमंत्री जी बोल देते कि भूपेश बघेल जी का जो मॉडल है, उसको मैं पूरे देश में अपना मॉडल बनाऊ।....(व्यवधान) यहां चंद्राकर जी बैठे हुये हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- डॉ. साहब सुनिये। छत्तीसगढ़ का राज्यांश कितना है ?..(व्यवधान) साहब आप उधर देखिये न।

डॉ. विनय जायसवाल :- जब गोबर खरीदी की बात हुई थी तो इनके ट्वीटर आई.डी. में और फेसबुक आई.डी. में गोबर से पूरे राजकीय चिन्ह बना दिये थे। गोबर तो गोबर होता है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे उत्तरप्रदेश के चुनाव में अपने भाषण में जगह-जगह पर बोला है कि जो छुट्टा जानवर है वह लोगों का इनकम बनेगा। यह यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। ये छत्तीसगढ़ मॉडल है, यह छत्तीसगढ़ मॉडल है ?

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, बैठिये। चलिये पाण्डे जी बोलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- तो यह कोई छुट्टा से कम हस का।

डॉ. विनय जायसवाल :- (व्यवधान) गाय के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं और प्रधानमंत्री जी उसको छुट्टा जानवर बोलते हैं और आप लोग गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं।

सभापति महोदय :- चलिये डॉ. साहब। अब कोई नहीं बोलेगा, प्रमोद जी। दो मिनट में समाप्त करिये।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मैं जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कर रहा था। जिस छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा दिल्ली में है, उत्तरप्रदेश में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है और पूरे देश में है, आखिर यह क्या है। वास्तव में यदि आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने जो बड़ा काम किया, जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया कि उसने गरीब आदमी की जेब में पैसा डाला, यह सबसे बड़ा काम था। वह पैसा उसने 2500 रूपये धान लेकर डाला, वह पैसा उसने राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत डाला, वह पैसा उसने गोधन न्याय योजना के तहत डाला, वह पैसा उसने जो हमारे 52 वनोपज है, उनके समर्थन मूल्य देकर डाला। भूमिहीन किसानों, मजदूरों को 6 हजार रूपये देकर डाला। वह यह सारी चीजें जो हैं..।

सभापति महोदय :- माननीय पाण्डे जी, अब समाप्त कीजिए, आपको 18 मिनट हो गये हैं। श्री अजय चन्द्राकर।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, आज अगर छत्तीसगढ़ के मॉडल की बात हो रही है तो मैं इस बात को कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की गरीब जनता का आर्थिक स्थिति का उन्नयन किया है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय सभापति महोदय, पहले आप बोलवा लीजिए कि जो कहूंगा, सच कहूंगा और सच के सिवाये कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि आज यह सारा असत्य ही बोलने वाले हैं।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, यह जो पैसा है, चाहे वह गरीब आदमी हो, चाहे वह किसान हो, चाहे वह आदिवासी हो, चाहे वह मजदूर हो, अगर उसकी जेब में पैसा डाला है तो यही है छत्तीसगढ़ मॉडल, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि हमने अपने प्रदेश की जनता को आर्थिक रूप से समृद्ध किया और वह किया है तो हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया है। यह सबसे बड़ी बात है। आज इसकी चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय :- चलिये, अजय चन्द्राकर जी।

श्री शैलेश पाण्डे :- माननीय सभापति महोदय, मेरे पास बोलने के लिए विषय बहुत सारे हैं। यदि आप अनुमति देते तो मैं दूसरे विषयों में भी बोलता और भी बातें रखता। लेकिन मैं पीछे की पंक्ति का वाक्ता रहा हूँ इसलिए आपकी आज्ञा है और आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार और आभार व्यक्त करता हूँ। अंत में एक छोटी सी बात जरूर कहूंगा। आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर यह बहुत ही गरिमामयी सदन है और पिछले कई दिनों से हमारी छन्नी साहू जी टू-व्हीलर में आ रही है। मुझे बिल्कुल इस बात का खेद है कि एक महिला होने के नाते नक्सली एरिये से आती है और वह टू-व्हीलर में आती है। इस सदन में आसंदी से मैं निवेदन करूंगा कि इस समस्या को विधायक जी की सुरक्षा का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, उनके परिवार के भविष्य का सवाल है हमें इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए और हमारी सरकार भी है मैं सरकार और आसंदी से भी दरख्वास्त करूंगा कि छन्नी साहू जी को सुरक्षा दी जाए। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- छत्तीसगढ़ मॉडल में विधायक लोगों के साथ ऐसी हो रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीगणों की पूरी दीर्घा खाली है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ शिवकुमार डहरिया) :- तैं तो एक बार बोल डरे हस का?

श्री अजय चन्द्राकर :- अब ते बोल दे हस तो मैं थोड़ा देर में तोरे तरफ आवत हों। माननीय सभापति महोदय, कौन बोल रहा है, कौन लिख रहा है, कौन हमारे बोलेंगे, उसका उत्तर देंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इधर की भी दीर्घा खाली है। इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी का शानदार जानदार प्रवेश हुआ है। वह आ गये। तो बाकी सारी दीर्घाएं खाली हैं। माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में सरकार की यह गंभीरता है। आप आ गये, मैंने आपका स्वागत किया है। आप बाजू में देख लीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप इधर देखिए। आप अपनी तरफ भी देख लिया करें। आपके सामने की सीट खाली है इधर की सीट खाली है। आप इधर आ जाईये। अच्छा आप यह बताईये कि आप इधर कब आएंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, मैं बात शुरू करने से पहले ...।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं। आप पहले यह बताईये कि सब ठीक है। पहले यह बताईये कि इधर कब आ रहे हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय भईया, उसी के प्रयास में लगे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर:- सब आपके खिलाफ प्रदर्शन में लगे हैं वहां गये हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी बोलने के पहले मेरी एक जिज्ञासा है । यहां अधिकारी लोग भी बैठे हैं। मैं ग्रामीण विकास विभाग में 10 सालों तक काम किया। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इसमें लिखा है कि महात्मा गांधी नरेगा तथा अन्य योजनाओं के अनुसरण से 4 लाख से अधिक निर्माण कार्य कराए गए हैं। यह अनुसरण क्या होता है? मेरी जानकारी में अभिसरण होता है। तो इसको कौन स्पष्ट करेगा कि यह अभिसरण है या अनुसरण है, आप पेज नं. 08 में देख लीजिए। यदि माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में यह गलती हुई तो यह दोष किसका है? क्योंकि इसको कैबिनेट अनुमोदित करती है। यह अभिसरण है या अनुसरण है । अनुसरण नाम की कोई योजना नहीं चलती। रूलर डेवलपमेंट में अभिसरण ही होता है। हिन्दी में उसको अभिसरण ही कहा जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे इसमें व्यवस्था चाहता हूँ ताकि मैं उस विषय में बोल सकूं। यह क्लियर हो जाए कि यह अभिसरण है या अनुसरण है?

सभापति महोदय :- चलिये, आप अपने भाषण को जारी रखिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बड़ी गलती है। यदि मैं सही हूँ तो यह राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में गलती है, यह बड़ी गलती है।

सभापति महोदय :- आपकी बात को मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में जवाब दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन के नेता, कार्यवाही की घोषणा करें, अगर सुन रहे हैं तो। यदि राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में गलती है तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे ? आप कार्यवाही की घोषणा कीजिए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है ?या तो अभिसरण सही है।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- यह टंकण त्रुटि है। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कितनी गंभीरता है । मैं अपना भाषण आपको समर्पित कर देता हूँ। आपने ऐसा रास्ता निकाला कि मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता था, क्योंकि आप मेरे मुरशिद हैं। माननीय सभापति महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कर्ज को 51 हजार करोड़ रूपये में स्थिर रखा है। मैं हर सत्र में पूछता हूं। पिछले सत्र में भी 51,125 करोड़ कुछ बताये थे, उतने में ही अभी तक स्थिर है। आज के प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ...।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय कम से कम हम लोगों को यह अभिशरण और अनुसरण का तो बता दीजिए। (हंसी)

सभापति महोदय :- देखिए, वह विषय समाप्त हो गया। माननीय अकबर साहब ने उसको क्लीयर कर दिया।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अजय जी ने उठाया है..।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं बोल रहा हूं कि वह अभिशरण है। यदि राज्यपाल के अभिभाषण में गंभीरता होती तो अभी कार्रवाई की घोषणा हो जाती। सदन के नेता बैठे हैं। यह मजाक का विषय नहीं है।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, अभिशरण का शाब्दिक अर्थ है और अनुसरण का जो शाब्दिक अर्थ है। उसको थोड़ा बता दीजिए। क्लीयर कर दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति महोदय, मैं गंभीरता नहीं है बोल रहा हूं। आज के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है कि छत्तीसगढ़ के बजट का 87 प्रतिशत कर्ज का है। मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूं। मैं आपकी भाषण को सुन रहा था। विपक्ष नहीं था, कौन अंग्रेजों की मुखबिरी करता था, कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ? मैंने लिखा था, इलाहाबाद चले जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाईट है। चंद्रेशखर आजाद अपनी जीवन में किससे आखिरी बार मिले थे। उधर के लोग और इतिहास क्या कहता है कि उसके खिलाफ मुखबिरी किस परिवार ने की थी। भाजपा ने वर्ष 1971 के युद्धवार को बंद कर दिया। वार मेमोरियल छत्तीसगढ़ में बनाना चाहते हैं। वार मेमोरियल बनाना चाहते हैं राजनीतिक कारण है, व्यक्तिगत कारण है, मैं नहीं जानता। शहीद स्मारक छत्तीसगढ़ में है। आप इतिहास वेत्ता हो गये हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास जानते हैं, सबसे पहले कांग्रेसी कौन मरे, मुझे बता दीजिए और यदि वह न बताएं तो आजादी की लड़ाई में छत्तीसगढ़ से कौन शहीद हुए हैं, मुझे कांग्रेस का 5 नाम बता दीजिए, जिन्होंने कांग्रेस की शहादत दी। फांसी में चढ़े, गोली मारी गयी या उनको रिवाल्वर से कुछ किया गया, जहर के इंजेक्शन दिए गए। आजादी की लड़ाई में पांच नाम बता दीजिए। आप हमेशा बोलते हैं न कि आजादी की लड़ाई में ये शामिल था, वह शामिल नहीं था। यह मुखबिरी करने वाले लोग हैं, यदि इतिहास जानते हैं तो मैं जो बोल रहा हूं वह सत्य है और नहीं तो आपकी तरफ जो इतिहास जानते हैं उनसे बहस हो जाए।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय ...।

श्री अजय चंद्राकर :- डॉ. साहब हल्की बातें मत करो। जा आंखी के आपरेशन कर।

डॉ. विनय जायसवाल :- हल्की बातें नहीं कर रहा हूं। आप यह बताईए कि क्या आप गोडसे को शहीद मान रहे हैं ? कांग्रेस के लोग शहीद नहीं हुए ...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पांच नाम बता देना। छत्तीसगढ़ में कौन पहला कांग्रेसी बना। यह मुझे बता देना। मैं ईनाम दूंगा।

डॉ. विनय जायसवाल :- आप बता दीजिए न कि मुखबिरी किसने की ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मुद्दे में, किताब में आ जाता हूं। उस मोटे किताब को मैं संक्षिप्त कर लिया हूं। आप मुझे समावेशी विकास का मतलब समझा दें। "छत्तीसगढ़ मॉडल समावेशी विकास" में समावेशी विकास में आऊंगा। माननीय सभापति महोदय, 13 दिन का सत्र बुलाना, चाहे मैं सरकार में रहूं, चाहे आप सरकार में रहें। सरकारी बिजनेस में अभी तक एक विधेयक आया है। इसका मतलब यह होता है कि उस सरकार के पास कोई दृष्टिकोण नहीं है। उस सरकार के पास कोई सोच नहीं है, उस सरकार के पास कोई दिशा नहीं है, उस सरकार के पास कोई कार्यक्रम नहीं है। जो सदन के सामने रख सकें और वह प्रमाणित कैसे होता ? मैं प्रमाणित नहीं कर रहा हूं, दो बार पेपर में छपा कि बार-बार चिट्ठी लिखने के बाद विभाग राज्यपाल के अभिभाषण के लिए सामग्री नहीं दे रहे हैं, विषय नहीं दे रहे हैं, दो बार पेपर में छपा और उसकी तारीख बढ़ाई गयी। उसके प्रमाण क्या हैं ।

**<u>सदन को सूचना</u>**

सभापति महोदय :- अजय जी, एक मिनट। आज की कार्यसूची के पद क्रमांक (6) का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाए। मैं समझता हूं, सभा सहमत है।

**(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)**

**<u>माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव (क्रमश:)</u>**

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय सभापति महोदय, जो सरकार दृष्टिकोण विहीन होती है, आरोप की ओर अभी नहीं आ रहा हूं। गोधन न्याय योजना, जैविक खाद योजना, बिंदु क्रमांक 6, यह वर्ष 2021 में भी था, वर्ष 2020 में भी था, वर्ष 2019 में भी था। यह सभी बिंदु क्रमांक में पटल में रख दूंगा। तीनों बार गोधन न्याय योजना है। भूमिहीन कृषि मजदूरों को रूपया देना है। यह पहली बार आया है। तेंदूपत्ता संग्रहण दर पिछले साल भी आया था, उसके पहले साल वर्ष 2020 में भी यह विषय आया था। तेंदूपता संग्रहण योजना, आप महामहिम का अभिभाषण निकालकर देख लीजिए। चौथा, बिजली बिल हाफ और नि:शुल्क वितरण, अभी बिंदु क्रमांक-13 में है । यह वर्ष 2021 में भी आया था, वर्ष 2020 में भी आया था । उस समय 45 नंबर में था, सिंचाई योजना अंतर्गत सिंचाई क्षमता निर्मित की गयी । यह वर्ष 2021 में भी आया था, इन लोगों ने एक नया शब्द ढूंढ़ा है । रूपांकित कितना था और ओरिजनल हमने इतना किया । इसको वह चीफ इंजीनियर भर रूपांकित की परिभाषा को जानता है और बाकी लोग तो

उसे पढ़ने वाले हैं और कोई नहीं जानता । एक यूनिट बिजली पैदा नहीं की, एक इंच सिंचाई नहीं बढ़ी यह शब्दों की बाजीगरी है कि रूपांकित इतना हुआ और सकल इतना हुआ यह सब शब्दों की बाजीगरी है । एक योजना पूरी नहीं हुई । जितने फीते लग रहे हैं, अभी कुलेश्वर महादेव में अपनी फोटो लगाकर आये हैं वह कब की है उसे मैं जानता हूं । कौन-कौन सी योजना कब की है और उसका किसने उद्घाटन किया ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- अजय भैया, छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन बढ़ा कि नहीं बढ़ा ? आप धान का उत्पादन बताईये न कि आपने कितना खरीदा था और अभी सरकार ने कितना खरीदा है ?

श्री अजय चंद्राकर :- ममा, तें बइठ । बाद में तें बोलबे कि विषय में नइ बोलत हस कहिके । माननीय सभापति महोदय, जल-जीवन मिशन, घरेलू कनेक्शन, कनेक्शन प्रदाय । यह पिछले साल के अभिभाषण में भी था । कुपोषण, एनीमिया अभियान का उल्लेख, सुपोषण का उल्लेख यह पिछले अभिभाषण में भी था, कोई नयी बात नहीं है । अब कोविड-19 और फसल क्षति का मुआवजा अभी इस साल नया जुड़ा है। कौन सी फसल क्षति को देंगे, रबी को कि खरीफ को चूंकि दोनों पानी खाये हैं । दोनों में किसको देंगे, मेरा चना खराब हो गया । जितना होना था, उससे इस साल कम चना होगा । अब इसके बाद स्वामी आत्मानंद स्कूल दोबारा आया । इस साल भी है और पिछले साल भी है । रामवनगमन पथ तीन बार से आ रहा है लेकिन कौशल्या मंदिर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं और उसमें कांग्रेस ने ऐतिहासिक जगह में विवाद भी पैदा कर दिया तो वह कौशल्या मंदिर से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, 79 से 9 स्थान और 9 स्थान से 1 स्थान । अभी वह प्रश्नों में आयेगा और ध्यानाकर्षण में भी आयेगा इसलिये ज्यादा नहीं बोलता । चिटफंड कंपनियों से राशि वापसी यह भी दोबारा आया है, यह वर्ष 2019 से चल रहा है । 11 करोड़ की राशि नीलाम किये हैं, कितनों को बांटे हैं और कितना वसूले ? क्या आपने घोषणा पत्र में लिखा था कि हम उस संपत्ति को नीलाम करके आपको वापिस करेंगे, आप खजाने से वापिस कीजिये । आप वसूलते रहिएगा ।

माननीय सभापति महोदय, दोबारा शराबबंदी का उल्लेख अब इस सरकार की निर्णय क्षमता । शराबबंदी के लिये कमेटी बनी है । स्काईवॉक के लिये कमेटी बनी है। जोश में बोधघाट की कसम खा लिये कि बिल्कुल चैलेंज स्वीकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने डॉ. रमन सिंह जी को चैलेंज किया कि बोधघाट परियोजना हम बनाकर देंगे यह चैलेंज है, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं करके । उसके बाद पेपर में छपता है कि कई कारणों से अभी बोधघाट परियोजना स्थगित करके रखी गयी है, ठीक है भई । जो आपकी मर्जी, आप शासन में हैं । छोटे भूखंडों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने का उल्लेख यह वर्ष 2020 में भी है और वर्ष 2019 के अभिभाषण में भी है । हथकरघा वस्त्रों की खरीदी यह वर्ष 2021 में भी है और वर्ष 2020 के अभिभाषण में भी है, जो अब नये अधिकारी लोग कहां से लिखकर लाकर दें तो अब मैं बार-बार बोल रहा हूं कि इस सरकार के पास किसी तरह का दिशा-

दृष्टिकोण, चेतना और सोच नहीं है । दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत पर संदेह नहीं करता, वे कुछ करना चाहते हैं, कुछ करने का अवसर मिले तब की बात है । इस प्रदेश में समानांतर सरकार चल रही है, अब मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि नहीं जानते, वे जानें । प्रदेश का मुखिया जिसके पास कुसिया, वह जरूर जानेगा। 10 रूपया बॉयोडीजल में, कल्लू दादा, राधे दादा, पाटेकोहरा में वसूल रहे हैं, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ । ड्यूटी बदलती थी, ये वसूली करने वाले आते थे, ये वसूली करने वाले जाते थे । ये वसूली करने वाले आते थे, वसूली करने वाले जाते थे । बिल्कुल दम से, मैं पूरा नाम नहीं बोलता । मैं भागीरथी प्रयत्न बोलता हूं, जब मैं लिखता हूं तो भी इस बात को लिखता हूं कि भागीरथी प्रयत्न में वह भागीरथी आदमी का नाम है, यह बोल देता हूं । कौन से विभाग का है यह नहीं बोलता । 3 से 5 और आदमी देखकर 10 प्रतिशत तक कमीशन नहीं खायेगा, वह राशि रिलीज नहीं करेगा। अब समानांतर सरकार में समावेशी विकास पर मैं आउंगा, बोल रहा था।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय सभापति महोदय, माननीय रमन सिंह जी जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, वे हमेशा एक बात बोलते थे अपने सभी मंत्रियों को, विधायकों को, कार्यकर्ताओं को कि आप लोग 2 साल कमीशन लेना बंद कर दीजिए तो हमारी सरकार आ जायेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? अभी कितनी पारदर्शिता से तो सरकार चल रही है और माननीय सभापति महोदय, एक बात और बोलना चाहता हूं। अभी आप बोले कि कौशल्या माता मंदिर का नाम दो बार आ गया तो आपको तकलीफ हो गई। आप 40 साल से राम मंदिर-राम मंदिर कर रहे हैं। देश में भी आपकी सत्ता सरकार चल रही है।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब बैठिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे आपसे असत्य कथन की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। आपने बयान दिया। मैं आपको पेपर के चारों कटिंग दे दूंगा। 5 लाख रोजगार दिया। जनसंपर्क ने छापा कि 4 लाख 65 हजार से अधिक, फिर एक बार आपने छापा 2 लाख 80 हजार, फिर एक बार 2 लाख 60 हजार और आज बहुत बहस हुई है, उसमें आपने पूरा सुना है कि रोजगार को, नौकरी को, किस चीज को कैसे परिभाषित करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अब 2-3 तरह की स्वसहायता समूह हैं। एक महिला बाल विकास में है। एक ग्रामीण विकास विभाग में है। एक जो पंजीकृत नहीं हैं, राजनांदगांव जिले में उसकी संख्या ज्यादा है। महिला बाल विकास में भी और ग्रामीण विकास विभाग में भी। आप 12 करोड़ 70 लाख को ऐसे ढिंढोरा पीट रहे थे जैसे बिल्कुल हिमालय फतह करने वाले पहले आदमी निकले हो। आप बताये तो। वित्त सचिव बैठी हैं। आप पूछ लीजिए। इन तीनों तरह के स्वसहायता समूहों के कर्जे हजार करोड़ रूपये, 1200 करोड़ रूपये से ऊपर जायेगा। यदि नैतिकता है। ऋण माफी का आपने विज्ञापन दिया है। सभी स्वसहायता समूहों के ऋण माफ, मैं आपको यह पेपर भी दे दूंगा। तो आपको घोषणा करनी चाहिए। आप 12 करोड़ 70 लाख का ढिंढोरा मत पीटिए। माननीय

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मुख्यमंत्री जी आपने समावेशी विकास का मॉडल कहा। आपके मंत्री बहुत बोलते हैं। मैं दो मिनट बैठ जाता हूं। मुझे समावेशी का मतलब तो समझा दीजिए। माननीय डहरिया जी, मुझे समावेशी विकास का मतलब समझा दीजिए। आप बहुत तो खड़े होते हैं। विद्वान भी माननीय रविन्द्र चौबे जी की संगत में हो गये हैं। (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं जहां तक समझता हूं समावेशी विकास का माननीय चौबे जी..।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत देर से सोच रहा था कि चौबे जी आये हैं, लेकिन अजय जी उल्लेख क्यों नहीं कर रहे हैं? (हंसी) लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- चौबे जी के बगैर आये भी चौबे जी का उल्लेख हो चुका है।

श्री भूपेश बघेल :- चौबे जी के आने के बाद भी उनका उल्लेख नहीं हो रहा था, यह सोच रहा था।

श्री कवासी लखमा :- रात को सपना भी आता होगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढ़ मॉडल, माननीय कृषि मंत्री महोदय, आप जितना भी छिपायें, 4 लाख 61 हजार टन खाद हमने सप्लाई किया, जो 1 लाख 81 हजार से और ज्यादा है, यह केन्द्र सरकार का स्पष्टीकरण आया था।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- असत्य।

श्री अजय चन्द्राकर :- बिल्कुल आया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- असत्य।

श्री अजय चन्द्राकर :- दूसरा, पहला फ्लेगशिप हिन्दुस्तान में मुख्यमंत्री फ्लेगशिप की योजना, जिसमें इस विधान सभा में बहस नहीं हुई, जिसमें किसी सदस्य को नहीं बताया गया। जिसके वित्तीय प्रबंधन नहीं बताये गये, वह है नरूवा, घुरूवा, गरूवा, बाड़ी। आप एक दिन घोषणा करते हैं कि ग्रामीण मंत्रालय उसका एक नोडल होगा। दूसरे सत्र में मुख्यमंत्री जी का दिमाग घूम जाता है। बोले कि कृषि विभाग इसका नोडल होगा। तो कानून का शासन चल रहा है या शासक का कानून चल रहा है। शासक का कानून चल रहा है। शासन का कानून नहीं चल रहा है। जो बोल दे, वह कानून है। कितनी जगह से आपने अभिसरण किया है, मैं पढ़ देता हूं। केन्द्रीय योजनाओं से कितना अभिसरण किया है आपके नरूवा, घुरूवा, गरूवा, बाड़ी में, आप मुझे गोठान दिखा दीजिये कि निर्देश में मनरेगा में गोठान बनाया जाता है करके। आप एक किसी से निकलवा कर दिखा दीजिए कि गोठान बनता है। आप किस तरह से बना रहे हैं, मैं आपको जगह गांव बताता हूं, वहां के इस्टीमेट को निकाल लीजिए। आप उस योजना में जितनी बड़ी गड़बड़ी कर रहें हैं, उतनी इतिहास में नहीं मिलेगा। आप 15 साल, 15 साल की बात यदि करते हैं तो 15 साल के लिए एक विशेष सत्र बुला लीजिए। हम 15 साल में बहस कर लेंगे। हमारे ऊपर



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जो आरोप होगा, आप जांच करवाइए, फांसी में टांग दीजिए, हम यही बोलेंगे कि इससे ज्यादा क्या बोलेंगे ?

श्री कवासी लखमा :- हम लोग 15 साल की बात करते हैं, आप तो 70 साल की बात करते हो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी आपको फांसी पर टांग देंगे तो हम लोग के बीच में बोलेगा कौन ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी, आप रहते हैं, आप रहते हैं, अकबर जी रहते हैं, तो आपका पक्ष दबता है क्योंकि एक दो लोग अक्ल की बात कर नहीं पाते। आपने एक नई प्रशासनिक शैली विकसित की । वह है प्रशासनिक अधिकारियों की पिटाई । महासमुंद में अधिकारी, कलेक्टोरेट में पीटा गया, विधायक की उपस्थिति में पीटा गया, कलेक्टर की उपस्थिति में पीटा गया ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तो बहुत परेशान थे, अब पता चला है कि क्यों परेशान थे । आपके इसी काम से परेशान थे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय रविन्द्र भइया, मैं यदि कलेक्टर होता तो इस्तीफा दे देता । यदि मेरी बात सुन रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं । मोहन मरकाम जी के इलाके में डी.एस.पी. को पीटा गया । ट्रैफिक पुलिस को पीटा गया, जिसका वीडियो बना और वायरल हुआ, और कौन, नाम नहीं लेता वे कानून से परे लोग हैं । आप भी प्रकाशमुनि साहब के साथ पीछे में लाईन में लगते हैं । आपके पड़ोसी जिले से, कबीरधाम नाम ही हे । कुदुरमाल कोरबा देखे हैं, किधर से घूमकर कबीरपंथी कैसे पहुंचे ? कौन से वंश के लोग यहां आकर बसे, यह इतिहास है । आपने तो जिन 20 महापुरूषों का चयन किया है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को लिखकर दिया कि इन 20 लोगों की हम अलग पुस्तक छपवाएंगे । 20 के अलावा और 2 लोग हैं । पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय क्या छोटे-मोटे आदमी थे, वल्लभाचार्य क्या छोटे-मोटे आदमी थे । ऐसे लोगों के नाम उस सूची में नहीं हैं । ये सदियों के नाम हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ को दिया और अमर रहेंगे । दुनिया के सबसे पुराने शैल चित्र को पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय ने खोजा था । जो भारतीय दर्शन को दिया, शुद्ध विशिष्टता, द्वैत, अद्वैत, वल्लभाचार्य जी यहीं जन्मे थे । उनका नाम कहां शामिल करेंगे । यह युद्ध स्मारक बनवा रहे हैं । युद्ध स्मारक की आइडियोलॉजी क्या है । किसका नाम रहेगा, डबल बनाने की जरूरत क्या है, आप उसी को मॉडल कर दीजिए ना । तीसरी बात, यदि आप ज़िद में हैं तो मैं पहले बोल चुका हूं छत्तीसगढ़ से ऐसे पांच लोगों का नाम बताइए जो फांसी पर झूले हों, सिर्फ पांच लोग । माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समावेशी विकास के मॉडल । मैं इस बात से सहमत हूं मैं जिसे समावेशी समझता हूं कि विकास ऐसा हो जिसमें लोगों को लाभ मिले, यह विकास मॉडल होना चाहिए । समावेशी विकास में आप छत्तीसगढ़ में एक ही बात गिनाते हैं कि मैं 2500 रूपया देता हूं, ठीक है देते हैं । आपके अफसर लोग बैठे हैं, 15वें वित्त में पंचायतों को एक भी निर्देश देने के

अधिकार हैं तो मुझे निकालकर बता दीजिए । यदि कानून का शासन चलाते हैं तो निकालकर बता दीजिए कि 15वें वित्त आयोग में ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया जा सकता है । बिजली कंपनियां 800 करोड़ के घाटे में चल रही हैं । आपके बड़े मित्र, आडवाणी और क्या-क्या नाम लेते हो, इसके मित्र हैं, उसके मित्र हैं । आपके मित्र लोग, आज सुबह भी यह साबित हुआ जब सल्फर डाई ऑक्साइड की जब बात हुई, बिजली में भी स्वीकार किया है इतनी बार नोटिस देते हैं, इतनी बार यह करते हैं, उतनी बार वह करते हैं । मैं कोरबा ईस्ट के बारे में भी बोलूंगा, जिसमें आपको कहां से ज्ञान प्राप्त हुआ, बेचने का आपने 70 करोड़ में दिया है । उस ज्ञान पर भी बात करूंगा, लेकिन आज उस पर बात नहीं करता । लेकिन एक भी बात बता दीजिए । अगर आप किसानों के हितैषी हैं तो किसान का मतलब धान खरीदना ही नहीं होता । एलाईट सेक्टर के लिए आपकी एक भी नीति नहीं बनी, एक नीति नहीं बनी । क्या किसान मतलब वही होता है । अब मुझे यह बताइए कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम एम.एस.पी. पर रबी फसल खरीदेंगे । आपके पास रबी की फसल खरीदने का क्या सिस्टम है । नान के उद्देश्य क्या हैं, मार्कफेड के उद्देश्य क्या हैं और कौन सी संस्था है आपके पास ? आप फिर लिखेंगे कि इसमें प्रयास किया जा रहा है, इसमें चालू किया जा रहा है, 24 हजार करोड़ के पुल-पुलिया बनने जा रहे हैं । समावेशी विकास और जहां से आपके असत्य कथन की बात..।

सभापति महोदय :- चलिए, संक्षिप्त कीजिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- बस दो मिनट में खत्म कर रहा हूं। 1715 उद्योग लगे। मुख्यमंत्री जी आप आपके दल के मंत्री और हम लोगों को शामिल करके संसदीय समिति बना दीजिए कि 1715 उद्योग कहां पर लगे हैं? आपका बयान है छत्तीसगढ़ में 1715 उद्योग कहां लगे हैं। समावेशी विकास, छत्तीसगढ़ में तस्कर आ गये, गंजेड़ी आ गये, सार्प शूटर आये, मॉब लीचिंग वाले आ गये, पेशावर हत्यारा आ गये, सतवरिया आ गये। प्रशासन के लोगों की पिटाई छत्तीसगढ़ में हो रही है। दुनिया ऐसा कोई अनैतिक काम नहीं है जो छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहा है तो यह समावेशी विकास है। अब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया इनका माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत उपयोग करते हैं। मैं हर बार विनम्रता से मांग करता हूं कि छत्तीसगढ़िया की परिभाषा आप तय कीजिए। who is छत्तीसगढ़िया। तो मेरा यह कहना है ...।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय सभापति महोदय, एक घंटा से ज्यादा हो गया है। चंद्राकर जी, दो मिनट में समाप्त करिए।

सभापति महोदय :- यह आसंदी का काम है। आप आसंदी को निर्देशित नहीं कर सकते। मुझे ध्यान है। मैंने उनको टोका है। आप अपने आदत को सुधारइये।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- नहीं, सभापति महोदय, मैं आपको निर्देशित नहीं कर रहा हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- सभापति जी, मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- दो मिनट में समाप्त कीजिए आप।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय मोहम्मद अकबर भैया। जो आप समझ रहे हैं, आप मंत्री हैं। आप समझ रहे हैं आप मंत्री हैं तो आप गलत हैं। शिवाजी का अष्ट प्रधान मण्डल होता था या अकबर के नौ रत्न होते थे। संवैधानिक सत्ता का संचालन करती है, आप दस्तखत करते हैं। लल्लू दादा, कल्लू दादा, कहां गये खाद्य मंत्री जी। भागीरथी का नाम लिया, मैं और नाम ले दूंगा । एक ड्राइवर थे, उसका नाम जानते हैं, ड्राइवर कितना पावरफूल है यह मैं नहीं जानता। पहले तो ड्राइवर बहुत पावरफूल था। अकबर भैया, गलत है या सही है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी ड्राइवर और कितना पावरफूल है, यह मैं नहीं जानता। पर बहुत पावरफूल था वह। तो ऐसे लोगा हैं जो इस प्रदेश का संचालन करते हैं। अब शैलेष पाण्डेय जी बोल रहे थे कि मोदी जी ने कोरोना में क्या दिया, क्या नहीं दिया, कैसे नहीं दिया। उसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। आप समझ रहे हैं न? लेकिन, आपने कोरोना सेस का हिसाब कभी नहीं दिया और आपने जो उत्तर दिया है। आज बता देता हूं मैं कोर्ट में हम लोगों की बात फाइल हो चुकी है। आप कोरोना के नाम पर दारू के हर साइज में सेस लगाकर...।

सभापति महोदय :- चलिए, चंद्राकर जी समाप्त कीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, बस एक मिनट ।

श्री धरम लाल कौशिक :- अजय जी, एक मिनट। माननीय सभापति जी, हम लोगों ने दो दिन का समय इसलिए रख रहे थे कि सभी पक्षों के लोग इसमें आराम से बोलेंगे। चार नाम उधर से आया। इधर से जो गया है तो आप इतनी जल्दबाजी कर रहे हैं। महामहिम जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं करेंगे, बाकी पर चर्चा नहीं करेंगे तो किस पर चर्चा करेंगे? अभी वे बोल रहे हैं कि दो मिनट में समाप्त करूंगा। समाप्त कर ही हरे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- दो मिनट में समाप्त कर देता हूं।

सभापति महोदय :- बहुत समय हो गया है। आप लगभग 25 मिनट बोल चुके हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- तो यह समावेशी विकास की परिभाषा आप समझ लीजिए। छत्तीसगढ़िया की परिभाषा के बाद अब छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी मैं बोलूंगा, आप उसको विलोपित मत करियेगा। आप क्या प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भाषा बन जाय और छत्तीसगढ़ी की जितनी बोलियां है वह बन जाये। बोलने भर से, नारा लगवाने से या सांकर पिटवाने से ही नहीं होता। छत्तीसगिढ़या, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ । अब छत्तीसगढ़ी में हम मंत्री जी पुन्नी नहाते देखा हैं। इस साल मंत्री जी क्यों नहाए नहीं, वह मुझे नहीं मालूम। पुन्नी नहात देखेन त खुश हो गयन, भंवरा ल देखेन त खुश हो गयन, सांकर ल देखेन त खुश हो गयन और रेती खदान कितको मिला है 385 का? कोरबा ईस्ट का ठेका किसको मिला

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है? आरी-डोंगरी कौन चला रहा है? उस समय छत्तीसढ़िया शब्द हट जाता है, आपकी परिभाषाएं बदल जाती है। आप थोड़ा-सा विश्वसनीयता बनाइये कि जो इंस्टीट्यूशन है।

सभापति महोदय :- चलिए, समाप्त करिए।

श्री अजय चंद्राकर :- रमन सिंह जी की घोषणा नहीं है, वह छत्तीसगढ़ सरकार की घोषणा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की घोषणा है और इस संकीर्णता से मुक्त होईये। मैं ऐसी संकीर्णता की अपेक्षा नहीं करता आपसे। जिसमें आप मंत्रिमण्डल में तथाकथित रूप से हो, माननीय अकबर जी हैं। आप 14-15 भाजपा नेता का नाम छपवाकर क्या साबित करना चाहते हैं कि यह सरकार कांग्रेस की है? मुख्यमंत्री का भाषण था कि सारे विधायक मेरे हैं, सबका मैं नेता हूं। बताईये कि 15 भाजपा नेता का नाम छपवाकर क्या साबित करना चाहते हैं। मत बेचिये । हम लोग लिखकर दे देते हैं कि आप धान नहीं बेचते करके। संकीर्णता इस सरकार की पूंजी है और बेलगाम यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी यदि सोचते हैं कि मैं हुक्का-बार बंद कर रहा हूं तो मैं आपको बार-बार बोलता था, मेरे साथ कुरूद चलो मैं आपको दारू पिला देता हूं। आप जहां पर बोलेंगे, वहां पर करके। भाई साहब उधर मत देखियेगा, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं।

सभापति महोदय :- चलिये, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- दूसरा, आपने हुक्का-बार को बंद करवाया तो आपको मोबाईल में हुक्का-बार देखना है क्या? मैं आपको दिखा सकता हूं। उसका कारण है, प्रशासन की नई शैली। कोयल से रायगढ़ तक कोयला का कॉरीडोर है।

श्री सत्यनारायण शर्मा (रायपुर ग्रामीण) :- धीरे बोलिये भैय्या, चीख मच जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- कोरिया से रायगढ़ तक कोयला का कॉरीडोर है। प्रशासन में ठेका पद्धति है। इनके उस एस.डी. को मुख्यमंत्री जी हटाये, उसके पास कितने लोगों के एडवांस पड़े हैं। माननीय शिक्षामंत्री को मालूम नहीं है कि एस.डी. के पास कितने हैं। अब इसकी तरह की घटनाएं हैं जो आपकी विश्वसनीयता को कम कर रही है। आप अच्छा करना चाहते हैं तो बाद में कायम रहिये। दृष्टिकोण को विशाल रखिये और मैंने मुख्यमंत्री जी पूछा है कि इस इसमें जो गलत छपा है उसमें आप किसमें कार्रवाई करेंगे करके। यदि कार्रवाई करते हैं तो ठीक है। यह छाया मंत्रिमण्डल है। वेस्ट मिनिस्टर की प्रणाली में असली सत्ता का सूत्र कहीं और है। ठेका पद्धति की सरकार है। वसूली की सरकार है। भ्रष्टाचार की सरकार है। हम कितने भी बड़े प्रमाण दे दे उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, यह हम जानते हैं। अवैध कब्जे की सरकार है। मैं आरंग में देखने गया था।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- यह आपकी सरकार इस तरह कर रही थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- सक्ती में, रायपुर में संस्थागत जमीन पर कब्जा हो रहा है। मैं अकबर भैय्या का बहुत हितैषी हूं। आज उनको सचेत कर देता हूं कि यदि उनके पीछे नाम किसी के हाथ हैं तो

अकबर जी का हाथ है । वह बेमतलब बदनाम हो रहे हैं। आप यह सुन लो कि छत्तीसगढ़ में और रायपुर में जितने जमीन विवादास्पद इधर-उधर हो रहे हैं गली-गली में चर्चा हैं और उसके पीछे एक ही नाम है। जो बड़ी चीजें बिक रही हैं उसमें एक ही नाम है और कहीं न कहीं से सूत्र आपके शीर्षस्थ स्थान तक जुड़ रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? 15 साल, 15 साल, 15 साल, जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश ऐसा कितने लोगों को मिला है? ऐसा कितने लोगों को मिला है?

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- ऐसे ही काम के संरक्षण के लिए आपको जनादेश मिला है? आज के पेपर में हैं परसों के। दो दिन पहले के। वह मंत्री जी बैठे हैं। नामांतरण में हजार रूपया, 2 हजार रूपया पेपर में इतने बोल्ड में छपा है।

सभापति महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, अब जो बचा है। आपको और अवसर मिलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है। चलिये मैं बैठ गया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय :- माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हेतु अभी 11 सदस्यों के नाम शेष हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि 5-5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण जो हुआ, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूं। राज्यपाल जी पढ़ना शुरू नहीं किये थे और हमारे विपक्ष के लोगों ने बिना सुने, बिना जाने, बिना समझे अनुशासन को भंग किया, उसकी मैं निंदा करती हूं। वह महामहिम हैं। संविधान की संरक्षक हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम नागरिक हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या और पुरानी सरकारों ने जो कर्ज से लाद दिया था, उन सबको उन्होंने समझा और समझने के बाद हमारी सरकार के मुखिया के द्वारा छत्तीसगढ़ में रहने वाले 80 प्रतिशत किसानों के लिए जो कार्य हो रहा है उसको उन्होंने जाकर जमीनी तौर पर देखा है और इसीलिए उन्होंने माननीय मुखिया के जो जनहितकारी विकास कार्य के बारे में कहा कि दुनिया में वह अलग पहचान बना रहे हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ मॉडल की न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी चर्चा हो रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस चीज की महत्ता को समझ चुके हैं और इसलिए अपने सचिव लेबल के अधिकारी को यहां पर सर्च करने के लिए भेजा है कि वास्तव में पूरे देश में 80 परसेंट किसान हैं और हमारे जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तो उन्होंने 21 वीं सदी में जाने की बात कही थी। लेकिन आज 21 वीं सदी की बात कहीं नहीं होती है तो इसका क्या कारण है? 80 परसेंट जनसंख्या का विकास रूक जाना किसी भी प्रदेश ने इस ओर सोचा नहीं है।

समय :
5:50 बजे **(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)**



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(पूर्व से जारी) डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी में जाने की बात कही थी। अगर 21वीं सदी की बात नहीं कही होती तो इसका क्या कारण है ? 80 प्रतिशत जनसंख्या का विकास रूक जाना । किसी भी प्रदेश ने इस ओर नहीं सोचा है, लेकिन हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने इस ओर ध्यानाकर्षित किया है । हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी सुराजी गांव की कल्पना करते थे । उनकी उस वाणी को याद करें तो वास्तव में सुराजी गांव क्या है, वह छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहा है । हमारे विपक्ष के साथीगण यही कहते हैं कि यह सब असत्य है, यह कुछ नहीं दिखता है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की बात है, मैं विपक्ष के साथियों को आंकड़े सहित बता देना चाहती हूं कि क्या-क्या काम हुआ है ? हमारी सरकार ने किसानों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, श्रमिकों, विद्यार्थियों, युवाओं के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में, नगरीय विकास में, मुख्यमंत्री सड़क योजना के रूप में, राजीव मितान योजना के रूप में, पर्यटन के रूप में, पत्रकारों के लिए, कोरोना संकट से उबरने के लिए और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण काम किये हैं । मैं विपक्ष के साथियों को आंकड़ा बता देना चाहती हूं, वैसे वे जानते हैं, लेकिन जान-बूझकर उसको नकारना चाहते हैं । इसकी पीछे इनकी क्या मंशा है, यही जानें । यदि सोच सकारात्मक है तो परिणाम अच्छा होगा । कृषि ऋण माफी की बात है तो आप आंकड़ा देख लीजिए । पैसा क्या अपने आप उठकर चला जाएगा ? 18 लाख, 82 हजार रूपए दिए गए हैं, सिंचाई कर 224.18 करोड़ रूपए माफ किया गया है । किसानों की 1764.61 हेक्टेयर भूमि लौटाई गई है । धान खरीदी में सबसे रिकार्ड तोड़ 97.58 लाख मेट्रिक टन धान खरीदी हुई, आजतक कोई सरकार नहीं खरीद पायी है । राजीव किसान न्याय योजना के तहत अब तक तीन किश्तों में 4523.77 करोड़ माफ किया जा चुका है । साथ ही जो किसान एक एकड़ में वृक्षारोपण करेगा, उसको 10 हजार रूपये देने की बात कही ।

माननीय सभापति जी, मैं यह कहना चाहती हूं कि आजतक सीधे व्यक्ति के हाथों में, सीधा जनता के हाथ में पैसा नहीं गया है, लेकिन ऑनलाईन सुविधा के कारण हर व्यक्ति के हाथ में पैसा गया है, जिसका वे लाभ उठा रहे हैं । राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना में 3.50 लाख परिवारों को फायदा हुआ है । गोधन न्याय योजना की चर्चा, जब मैं उत्तरप्रदेश गई थी तो उत्तरप्रदेश के लोगों ने गोधन न्याय योजना की बहुत तारीफ की । वे कहते थे कि काश, हमारे योगी जी की सरकार यह काम करती तो आज उत्तरप्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी होगी, उत्तरप्रदेश बहुत प्रगति करता । इसी तरह से सुराजी ग्राम योजना के तहत 8119 गोठान, 2008 नरवा और 5958 घुरवा के कार्य चल रहे हैं । उसी तरह से 2 लाख, 13 हजार बाड़ियों का विकास और मिलिंग योजना के तहत कोदो-कुटकी को कोई सरकार नहीं खरीदती थी, पूछते भी नहीं थे, उसे भी हमारी सरकार 3 हजार रूपये समर्थन मूल्य में खरीद रही है, ताकि यहां के किसानों का विकास हो । जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, तब तक


अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हम विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं । यह सब चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, जिस देश में 80 प्रतिशत किसान रहता है, यदि उसकी संस्थागत् संरचनाओं का विकास नहीं करेंगे, उनके हित की बात नहीं करेंगे तो वे कैसे विकास करेंगे । पिछली सरकार ने 2100 रूपये समर्थन मूल्य की बात कही थी, बोनस देने की बात कही थी, लेकिन जब मांग की गई तो उन्होंने डंडा बरसाया। यह धमतरी की घटना है, माननीय अजय चन्द्राकर जी भी जानते हैं । उनको लाठियां मिली, लेकिन कुछ नहीं मिला । हमारे मुखिया हैं, जो किसानों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं क्योंकि किसान खेती करना भूल गए थे । किसान लोग खेत को रेगहा में चला रहे थे। कई लोग तो पलायन भी कर रहे थ। बड़े किसान तो खेती करना लगभग छोड़ चुके थे। तो जब उनका विकास करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा, तभी तो समावेशी विकास होगा। माननीय मुखिया ने इस बात को बारीकी से समझा और इसके अनुरूप कानून बनाया। लोगों के हाथों में सारा पैसा गया है। यह केवल ढकोसला और खोखला नहीं है। यथार्थ में काम हुआ है। ये लोग रायपुर में बैठकर राजनीति करेंगे। उनके मुखिया माननीय पुरंदेश्वरी जी की ही बात सुनते हैं और उनके निर्देश अनुसार कदम उठाते हैं। यह बिलकुल गलत है। आप जमीन में जाकर देखें, आप गांव में जाकर देखें। पहले नरवा का कितना विकास हुआ था क्योंकि ये लोग नरवा को पाट दिए थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं स्कूल की बात कहूं, तो पिछले 15 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र के 50 स्कूल डिसमेंटल के लायक थे। डेढ़ सौ स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। इन्होंने 15 साल तक स्कूलों की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या स्काई वॉक जरूरी था या स्कूल जरूरी था ? ये लोग इस पर क्यों ध्यान नहीं दिए ? यदि वन विकास की बात कहूं तो अभी तक इन्होंने जो वादा किया था, वह नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार ने जो बात कही थी, उसको पूरा किया और वन अधिकार के तहत 4,51,502 व्यक्तिगत पट्टा, 46 हजार से अधिक सामुदायिक वन अधिकार दिया गया है। देश में अग्रणी राज्य है, यहां तक नगरीय निकाय में नगरी को दिया गया, जो आज तक एशिया में नहीं हुआ है। वहां भी अधिकार दिया गया है। अभ्यारण्य में कहीं पट्टा नहीं दिया गया था, लेकिन 6 अभ्यारण्य में भी सामुदायिक वन अधिकार पट्टा देकर आदिवासियों के हित के लिए काम किया है। तेन्दूपत्ता का मानक बोरा भी 4 हजार रूपया किया गया है। जो 65 वन उपज हैं, उसको भी समर्थन मूल्य में लेने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह सब समर्थन मूल्य देकर आदिवासियों की आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने का प्रयास किया गया है। यदि मैं श्रमिकों की बात कहूं तो श्रमिकों की ओर भी ध्यान दिया गया है। सेवानिवृत्ति की आयु भी 58 से 60 वर्ष कर दी गई। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रमिक नीति बनाई गई है। आप लोगों को पता ही है कि श्रमिक कोरोना काल में किस तरह से भटक रहे थे। उनको व्यवस्थापित करने के लिए, उनके लिए क्वारनटाइन, उनके लिए वेंटीलेशन, उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाने-पीने की सारी व्यवस्था की गई। मजदूरी की व्यवस्था किसने की ? माननीय सभापति

महोदय, मैं यह बताना चाहती हूं कि इस कार्यकाल में एक तरफ प्राकृतिक विपदा थी, एक तरफ कोरोना की महामारी और तीसरा राज्य कर्ज से दबा हुआ था। ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश की नागरिकों को स्वस्थ रखने और उनको आगे बढ़ाने के लिए किसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया है, तो उसमें माननीय भूपेश बघेल जी का नाम आता है। आज तक इतने संकटों से जूझते हुए किसी ने शासन नहीं किया है और न ही जमीन के लोगों को उठाने का प्रयास किया है। हमारे छत्तीसगढ़ की जनता जब इस स्थिति को देखती है, तो वह कहती है कि छत्तीसगढ़ में ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। आज तक ना ऐसा मुख्यमंत्री मिला है, ना मिला होगा जो छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचता हो, जो छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में सोचता हूं। महिलाओं के विकास के लिए भी ध्यान दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री विवाह योजना में जो 15 हजार रूपये देने का प्रावधान था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाकर 25 हजार रूपया किया है। महिला बाल विकास की जो महिला स्वसहायता समूह थी, उन बहनों का कर्ज माफ किया गया। क्योंकि वे लोग कोरोना काल में परेशान थीं, उनको घाटा था। तीजा के दिन 77 लाख रूपये माफ किया गया। इसके अलावा 11 करोड़ 65 लाख का ऋण भी दिया ताकि आर्थिक दृष्टिकोण से महिलाएं अपना कारोबार कर सकें और सशक्त हो सकें। बजट में भी 5 गुना बढ़ाने की बात कही गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि की गई तथा मृत्यु दर में भी 10 हजार तथा सेवानिवृत्ति में भी 50 हजार रूपये देने की घोषणा की है। बहुत सारी घोषणाएं हैं, मैं तो बहुत कम बात बता रही हूं। लेकिन इतनी सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को महिलाएं स्वीकार कर रही हैं, अनुकरण कर रही हैं, अनेक स्वसहायता समूह की बहनें आर्थिक दृष्टि से कुछ न कुछ क्रियाकलाप कर रही हैं, जिसके कारण वह आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है । महिलाओं का जितना ज्यादा विकास हो, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, महिलाओं का विकास तेजी से हो रहा है, विद्यार्थियों और युवाओं के लिए भी बहुत सारे कार्य किये हैं । स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल मील का पत्थर है । भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तो स्कूल भी बंद हो रहे थे । भिलाई का हिन्दी मीडियम पूरा बंद हो रहा था । आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, भूमण्डलीकरण का युग है । इस स्थिति में यदि छत्तीसगढ़ के बच्चों को उसके अनुरूप नहीं बनायेंगे तो कैसे काम चलेगा । हमारे मुख्यमंत्री जी ने ग्लोबलाइजेशन के युग में बच्चों को ग्लोबल दिशा देने का प्रयास किया है और यह स्कूल बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है । उसी तरह से महतारी, दुलारी योजना के तहत 2372 लोगों को जो सुविधायें मिल रही है, शिक्षकों की भी भर्ती हुई है, पढ़ई तुंहर द्वार, तुंहर पारा, इसको भी सराहना मिली है । प्राध्यापकों की भी भर्ती हुई है, जो भर्ती हुई है, रोजगार भी दिया जा रहा था, जैसे यदि गंभीरता से सोचा जाये, एक के बाद एक जो प्राथमिक पाइंट था, उसकी इस छत्तीसगढ़ में बहुत आवश्यकता थी । उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा, हमारे कैबिनेट के मंत्रियों ने समझा, पर्यटन को भी दिशा देने का प्रयास किया, मेरे सिहावा विधान सभा में राम वनगमन पथ के

तहत डेवलप करने का काम किया है । मैं यही कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के साथी ने छत्तीसगढ़ के विकास में बहुत अचछा काम किया है । समावेशी विकास करने का प्रयास किया है, आप लोगों के हाथ में पैसा मिल रहा है, बस यही कहना चाहती हूँ और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ । आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद ।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- सभापति महोदय, माननीय महामहिम जी ने सदन में जो अपना अभिभाषण पढ़ा है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है, महामहिम के इस धन्यवाद प्रस्ताव का हम विरोध करते हैं । माननीय सभापति महोदय, जिन बिन्दुओं का उल्लेख अभिभाषण में किया गया है, उसका सरकार के कामकाज से कोई ताल्लुकात नहीं है । यह तीसरी बार है, उन्हीं शब्दों का उल्लेख किया गया है । माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, अटल जी ने एक बार कहा था कि सरकारें आती-जाती हैं, देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिये, प्रजातंत्र जिंदा रहना चाहिये । वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो परिवेश है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा है और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इस पर मुख्यमंत्री को ध्यान देने की आवश्यकता है, इस सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है । 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, तीन साल से यह भी सरकार है । माननीय सभापति महोदय, इस सरकार के पास न तो कोई विजन है, इस सरकार की नीति और नियम दोनों खराब है, इस छत्तीसगढ़ सरकार की दिशा और दशा दोनों खराब है । आज गांव-गांव में इस बात का हाना होता है कि दूध के बंधा गे हे चण्डी अऊ गांव-गांव में खुल गे हे शराब के मंडी । यह गांव वाले लोग बोलते हैं, गुड़ी में चौपाल में, चर्चा में और छत्तीसगढ़ शनैः शनैः अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है । छत्तीसगढ़ में इन तीन सालों में जितने नित-नये प्रकार के अपराध हो सकते हैं, वह सारे घटित हो रहे हैं, जिसकी कल्पना छत्तीसगढ़ की जनता नहीं कर सकती है । यहां का अवाम नहीं कर सकता है । चाहे वह शहर हो या गांव हो । आज एक ध्यानाकर्षण में साईबर अपराध के बारे में चर्चा हो रही थी । यह अपने आप में अनूठा है । देश के महानगरों के तर्ज पर अपराध हो रहे हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास उर्जा विभाग भी है ।

श्री रामकुमार यादव :- भईया, एक ठन गांव में घलो चर्चा होथे गा ।

श्री नारायण चंदेल :- कले चुप बैठ ।

श्री रामकुमार यादव :- अऊ ला कछु कइथे अंबर, हमर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हावय देश में एक नंबर ।

श्री नारायण चंदेल :-माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पास उर्जा विभाग भी है, मेरे क्षेत्र में मड़वा पॉवर प्लाण्ट है । पिछले 2 जनवरी को आपसे और आपके एम.डी. से उन्होंने वार्ता के लिए समय मांगा। जो मडंवा पॉवर प्लाण्ट के भू-स्थापित लोग हैं, जो वहां पर नौकरी करते हैं, जिनका नियमितिकरण आज तक नहीं किया गया है। लेकिन न तो एम.डी. ने समय दिया, न प्रशासन के आला अधिकारियों ने समय

दिया। शायद आपके पास भी वह अर्जी आई होगी। अगर समय पर वार्ता हो जाती तो मुझे लगता है कि शायद उस समस्या का समाधान निकल जाता। क्योकि बातचीत से, वार्ता से ही समस्या का समाधान निकलता है। लेकिन 2 जनवरी को, उनका क्रमबद्ध आंदोलन एक महीने से चल रहा था। पिछले 2 जनवरी को ठीक नये साल के दूसरे दिन मड़वा पॉवर प्लाण्ट के बाहर में उन कर्मचारियों के ऊपर में भीषण लाठीचार्ज होता है और 19 लोगों को जेल भेज दिया गया है। 400 लोगों के ऊपर non-bailable मुकदमें दर्ज किये गये हैं। यह सिर्फ मड़वा पॉवर प्लाण्ट की बात नहीं है। आज भी हमारे नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जी गये थे। पूरे राजधानी में कर्मचारी आंदोलनरत हैं। क्यों न हम कर्मचारियों के साथ बैठ करके बातचीत करके उनकी जो न्यायोचित बातचीत है, उनकी जो मांग है, उस पर हम अमल करें। यह शासन, प्रशासन का काम है। लेकिन यह सरकार उस पर विफल है, यह दुर्भाग्य की बात है। आज चारो तरफ हताशा और निराशा का वातावरण है। इस प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता का भी वातावरण है। माननीय सभापति महोदय, क्या होगा, कैसे होगा? बहुत से अधिकारी, कर्मचारियों से बातचीत होती है तो वह बोलते हैं कि अभी तो हम काम नहीं कर रहे हैं। हमने फाईल को आलमारी में रख दिया है। हमने कहा कि क्यों रख दिये हो? पता नहीं इस प्रदेश में क्या स्थिति बनने वाली है। यह ऊहापोह की जो स्थिति है, यह साफ होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, हमारे सारे विधायक साथी हैं, सब लोग जनता के आशीर्वाद से इस सदन में चुनकर के आये हैं। लेकिन आपने छाया विधायक बना दिया है। यह छाया विधायक क्या है, यह साफ होना चाहिए। छाया विधायक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन वह सरकारी कार्यक्रमों में जा करके भूमिपूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। विधिवत रूप से सरकारी अधिकारी कलेक्टर, वहां का विकासखंड अधिकारी, एस.डी.ओ., तहसीलदार उनके नाम से कार्ड छपवा रहे हैं और वह आयोजन कर रहे हैं। यह नेता प्रतिपक्ष जी के क्षेत्र में भी हुआ है। यह प्रजातंत्र, लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के इस धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से आप तक इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूं।

माननीय मुख्यमंत्री जी खेती, किसानी की बहुत बात होती है। आप किसान हैं। इस सदन के अधिकांश लोग किसान हैं। लेकिन अभी जो खरीफ फसल में धान खरीदी हुई है, हमारा जांजगीर-चांपा जिला सर्वाधिक कृषि का रकबा वाला जिला है और सर्वाधिक सिंचित जिला है, लेकिन पूरे जिले में तालाब को खेत बता करके धान बेच दी गई है। निस्तारी भूमि को खेत बता करके उसका रकबा और खसरा नंबर दे करके धान बेच दी गई है। सिर्फ हमारे जिले में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुनियोजित ढंग से एक पूरा रेकेट काम कर रहा है जो किसानों के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। समाचार-पत्रों में बड़ी प्रमुखता के साथ में छपा है। मैं आपको उन धान खरीदी केन्द्रों का नाम भी बता देता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ग्राम महंत, कीरित, तुलसी, किरकोट है।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- कृपया संक्षिप्त करें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ी अलग टाईप की बात बोल रहा हूं। क्योंकि जितने लोगों ने अभी तक अभिभाषण में बात की है, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं, इसलिए मैं उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि सुधार की आवश्यकता है। प्रशासन को सशक्त होने की आवश्यकता है, नहीं तो छत्तीसगढ़ बेलगाम होते जा रहा है। आपने सत्तू भैया की कमेटी बना दी। जब शराब की चर्चा होती है, यह ढरक जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, अब शराबबंदी की चर्चा सब लोगों ने छोड़ दी है। क्योंकि अब लोगों का विश्वास सरकार से उठ चुका है और जितने वायदे इस सरकार के द्वारा किये गये हैं, 1-2 वायदों को छोड़कर इस सरकार ने किसी भी वायदों को पूरा नहीं किया है और इसलिये जनता के मन में हताशा और निराशा है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में है और मेरा आग्रह है कि जब आप का उत्तर आयेगा या आम बजट में उत्तर आये कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है । 51 हजार करोड़ के कर्ज से हम करहा रहे हैं। कर्ज के ब्याज से छूटने के लिये हमको कर्जा लेना पड़ रहा है। आपसे निवेदन है कि आपका जब उत्तर आये, या अभिभाषण में आये या आम बजट में आये तो इस प्रदेश में सदन चल रहा है, आर्थिक श्वेत पत्र जारी होना चाहिये ताकि इस प्रदेश की जनता को मालूम चल सके कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। यह मार्च का महीना है, क्लोजिंग का महीना है। पिछली बार 6 महीने, 7 महीने से वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन और कर्मचारियों को वेतन के लिये 6-6 महीने के लिये लाले पड़ गये थे।

सभापति महोदय :- चंदेल जी संक्षिप्त करें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, जब वह ट्रेजरी में जाते थे, तो पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के बाद में वहां के ट्रेजरी अधिकारी का जवाब होता था कि सर्वर डाऊन हो गया है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के 2000 में बनने के बाद 22 साल में पहली बार यह स्थिति आयी है कि वे बेचारे सर्वर डाउन वाले शब्द सुनते थे और हताश और निराश होकर वापस आते थे। इसलिये हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस सरकार से आग्रह है कि प्रशासन को थोड़ा चुस्त-दुरूस्त करिये और जिस प्रकार से प्रशासनिक अमला बेलगाम होता जा रहा है और शासन के संरक्षण में होते जा रहा है, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि इस प्रदेश के राजस्व मंत्री अपने ही जिले के कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वह सर्वाधिक भ्रष्ट कलेक्टर है। इस प्रदेश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है, इसलिये संवैधानिक संकट पैदा हो गया है कि जिस मंत्री ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है, सरकार को संचालित करने की। उसने प्रशासन के एक आला अफसर के ऊपर में यह आरोप लगाया कि यह सर्वाधिक भ्रष्ट है, इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता है और आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

सभापति महोदय :- श्री प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल जी के धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश, कृषि प्रधान प्रदेश है और इसे धान के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है और हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिये जो किया है वह आज तक इतिहास में न हुआ था, न हुआ है। आज हम किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं और खासकर की राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हमने उनके धान को 2500 रूपये की कीमत में लाभ देकर, किसानों की आय को निरंतर बढ़ाने का काम किया है। न केवल धान बल्कि मक्का, सोयाबीन, गन्ना व चना के अलावा रागी, कोदो, कुटकी जैसी जनजाति फसलों को भी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करके उनका क्रय किया जाएगा। इस वर्ष धान खरीदी के लिये 173 नवीन धान खरीदी केंद्र बढ़ाये गये और जिससे किसानों को लाईन में नहीं लगना पड़ा और उनका धान आसानी से क्रय हो गया जिससे किसान खुश है। गोधन न्याय योजना, जिसकी न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में चर्चा हो रही है और इस मॉडल को पूरे देश के लोग अपनाने के लिये तैयार है। हर राज्य में इसकी चर्चा हो रही है। इस योजना के तहत गोबर विक्रेताओं से लगभग 127 करोड़ रूपये की गोबर खरीदी की गयी और 6 लाख मीट्रिक टन से जैविक खाद का निर्माण किया गया, यह अपने आप में एक इतिहास है। जो गौ पालक है उनके गौ वंश के रक्षा के लिये जो गोधन न्याय योजना है यह बहुत ही सफल साबित हुई है, उनके जेब में पैसा गया है और हमारे गौपालक सुदृढ़ हुए हैं। न केवल गौधन योजना बल्कि उद्यानिकी को भी हमारे प्रदेश में बढ़ावा दिया गया है। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। दुर्ग जिले के सांकरा में उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। जिसका शिलान्यास 2 अक्टूबर, 2020 में किया गया एवं उद्यानिकी संबद्ध किसानों के कल्याण के लिए साकंबरी बोर्ड का गठन किया गया है। बिजली बिल हाफ की योजना बहुत अच्छी योजना है इससे लगभग 40 लाख, 56 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को 2 हजार 100 करोड़ रूपये से अधिक की छूट मिल चुकी है और 5 लाख 81 हजार किसानों को सिंचाई के पम्प कनेक्शन में छूट का लाभ तथा 17 लाख से अधिक परिवारों को 30 यूनिट तक प्रति माह नि:शुल्क बिजली आपूर्ति की जा रही है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार लगातार लोगों की आय वृद्धि के लिए काम कर रही है जल जीवन मिशन में हम लोगों ने 48 लाख 59 हजार448 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, जो बहुत जल्द पूरा होगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश में सिंचाई क्षमता के विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। 42 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के लिए निर्मित और 3 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। जैसे खारंद, मनियारी, अरपा, केलो की सिंचाई की क्षमता में विकास किया जा रहा है। किसानों की लंबित 142 करोड़ रूपये जल कर माफ किया गया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिला है।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- प्रकाश भईया, आपके यहां के सिंचाई के व्यवस्था ला दूरूस्त करवा लो आज। आज आप ध्यानाकर्षण लगवाए रहेव।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय सभापति महोदय, आज मैंने ध्यानाकर्षण लगाया था। माननीय मंत्री जी का उसमें आश्वासन आया है कि वर्ष 2023 तक उस केलो जलाशय...।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :-उसमें कहा गया कि इसकी समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय मंत्री जी वर्ष 2023 बता दिये हैं।

सभापति महोदय :- माननीय प्रकाश जी, आप विषय में आईये।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य सुविधा में भी हमारा प्रदेश अग्रणी क्षेत्र में जा रहा है। लगातार स्वास्थ्य सुविधा के विकास के लिए काम किये जा रहे हैं। हमारे प्रदेश में 03 नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई है। नए 50 उपस्वास्थ्य  केन्द्र तथा 30 प्राथमिक स्वास्थय  केन्द्र, 2 जिला अस्पताल, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य योजना, श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई-दीदी क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना से आमजन को लगातार स्वास्थ्य में सुविधा मिल रही है। कोविड में जो मृत व्यक्ति के परिजन हैं, उनको 1 से 2 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब की चर्चा पूरे प्रदेश, देश में है। इसमें प्रदेश के युवाओं के सामाजिक विकास, कार्यों में भागीदारी तथा उनकी नेतृत्व क्षमता को विकसित करने के लिए 13 हजार 269 राजीव गांधी युवा मितान क्लब की स्थापना की जा रही है। इसमें हमारे जो युवा हैं वह लगातार खेल में आगे बढ़ेंगे और रायपुर के गैर आवासीय हॉकी, तीरंदाजी, बालिका फुटबॉल, एथलेटिक, धनुर्विद्या अकादमी तथा बिलासपुर में आवासीय तिरंदारजी हॉकी तथा एथेलेटिक एकादमी के माध्यम से खेलकूद को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। श्री केशव प्रसाद चन्द्रा जी।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक :- एक मिनट। यह आखिरी है। माननीय सभापति महोदय, राम वनगमन पर्यटन परिपथ के तहत हमारे प्रदेश के 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है जिसमें से प्रथम चरण में 9 स्थानों पर अधोसंरचना विकास का काम किया जा रहा है। रायपुर के निकट ग्राम चंदखुरी में माता कौशल्या के प्राचीन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार किया गया है। शिवरीनारायण, जगदलपुर, राजिम एवं रामाराम (सुकमा)आदि है।  माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण मा कृतज्ञता ज्ञापन मा बोलना चाहत हौं।

माननीय सभापति महोदय, सबले पहली तो ये अभिभाषण में ए बात के जिक्र होना रिहिस कि ए सरकार के आये के पहली जब जनघोषणा पत्र बनाये के कमेटी बनीस, ओकर अध्यक्ष हर ये प्रदेश के कतका झन ला ओ चिट्ठी ला लिख के दे रिहिसे, तुंहर बर का-का करबो। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मन ला सरकार बनते साथ, तुमन ला नियमित कर देबो। अउ तो अउ गांव में जनभागीदारी समिति के माध्यम से स्कूल खुले रिहिस हे, ओमा पढ़ाए रिहिन हे, तुहू गुरूजी मन लाकहे हावए कि सरकार बने के बाद तुमन ला शिक्षक बना देबो । बेरोजगार मन ला बेरोजगारी भत्ता देबो। प्रदेश के अइसे कोई नई बाचे रिहिस जेला ओ अध्यक्ष के चिट्ठी नई मिले रिहिस। ओ तो हमन ला तब पता चलिस जब ओमन आथय, ज्ञापन देथे अऊ चिट्ठी के कापी ला ओमा लगाय रथय। लेकिन अभिभाषण मा ए बात के जिक्र नई हे। अगर सरकार ला अपन उपलब्धि गिनाना रिहिस ता ए बात के उपलब्धि ला गिनाना रिहिस हावए कि तकता अकन झूठ, फरेब अऊ कतका अकन धोखा दे करके ए सरकार ला हम बनाय हाबन। अऊ आज ओतके अकन आदमी मन ला जो हे झूठा आश्वासन मा रख हावन। धान खरीदी के बात हे, सबले ज्यादा लक्ष्य ला प्राप्त करे हन कहात हे, सही बात हे। ऐ साल सबले ज्यादा धान बिकीस हे। छत्तीसगढ़ मा जब ले समर्थन मूल्य मा धान खरीदी शुरू होय हावय, हर साल एक नया लक्ष्य हासिल करत जात हे, मोर हिसाब से ओमा सरकार के कोई उपलब्धि नई ए। सरकार के उपलब्धि तब होतिस जब सरकार हा 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन के जो लक्ष्य रखे रिहिस हे, ओ लक्ष्य ला पूरा करतिस तेहा सरकार के उपलब्धि होतिस। 173 खरीदी केन्द्र ला भी अपन उपलब्धि बतात हे लेकिन मैं सरकार करा ले जानना चाहत हव 173 खरीदी केन्द्र खुलिस तेहा कोन मापदंड मा खुलिस। जिहां 50 हजार क्विंटल टन धान खरीदी होत हावय, ओमा नया उप केन्द्र खोलए, 65 हजार धान खरीदी केन्द्र मा उपकेन्द्र खोलए, 80 हजार क्विंटल जिहां धान खरीदी होत हे, तिहा उपकेन्द्र खोलए या केवल सत्ता पक्ष के विधायक हे जिहां सिफारिश करिन ऊहां नया उपकेन्द्र खोलए या फिर दूरी के हिसाब से खोलए। सरकार के कोई न कोई तो मापदंड होही जेखर आधार पे आप नया उपकेन्द्र खोलए के काम करय हावव।

माननीय सभापति महोदय, केवल सरकार के पक्ष के विधायक मन के क्षेत्र मा उपकेन्द्र खोलए या केवल सत्ता पक्ष के विधायक हे, तिहेच किसान मन ला सुविधा मिलय, ए सरकार के लक्ष्य नई होना चाहिए बल्कि सरकार के लक्ष्य होना चाहिए कि या तो दूरी मापदंड रहाय या खरीदी मापदंड रहाय, अऊ जहां किसान मन ला सुविधा मिलय ऊहां खोलना चाहिए। अभी अपन उपलब्धि मा बताय हावए कि छोटे उपखंड ला, छोटे भूमि ला जेला ए सरकार हा प्रतिबंध लगा दे रिहिस ओला बेचे के अधिकार दे हन। लेकिन हमर विधानसभा अध्यक्ष जी के क्षेत्र सक्ती मा, एक आई.ए.एस. एस.डी.एम हे, ओ हा सरकार के कानून ला नई मानय, काबर की ओ आई.ए.एस. ए, जतका छोटे उपखंड के प्रतिबंध हे, ओमा रोक लगा दे हे। सक्ती मा छोटे उपखंड के खरीदी, बिक्री नई होत हे। ओहा सरकार से ऊपर हे। अऊ ओकर प्रोटोकाल अधिकारी आए ता ओकर क्षेत्र मा कोई भी जनप्रतिनिधि के सम्मान नई हे। माननीय सभापति

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सर्किट हाऊस मा एक दिन फोन कर देहें कथए आप सर्किट हाऊस मे क्यों रूकोगे। आपका तो घर है। ए आपके प्रशासन मन के मुखिया मन के जवाब ए। अतका प्रशासनिक आंतक हो गेहे, अऊ ऐ रवैया हावए। आपके आदेश हे, बढ़िया बात हे, छोटे भूखंड से वास्तव में बहुत आदमी परेशान रहिस हे। आप आदेश करव, राहत मिलिस, लेकिन आपके आदेश सरकार के आदेश के पालन एक एस.डी.एम. नइ करत हावय। आप अपन अधिकारी के माध्यम से पता करवा लिहा। आप जिला खनिज न्यास संस्थान के उपलब्धि बताय हावव। अऊ ओमा का होवत हावए। का विकास होत हे, केवल ठेकेदार मन के विकास होत हे। तमाम काम ठेका के माध्यम से होत हे। कहां ले ठेकेदार गे हे, पता नई हे। का काम के स्वीकृति हे, पता नई हे, सरपंच ला पता नई हे, विधायक ला पता नई हे, गांव के आदमी ला पता नई हे, ऊहां काम होगिस आ गिस, कोई बोर्ड नई लगय हे। आप हमन ला शामिल करव हव, धन्यवाद। ओ खनिज न्यास संस्थान मा आप हमन ला सदस्य बनाय हव ओखर लिए धन्यवाद। लेकिन शायद हमन ओमा सदस्य नइ बन के ज्यादा खुश रेहेन। आज सदस्य बन करके ओ जनता ला जवाब नई दे सकत हन। यात्री प्रतिक्षालय कहां बनगे जहां बस नई चलत हे, जहां यात्री नई रूकना हे। काबर साढ़े 6 लाख मा यात्री प्रतिक्षालय बने हे, 50 प्रतिशत के कमीशन हावय, अऊ केवल 50 प्रतिशत मा बनना हे ता शायद ओधा मा बनही ता ओ हा ज्यादा बढ़िया रही। सब के बीच मा बनही आदमी मन के बइठे के लायक बनही ता आदमी मन दुखी होही। गांव मा बिजली लग ले, गांव के सरपंच ला मालूम नई हे, कोन मद के बिजली लिगस। गांव मा जिम खुलगे, मोर गांव हा भी सौभाग्यशाली हे, ए ठन जिम स्वीकृत होय हे। का के जिम हे भैया ? नइ पता, बोर्ड ला लगा दे हे । अगर जिला खनिज न्यास संस्थान के एक बोर्ड लगा दे हे कतका लागत के ? नारियल तोड़वा दे भई, नारियल तोड़वाये के आदेश नइ हे । कोई जनप्रतिनिधि नारियल नइ तोड़ सकय, अधिकारी आकर नारियल तोड़हीं । माननीय चंदेल जी कहिन हवय जनप्रतिनिधि के कतका अकन अगर अवहेलना होत हे, अगर ओ कोई जिला में हे ता जांजगीर-चांपा जिला में हे ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्व न्यायालय में पारदर्शिता अइस हवए । ऑनलाईन आवेदन होत हवए । लोकसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन आये हे । अभी लगातार पेपर मा छपिस है । राजस्व विभाग के सचिव समीक्षा करिन, कतका अकन नामांतरण के, कतका अकन फौती के, कतका अकन अविवादित बंटवारा के प्रकरण न्यायालय मा लंबित हे । जब आप ऐमा पारदर्शिता लात हओ ता समय-सीमा में ये काबर पूरा नइ होत हे ? आज गांव वाला मन के आदमी मन के कहना हे कि ग्राम पंचायत ला अधिकार रहिस, पटवारी हा फौती काट देवए, अविवादित बंटवारा ला कर देवए, नामांतरण ला कर देवए ता सस्ता मा निपट जान अब तो ऑनलाईन आवेदन करत हन, वकील खड़ा करत हन, तहसीलदार करा बहस करत हन अऊ ओ नोटिस काटत हवए, इश्तिहार प्रकाशित करत हे, कोई दावा आपत्ति कर देत हे तो साल-साल भर केस चलत हे अऊ आदेश भी कर देत हे ता पटवारी हा अपन हिसाब-किताब बर

तगड़ा उंहा बइठेच हे, जब तक हिसाब-किताब नइ करबे तब तक मैं तोर ऑनलाईन नइ चढ़ाओं ।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, बस दू मिनट । सुविधा कहां मिलिस उल्टा आदमी परेशान होगिन । दिक्कत मा आगिन अऊ फौती जइसे महत्वपूर्ण, फौती जइसे चीज बर अगर एक साल आदमी घूमत हे, कतका किसान धान बेचे से वंचित होगिन ? बंटवारा बर कतका अकन घूमत हांवएं ? स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल बढ़िया हे, ओकर बर धन्यवाद हे ।

सभापति महोदय :- श्री पुन्नूलाल मोहले ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, आपका आदेश रहेगा तो एक मिनट बोल लूंगा ।

सभापति महोदय :- चलिये ठीक है, जल्दी समाप्त करें ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, मैं समाप्त कर दूहूं । मैं ज्यादा समय नइ लओं लेकिन अउ बाकी सदस्य मन ला समय दे हा तइसनहे कृपा बना देता कहत हंओं ।

सभापति महोदय :- 10 मिनट हो गये हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम 171 स्कूल खुले हे । या तो हमन ला समझ मा नइ आत हे या मंत्री जी ला समझ में नइ आत हे कि जो पुराना स्कूल हे ते हा काबर बंद होत हे ? मंत्री जी अपन जवाब में कहत हे कि बंद नइ करत हां लेकिन वही आदेश करके पूरा के पूरा गुरूजी ला वहां से ट्रांसफर कर दे हें । अऊ कइसनहा स्कूल हे पूरा के पूरा कन्या स्कूल । अगर आपके नीयत हे ओ स्कूल ला चलाना हे, पुराना हिंदी माध्यम ला ता आप पूरा के पूरा स्टॉफ के काबर ट्रांसफर करत हओ मतलब कहीं न कहीं सरकार के नीयत मा खोट हे कि ओ लइका मन ला प्रताड़ित करए अऊ कौन लइका अऊ कौन पालक अपन लइका ला बिना गुरूजी के स्कूल मा भर्ती करे बर भेजहीं । एक तरह से ये षड़यंत्र चलत हावय ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें । श्री पुन्नूलाल मोहले जी ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय सभापति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण मा सरकार के तरफ से आये हे कि पुलिस बल को विश्वास, विकास, सुरक्षा का मंत्र दिया गया है । ये हमर एक विधायक हें, पुलिस के कतका अकन आतंक हे, सत्तापक्ष के विधायक हे । एक विधायक आरोप लगात हे मंत्री के ऊपर कि मोर हत्या कर दिहीं करके अऊ मोर क्षेत्र में एक घटना घटिस हे 12 साल के लड़की लापता होगे । पुलिस करा दू दिन ले रिपोर्ट लिखाय बर गिन ता नइ लिखिन, संदेह करिन हे कि ए लड़का के ऊपर हमन ला शंका हे, पुलिस ध्यान नइ दिस, न ओ लड़का ला बुलइस नहीं । हम शंका के आधार पर कुछू नइ करन करके । जब तीसरा दिन ओ लड़की के लाश मिलिस तब गांव के मन घेर लिन, लाश ला उठान नइ दिन ता ओ लड़का ला गिरफ्तार करिन अऊ एक झन के ऊपर



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अपराध कायम होए हे कि लड़की के साथ जो हे अवैध संबंध बनाए गे हे, आरोप तो ये भी हे कि ओकर साथ जो हे सामूहिक बालात्कार किये गये हे लेकिन ओ दिशा मा पुलिस काम नइ करत हे अइसे पुलिस के काम हवय । माननीय सभापति महोदय, आप समय दे हा ओकर बर बहुत-बहुत धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से सरकार करा निवेदन भी करत हावओं कि ये तमाम चीज में भी ध्यान देवएं । धन्यवाद ।

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कुछ ही बातें कहूंगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात की और शराबबंदी की कमेटी बनी लेकिन अभी तक 3 वर्ष हो गये, 3 वर्ष में एक इंची आगे नहीं बढ़ा और शराबबंदी क्या हो रही है, सबको मालूम है। उससे ज्यादा शराब बिक रही है और घर-घर में शराब बिक रही है। इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना। 8 लाख आवास वापस हो गये और मुख्यमंत्री जी इधर ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारी सरकार अच्छी चल रही है। अच्छे कार्य हो रहे हैं और उत्तरप्रदेश में जाकर एक मॉडल तैयार करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास का यहां का मॉडल क्या है? बहुत लोगों को किस्त भी नहीं मिला है। प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त और लोगों का मकान अपूर्ण है। तो यह ऐसा भी कौन सा मॉडल है। मैं गांव गया था और गांव का नाम बताउंगा। कुमुसदा। कुमुसदा गांव में आदिवासी मोहल्ले में मैंने कहा कि सब बढिया है जी। आवास दे दीजिए। तो मुख ला का देखबो विधायक जी, मोला बोलिस। मैं कहे हों मोर मुख ला नहीं देखो मैं मुख्यमंत्री ला जरूर बोलहूं। अउ मुख्यमंत्री जी नहीं करही तो फिर ओ काम नहीं करय तो ओला इस्तीफा देना चाहिए। मैं कहे हो कि बात जरूर पहुंचाहूं भले मुख्यमंत्री मोला गलत माने। तो मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करथव यह बहुत बड़ी भारी बात गांव वाले बोले हे। एक गांव वाले नहीं, हर गांव वाले कई झन के आंसू टपकथे। कई झन मन ला दुख होथे, पानी चूहथे, टूटथे। देख ले भाई विधायक। हम तोला जानथन भाई। तै तो मंत्री रहेस। तै मुख्यमंत्री ला बोल सकथेस। ते बोलबे तो जरूर तोर प्रभाव पड़ही। तो मैं मुख्यमंत्री ला अतके बोलव कि ये बात ला सोचय। मुख्यमंत्री अतेक आवास बनवावथे, सब चीज करथै। मॉडल हावै। हम पूरा छत्तीसगढ़ में मान ले हन कि तोर मॉडल बड़े हे। इहू मॉडल ला तैयार कर। दूसर हे कि आप शराबबंदी के बाद कहे हो, नरूवा, घुरूवा, गरूवा, बाड़ी तोला कई झन देथे गारी, अउ मोर बात ला नहीं देव भारी। गोठान योजना हे। अब गोठान में सब हे परेशान। ओमा गरूवा हे ही नहीं हे। पानी पीते नहीं हे। कहां-कहां देख ले, कतका गरूवा हे। रोड मा हावव। तो अब गोठान योजना आप बनावथ जरूर, गोठान जरूर बनाये हो, पर गोठान तो नियम में नहीं हे नरेगा मा। अब नरेगा योजना में नहीं हे, मनरेगा हे ओ तो। मन से रेंगथे आपके योजना। तो ये योजना में सी.सी. गली बनाना, पक्की सड़क बनाना, नाली बनाना, अउ गोठान बनाना, वहां पर स्कूल बनाना, यहां तक कि सामुदायिक भवन भी बनाना हे, अउ पंचायत भवन बनाना। तो आपसे अनुरोध हे कि ओमा सी.सी. वे बनाये के हे। पक्का नाली के जगह। पर सी.सी. योजना ला, आपके द्वारा आपकी सरकार के द्वारा रोक दे गेहे। तो

गांव वाले में सी.सी. रोड बनही । पक्का नाली बनथे। अब जल मिशन योजना भी शुरू हे। दिल्ली से आपके बीच 60:40 के परसेंट हे। तो सब बन जाही। नाली बन जाही। पर सी.सी. रोड नहीं बनही तो गांव वाले मन के विचार भावना हे कि मनरेगा में सी.सी. वे और नाली दोनों दिये जाये। ओ प्रतिबंध ला आपला हटाना चाहिए। एखर से गांव वाले ला ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलही, नहीं तो पंचायत मन के दुर्दशा काहे, चाहे 15वां वित्त में अन्य हे, ओला भी आप यहां से आदेश देथौ। ओ तो पंचायत के अधिकार हे। ओमा भी आप पालन करव। डी.एम.एफ. फंड हे। ओ फंड मा आप पिछले समय मैं आप ला बोले रहव कि 20 परसेंट ले ज्यादा पैसा होगा अधोसंरचना राशि मा तो जरूर बचता है। तो 40 परसेंट करिहौ। ज्यादा से ज्यादा ओमा विकास होही। अउ बता दो कि दिल्ली से 5 किलो चावल सब बर आथे। काकर बर, गरीब मन बर। अउ 5 किलो चाउर आथे तो एक यूनिट, दूसरे यूनिट वाले ला दैथौ, बाकी ला देबे नहीं करौ, तीन, पांच यूनिट वाले ला। ओ चाउर कहां जाथे। ओ चाउर ला देवौ। अइसे मतलब सब जनता मन गारी देथे, मैं नहीं कहथव। हम तो विरोधी हन, कहबोच। हम करबो विरोध, तोला आही क्रोध, तब सब ला करबे तब ता..।

श्री रामकुमार यादव :- त जनता मन भी कहाथे ग। गैस के भाव ला बढ़ादेहौ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- एखर बर बोलथे। दूसर अउ हे। लेना तै हा बोलत रहू बाबू। दूसरा, अब आपके विधायक मद। आप यहां पर घोषणा करे हो कि कोरोना के बाद भी पैसा वापस ले लौ सबके। बात सही हे, इसलिए कोई नहीं बोल रहिन। जेन कोरोना के पैसा कटगेहे, बाकी विधायक मन ला पैसा देबो। तो शायद दूसर विधायक के ला नहीं जानौ। ए तरफ के बहुत झन विधायक ला पैसा नहीं मिले हे। ओ तरफ ला आप जानौ। तो सब विधायक मन ला आप पैसा देहौ। अउ बढिया अनुपूरक बजट भी पास कर देहौ। तो मैं अतक बिंदु ला बोलव, मोला ज्यादा बोले के जरूरत नहीं, अतका ला समझदार ला इशारा काफी हे। बस अतका ही कहके अभिभाषण के विरोध करके अपन वाणी ला विराम देथौ।

सभापति महोदय :- धन्यवाद, मोहले जी। श्री रामकुमार यादव जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब बोल ते।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय राज्यपाल महोदया जी के अभिभाषण में धन्यवाद् दे के लिए खड़े हौं । मैं ओला प्रणाम करत हौं कि आज जिस प्रकार से मैं सुनत रहे हौं, बहुत वरिष्ठ वक्ता मन कई प्रकार के तर्क लगा लगाकर, पता नइ कहां से आंकड़ा लाने रहिस हे । मोर छत्तीसगढ़ के भोलाभाला जनता ला जिस प्रकार से ठके रिहिन हे, एमन फिर ठग डारबो कहुस । हमन के योजना के सामने एमन नाना प्रकार के आंकड़ा पेश करत रहिस हे । आज आप यहां टी.वी. के माध्यम से अउ जतका अधिकारी, कर्मचारी सुनत होही, एला तर्क मा तौलही । 15 साल के सरकार जिस भावना के साथ छत्तीसगढ़ के भोला भाला जनता, छत्तीसगढ़ के जनता के बारे मा देश के कोई भी कोना मा जाकर पूछिहौ तो कथे, छत्तीसगढ़िया बहुत भोला भाला हे । भोला भाला जनता ला

एमन ठगे रिहिन हे । आज मोर छत्तीसगढ़ के सरकार, भूपेश बघेल जी के सरकार जिस प्रकार से काम करत हे, एक महतारी अपन लइका ला कोख से जब पइदा करथे तो पइदा करके सोचथे, जब छोटे ले बड़े होही ता जब मैं बेसहारा हो जाहूं, मैं थक जाहूं, मैं कमजोर हो जाहूं ता मोर बर लाठी बनकर, मोर सहारा बनकर मोला चलाही । इसी भावना के अनुसार प्रदेश के सरकार का 15 साल चुने रिहिस हे, ये मन फेल होगिस । लेकिन आज मोर सरकार लाठी बनकर प्रदेश के सहारा बने हे। मैं चार-छै ठन उदाहरण बताहौं, मैं जानत हौं, आप मन मोला लास्ट मा मउका दे हौ, समय कम रथे, ओखर खातिर मैं 2-4 उदाहरण पेश करिहौं । आज पूरा देश, पूरा विश्व महिला दिवस मनात हे । एखर पहिली भी मनात रहिस हे, आज गांव के गरीब, जंगल मा रहने वाला आदिवासी समाज के मोर बहिनी मन ले पूछ के देखौ, उंखर मन मा कतना खुशी हे । काबर, ओमन गोबर ला बेचके अपन लुगरा के छींठ मा पइसा ला गठिया के धरे हे । एमन के सरकार मा गरीब आदमी ला जम्मू कश्मीर मा जाके ईंट बनावै, उहां जाकर बंधुवा मजदूर बन जावै । लेकिन आज गांव के गरीब महिला मन, जब झौंहा ला लेकर गांव में किंजरत हे, 200 रूपए के गोबर बेच डारत हे, वो महिला जे महिला कभू नइ जानय कि काला रेक्सोना साबुन कथे, काला डिटॉल साबुन कथै, काला लाईफबॉय साबुन कथे, वो सपना मा नइ देखे रिहिस हे । कभू तिहार-बार आ जाति, छट्ठी बरही होतिस ता कहीं मेर के चांदनी साबुन, सर्फ ला चुपरय, लेकिन आज भूपेश बघेल के सरकार बनिस हे तो गोबर ला बेचके लाईफबॉय साबुन ला गरीब महिला मन चुपरत हे ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अब अतका लम्बा-लम्बा मत फेंक भाई ।

श्री रामकुमार यादव :- एकदम सही हे । आज वो गरीब आदमी गोबर ला बेचकर पइसा नइ कमात हे का । तू एकर खातिर नइ जानव, तू बड़का घर के जन्मे वाला हौ, गरीब के बात ला का जानिहौ । मैं जानत हौं शर्मा जी तू बड़ा घर के हौ । तू काजू बादाम खाने वाला आदमी हौ, बासी अउ अंगाकर रोटी ला का जानिहौ । मैं धन्यवाद दूहूं चंद्रपुर विधान सभा क्षेत्र का एक गरीब के कोख ले पइदा हुए लइका ला आज इहां विधायक बनाकर भेजे हे, मैं गरीब के बात लो बोलिहौं, ए मेर । आज मैं मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद् देहौं, धन्यवाद् देहौं सरकार ला, रविदास हा कहे रिहिस - ऐसा राज चाहूं मैं, सबन को मिले अन्न । छोट-बड़ सब रहै, रविदास प्रसन्न ।

आज ए भावना के अनुरूप मोर छत्तीसगढ़ के सरकार हा काम करत है। आज मोला बता तो जतका वक्ता मन गोठियावत रिहिस हे, हमन नारायण चंदेल जी, केशव चंद्रा जी, हमर ठाकुर साहब एमन धान ला बेचत हे तो गौठिया के खाता अलग खुले हे अउ गौठनिन के खाता अलग खुले हे । मैं तो ओखर तीर के रहइया हौं, कतेक बोनस पाए गौठिया ता लटपट कहिथे, काबर के मैं गरीबहा हौं तो मांग-मूंग लिही कहिके । नइ पाए हौं यादव, तीन लाख पाए हौं कथे । महूं जानकार व्यक्ति हौं, मैं पूछेंव अउ गौठनिन के खाता का, तो कहै ओमा डेढ़ लाख घलो आए हे ।

सभापति महोदय :- समाप्त करें, रामकुमार जी ।

श्री रामकुमार यादव :- सभापति महोदय, आज मैं कहना चाहत हौं । आज सर्वहारा समाज प्रदेश में खुश है । एमन अतका दिन मा बाहर के बड़े बड़े कलाकार ला लानय । मध्यप्रदेश ले छत्तीसगढ़ एखर खातिर बने रहिस हे कि छत्तीसगढ़ के विकास होवय । आप महाराष्ट्र जाहू तो महाराष्ट्र के हीरा पाइहा, ओड़िसा में जाहू तो ओडिसा के हीरा पाइहा, आप उत्तर प्रदेश जाहू तो उत्तर के सुपर स्टार पाइहौ । छत्तीसगढ़ मा अमिताभ बच्चन, श्री देवी, माधुरी दीक्षित । लेकिन 15 साल के सरकार मा तुमन ओही ला बढ़ाए के काम करौ । छत्तीसगढ़ जेन भावना के अनुरूप अलग होइ रिहिस हे, ओमा कोई काम नइ करेव । लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल के सरकार ला धन्यवाद दिहौं, अमरजीत भगत ला, जे हर आज मंत्री बनीस त वहां पर काय पैदा कर रहीस। आज वो गांव के गरीब व्यक्ति भी सोचथे कि मोरो बेटी हर श्रीदेवी बनहीं, माधुरी दीक्षित बनही। मोरो बेटा हर आज जइसे मिथुन चक्रवर्ती बने हे, ओसने मोरो बेटा हर भी बनही।

श्री सौरभ सिंह :- तैं हर ये तो बता कि तैं हर कब माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी के बारात ले जाबे?

सभापति महोदय :- राम कुमार जी, समाप्त करें। समय का ध्यान रखे।

श्री रामकुमार यादव :- जी राजा साहब। सभापित तो हैं ही। ओहर राजा भी हावय।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- रामकुमार भैया, संस्कृति विभाग के जितना कलाकार हावय, ओमन ल तीन साल से वेतन नहीं मिले हावय। पता करा लो आप।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी । राम कुमार जी।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब, तुंहर ल लाने हावा, तुंहर आंकड़ा मैं जानत हव। सुना न ठाकुर साहब, तुमन कहां ले आंकड़ा ल लाने हावा अउ भारतीय जनता पार्टी हर तुंहर गुरू हे, जानत हावा। तुमन ओकर नाम रख देहर हव अल्टू राम, ओकर नाम तो फेंकूराम हावय। हमन नइ जानथन।

सभापति महोदय :- रामकुमार जी, कृपया बैठ जाईये।

श्री रामकुमार यादव :- मैं आज इस सदन में एतके कइहव कि जिस प्रकार से भूपेश बघेल के सरकार काम करथे, ओला छत्तीसगढ़ के जनता देखथे। आप मन के झूठ में जाने वाला नइ हे। मैं प्रणाम करथव मोर सदन के नेता मन ल, जेहर गरीब ल भी बोले के मौका देथे। बहुत-बहुत धन्यवाद राजा साहब।

सभापति महोदय :- डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तुरी) :- माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहते हैं कि इसमें खुशहाल छत्तीसगढ़ और गौरवशली छत्तीसगढ़ की कल्पना है। अब किसानों की कल्पना है। यह कैसे कहते हैं? मेरा दो-तीन छोटे-छोटे प्रश्न हैं। अगर खुशहाल किसान हैं, तो फिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उसके लिए क्या प्रोविजन है? यदि किसान खुशहाल हैं तो

कितना तिवरा बोये हैं, कितना गेहूं हुआ, कितना रकबा बढ़ा इसमें? सभापति महोदय, केवल एक बहाने हैं, केवल एक बातें हैं जो छत्तीसगढ़ के लोगों को उनको भोंदने का काम कर रहे हैं। अगर हम सुनते हैं कि छत्तीसगढ़ गौरवशाली बनेगा तो पाठ क्या पढ़ाया जा रहा है, गोबर का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अभी जितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उसकी दयनीय स्थिति है। क्या उसके लिए महामहिम जी के अभिभाषण पर उल्लेख आया? उनके लिए कोई योजनाएं बनीं? कि कोरबा के इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी क्या स्थिति है? जिसको बड़े मुश्किल से स्टार्ट किया गया था। आत्मानंद इंग्लिश स्कूली की आपकी कल्पना ठीक है लेकिन आपने जिस तरीके से उसको किया कि आपने आने वाले बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। यह आपकी कैसे गौरवशाली कल्पना है? छत्तीसगढ़ के लोगों को किस दिशा की ओर ले करके जा रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को फायदा नहीं है।

(श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के कुछ कहने पर)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- शर्मा जी, बच्चे लोग कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं । कलेक्टर का घेराव कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि हमें उसी स्कूल में पढ़ने दीजिए। दूसरी जगह जाने के लिए बच्चों को बोला जा रहा है, शिक्षकों को और यहां तक की सुझाव दे रहे हैं भैया कि आपके पास न बिल्डिंग है, न दूसरा कोई स्कूल है। सभापति महोदय जी, शर्मा जी बोले कि हम लोग सुझाव दे रहे हैं। उसी स्कूल में एक पाली में बच्चों का लगा लिये, उसी स्कूल में एक पाली में इंग्लिश मीडियम का लगा लिये। इतनी टेक्निकल बात कर रहे हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको जिद्द है। क्योंकि इससे छत्तीसगढ़ का गौरव कैसे बढ़ेगा। गौठान बने तो बोले बहुत परिवर्तन आ रहा है। शर्मा जी अपने क्षेत्र के एकाध गोठान में घुमाने के लिए जाए । धमर भैया को भी ले चलिए।

श्री सत्यनारायण शर्मा :- चलो न तो।

डॉ. कृष्णूर्ति बांधी :- हां, तो कब चलना है यह बता दीजिए। सभापति महोदय, हम इन्हीं के साथ इनकी क्षेत्र में जाये, वहां की इकॉनामी देखें, ग्रामीण इकॉनामी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है? कितने लोगों को रोजगार के अवसर हैं? कितने लोगों को रोजगार के अवसरों में जोड़ा गया? इस दिशा से बढ़ेगा क्या? अपराध की बात-चीत करते हैं। सभापति महोदय जी, पटवारी इतने सीमांकन जिस तरीके से फौती बंटना, सीमांकर करना, रकबा का चेंज करना, इतनी द्रूत गति से चल रहा है कि यह भू-माफिया को पैदा किया है और भू-माफियाओं से पेपर रंगा हुआ है। एस.डी.एम. सक्षम अधिकारी से बात करते हैं कि भैया यह प्लाटिंग चल रही है, ग्रामीण अंचलों में प्लाटिंग चल रही है, उसका कोई रोक-टोक है या नहीं? कोई डायवर्सन होता है या नहीं होता है। इसीलिए हम इतने दिनों से इस बात को रख रहे हैं कि सदन की भू-माफिया अचानक भू-फोड़ देवता टाइप के फूंकते हैं। उनके लिए क्या इसमें कोई रोकथाम का उपाय है? नहीं है, सभापति महोदय। पुलिस की बात करते हैं, अभी हमने एक बातचीत कही कि मेरे क्षेत्र में एक गांव है ऐसे बहुत सारे क्षेत्र में अपराध, एक तो बलात्कार है, अपहरण है, अनुसूचित जाति के लिए जो

आंकड़े हैं, हम देश में पांचवें स्थान पर आकर खड़े हुए हैं। हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी है और दूसरा, जिन बच्चों ने, गांव के लोगों ने नशे के एडिक्ट के कारण, एक गांव है जिसमें सबसे बड़ा अपराध, हत्या, बलात्कार, ड्रग का ऐसा है तो हमने वहां पर कहा चौकी लगाने के लिए मांग कर रहे थे। हम यह लिखा-पढ़ी कर रहे थे, बात कर रहे थे चौकी नहीं, एक सहायता केंद्र कर दीजिए।

सभापति महोदय :- डॉ. साहब, संक्षिप्त कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- तो इनमें कानून में कोई प्रावधान नहीं है। कोई प्रावधान नहीं है बल्कि जिन लोगों ने सूचना देकर के काम किया और जिन लोगों ने चक्काजाम करने के सत्कार को सचेत करने के, उन पर कार्रवाई करते हैं। जबकि उन ड्रगिस्ट लोगों को रोकना चाहिए। यह कार्य प्रणाली है। ऐसी कार्य प्रणाली से क्या कानून से हमारी छत्तीसगढ़ की जनता सुरक्षित और संरक्षित रहेगी? है न।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त कीजिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, बस एक मिनट और।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त करें। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय सभापति महोदय, धान खरीदी में अभी भी उठाव नहीं आ रहे हैं। हम उसको किस तरीके से उठाव करे कि हमारा जो नुकसान न हो, हमारे राज्य का नुकसान है। जो धान का नुकसान होगा, अब चिंता खत्म हो गई क्योंकि उससे एथेनॉल बनना है। अब धान नहीं उठेगा, सड़ेगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है उससे एथेनॉल बनेगा। एक उसकी प्रापर्टी होनी चाहिए। इससे छत्तीसगढ़ का भला होने वाला नहीं है। इस तरीके से महामहिम के जो छत्तीसगढ़ को गौरवशाली बनाना है, संपन्न बनाना है, इसमें कोई लक्षण नहीं दिख रहा है।

सभापति महोदय :- कृपया समाप्त कीजिए। श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय सभापति महोदय, महामहिम माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं। यहां पर बैठी और पूरे प्रदेश की महिलाएं गौरवान्वित महसूस करती हैं कि यहां की राज्यपाल महोदया वह एक महिला हैं और उनको अभिभाषण हुआ है और उनके अभिभाषण में इस तरह से उनको झूठ बोलवाया है शायद हमें बोलते हुए भी हमें इस सदन में बहुत खराब लग रहा है। अभी कुछ समय पहले राज भवन और सरकार के बीच जो टकराहट हुई, जो सार्वजनिक हुआ और प्रदेश की पूरी जनता समझ गई है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान माननीय राज्यपाल महोदया की, जो कि एक महिला भी हैं उनके लिए बयान आता है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि राज भवन में बैठकर राजनीति न करें। यह इस तरह के शब्द उनके लिए शोभा नहीं देते, क्योंकि वह एक महिला भी हैं। प्रशासनिक कार्यों में कसावट लाने की और सरकार की कार्यशैली में कसावट लाने का राज्यपाल का यह संवैधानिक पद होता है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी को जान लेना चाहिए। सुनने में और बोलने में ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। सुराजी गांव योजना के माध्यम से

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजनाओं का संकल्प, जो कि सरकार की फ्लैक्शिप योजना थी, मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि ढाई से तीन सालों में सरकार ने अपनी इस फ्लैक्शिप जो महत्वपूर्ण योजना है उसके लिए क्या कोई बड़ा बजट रखा था? इन्होंने केवल और केवल केंद्र सरकार के पैसे से, केंद्र सरकार की राशि से इन्होंने सफलता के नये-नये आयाम चुमे हैं। केवल और केवल केंद्र सरकार के पैसे से। माननीय सभापति महोदय जी, बहुत अच्छा लगता है ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग। यह सुनने में ऐसा लगता है कि वास्तव में पंचायतों का जब विकास होता है तो एक अलग से विभाग होता है उसमें फंड जारी होता है। यहां पर विभाग के माननीय मंत्री जी नहीं बैठे हैं लेकिन फिर भी मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए पिछले समय में उनको कितना बजट जारी हुआ था? क्या उन्होंने अपनी पूरी राशि खर्च कर ली? क्या ग्रामीण विकास के लिए एक भी रूपये का खर्च उन्होंने गांव के विकास के लिए नहीं किया है। यहां तक कि जितनी अलग-अलग योजनाएं समग्र विकास से लेकर अन्य जो प्राधिकरण हैं उसमें पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायकों के साथ भेदभाव किया गया है। जितने विपक्ष के विधायक हैं, उनको कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं भी कोई राशि नहीं देनी है, यह सरकार ने निर्णय लिया और आज स्थिति यह है हमारे क्षेत्रों में हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी विकास का काम नहीं करा पा रहे हैं। 14 और 15वें वित्त की जो राशि होती है, जो गांव के विकास के लिए केन्द्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना के तहत यह राशि होती है, लेकिन आज स्थिति यह है कि 14 और 15वें वित्त के पैसे को राज्य सरकार अपना समझती है और अपना समझकर जबरदस्ती पंचायतों में वहां के सरपंचों को मजबूर करती है, प्रशासन वहां पर जाकर मजबूर करती है कि आप जाईए और सारा पैसा गौठान में खर्च करिए । यदि यह राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजना है तो राज्य सरकार को स्वयं होकर उस योजना के लिए अलग से बजट जारी करना चाहिए । सत्ता पक्ष के साथ गोधन न्याय योजना की बात करते हैं और इसे जगह-जगह प्रचारित करते हैं । प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों में जाते हैं और छत्तीसगढ़ का मॉडल बताते हैं । गोधन न्याय योजना की बात करते हैं तो शुरू होने के पहले ही इस योजना ने दम तोड़ दिया । इसका कारण भी यही रहा है । यह जो गोबर इकट्ठे करते हैं और कहते हैं कि हम उसका कम्पोज़ड खाद बनवा रहे हैं । आप कहीं पर भी घूमकर निरीक्षण करवा लीजिए, पर कहीं पर भी कम्पोज़ड खाद नहीं बन रहा है । यह तो गोबर को सूखा-सूखा कर वैसे पैकिंग कराकर जबरदस्ती सोसायटियों में भेजते हैं और किसानों को मजबूर करते हैं कि जब तक आप कम्पोजिट खाद नहीं खरीदेंगे, तब तक आपको अन्य खाद नहीं दिया जाएगा। यह किसानों के साथ जबरदस्ती करते हैं ।

माननीय सभापति जी, यह बार-बार गोठान, गोठान करते रहें, सरकार और इनके कार्यकर्ता जब भी गोठान में जाते हैं, केवल गोठान में घूमकर आ जाते हैं । वहां पर क्या हो रहा है, उससे उनको मतलब नहीं है । क्या सही में वहां पर कम्पोजिट खाद बन रही है, इससे उनको मतलब नहीं है ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

मानननीय मंत्री जी कह रहे थे कि वहां पर फूड मेगा पार्क बन रहा है तो सरकार कहीं पर भी अपनी बातों को अमल नहीं कर पायी है । सरकार कहती है कि हमने 35161 कृषि पम्पों के कनेक्शन को एक साथ स्वीकृत किया है । आपने एक साथ कैसे स्वीकृत किया है? तीन सालों में आपने एक भी स्थायी कनेक्शन की स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, पूरे प्रदेश में यह लंबित थे, उसके बाद सरकार ने एक साथ 35161 कृषि पम्प कनेक्शनों को एक साथ स्वीकृति प्रदान की है क्योंकि इन्होंने एक साल तक स्वीकृति प्रदान नहीं की थी।

समय :
6:53 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

मानननीय अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष के सदस्यगण ऊर्जा में कुशल प्रबंधन क्षेत्र की बात करते हैं । आप ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति देखेंगे तो जब वहां पर एक दिन ट्रांसफार्मर खराब होता है तो उसे बनाने के लिए 72 घंटे का समय रहता है । या तो ट्रांसफार्मर खराब है तो उसे बदलिए या रिपेयरिंग के लायक है तो उसको रिपेयरिंग करके आप चला लीजिए, यह व्यवस्था होती है, लेकिन 72 घंटे तो दूर की बात है, 20 से 25 दिन हो जाते हैं, अधिकारी यह बोलने के लिए मजबूर होते हैं कि हमारे पास कोई फंड नहीं है, जब ऊपर से आएगा, तब ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा । किसानों की स्थिति यह है कि पूरा फसल सूखा होता है, पूरा फसल बरबाद हो जाता है । यह स्थिति प्रदेश की है और इसमें सरकार वाहवाही लूटती है । स्थिति बद से बदतर इसलिए और भी है कि जिनको थ्री फेस कनेक्शन चाहिए, ऐसे लोगों को 3-4 महीने बाद भी मीटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उनको आवेदन दिए साल भर हो गए हैं, अब उनसे यह कहा जाता है कि जैसे-जैसे आवेदन आएगा, थ्री फेस कनेक्शन में जिनकी एप्रोच लगेगी, उनको थ्री फेस कनेक्शन दिया जाएगा, यह सरकार की स्थिति है और सरकार कहती है कि हम कुशल प्रबंधन कर रहे हैं । यह सरकार का कुशल प्रबंधन है ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विषय और है। आज महिला सशक्तिकरण दिवस है तो मुझे समय दीजिए ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- महिला सशक्तिकरण हे तो तोर नाम ला पहिली देना रिहीसे, एमन ला तोला पहिली बोलवाना रिहीसे ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, सरकार का कहना है कि छोटे भूखण्ड की खरीदी-बिक्री के बाजार मूल्य में इन्होंने 40 प्रतिशत मूल्य कम किया है । इसमें यह विषय है कि इन्होंने पंजीयन शुल्क कम किया है, लेकिन जो पंजीयन शुल्क है, वह .85 प्रतिशत था, उसे पिछले साल इन्होंने बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया । अब पंजीयन शुल्क बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है । कान इधर से

पकड़ें, चाहे उधर से पकड़ें, मतलब वही है । पैसे आम नागरिक के जेब से ही निकल रहे हैं । आप यह आदेश जारी कर रहे हैं कि छोटे भूखण्डों की खरीदी-बिक्री पर हमने रोक लगा दी है, लेकिन कहीं न कहीं पंजीयन शुल्क बढ़ाकर आम जनता को ही परेशान करने का काम किया है । ये कहते हैं कि पंजीयन कराने पर स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दे रहे हैं । महिला है इसलिए एक प्रतिशत की छूट दी गई है। यह कोई नयी बात नहीं है, यह वर्षों से चला आ रहा है, महिलाओं को 1 प्रतिशत की छूट मिल भी रही थी। तो यह कोई नई चीज नहीं है। ये कहते हैं कि जितने पंजीकृत हितग्राही हैं, प्रथम दो पुत्रियों के बैंक खाते में 20 हजार रूपये की राशि एकमुश्त की जायेगी। यह शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन जब पंजीकृत श्रमिक अपनी बेटियों का विवाह करता है तो शासन 20 हजार रूपया देती थी। इन्होंने इस महत्वपूर्ण योजना को बंद कर दिया है। यदि वास्तव में यह सरकार उन भाई-बहनों की हितैषी है तो वह आज ही घोषणा कर दे कि वह विवाह के वक्त जो 20 हजार रूपये की राशि दे रहे थे, वह 20 हजार रूपये की राशि सीधे बेटियों के खाते में चली जाये।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अच्छा सुझाव दिया, धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, आपका भी धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- श्री धरमलाल कौशिक। सब बातें तो इन लोग बोल चुके हैं। मेरे ख्याल से आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हां, अध्यक्ष महोदय ?

अध्यक्ष महोदय :- इन लोगों ने सब बोल दिया है, आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- नहीं छोड़े हैं, तब भी बोलना पड़ेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपके विषय ला तो अजय चन्द्राकर और बृजमोहन भैय्या दूनो पहिली से बोल चुके हे।

श्री धरमलाल कौशिक :- बोलने के लिए तो बहुत है। इस सरकार में बोलने के लिए कोई कमी नहीं है, चाहे जितना बोल लें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना है। जिस प्रकार से इस सरकार द्वारा असत्य और छलावा उनके द्वारा बुलवाया गया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, आपका भाषण सुनने के लिए 3 लोग और मुख्यमंत्री जी बोलेंगे तो हो सकता है कि उधर 4 लोग हो जायेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अजय जी की पीड़ा समझ सकता हूं। यहां बैठते थे तो दिन भी बतियाते रहते थे और वहां जाने के बाद उनको कोई मिल नहीं रहा है। पीड़ा है तो बार-बार उभर आता है, उभर आता है। भाई, आपके समय में भी यही हालत थी।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- ठीक है, ठीक है। 5 हो गये।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपके समय में भी यही हालत थी। आप कुछ सुधारोगे कहकर, जनता ने आपको भेजा है। वही रखना है तो आपके वहां जाने का क्या फायदा हुआ ?

श्री भूपेश बघेल :- शिवरतन जी, क्या है कि वहां पर जंग लगा था। काम करना नहीं था, अधिकारियों का राज था। आप लोगों की कुछ नहीं चलती थी। यहां जनप्रतिनिधियों का राज है, जनता का राज है। अधिकारी काम करता है। ऐसा नहीं है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री शिवरतन शर्मा :- कितना जनप्रतिनिधियों का राज है, जयसिंह अग्रवाल जी ने सार्वजनिक रूप से अपने अधिकार को अपने राज को बता दिया है। वेदना और पीड़ा दोनों समझिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- जनता ने चुना है, बहुमत दिया है, लेकिन हाईकमान कहां-कहां भेज देती है, वह तो छत्तीसगढ़ में रहते ही नहीं है। यह गड़बड़ हो रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप इत्मिनान से बैठिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, वास्तव में राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं, वह काल्पनिक है और वास्तविकता और धरातल से कोई सम्बन्ध नहीं है। मुझे कहते हुए दुःख भी है कि इस अदूरदर्शी और आत्ममुग्ध, अराजक और अव्यवस्थित सरकार ने पिछले 3 सालों में एक भी ऐसा काम नहीं किया है, जिसको हम 3 साल की उपलब्धि कह सकें। हमारी भी 15 साल सरकार रही और 15 साल में सरकार ने एक विजन, एक विश्वास और विकास के लिए काम किया है, जो आज भी दिखाई दे रहा है। हम लोग पिछले 3 साल से कांग्रेस की सरकार को देख रहे हैं। एक अच्छी सरकार का काम पुरानी सरकार के अच्छे कामों को आगे बढ़ाना होता है। क्योंकि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ यहीं है, जहां आपको भी रहना है और हमको भी रहना है। योजनाओं के नाम पर राशि का कैसे पलीता लगाया गया है, यह हम सबके सामने है। अंधेर नगरी चौपट राजा की कहानी हम सब लोगों ने सुनी है और आज छत्तीसगढ़ में वही चरितार्थ हो रहा है। पिछले 15 सालों में छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही थी, अब तो सर्कस चल रही है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या चल रही है?

श्री धरमलाल कौशिक :- सर्कस, लूट, भ्रष्टाचार, कमीशन, गुण्डागर्दी, वसूली चल रही है। पिछले 3 साल में छत्तीसगढ़ में अड़ा है और खड़ा है और छत्तीसगढ़ डोल रहा है । आपसी लड़ाई चल रही है, रायपुर टू दिल्ली और दिल्ली टू रायपुर यह नौटंकी चल रही है । यह सर्कस नहीं तो और क्या है ? यह ऐसी सरकार है जो छत्तीसगढ़ को बरबादी की दिशा में ले जा रही है । माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन साल के अंदर में आप देखेंगे 51 हजार रूपये का कर्ज ले लिया । कर्ज लेने के बाद भी सड़क खस्ता हाल, अस्पताल बेहाल, युवक परेशान, आखिर यह पैसा जा कहां रहा है ? इतने कर्जा लेने के बाद में लगभग 10 हजार करोड़ रूपये ब्याज की अदायगी करनी पड़ रही है। यह सरकार की स्थिति है ।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सफल रहा है, जो कोड किया गया है । यह अनूठा मॉडल है, जिसकी छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर भी चर्चा होनी चाहिये । आखिर मुख्यमंत्री जी बार-बार यह कहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल और इस छत्तीसगढ़ मॉडल को यदि इतनी लोकप्रियता है तो मुझे यह समझ नहीं आया कि 400 करोड़ रूपये के विज्ञापन देने की क्या आवश्यकता है । यदि कार्य होगा तो लोग अपने आप जानेंगे । अपने आप मॉडल को पहचानेंगे । न केवल यहां बल्कि छत्तीसढ़ के बाहर के लोगों को भी इस मॉडल को बताने के लिए, इससे यह सिद्ध हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का मॉडल कितना सफल है । तीन साल में 15 हजार लोगों ने आत्महत्या किया, यह आपका छत्तीसगढ़ मॉडल है । आखिर युवा अवसाद में क्यों जा रहे हैं ? सरकार उनके मनोभाव को क्यों नहीं समझ रही है ? इस दिशा में कोई कारगर पहल क्यों नहीं हुये ? किसानों की बात करते हैं, खुशहाल है । आखिर किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं ? आज भी लगातार यह जारी है । अभी कुछ दिन पहले की ही घटना है । राजनांदगांव जिले की घटना है । इसके पहले कई जिलों की घटना है । अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री का ह्दय बहुत विशाल है । यू.पी. की घटना होती है तो 50 लाख रूपये दे देते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसान जब आत्महत्या करते हैं, पैसे देने की बात तो दूर है, उसके पीठ को सहलाने के लिए उसके परिवार के पास जाना भी सरकार का जो तंत्र है, यह भी महसूस नहीं करती कि उनके पास में चले जायें ।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरकार सब को नहीं देती, कांग्रेस-भाजपा ऐसा छांटकर देती है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- यहां के बहुत सारे ऐसे लोग मरे हैं, उन्ही को उसमें छांटकर दे देते । कम से कम यह तो कहते कि यह मिला है करके । जनघोषणा पत्र को आत्मसात किया है । हम लगातार देख रहे हैं कि यह चौथा अभिभाषण है । चौथे अभिभाषण में इन्होंने जो असत्य कथन करवाया, वास्तविक में इस घोषणा पत्र का इस अभिभाषण से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं है । इसके कारण में आज चाहे वह छात्र हो, कर्मचारी हो, युवा हो, अनियमित कर्मचारी हो, मितानिन हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे बिजली कर्मचारी हो, सभी परेशान है । मजबूर होकर इन्हें सड़क में आखिर क्यों निकलना पड़ रहा है । आपने आत्मसात किया, जनघोषणा पत्र को अंगीकृत आपने किया है, यह बात आ जानी चाहिये कि कम से कम उसको स्वीकार कर लें, सरकार का समन्वय बहुत अच्छा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में इस बात को हम लोगों ने देखा है, कार्यकर्ताओं का जनप्रतिनिधि से नाराजगी, विधायक का मंत्री से नाराजगी, मंत्री का मुख्यमंत्री से नाराजगी । इनके साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी, इनका जो समन्वय की बात है, अनेक उदाहरण हम लोग देख रहे हैं । मैं इस बात को समाचार पत्रों में देख रहा था, आपने खुद स्वीकार किया है कि प्रदेश में किस प्रकार से प्रशासनिक प्रदूषण चल रहा है। अभी शिवरतन शर्मा जी एक कद्दावर मंत्री के बारे में बोल रहे थे, उनके मन की

व्यथा है, पीड़ा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मैं अभी गया था तो ये बातें सामने आईं। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। उस बात को आपने वीडियो में देखा कि कलेक्टर कितने भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट होने के बाद में एक कद्दावर मंत्री की बात में वहां पर उनके कॉन में जूं नहीं रेग रही है। आखिर उस पर कार्यवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन वहां के लोगों का यह कहना है कि वह मंत्री के ऊपर नकेल कसने के लिए उसकी वहां पर पोस्टिंग की गई है। इस बात की भी चर्चा वहां पर हो रही है। क्योंकि कलेक्टर की सुनवाई हो जाती है, लेकिन जब मंत्री बात करते हैं तो मंत्री की कही हुई बातों की सुनवाई नहीं होती। यहां पर जो छत्तीसगढ़ में अंतरद्वंद चल रहा है, वह हम सबके सामने में है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये पेमेन्ट सीट की कलेक्टर हैं। क्योंकि यदि इतना कहने के बाद में फर्क न पड़े तो आखिर उसकी वास्तविकता क्या है, अर्थ क्या है? एक विधायक ने तो कलेक्टर के ऊपर बोला कि इनके ऊपर राजद्रोह का मामला चलाना चाहिए। पांच विधायकों ने एक मंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि ट्रांसफर और पोस्टिंग में लगे हुए हैं। इस मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। एक विधायक ने एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाया कि यह मुझे जान से मरवाना चाहते हैं और अंततः यहां पर उनको माफी मांगनी पड़ी, चाहे जिस भी मजबूरी में हो। एक विधायक रेत माफिया के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उनके पति की गिरफ्तारी हो जाती है। आज "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" है और "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" में उनका इतना भी सम्मान नहीं किया गया कि यदि उन्होंने जिद में आ करके अपनी सुरक्षा को छोड़ दिया, गाड़ी को छोड़ दिया तो कम से कम आज के दिन भी यह बात तय हो जानी चाहिए कि उन महिला विधायक का सम्मान होना चाहिए। तब आप "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" मनायें और अपने ही विधायक का सम्मान नहीं कर पाये तो काहे को "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" का दिखावा करते हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। राज्यसभा में एक प्रश्न आया।

श्री अजय चन्द्राकर :- आज के दिन में माननीय विधायक को एक स्कूटी खरीद कर दे देनी चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन को अवगत जरूर कराना चाहिए कि उन्होंने अपनी सुरक्षा क्यों वापिस की, शासकीय गाड़ी क्यों वापिस की?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- विधायम मन ला शासकीय गाड़ी नई मिलै।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यसभा में एक प्रश्न आया। उस प्रश्न के जवाब में आया कि वहां पर जो बच्चे मरे हैं, एक कद्दावर मंत्री ने कहा कि ये असत्य है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने कहा कि वहां पर हमने रिपोर्ट भेजी है। यह सत्य है। कम से कम इतना तो समन्वय होना चाहिए कि यह तो पूछ लें कि जिस विभाग का है, उस मंत्री का क्या कहना है और यह जानकारी कहां से चली गई? इस सरकार में यह इनका समन्वय है। एक विधायक ने कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री का आदमी हूं इसलिए मुझे नहीं बुलाया जाता और मेरा अपमान किया जाता है। माननीय



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय, न केवल जनप्रतिनिधि का, इसी प्रकार से विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों का भी जो अंतरद्वंद है, वह छत्तीसगढ़ में सपष्ट तौर से खुलकर दिखाई देने लगा है। यह छत्तीसगढ़ का मॉडल है। असत्य और फरेब का छत्तीसगढ़ मॉडल है। पता नहीं इन्होंने हाईकमान को क्या कहा, लेकिन हाईकमान ने जिस प्रकार से वहां पर भाषण और भाषण देने के बाद में यदि उन्होंने कुछ बातें कही तो अब तो हाई कमान के राष्ट्रीय नेता को यह भी देखना पड़ेगा कि अपने सूत्र से जांच कराना चाहिये कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता यदि कोई बात बता रहे हैं तो उसमें कितनी सच्चाई है।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- नेता जी, मेरा जिक्र नहीं किये, मेरे नाम पर भी एफ.आई.आर. हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- कर दीजिये, उसका भी जिक्र कर दीजिये।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधायक श्री प्रमोद के ऊपर एफ.आई.आर हुआ है।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे का क्या मतलब है, क्या यह बी.जे.पी. ज्वाईन कर लिये हैं, कि और भी है, हमारे बोल रहे हैं, क्या बी.जे.पी. ज्वाईन कर लिये है ?

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- प्रमोद जी, ऐसा है कि आप टी.एस. बाबा के साथ दिल्ली गये थे, आप उसकी सजा भुगत रहे हो।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधी जी ने अमेठी में भाषण दिया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिव कुमार डहरिया) :- वह तो आप कई बार बोल चुके हो।

श्री धरम लाल कौशिक :- मैं इसलिये इस बात को बोल रहा हूं कि अब राहुल गांधी जी के सामने आप लोगों की विश्वसनीयता समाप्त हो गयी है। अब यदि राहुल गांधी जी आयेंगे तो उनके पास जाकर इस बात को जरूर रखना है कि आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो आपको यह बातें कहलाई है कि यहां जिले-जिले में फुड पार्क बना हुआ है, किसान टमाटर लेकर के जाते हैं, फैक्ट्रियों में बेचते हैं और पैसा ले करके आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो नहीं दिखा पाये लेकिन राहुल गांधी जी जरूर दिखायेंगे और वह आयेंगे तो इनसे जरूर इस बात को पूछना चाहिये। इस सरकार की जो कथनी और करनी है उसका पता लग सके। एक प्रेस वार्ता में प्रियंका जी कहती है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने 2 घण्टे में कर्जा माफ कर दिया, यहां पर आज भी 96,724 किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। कॉपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक और इसके बाद में, आज भी यहां के किसान भुगत रहे हैं कि कर्जा माफ हो जाये। आज आपकी 5 लाख लोगों को नौकरी देने वाली बात तो आ गयी, इसलिये मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, कि आप कितना झूठ और फरेब करेंगे। आज छत्तीसगढ़ में दिखने के लिये बहुत सारे मंत्री हैं लेकिन इतना ज्यादा हस्तक्षेप है कि मंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं। यदि कहीं पर कोई कार्य हो रहा है, वहां कोई कार्यकर्ता चला जाता है किसी काम की बात करता है, तो वहां से कहा जाता है कि आप चार लोगों में से किसी एक से बात कराईये तब यहां से काम लेकर के जाईये, नहीं तो आपको काम नहीं मिलेगा और भ्रष्टाचार की

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

आकंठ में डूबा हुआ है, कि बीज निगम, अमानक खाद, अमानक बीज, अमानक पेस्टीसाईट। माननीय रविन्द्र चौबे जी के द्वारा बीज निगम को यहां पर ब्लैक लिस्ट किया गया, हम लोग प्रश्न उठाये थे, और ब्लैक लिस्ट करने के बाद में जो बीज निगम में अध्यक्ष बैठा हुआ है, उन्होंने उस कंपनी को 4 करोड़ का भुगतान भी कर दिया और जब उसके बाद में बात आयी तो बात आने के बाद में वहां के प्रबंध संचालक ने आदेश जारी किया कि जो अध्यक्ष ने आदेश जारी किया है उसको अधिकार नहीं हैं, वह ब्लैक लिस्ट रहेगा। मंत्री ने ब्लैक लिस्ट किया, जिसे अध्यक्ष ने बहाल कर दिया और बहाल करने के बाद में भुगतान भी कर दिया, यह भी अंकुश में नहीं है और इस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार हो रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आज बीज निगम में कोई भी व्यक्ति बीज से संबंधित जो प्रयोगशाला है, जो अनुबंध किया जाता है, जो प्रयोगशाला है उससे परीक्षण कराया जाता है। 70 से अधिक परीक्षण प्रयोगशाला में कराये ही नहीं गये और इसी कारण किसानों को बड़ा नुकसान हुआ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- नेता जी, धार में थोड़ा तेजी लाईये। वहां अजय जी सो रहे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- नहीं, अजय जी सो नहीं रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- उंघ रहे हैं, एकदम उंघ रहे हैं, थोड़ा तेजी करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं ध्यान से सुन रहा हूँ।

श्री भूपेश बघेल :- देखिए, वह अभी भी उनका चेहरा दिख रहा है। वह सोते नहीं हैं, ऊंघ रहे हैं। थोड़ी सी तेजी लाईये।

श्री अरूण वोरा :- हमारे कौशिक जी, बहुत ही सीनियर हैं। पर मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका यह खुफिया तंत्र कौन सा है, करमचंद कौन सा है जो आपको इतनी गलत-गलत जानकारी दे रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां जितने संसदीय सचिव हैं, वह सब बताते हैं।

श्री अरूण वोरा :- हमको पूरे प्रदेश में ऐसी जानकारी तो कभी सुनायी नहीं दी।

श्री अजय चन्द्राकर :- यहां जितने संसदीय सचिव हैं, वह सब अपनी पीड़ा हमको बताते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय वोरा जी, बातचीत, मैं आपका नाम बोलना नहीं चाहता। सत्तू भईया सामने में बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बताये या नहीं बताये?

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितना पालन हो रहा है ? जब वर्ष 2021 में बजट सत्र में ही घोषणा किये कि चलिए मैं किसानों के लिए 35 हजार कनेक्शन की घोषणा करता हूँ। आज तक वह पम्प कनेक्शन नहीं हुआ है। आज भी वह लंबित है। नहीं 50 प्रतिशत की बात नहीं है, अभी जब किसानों ने पैसा पटाया ...।

श्री भूपेश बघेल :- 90 प्रतिशत बोल रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- अभी जब किसानों ने पैसा पटाया तो मैंने उनको कहा कि उनके खेत में बिजली का कनेक्शन लगवा दीजिए तो उन्होंने कहा कि...।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 31 जनवरी, 2021 के बाद वर्कऑर्डर नहीं हुआ है। एक साल से ऊपर हो गया है। आप पता कर लीजिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- वह 90 प्रतिशत के धोखे में है। आपको मिस गाईड किया गया है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको मिस गाईड किया गया है, आप पता कर लीजिए। अभी जनवरी, 2021 के बाद में किसी को पम्प का कनेक्शन देने पर यहां से रोक लगा दी गई है। यह आप पता करवा लीजिए। मैंने अधिकारियों से बातचीत की, जब किसान ने हमें फोन किया तो बताया कि साहब, अभी कनेक्शन नहीं दे सकते। आपका तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बोले कि 3-4 सालों बाद आपका नंबर आएगा। मैंने किसान को बताया कि हम बात करेंगे और इस समस्या का समाधान करायेंगे। यह आपकी स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। कल से रेत के अवैध खनन बंद हो जाएंगे। सारे एन.जी.टी. के नियमों को तार-तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी की बात का दो दिन ही असर रहा और दो दिनों के बाद में पूरे प्रदेश में अवैध जो उत्खनन के मामले धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं होती। अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि वह कार्यवाही कर ले। क्योंकि जो अधिकारी कार्यवाही करने के लिए जाते हैं उसके साथ में बदतमीजी होती है, उसके साथ में मारपीट होती है। आज अधिकारी सुरक्षित नहीं है। इस प्रदेश में माफिया उनसे ज्यादा तेज है क्योंकि सरकार का संरक्षण माफियाओं के साथ में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल उतना ही नहीं, गांजा के बारे में आप देख रहे हैं कि रोज गांजा के प्रकरण आ रहे हैं एक पत्ती गांजा का इधर से उधर नहीं जाएगा। आखिर करोड़ों रूपये के गांजे की खपत कहां हो रही है कभी गिरफ्त में आ जाते हैं। बाकी तो ऐसा लगता है कि जो छत्तीसगढ़ रायपुर है, यह गांजे की तस्करी का कॉरीडोर बन गया है। यहां से देश के अन्य हिस्सों में गांजे की सप्लाई हो रही है। यह स्थिति है। कांग्रेस ने एक नई संस्कृति ये चाकू मारने को जन्म दिया है, छत्तीसगढ़ में कभी परम्परा नहीं रही है कि दिन दहाड़े जयस्तंभ चौक में लोग चाकू से मारे और इसके पीछे जो मुख्य कारण है वह क्या दवाई बता रहे थे, नाइट्रा क्या बता रहे थे। नाइट्रा खाने के बाद उसको इतना होश भी नहीं है कि वह क्या कर रहा है? यहां लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही हैं, आज मुख्यमंत्री जी जो सबसे विकास की बात करते हैं विकास तो एक तरफ है, सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि यहां के युवाओं को बचाया जाए। उनका भविष्य चौपट हो रहा है। हम लोगों ने पंजाब के बारे में सुना था कि उड़ता पंजाब है, लेकिन पंजाब से आगे यह छत्तीसगढ़ निकल गई है यह उड़ता छत्तीसगढ़ बन गया है। ऐसे देश में कौन से मादक पदार्थ हैं, यहां पर जिसका आराम से विक्रय नहीं होता। अवैध दारू, अफीम, चरस, हुक्काबार से लेकर बहुत सारी बातें आयीं हैं। हुक्काबार को बैन किया गया, लेकिन कहीं भी हुक्काबार बैन नहीं है। आप व्ही.आई.पी. रोड में चले जाईये। आपको अंदाजा लग जाएगा कि



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

हुक्काबार कहां चल रहा है, पूरे प्रदेश में यह स्थिति है। इसलिए प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा जो खतरा मण्डरा रहा है वह युवाओं के ऊपर है। क्योंकि अवैध नशे का जो कारोबार है वह युवाओं को निगलने का काम कर रही है, लेकिन सरकार उसमें कार्यवाही नहीं कर पा रही है। क्योंकि उनके संरक्षण में लोग काम कर रहे हैं उनको सरकार ज्यादा सुरक्षा दे रही है। इसके कारण में अवैध नशे के कारोबार हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धान के 2500 रूपये की बात आई। आपने 2500 रूपये में धान लिया और 2500 रूपये में धान लेने के बाद क्या-क्या हुआ ? एक यूरिया खाद है, जो केन्द्र सरकार की है, उसके बाद सारे खाद राज्य सरकार के अधीन है लेकिन अभी जो खाद है, आखिर खाद का ब्लैक मार्केटिंग क्यों हो रहा है ? हम लोगों ने खरीफ फसल में भी देखा। खरीफ फसल में देखा कि आपकी सोसायटी में यूरिया नहीं है लेकिन सोसायटी के बाहर दुकान में यूरिया है। लोगों को 600-700 में यूरिया खरीदना पड़ा। आज वही स्थिति है। आपकी जो यूरिया है, उसको लोग 600-700 में खरीद रहे हैं। आपकी सहकारी दुकान में यूरिया नहीं है। यह 2500 रूपये के नाम पर आखिर किसानों का शोषण क्यों ? आज स्थिति यह बन गयी है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अच्छा यह बताईये, क्या डी.ए.पी. छत्तीसगढ़ सरकार बनाती है ? नेता जी, आप गलत बात करते हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। आपकी बाहर की दुकान में उपलब्ध है। आपकी सहकारी दुकान में उपलब्ध क्यों नहीं है ? इसका कारण यह है कि आपने जानबूझकर ऐसे लोगों को दिया कि लोग उसमें जा करके ब्लैक मार्केटिंग करें और ब्लैक मार्केटिंग करके उसमें कमाएं। उसके बाद यदि किसानों को जरूरत हो तो उनको जा करके ब्लैक में खरीदना पड़े। यह यहां की स्थिति है।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय मुख्यमंत्री जी, 60-40 का रेश्यो फॉलो नहीं हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा दिया जा रहा है और सरकारी सेक्टर को कम दिया जा रहा है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट सेक्टर में कितना जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना जाएगा ? यह तो राज्य सरकार को तय करना है। उसको कम ज्यादा करने का भी अधिकार है। प्राईवेट सेक्टर में जा रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं जा रहा है, उसके लिए आप दोषी हैं।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आदरणीय शिवरतन जी और सौरभ जी, आपने कहा कि 60-40 का रेश्यो पार नहीं हो पा रहा है। अभी तक छत्तीसगढ़ में 40 प्रतिशत से ज्यादा प्राईवेट को नहीं दिया गया है, अभी भी प्रायमरी सोसायटी और गवर्नमेंट के थ्रू जाता है, वह 60 प्रतिशत से ज्यादा है।

श्री सौरभ सिंह :- मेरे विधानसभा में....।

श्री शिवरतन शर्मा :- सर तो फिर कम क्यों पड़ रहा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक मिनट सुन लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- सुन तो लो भाई। जब प्रश्न किये हो तो सुन लो।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैं आपको सन् बता दूंगा। जब पिछली सरकार थी तो 65 प्रतिशत तक प्राईवेट लोगों को दिया गया था। मैं आपको सन् बता दूंगा। (शेम-शेम की आवाज)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय कृषि मंत्री जी, जांजगीर चांपा जिले का उदाहरण है, आप फाईल मंगवाकर देख लीजिए कि पिछला चार रैक गिरा है उसमें कितना प्रतिशत किस रेट में दिया गया है ? कितना प्रतिशत प्राईवेट और कितना प्रतिशत सरकारी है, आप फाईल मंगवाकर देख लीजिए। बात स्पष्ट हो जाएगी ?

श्री अजय चंद्राकर :- मंत्री जी, एक संकल्प है, आप स्वीकार कर लीजिए। जो निजी क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र का है। उसमें सारी बातें सामने आ जाएंगी कि आप कौन-कौन से सन् में कितना प्रतिशत सहकारी सेक्टर को दिये हो और कितना प्राईवेट सेक्टर को दिए हो।

श्री रविन्द्र चौबे :- पिछले 15 साल और हमारे 3 साल की चर्चा कर लेंगे उसमें कोई बुराई नहीं है। चर्चा कर लेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो सरकार है और बदहाली की स्थिति है, उसके जवाबदार यह हैं। आप 15 साल की चर्चा तो कर ही रहे हैं। जब चाहे कर लेंगे लेकिन यहां 15 साल के बारे में बात करें कि 3 साल की सरकार की जो सरकार है, उसके बारे में बात करें।

श्री रविन्द्र चौबे :- आदरणीय धरम भैया, बात जब आई न तो पहले कैसे होता था यह मैंने बताया। 15 साल की चर्चा करने की हमें जरूरत नहीं है। जनता ने आपको 15 सीट से भी कम में आपको बैठा दिया है, उसमें हम क्या चर्चा करेंगे ? (मेजों की थपथपाहट)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह हम लोगों को मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आप और कितना समय लेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- नेता जी, एक मिनट। निश्चित रूप से हम लोग 15 सीट में आए और आप जैसे महान नेतृत्वकर्ता थे, उसके बावजूद 6 महीने के अंदर भाजपा ने 56 प्रतिशत, 57 प्रतिशत वोट पाकर 1952 का रिकॉर्ड तोड़ा है। उसमें आपकी विधानसभा भी शामिल है और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा भी शामिल है।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- उसके 6 महीने बाद जब नगर पंचायत चुनाव हुआ तब क्या हुआ ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आप लोगों ने नियम परिवर्तित कर दिया।

श्री देवेन्द्र यादव :- नगर-निगम का चुनाव भूल गये।

श्री रविन्द्र चौबे :- मरवाही में क्या हुआ ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- मरवाही में रहने वालों की पीड़ा सुन लो।

श्री अजय चंद्राकर :- मरवाही में तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई।

श्री देवेन्द्र यादव :- पूरे प्रदेश भर में शहर की सरकार शहर में ही साफ हो गयी।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, आज यदि किसान सबसे ज्यादा पीड़ित है तो राजस्व विभाग से पीड़ित है। यह पहली बार देखने में आया है कि डायस में बैठ करके, उसमें मंत्री जी का नहीं है। मंत्री जी की कितनी सुनवाई हो रही है वह हमने देख लिया है। इसलिए मैं मंत्री जी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। मैंने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखा है। इसके पहले भी न्यायालयीन कार्य होते थे, डायस के ऊपर में बैठ करके जो अधिकारी हैं, वे तय करते हैं कि आपका नामांतरण करना है, बंटवारा करना है तो कितना दे सकते हो ? यह छत्तीसगढ़ में कभी नहीं हुआ है। यह नयी संस्कृति को जन्म दे रहे हैं और आज इनके नीचे के अधिकारियों का इतना बल बढ़ा हुआ है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, लेकिन इसमें जयसिंह जी को दोषी मत ठहराईयेगा । वे सहानुभूति के पात्र हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने बेचारा जयसिंह को बता दिया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- हां, वे सहानुभूति के पात्र हैं ।

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) :- नहीं-नहीं, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं है। पहली चीज यह कि मैं अपने आपमें सक्षम हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्व के मामले में जो इन्होंने कहा कि दो साल के कोरोना काल में पूरा राजस्व का अमला काम करते रहा । राजस्व का काम कोई दूसरा विभाग नहीं कर सकता लेकिन दूसरे सब काम राजस्व के लोग करते हैं । (मेजों की थपथपाहट) आपको भी यह बात मालूम है कि लाखों मजदूर बाहर से लाये गये, उनके रहने की, खाने की, दवाई की, पानी की व्यवस्था किसने की ? सबसे ज्यादा काम उसमें राजस्व अमले ने ही किया और उसके बाद भी आपकी 15 सालों की सरकार में राजस्व के जितने निर्णय नहीं हुए उससे ज्यादा निर्णय 3 साल में हुए। (मेजों की थपथपाहट) इसके साथ-साथ आपने 15 सालों में 15 तहसील नहीं बनायी । हमने 73 तहसील बनायी और हम सौ पार करेंगे और बहुत सी चीजें हैं । हम और बोलेंगे ।

श्री रंजना डीपेन्द्र साहू :- लेकिन राजस्व विभाग का भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सका ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं ?

श्री संतराम नेताम :- मेडम, आप पिछले वाले समय का देख लीजिये । आप 15 सालों का रिकॉर्ड निकाल लीजिये ।

श्री रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धमतरी का ही एक बहुत बड़ा उदाहरण देना चाहती हूं । आप बोलते हैं न कि हम प्रत्यक्षदर्शी हैं और सारी चीजें पारदर्शिता से होती है । धमतरी



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

में एक गरीब आदमी से बैठे-बैठे वहां के अधिकारियों ने उससे कमीशन मांगा और तब उसका काम किया है, मैं उसकी गवाह हूं । आप कार्यवाही करिए ।

श्री देवेन्द्र यादव :- क्या आपने उसकी लिखित शिकायत की ?

श्री जयसिंह अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी कोई बात संज्ञान में आयी है । आप कौशिक जी से पूछ लीजिये कि बिल्हा में एक जमीन का मामला आया । जब मुझे जानकारी मिली तो मैं स्पेशल बिलासपुर गया, वहां पर मैंने एसडीएम तहसीलदार को बुलाया और उससे पूछा । तहसीलदार ने बोला कि मेरी गलती नहीं है, किसी कोर्ट का निर्देश है तब मैंने पूछा कि कौन से कोर्ट का निर्देश है, उसने कोर्ट का हवाला दिया तो मैं बोला कि कोर्ट का साइटेशन इसमें लागू नहीं होता और ये निर्देश इस जमीन के लिये नहीं था । वहीं बैठकर मैंने छत्तीसगढ़ भवन में उस तहसीलदार को सस्पेंड किया, जो आज तक सस्पेंड है । ऐसा नहीं है, अगर जानकारी मिलती है । जब भी मैं बिलासपुर-कोरबा आते-जाते बिलासपुर रूकता हूं, हमेशा यह बात आती है कि राजस्व के मामले में यह गड़बड़ी है या राजस्व के मामले में यह गड़बड़ी है । ठीक है, राजस्व विभाग बहुत बड़ा विभाग है, पूरे प्रदेश का हर आदमी राजस्व से जुड़ा हुआ है लेकिन जिस चीज की शिकायत मिलती है तो तत्काल मैं संबंधित अधिकारी को निर्देश देता हूं कि इसमें कार्यवाही कीजिए लेकिन पर्टिकूलर उसकी जानकारी होनी चाहिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- यह अलग बात है कि आपका निर्देश माना जाता है कि नहीं माना जाता है ।

श्री नारायण चंदेल :- दूसरे विभागों में क्या है कि लोग बोलते हैं कि टेबल के नीचे से दो और राजस्व विभाग में बोलते हैं कि टेबल के ऊपर ले आ, यह समस्या है।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप सुन लीजिये, विधानसभा में नहीं बता सकते नहीं तो अगर एक जो और इसके ऊपर जो है वहां क्या होता है सामने कौन बैठता है ऊपर में और नीचे में बाबू क्या करते हैं यह चीज आप लोगों को मालूम है ।

डॉ. विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके समय में वर्ष 2018 के पहले भवन अनुज्ञा के लिये एक मेरे मित्र को...|

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब ये बातें छोड़िए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- जयसिंह अग्रवाल जी, तहसीलदार के ऊपर डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, कलेक्टर भी राजस्व विभाग के अंतर्गत है लेकिन वह आपके नियंत्रण से बाहर है तो बिना मुख्यमंत्री के तो आपका नियंत्रण तो राजस्व विभाग में हो ही नहीं सकता ।

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी, आप अपनी बात करें ।

श्री अजय चंद्राकर :- जयसिंह जी, जब इधर एक मंत्री बैठते हैं । मैं उनका नाम नहीं बताउंगा । जब वहां बैठते हैं तो बोलते हैं कि मैं एक काम नहीं करवा सकता, मेरे अधिकारी मेरा फोन नहीं उठाते

और यहां आकर बहादुर बन जाते हैं । अंदर आकर बहादुर बन जाते हैं और वहां बोलते हैं कि मेरा फोन नहीं उठाते करके । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नाम ले दूंगा । मैंने गृह सचिव जी को बताया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जिस अधिकारी की ओर ईशारा कर रहे हैं वे मेरे ही विधानसभा क्षेत्र के हैं । उन्होंने उनको तत्काल हटाया लेकिन उसने इतने गफलत किये हुए हैं लेकिन उसकी जांच नहीं हो रही है ।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धमतरी में बेमार ग्राम पंचायत में 54 एकड़ की जमीन एक व्यक्ति के नाम सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में पर हो गयी । जिसमें सोसायटी भी है, गौठान भी है और यह 54 एकड़ की जमीन कैसे एक व्यक्ति के नाम में हो गयी । आप चाहें तो इसकी जांच करवा लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- रंजना जी, लगता है कि आप जयसिंह जी से मिलते नहीं हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- आज महिला दिवस है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल तो रहा हूं इसीलिये तो उन पर विशेष ध्यान दे रहा हूं ।

श्री जयसिंह अग्रवाल :- आप लिखकर दे दीजिये उसकी जांच करा लूंगा । आप लिखकर दीजियेगा ।

श्री अजय चंद्राकर :- जयसिंह जी ने बोल दिया कि मैं निर्देश देता हूं करके लेकिन उनका निर्देश कोई माने तब तो, तब तो रंजना जी के बोलने का मतलब है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सब तरफ काम केवल बिल्हा ही मे होथे का।

श्री धरमलाल कौशिक :- तोर विभाग में तो कुछ भी हो जाही डहरिया जी।

तोर विभाग में तो अउ कुछ भी हो जाही।

श्री अजय चन्द्राकर :- अरे भैया, तोर विभाग हे। भागीरथी बहथे विकास के।

अध्यक्ष महोदय :- जयसिंह जी, आप बिल्हा पर ही ध्यान मत दीजिए। कभी-कभी कुरूद और धमतरी की तरफ जाया करो।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, धमतरी का ही है। यहां का नहीं है।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर विषय है। मैंने इसमें ध्यानाकर्षण भी लगाया था और माननीय मंत्री जी को मैंने दो बार लिखित में इस विषय पर ध्यानाकर्षण भी लगाया है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- रंजना लिखकर दे देना। प्रश्नकाल नहीं चलथे।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- माननीय मंत्री जी, मैंने तीन बार लिखकर दिया है और विधान सभा में मैं इसमें ध्यानाकर्षण भी लगा चुकी हूं, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई है। कहां पर कहा जाता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप। और कितने पेज बच गये हैं ? (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- मैंने कहा किसानों का शोषण। बिजली बिल हाफ। पिछली बार विधान सभा में जवाब आया। इन्होंने 800 करोड़ रूपये माफ किया और 1 हजार करोड़ रूपये की जनता से वसूली कर ली। 8 परसेंट बढ़ा और 8 परसेंट बढ़ने के बाद में केवल 800 करोड़ रूपये आपने माफ किया और 1 हजार करोड़ रूपये की जनता से वसूली हो गयी। 15 साल में किसानों का बिजली का बिल नहीं आया और कांग्रेस की सरकार बनी है और किसान हितैषी सरकार आने के बाद में हर किसान को बिजली का बिल भेजा जा रहा है। आज किसान परेशान हैं। उनसे जबर्दस्ती वसूली की जा रही है। ये कांग्रेस के किसान हितैषी सरकार की पहचान है। आज सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वह किसान हैं। चाहे खाद को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, कटौती होती नहीं थी, आज कटौती प्रारंभ हो गयी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 51 हजार करोड़ रूपये कर्जा लेने के बाद में आप प्रधानमंत्री आवास का पैसा राज्यांश नहीं कर पाये। उसमें भूपेश बघेल जी का घर नहीं बनता। उसमें डॉ. रमन सिंह जी का घर नहीं बनता। घर बन रहा है गरीबों का। यदि 18 लाख गरीबों का आवास नहीं बन रहा है तो उसके लिए कोई दोषी है तो भूपेश बघेल की सरकार दोषी है, क्योंकि इनकी गलत नीति के कारण में आज किसान मकान से वंचित हो रहे हैं और लगभग 9 हजार करोड़ रूपये जो इस राज्य को प्राप्त होता है, उससे भी इस प्रदेश को वंचित करने का काम इस सरकार ने किया है। डॉ. रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करना, उनके लिए रोजी-रोजगार की व्यवस्था करना, उन्हें संबल प्रदान करना और इसलिए रेडी-टू-ईट को उनके हाथों में दिया गया। इस सरकार में केवल रोजी-रोजगार देने की बात तो अलग है, बल्कि जो रोजगार कर रहे थे, उन्हें छिनने का काम इस सरकार ने किया। उसमें बीज निगम माध्यम बना और बीज निगम बनने के बाद में एक ऐसे व्यक्ति, आपका ही नाम आया है बीज निगम का। 74 परसेंट की हिस्सेदारी प्राइवेट व्यक्ति का है। बाकी हिस्सेदारी बीज निगम की है।

श्री अजय चन्द्राकर :- छत्तीसगढिया नहीं है। हरियाणा का है।

श्री धरमलाल कौशिक :- हरियाणा का है और उसे यह देना षड्यंत्र है। आपने इस भ्रष्टाचार की भेंट 20 हजार महिलाओं के परिवार को चढ़ाने का काम किया है। ये महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको महिलाओं का श्राप लगेगा। (हंसी) मैं नहीं दे रहा हूं। आपको महिलाएं दे रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुपोषण की बहुत बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना में केन्द्र से राशि मिली, राज्य की राशि मिली। 500 करोड़ रूपये आप डी.एम.एफ. से लिये और उसके बाद में उसकी क्या स्थिति बनी ? तो मार्च-2021 में कुपोषण 15 प्रतिशत, यह विधान सभा का जवाब है न और जुलाई-2021 में 19 प्रतिशत से अधिक, अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई या नहीं हुई, लेकिन जवाब आया। इसमें कितना विश्वास किया जाये न किया जाये, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भाग-5 में

प्रदेश में लगभग 32 प्रतिशत कुपोषण बताया गया। सतत् विकास लक्ष्य में प्रदेश ने 40 प्रतिशत बताया है। आखिर आप सुपोषण योजना की जो दुहाई दे रहे थे और कुपोषण के मामले में राज्य का स्थान 30वें नम्बर पर है । यह स्थिति सुपोषण योजना की है । यानी राशि का बंदरबांट हो गया, राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और कुपोषण की दर जो पहले कम हो रही थी, जो प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत कम हो रही थी, इतना खर्च करने के बाद भी उसमें ज्यादा अंतर नहीं पड़ा । आपकी सुपोषण योजना फेल हो गई ।

अध्यक्ष महोदय, भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे । उन्होंने चिंता जाहिर की थी कि प्रदेश में 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं और इस प्रदेश का भगवान मालिक है । आज सुपोषण योजना चलाने के बाद क्या स्थिति है । आज इस प्रदेश में 61 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं ।

श्री कवासी लखमा :- इनको (xx)[14] बोलना कौन सिखा देता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, आपको गड़बड़ समाचार कौन देता है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मैं आपको दिखा दूंगा, मंत्री जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, फिर वही बात हो रही है । आराम से सदन चल रहा है । नेता प्रतिपक्ष (xx) बोल रहे हैं, यह शब्द नहीं चलेगा । यह विलोपित होना चाहिए और उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए । एक तो (xx) अपने आप में असंसदीय शब्दावली है, आप निकलवाकर देख लीजिए । अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इसमें कुछ कहें ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं देख लूंगा और उसको विलोपित कर दूंगा । नेताजी अच्छा भाषण दे रहे हैं, सब लोग शांति से सुन रहे हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी। अब मैं नइ जानव संगवारी । जब पहली बार भाषण हुआ था उस समय मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था इसका क्या हश्र होगा, मैंने कुछ नाम बताया था। मुख्यमंत्री जी उसमें पीठ थपथपा रहे हैं । पहले विधान सभा सत्र से आज तक कितने का गोबर खरीदी की । उसमें भी कितना भ्रष्टाचार हुआ, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं । कितना हुआ, 127 करोड़ रूपए । इसमें कितना लाभ मिला होगा । दूसरी बात, जो गोबर खरीदी हो रही थी, वह अधिकांश जगह बंद हो गई है । मैं जिस गांव में जाता हूं वहां पूछता हूं मुख्यमंत्री जी की चार चिन्हारी योजना है, उसके बारे में बताओ कि यहां बारी बना, घुरवा बना, यहां पर गोबर खरीदी हुई तो लोग हाथ उठाकर बोलते हैं कि साहब हमारे यहां कुछ काम नहीं हुआ है । आप लोग किसी गांव में जाकर पूछते नहीं हैं ना, आप पूछेंगे तो आपको पता लगेगा और इसके बाद में इनके बनाए हुए खाद के बारे में मैं चौबे जी से पूछना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो सहकारी समितियों में जबरदस्ती दिया गया । उसको छोड़कर प्रायवेट लोगों ने कितना खरीदा है, आप यह बताएंगे । या तो सरकार के

---

[14] (xx) अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित



अप्रकाशित/प्रकाशन के लिए नहीं

द्वारा जबरदस्ती दिया गया कि यदि आपको चार बोरा यूरिया लेना है तो चार बोरा इसको लेना है, चार बोरा पोटाश लेना है तो चार बोरा इसको लेना है । यदि नहीं तो जो संस्थाएं हैं, उन पर दबाव डालकर बेचने का काम किया गया है । ये इनकी गुणवत्ता है । आज जिस योजना की बात कर रहे हैं, वास्तव में इस योजना का हश्र हम लोग देख रहे हैं, यह योजना केवल कागजों पर चल रही है । इसलिए हम लोग शुरू से बोल रहे हैं कि आपने जो योजना बनाई, यह अच्छी योजना है । आप 10-20 गांव का नाम दे दीजिए, हम लोग जाकर देख लेंगे और आपको भी साथ में ले जाएंगे । क्योंकि पहले बताकर जाएंगे तो बढ़िया सजाकर रखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यह है । लेकिन 10-20 गांव का नाम बता देंगे तो यह पता लग जाएगा कि किस गांव में अच्छा काम हो रहा है तो जाकर देखने के बाद लगेगा, लेकिन सरकार यह  बताने की स्थिति में अभी तक नहीं है । क्योंकि उनको भी मालूम है कि योजना की क्या स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ शांति का टापू था । आज अपराधगढ़ बन गया। मेरे साथियों ने इस बात को गिनाया है कि किशोरों के अपराध में छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, आत्महत्या की घटना में यह स्थान, अनाचार की घटना में यह स्थान, मेरे पास आंकड़े हैं, मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूं । लेकिन जिस प्रकार से यहां पर आम आदमी असुरक्षित है । कोई आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है । कोई शादी-ब्याह में चला जाए तो उसके घर में डकैती हो जाएगी,  चोरी हो जाएगी और मैं उससे ज्यादा दूर की बात न कहूं  कि आज आई.एस. और आई.पी.एस. के घर भी सुरक्षित नहीं है। यदि वे घर में नहीं है तो धावा बोलने से अपराधी का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि उनके घर में भी वे धावा बोलने से नहीं चुकते। आखिर पुलिस क्या कर रही है? और इसका मुख्य जो कारण है कि पुलिस को जो काम कर रही है, उस काम को छोड़ करके बाकी काम में लगाया गया है और यह लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर में कैसे एफ.आई.आर. दर्ज किया जा सके, उसको कैसे प्रताड़ित किया जा सके। यही इनके कार्यकर्ता इनका पुतला दहन करेंगे तो ठीक है। लेकिन यदि भाजपा के कार्यकर्ता ने यदि किसी का पुतला दहन कर दिया तो जिस प्रकार से उनके साथ में व्यवहार किया जाता है। पेपर में यह छपवाना कि के भूतपूर्व सांसद फरार। पुलिस लाईन से रोज फोन में उनके पी.एस.ओ. से बात किया जाता है। पी.एस.ओ. को बात किया जाता है कि सांसद कहां पर है। यह हाल-चाल पूछ लेते हैं और उसके बाद पेपर में छपवाते हैं कि फरार। आप उनको गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके बंद करिए न। 14, 15 धाराएं लगाए गए हैं। ऐसे लोगों के ऊपर में लगाए गए हैं जो जा करके कवर्धा में संभालने का काम किया, जो वहां पर प्रदर्शन हो रहा था,  उनको शांत करने उन्होंने काम किया कि किसी प्रकार की वहां पर घटना न घटे। भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर जाए तो आप 14-15 उनके खिलाफ में मामला बनाये और उनके खिलाफ में धारा लगाये। यह आपकी राजनीति की दिशा है, यह आपकी राजनीति की स्वच्छता है।



अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने कवर्धा का वीडियो देखें थे कि सम्मानित सांसद कवर्धा गये थे और किस भाषा का उपयोग हो रहा था, कैसे वहां पर लोगों को गाली-गलौज करके भड़काया जा रहा था, वह वीडियो सबने देखा है।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार यदि राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करेंगे। यह छत्तीसगढ़ के प्रतिकूल है, छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है। जिस प्रकार से सरकार के द्वारा यह काम की जा रही है, अपराध बढ़ने का मामला यह है कि केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के पीछे तुम इसको लगा करके रखो और बाकी जो चोरी, डकैती, अनाचार की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं चलेगी। लेकिन अगर वे पुतला दहन कर रहे हैं तो उनके खिलाफ में एफ.आई.आर. क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार की सोच के साथ में यदि राजनीति होगी तो मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में यह कभी इस प्रकार की स्थिति नहीं रही है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही। लेकिन आज जिस प्रकार से...।

श्री देवेन्द्र यादव :- माननीय अध्यक्ष महादेय, हम लोग छात्र राजनीति करते रहे, हमारे ऊपर में धाराएं पर धाराएं लग गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर जब-जब आंदोलन किये, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि हमारी सरकार में निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है। दोनों पक्षों की जब-जब जैसी-जैसी बात आती है। कानून का पालन होता है और आप अगर 15 साल की बात कर रहे हैं तो खुद अपने 15 साल के कार्यकाल को देख सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी से पूछ सकते हैं आपके बाजू में बैठे हैं।

श्री धरम लाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के द्वारा गरीब अन्न योजना के तहत चावल पिछले बार 9 महीना की दी गई और इस बार 8 महीने की दी गई। प्रत्येक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को पांच किलो चावल दिया जाना था। यहां पर उसकी कैटेगरी बना दी गई है। यदि वे चार-पांच व्यक्ति से ऊपर है तो तीन किलो दिया जायेगा। उसके नीचे के व्यक्ति है उनको दिया नहीं जायेगा। इतने सारे चावल आने के बाद में आखिर वह चावल गया कहां? या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई? वास्तिविक में 35 किलो चावल के बाद में 5 किलो चावल का उनका अधिकार था। कोरोना काल में जिस चावल को केन्द्र सरकार के द्वारा दी गई थी लेकिन लोग दुकानों में जा करके बात किये, व्यक्तियों से जा करके बात किये, लोग शिकायत ले करके आये कि साहब हमको चावल नहीं मिल पा रही है। आखिर वह चावल गया कहां? मैं समझता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए। कि जो भी उसमें दोषी हो, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। यह चावल भी भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ गई है। इस प्रकार से अनेक योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को मिलना चाहिए, उससे आज छत्तीसगढ़ के लोग वंचित हो गये हैं। आज यहां पर जिस प्रकार से सरकार चल रही है। एक तरफ भयादोहन किया जा रहा है और दूसरे तरफ हमको प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि वास्तविक में यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो क्या होता? यदि कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ नहीं बनता, कांग्रेस नहीं होती तो छत्तीसगढ़ कर्जगढ़ नहीं

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

बनता, कुप्रबंधन का शिकार न होती। यदि कांग्रेस नहीं होती तो छत्तीसगढ़ की पहचान करप्शन, कमीशन और क्राइम का गढ़ नहीं बनती। कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो ढाई-ढाई साल की नौटंकी नहीं होती, सरकार सर्कस नहीं होती। कांग्रेस नहीं होती तो आज विकास ठप्प नहीं होता । चारों तरफ विकास ठप्प हो गया है। कांग्रेस नहीं होती तो सरप्लस बिजली वाले राज्य में बिजली कटौती नहीं होती।

श्री देवेन्द्र यादव (भिलाई नगर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस नहीं होती तो..।

अध्यक्ष महोदय :- बड़ी जल्दी खत्म कर रहे हैं। बैठिये।

श्री धरमलाल कौशिक :- भारी-भरकम बिल न आते। कांग्रेस न होती तो किसानों को धान बेचने, खाद खरीदने में दिक्कत नहीं होती।

श्री अरूण वोरा (दुर्ग शहर) :- आदरणीय कौशिक जी।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज-प्लीज।

श्री धरमलाल कौशिक :- कांग्रेस न होती तो गरीबों को पूरा राशन मिलता, राशन में डाका नहीं पड़ता। कांग्रेस नहीं होती तो कवर्धा में सनातन धर्म का अपमान नहीं होता। खुले आम धर्मांतरण नहीं होता। कांग्रेस नहीं होती तो आदिवासियों के साथ छल नहीं होता। वन समितियों में नियम विरूद्ध वनवासी भाइयों के अधिकार न छीने जाते। कांग्रेस नहीं होती तो ईंट 3500 की जगह 5600, रेत 8 की जगह 3800, गिट्टी 32 की जगह 11 हजार 500, छड़ 40 की जगह 68, सीमेंट 220 की जगह 300 रूपये बोरी न मिलती। कांग्रेस नहीं होती तो 8 लाख से अधिक गरीबों को अपने घर का सपना पूरा होता।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- और कांग्रेस नहीं होती तो आप लोग वहां नहीं पहुंचते। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस न होती तो बाकी राज्यों की तरह जल जीवन मिशन से घर-घर पानी पहुंचता। कांग्रेस न होती तो केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेशवासियों को मिलता। कांग्रेस न होती तो स्व-सहायता समूह की महिलाओं को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का काम न छीनता। कांग्रेस न होती तो छत्तीसगढ़ के पैसे, छत्तीसगढ़ के विकास में लगता। कांग्रेस के चुनाव प्रचार में नहीं लगता। कांग्रेस नहीं होती तो छत्तीसगढ़ का निर्णय गांधी परिवार नहीं, हर छत्तीसगढ़िया का होता। कांग्रेस न होती तो 20,000 स्व-सहायता समूह और 60,000 बुनकरों समेत, 8000 गरीबों का रोजगार न छीनता। कांग्रेस न होती तो कोरोनाकाल में इतनी अव्यवस्थाएं न होतीं। न ऑक्सीजन की कमी होती न दवाइयों की कमी होती। न ही बिना मतलब के कोरोना फैलाने के क्रिकेट मैच जैसे मूर्खता के काम होते। कांग्रेस न होती तो सबको देश में सबसे पहले मुफ्त वैक्सीन मिल जाती। कांग्रेस न होती तो आज छत्तीसगढ़ बदहाल न होता। सनातन धर्म का अपमान न होता। विकास अवरूद्ध न होता। महिला, जवान, किसान परेशान न होता। ये सारे के यदि कोई जड़ है तो कांग्रेस है। इसलिए यदि कांग्रेस से यदि छत्तीसगढ़ को बचाना है तो यहां से कांग्रेस को उखाड़कर फेंकना पड़ेगा। आपने आज जो बोलने का समय दिया है मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)



अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद-धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- मैं राज्यपाल महोदया के धन्यवाद ज्ञापन चर्चा पर भाग लेने वाले सदस्य आदरणीय श्री संतराम नेताम जी, आदरणीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय श्री अरूण वोरा जी, आदरणीय श्री शिवरतन शर्मा जी, श्री शैलेष पाण्डेय जी, श्री अजय चन्द्राकर जी, श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव जी, नारायण चंदेल जी, आदरणीय प्रकाश शक्राजीत नायक जी, आदरणीय चंद्रा जी, पुन्नूलाल मोहले जी, आदरणीय रामकुमार यादव जी, डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, आदरणीया श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू जी, और अंत में अभी बहुत ही कवितामय भाषण लिखकर लाये, उसे पढ़ा, वाचन किया और हम सबका मनोरंजन किये, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदया ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्ष 2022 के पहले सत्र में पहले दिन अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण के माध्यम से हम सबका मार्गदर्शन किया। यह अवसर उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का है। यह सुखद संयोग है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसके एक दिन पहले ही ही हमारी राज्यपाल महोदया जो आदिवासी महिला हैं, वह पधारी और उन्होंने अपना भाषण दिया। मैं अभिभाषण की दो-तीन कण्डिकाओं के बारे में उल्लेख करूंगा। राज्यपाल महोदया ने कहा कि मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्म गौरव के प्रति मेरी के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है। समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल बहुत सफल रहा है। मैं चाहती हूं कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में आई तेजी का सिलसिला लगातार जारी रहे और इसमें आप सबका भरपूर सहयोग मिले और दो-तीन बाते हैं। माननीय सदस्यों ने, सत्ता पक्ष ने, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। विपक्ष ने बहुत-सारी बातें कीं, जिसमें जानकारियां भी थीं, सुझाव भी थे और आलोचना भी थी । मैं सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत करके तैयारी की, लेकिन खोदा पहाड़, निकली चुहिया । आज अजय जी का लाईन-लैंथ, सब बिगड़ा हुआ था और हंटर वाली का डर इतना था कि सबका लाईन लैंथ बिगड़ी हुई थी । अब अजय जी ने कहा कि ऐसे 5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम बता दो, जिन्होंने शहादत दी । अध्यक्ष महोदय, हम लोग तो गांधीवादी हैं । गांधीवादी तरीके से अहिंसा, अहिंसा का मार्ग है और यह प्रदेश कबीर का प्रदेश है, यह प्रदेश गुरू घासीदास का प्रदेश है, जहां सत्य, अहिंसा और प्रेम की बयार चलती है । वैसे भी छत्तीसगढ़ अहिंसक रहा है इसीलिए शांति का टापू कहा जाता है, लेकिन आपने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनकी शहादत हुई, ऐसा नाम बताईए । मुझे एक-दो नाम याद आ रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा नाम नहीं लूंगा । हमारे यहां पाटन में घसिया मण्डल हैं, ये औरी बहुत जाते हैं, इनकी रिश्तेदारी है । उसके पहले वाला गांव अमलीडीह है । वहां आचार्य देव का भाषण हो रहा था, वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो हमारे पूरे पाटन क्षेत्र में खूब दौरा करते थे और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

इसीलिए सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पाटन में हुआ करते थे। आचार्य देव के नाम से जानते हैं और कहां के रहने वाले हैं, कौन थे, मैंने इसके बारे में बहुत जानकारी पूछा, लेकिन वे बता नहीं पाये । अध्यक्ष महोदय, उनको गिरफ्तार करने रायपुर से सर्किल इंसपेक्टर गए हुए थे, बाजार का दिन था, वे चबूतरे में खड़े होकर भाषण दे रहे थे । इंसपेक्टर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जैसे ही मंच पर चढ़े, घसिया मण्डल खड़े हुए कि मेरे रहते आप आचार्य देव को छू भी नहीं सकते । फिर इंसपेक्टर ने उनको पकड़ने की कोशिश की, गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उस इंसपेक्टर को ही पटक दिया । पटककर उसकी छाती में बैठ गए और गला दबा दिया। अंग्रेज के पुलिस ने उन्हें सर पर कुंदों से मारा । उनके सिर से खून बह रहा था और उसे घाट में बांधकर रायपुर लाया गया । उसकी मौत जेल में हुई । यह शहादत की पहली घटना है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना मैं अपने क्षेत्र का ही बताऊंगा । ठाकुर राम नायक जो 25 साल के नौजवान थे, जिनकी कुछ वर्ष पहले ही शादी हुई थी, उनकी एक लड़की थी । उन्होंने नमक कानून तोड़ो के आन्दोलन में भाग लिया, उन्हें गिरफ्तार किया, दुर्ग जेल में रखा गया । उसे कहा गया, वे बीमार पड़े, उसे मलेरिया हो गया । अंग्रेजों के जेल में दवाई नहीं दी गई । उन्होंने कहा कि तुम माफीनामे में दस्तखत करो, तब तुम्हें छोड़ा जाएगा, तब जाकर अस्पताल में ईलाज कराओ । उस ठाकुर राम नायक नौजवान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा और ठाकुर राम नायक जी ही शहादत वहीं हुई । (मेजों की थपथपाहट) यह कांग्रेस के लोग हैं । वे माफी नहीं मांगे । उसकी लड़की अभी भी जिन्दा है । मैं और भी उदाहरण दे सकता हूं । मैंने अपने क्षेत्र की दो घटना के बारे में बताया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लिया, वे आजादी की कीमत क्या जानेंगे ? और वीर हो गए । कहीं लड़ाई लड़े नहीं और वीर बन गए । अध्यक्ष महोदय, आप ही के क्षेत्र रूद्री, धमतरी में मिंटू कुमार को 11.10.1930 की सत्याग्रह आन्दोलन में गोली चली थी, उस गोलीबारी में उसकी मृत्यु हुई थी, वह आप ही के जिले के हैं । शहीद रामाधीन गोड़ छुईखदान के थे, पुलिस की बरबरता से 21.1.1939 को उनकी मृत्यु हुई । और आपको कितने उदाहरण दें ? हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने बहुत बढ़िया कविता की । कांग्रेस न होता तो यह होता, कांग्रेस न होता तो यह होता । कांग्रेस न होता तो आजादी नहीं मिलती। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस न होता तो देश को संविधान नहीं मिलता । कांग्रेस न होता तो देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं होतीं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, कांग्रेस नहीं होता तो अभी आप अमित शाह जी और मोदी के सामने बोल नहीं सकते । यह बोलने की आजादी भी अगर आपको मिली तो कांग्रेस के कारण मिली । (मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि 70 साल में क्या किया ? हम तो 15 साल का पूछ देते हैं तो आप नाराज हो जाते हैं। शिवरतन जी कहते हैं कि आप कितनी बार 15-15 साल बोलोगे। अजय जी, आज ही आप बोल रहे थे। आप 15 साल का सत्र बुला लीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- हां, सत्र बुला लीजिये।

श्री भूपेश बघेल :- इसका क्या अर्थ है ? अध्यक्ष महोदय, इसका आशय यह है कि आप 15 साल सुन-सुनकर परेशान हो गए हैं। क्योंकि आपमें सुनने की आदत है ही नहीं। आपमें टालरेंट क्षमता ही नहीं है। आप असहमति का सम्मान कर ही नहीं सकते। असहमति आपमें है ही नहीं, असहमति का सम्मान करना। क्योंकि आपकी शिक्षा-दीक्षा उस प्रकार से हुई है। जो असहमत हो, उसे रौंद दो, कुचल दो, समाप्त कर दो, खत्म कर दो, यह आपका है। असहमति का सम्मान कांग्रेस के रग-रग में है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कांग्रेस के रग-रग में असहमति का कितना सहमति का रहता है, उसका एक उदाहरण है। थोड़ी सी असहमति व्यक्त करने पर ये जी-23 के नेताओं के विचारों की क्या गति हुई है? मैं अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही बोल रहा हूं। असहमति का कितना सम्मान होता है। प्रेस में जी-23 के नेता चले गये, उन बेचारों की क्या गति हुई है, बता दो ?

श्री भूपेश बघेल :- किसके बारे में ? क्या हो गया ? वह कहे कि चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव करवा रहे हैं। मेम्बरशीप हो गया, चुनाव हो रहा है। उसकी तिथि आ गई, तिथि आने के बाद, अच्छा वही लोग बोले कि कोरानाकाल है, सी.डब्ल्यू.सी. की बैठक में आप नहीं थे, मैं था। वह प्रस्ताव करने वाले थे, पहले ही चुनाव के तिथि की घोषणा हो गई। आप वही जी-23 का बोल रहे हैं न, उन्होंने ही कहा कि कोरोना है, अभी रोक दीजिये, दूसरी लहर की बात है। उसके कारण से रोका गया। अब चुनाव की तिथि आ गई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि कांग्रेस ना होता तो क्या होता ? अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात नहीं करूंगा। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनती तो किसानों का ऋण माफ नहीं होता। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस नहीं होता तो किसानों को 2500 रूपया क्विंटल धान कीमत नहीं मिलती(मेजों की थपथपाहट) केन्द्र सरकार के रोक के बावजूद, अड़चन के बावजूद भी, यदि आप समर्थन मूल्य से एक रूपया भी ज्यादा देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो यदि कांग्रेस ना होती तो 9 हजार रूपया एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ नहीं मिलता। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस नहीं होती तो 400 करोड़ जलकर माफ नहीं होता। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस नहीं होता तो प्रति परिवार 35 किलो चावल नहीं मिलता। (मेजों की थपथपाहट) कांग्रेस नहीं होता तो लोहण्डीगुड़ा की जमीन वापस नहीं होती। (मेजों की थपथपाहट) आप केवल 7 प्रकार के वनोपज खरीद रहे थे। कांग्रेस नहीं होता तो 61 प्रकार के वनोपज की खरीदी नहीं होती। (मेजों की थपथपाहट) देश में कहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

भी कोदो, कुटकी और रागी के लिए समर्थन मूल्य घोषित नहीं है। यह छत्तीसगढ़ में हुआ है, कांग्रेस नहीं होती तो कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी नहीं होती। मैं आपको कितना गिनाऊ ?

श्री बृहस्पत सिंह :- कांग्रेस ना होता तो हाफपेंट, फुलपेंट नहीं होता।

श्री कुलदीप सिंह जुनेजा :- आप कांग्रेस पार्टी को मान लो।

श्री भूपेश बघेल :- कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों, मजदूरों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, व्यापारियों, उद्योगपतियों सबके हित में काम करती है। मुझे आज इस बात की खुशी है कि छत्तीसगढ़ में आज हर वर्ग प्रसन्न है। वह चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे महिला हो, चाहे व्यापारी हो चाहे उद्योगपति हो। इसका प्रमाण यही है कि अभी जितने नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, आप धर्मान्तरण का बहुत जहर घोल रहे थे, धार्मिक उन्माद का बहुत जहर घोल रहे थे, लेकिन जहां-जहां चुनाव हुए, सब जगह सुपड़ा साफ हो गया। यह छत्तीसगढ़ की जनता है, यह शांतप्रिय जनता है, शायद आपने इनको समझने में गलती कर दी। माननीय बृजमोहन जी, चूॅं-चूॅं का मुरब्बा जरूर बोल देते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कम से कम आप तो यह नहीं बोलते कि पत्रकारों के साथ ऐसा हो रहा है, विधायकों के साथ ऐसा हो रहा है, खुद आप देख लेते कि रमन सिंह ने आपके के साथ क्या किया था ? पुराने दिन याद कर लेते, कम से कम यह लाईन तो नहीं बोलते । धर्मजीत सिंह बैठे हैं, उन पर क्या लगाया था, आर्म एक्ट ? आपके नेता से पूछ लीजिए, शर्मा जी वह बंदूक का ब नहीं जानते, उसका लायसेंस नहीं है, शब्दों के बाजीगर हैं, शब्दों से सब बात करते हैं, शब्दों से लोगों को जीत लेते हैं, कभी वह हथियार का प्रयोग नहीं किये, लेकिन इनकी सरकार ने आर्म एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था और आप फरारी की बात कर रहे हैं नेताजी । आपके जो पहले अध्यक्ष थे ना, हम लोग विधान सभा में जब थे, माननीय पाण्डेय जी । विधान सभा अध्यक्ष थे, फरारी में चालान प्रस्तुत हो गया था । आप किसकी बात कर रहे हैं । पुलिस तो वही है, जो आप के समय में था, वह मेरे समय में है । उसका आप लोक सभा में शिकायत करने पहुंच गये । आपके कार्यकाल में विधान सभा का अध्यक्ष फरार घोषित हो गया । आनन-फानन में केस वापस लिया गया । आप बोलते हैं तो अपने तरफ देख लिया करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी राहुल गांधी के भाषण पर बहुत बात बोल दिये । नेता जी ने बात कहीं और लोगों ने कही, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिये । मोदी जी ने क्या कहा, उस पर चर्चा नहीं करेंगे ? नाली से गैस बना रहे हैं । बताओ भला, कितने घर में गैस सिलेण्डर बंद हो गये और नाली के गैस से खाना पकाते हैं ? कितने लोग बनाते हैं, बताओ ? आप लोग भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक हैं, एकाध घर में नाली के गैस से खाना पकाते हैं बता दो ? उन्होंने डिमांस्ट्रेशन दिया था और यहां कुछ उत्पाद बिक रहे हैं । (मेजों की थपथपाहट) जिसके बारे में प्रतीक के रूप में राहुल जी बोले, उसको आप पकड़ लिये । क्या टमाटर यहां नहीं बनता, कैचप यहां नहीं

बनता, क्या इमली की कैण्डी नहीं बनता, क्या अमचूर नहीं बनता, क्या डेनेस्क ब्राण्ड यहां नही है, क्या यहां कोडेनार का ब्राण्ड नहीं है, सब चीज यहां बन रहा है । सब वेल्यू एडिशन कर रहे हैं, आपको कंडिल टार्च में नहीं, दिन के उजाले में आपको दिख नहीं रहा है बृजमोहन जी । आप लोगों की जो योजनायें थी ना, बड़े-बड़े स्काई वॉक, जिसमें कोई चढ़ता ही नहीं, एक्सप्रेस वे..।

श्री रविन्द्र चौबे :- तीन साल से एक्सप्रेस वे का मरम्मत नहीं हो पा रहा है । इधर शुरू करते हैं तो दूसरे तरफ बना रहे हैं तो उधर भसक जाता है । इतना खराब काम हुआ है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में अपने पहले बजट भाषण में घोषणा की थी कि स्काई वॉक के बारे में हम निर्णय करेंगे । एक्सप्रेस वे के बारे में आपने कमेटी बनाई थी । तीन साल बाद भी आप निर्णय नहीं कर पाये ।

श्री भूपेश बघेल :- मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन वो ..।

श्री रविन्द्र चौबे :- इधर बनाते हैं तो उधर भसक जाता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप स्काई वॉक के बारे में निर्णय करे ना ।

श्री भूपेश बघेल :- स्काई वॉक के बारे में क्या निर्णय करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- जो करना है, वह करो ।

श्री भूपेश बघेल :- मोदी जी ने बोला ना कि यह भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं का स्मॉरक है, उसको वहीं रहने देना चाहिये । (मेजों की थपथपाहट)

(पूर्व से जारी) श्री भूपेश बघेल :- वह मड़वा के बारे में बोल रहे थे। वह मड़वा पॉवर प्लाण्ट अजूबा है। दुनिया की सबसे मंहगी बिजली है, उससे मंहगी बिजली कहीं नही है। हमको विरासत में मिली है। जितने की जरूरत नही है, उतनी जमीन ले लिये हैं। चंदेल जी, उस समय आपने मुआवजा क्यों नहीं दिलवाया? सबको हमारे लिए छोड़ के रखे हो। नया राजधानी के बारे में कोई नहीं बोला। वह भी हमारे लिए छोड़ के रखा है। अब यह लोग आ गये हैं, नशा, गांजा, उड़ता पंजाब की बात कर रहे थे। नेता जी, "उड़ता पंजाब" कौन किया था? जब बादल जी मुख्यमंत्री थे और आप उसके सहयोगी थे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने "उड़ता पंजाब" का उदाहरण दिया, किसने किया, मैंने नहीं कहा। लेकिन आप सबक ले लो कि आज छत्तीसगढ़ पंजाब से ज्यादा खराब स्थिति में है। यहां के युवा जिस प्रकार से अवसाद में जा रहे हैं, जिस प्रकार से नशा के आदी हो गये हैं, इनको बचाना आपका भी दायित्व है और हम सब लोगों का दायित्व है।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल सही बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं तो हम विकास की गाथा लिखते रहेंगे, विकास की बात करते रहेंगे, आपकी युवा पीढ़ी समाप्त हो जायेगी।

श्री भूपेश बघेल :- मैं आपकी इस चिंता से शत-प्रतिशत सहमत हूं। हमको नौजवानों को नशा से



अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

बचाना चाहिए। लेकिन नेता जी "उड़ता पंजाब" का उदाहरण बहुत अच्छा दिया। आज भी वहां "उड़ता पंजाब" के लोग सक्रिय हैं। यहां जो गांजा आ रहा है, वह छत्तीसगढ़ का नहीं है। वह कहां पकड़ा जाता है, वह महासमुन्द के बार्डर में पकड़ा जाता है। वह उड़ीसा से आता है। पत्थलगांव में जो घटना घटी, वह गाड़ी कहां से आ रही थी, वह गाड़ी जा कहां रही थी? मध्यप्रदेश जा रही थी और उड़ीसा आ रही थी। वहां आपके इतने सारे सांसद लोग हैं, वह कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? उसका उत्पादन तो वहीं से हो रहा है। वह जा कहां रहा है, आपके शासित राज्यों मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश में जा रहा है। वहां कोई कुछ नहीं बोलते। आपकी सुनी नहीं जाती। हमारे पुलिस कार्यवाई कर रही है और डंके की चोट पर जितने भी गांजा तस्कर हैं, उनको पकडकर लाकर जेल की सीखचों में डालने का काम कर रही है। (मेजों की थपथपाहट) हुक्का बार आपके समय शुरू हुआ। उसको हमने बंद कराया। यह हमारी सरकार, हमारी पुलिस है कि हुक्का बार के खिलाफ कार्यवाई कर रही है। Narcotics control Bureau 10 ग्राम गांजा पकड़ने के लिए डेरा डालकर मुंबई में पडे हुए हैं। यहां थोड़ा बोलिये। वह उड़ीसा आ जायें। वहां क्विंटल-क्विंटल मिलता है। उसको पकड़ने के लिए आपका Narcotics control Bureau नहीं है। 10 ग्राम के चक्कर में वह हीरो, हिरोईन को पकड़ते हैं कि उनको पकड़ने से पेपर में नाम छपेगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- वहां भी जहाज में आता है, उसको नहीं पकड़ा जाता है। पीने, खाने वाले लड़कों को पकड़ा जाता है।

श्री भूपेश बघेल :- गुजरात 21 हजार करोड़ रुपये, अध्यक्ष महोदय, अब गुजरात के बारे में बात ही मत करिये। गुजरात ने बहुत सारे नेता दिये। दो नेता जिसमें बापू जी इधर खड़े (तस्वीर की ओर मुखातिब होते हुए) हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनके नेतृत्व में देश आजाद हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में देश की सारी रियासतों का एकीकरण किया गया। लेकिन अब दो की जगह चार आये हैं, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। (मेजों की थपथपाहट) सारे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और रायपुर एयरपोर्ट का भी अभी नंबर लगा हुआ है, भिलाई स्टील प्लाण्ट का नंबर लगा हुआ है। बालको को तो आपने बेच ही दिया। क्या आप कुछ बतायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपके भाषण के बारे में तो बाद में बोलूंगा कि आप कैसा भाषण कर रहे हैं। सीटी मॉल भी किसी के बाप-दादा ने बनाया है, मुझे मालूम नहीं। पहले 250 करोड़ रुपये का बेस प्राईस रखा गया, उसके बाद 140 करोड़ रुपये की निविदा निकाली गई। उसको भी कोई न कोई कभी न कभी बनाया है। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आप बेच रहे हैं या उसको रखे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में हम लोगों का जो नारा था, छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा, गरूवा, घुरूवा और बाड़ी। डॉ. रमन सिंह साहब कहते थे, पैसा कहां ले आये संगवारी ? आज गौठान भी बना है, गोबर भी खरीद रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, पेंट भी

बनायेंगे और बिजली भी बेचेंगे,(मेजों की थपथपाहट) जिसकी चर्चा आज पूरे देश में है और पूरी केंद्रीय टीम, लोकसभा के सदस्य यहां देखने आये थे। गुजरात के 21 विधायक यहां देखने आये थे और अभी आपकी भारत सरकार के अधिकारियों की टीम देख के गयी है। जिसको आप राजकीय चिन्ह बनाने की बात कर रहे थे, अब आप मोदी जी के बारे में क्या बोलेंगे क्योंकि वह भी खरीदने वाले है।

आज जो छोटी-छोटी चीजें हैं, उससे बहुत सारे गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। यह छुट्टा जानवर, आप की ही देन है। उत्तरप्रदेश में, मध्यप्रदेश में और छत्तीसगढ़ में हैं। पूरे 15 साल में जो मवेशी बेचने जाये, जो मवेशी खरीदने जाये, आप सबको यही समझते थे, कत्ल खाने ले जा रहे हैं, सबको पकड़ के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं, थाने में एफ.आई.आर. कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ में किसी भी मवेशी को बेचने, खरीदने का लाइसेंस किसी के पास नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ में कोइ भी मवेशी बाजार संचालित नहीं है। मैंने तो उत्तरप्रदेश में भी पूछा कि क्या एक भी मवेशी बाजार है ? बोले नहीं, तो आप गौ माता के नाम से वोट ले सकते हैं, गौ माता की सेवा नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में क्या हुआ ? गौ-शालाएं खोली गयी, फिर मंडी के पैसे से अनुदान दिया गया। गायें मरती रही और गौ-शालाएं चलाने वाले मोटे होते गये, यह आपके शासन काल में हुआ है।(मेजों की थपथपाहट) और यही उत्तरप्रदेश में भी हुआ है। फसले ? दूसरी फसल तो छोड़ दीजिये, एक फसल बचाना मुश्किल हो गया था। आज यह जो हमारे छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा है, उसे फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिक कर रहे हैं। हम उस व्यवस्था को लागू करें और उसके बाद, उससे लोगों की आय बनाये, अर्थ से हमने लोगों को जोड़ा, उसे लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। गोबर बेचने के लिये 2 लाख लोग पंजीकृत है और 2 लाख लोगों में से 98 हजार लोग, जिनके पास कोई जमीन नहीं है। 2 लाख में 47 प्रतिशत महिलाएं गोबर बेच रही है। तो हम लोगों की लगातार कोशिश है कि इन वर्गों के हित में भी काम करें, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है ? आज डेयरी चलाने वाले या जो पशु-पालक है, मवेशी उनके ऊपर बोझ नहीं रह गये हैं, पशु-धन बोझ नहीं है। अब गोबर खरीदने के कारण से वह जो दूध अनुत्पादक जानवर है, उसको भी घर में रख रहा है। दूसरी बात यह है कि उससे बहुत सारे रोजगार भी मिल रहे हैं। अब गांव-गांव में गौठान को ही हम इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करेंगे। जो हमारे पारंपरिक व्यवसाय हैं, जो गांव के कारीगर है, उन सब को वहां अवसर देंगे और नये लोगों को भी जोड़ने का काम करेंगे ताकि गांव में ही रोजगार मिल सके। अब आपके इंडस्ट्रियल पार्क की परिभाषा तो यह है कि बड़ी अट्टालिका बननी चाहिये, किसानों की जमीन खींच लो, पावर हब बनायेंगे, उसके चलते पूरी जांजगीर जिले की जमीन को ले लिये। क्या बना ? कुछ नहीं। कितनी बार इंडस्ट्रियल पार्क बनाये ? हमारी जो अवधारणा है वह यह है कि सुराजी गांव, गांधी जी का ग्राम स्वराज और वहीं इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना हो। क्योंकि यदि गांव सुधरेगा, गांव के लोग आर्थिक रूप से मजबूत होंगे तो शहर अपने आप मजबूत होगा। आर्थिक रूप से मजबूती। हमने इन 3 सालों में सीधे किसानों को, आम लोगों को 91 हजार

करोड़ रूपये दिया है। (मेजों की थपथपाहट) आप कहेंगे तो मैं गिन कर बता देता हूं कि हमने किसमें-किसमें दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, सदन के नेता के अब तक के भाषण उत्तर, प्रत्युत्तर में निकला। एक बात, कि आप उत्तर, प्रत्युत्तर में भाषण दे रहे हैं। दूसरी जो बात है कि, अब चलिये उसमें बाद में बात करेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- अब ऐसा है कि आपके नेता तो हम लोगों की सुनते नहीं थे। वह जो अधिकारी लिखकर दिये रहते, उसी को देखकर पढ़ते थे। हम लोग पूछते रहते थे कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे क्या ? आप 5 रूपये बोनस दे दीजिए। माननीय चौबे जी नेता प्रतिपक्ष थे, वह हाथ जोड़कर कहते थे कि डॉ. साहब 5 रूपये दे दीजिए। मैं छत्तीसगढ़ के किसानों की तरफ से हाथ जोड़ता हूँ। आप 5 रूपये दे दीजिए, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजा, क्योंकि वह अधिकारी लिखकर दिये थे, उससे टस से मस नहीं हुए। हम तो जीवंत रखना चाहते हैं। आपने क्या कहा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। माननीय बृजमोहन जी ने क्या कहा उसका उत्तर दे रहा हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने क्या कहा, उसका उत्तर दे रहा हूँ। आज माननीय धर्म भईया बोले नहीं। स्वास्थ्यगत कारणों से, आज उनके चुटीले अंदाज से हम लोग वंचित रह गये। अभी तो सत्र की शुरूआत ही हुई है। हम उनकी बातों को भी सुनेंगे, उसका आनंद लेंगे। यह  आप जो बोलते हैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल विरोध के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको संतुष्ट भी करूं और सदन को शासन की योजनाओं की जानकारी भी दूं। यह हमारी कोशिश है। आपके जो अच्छे सुझाव हैं उसको क्यों नहीं स्वीकार करेंगे, आप भी जनता से चुनकर आएं हैं, आप क्षेत्र में जाते हैं, प्रदेश में दौरा करते हैं वहां से जो सूचनाएं लाते हैं वह सदन के सामने रखते हैं, जनता के सामने जाता है हम लोगों के समक्ष भी आता है, अधिकारियों के सामने आता है और उस पर विचार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आप आलोचना करते हैं। जैसे आज माननीय चन्द्रा जी का सुर बिल्कुल बदला हुआ था। आज तो आप बिल्कुल सुझाव नहीं दिये। धान भी खरीदे, उसमें भी आलोचना हो रही थी। माननीय केशव चन्द्रा जी आप रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए कि यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हर साल बढ़ता रहा है, ऐसा नहीं है, कम भी हुए हैं। 70 लाख metric ton खरीदने के बाद 60 लाख metric ton भी हुआ है। आपको रिकॉर्ड निकालकर दे दूंगा। लेकिन हमारे शासनकाल में 60 लाख, 70 लाख से बढ़कर सीधा 82, 83 और 92 लाख और 98 लाख metric ton हुआ है। जो किसान हैं, उसकी संख्या बढ़ी है जहां इनके रजिस्ट्रेशन 15 लाख होते थे, 22 लाख किसानों ने धान बेचा है और वह भी 38 लाख हेक्टेयर का बेचा है। किसानों का रूझान, कृषि के प्रति बढ़ा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो बार-बार 91 हजार बांटे, 92 हजार बांटे, आपने 2500 रूपये दिया। दुनिया के किसी भी अर्थशास्त्री से आप बहस कर लीजिए और किसी को भी ले आएं, किसी तरह की बात कर लें, दुनिया से जो सब्सीडी हटा रहे हैं, जो सब्सीडी की अर्थव्यवस्था है, आप तो बैंक से

उधार लेकर पैसा बांट रहे हैं। इसमें बुद्धि कहां पर लग रही है। आप दुनिया, संसार के रिजेक्टेड चीजों को स्वीकार कर रहे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- यही समझ का फेर है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- किसानों को पैसा देने में आपको आपत्ति है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने सब्सीडी की बात कही है।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब्सीडी नहीं दे रहे हैं। प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे तो आपको इंटेसिव मिलेगा। यह प्रोत्साहन राशि है। आप ज्यादा मेहनत करिये, आपकी तरह नहीं कि चप्पल बांटो, किताब बांटो, टिफिन बांटो, मोबाईल बांटो, यह नहीं कह रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आप तेन्दूपत्ता तोड़ रहे हैं तो 2500 रूपये की जगह 4000 रूपये मिलेगा(मेजों की थपथपाहट) उनकी मेहनत, किसान के सम्मान की बात है। आपसे यही अंतर है। आपकी जो सोच है वह शोषकों वाली है, शोषक लोगों की है हमारी जो सोच है वह मेहनतकशों की सोच है। महात्मा गांधी जी ने समझाया कि जो श्रम है उसका सम्मान करो। उन्होंने चरखा चलाया, बुनकरों का सम्मान, नीम की खेती का आन्दोलन किया, किसानों का सम्मान, यदि चमड़ा सीले, जो अस्वच्छ धंधा करने वाले हैं, उनका सम्मान और यही बात आपके नेता को बर्दाश्त नहीं हुई, इस कारण से उनकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस श्रम का सम्मान करती है, यह हमारी परम्परा है हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आपके राज में बजट तो बढ़ता गया, लेकिन लोग गरीब होते गये। कुपोषण बढ़ता गया, अशिक्षा बढ़ती गई, इन 15 वर्षों में यह आपके समय हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अब कर्ज बढ़ रहा है।

श्री भूपेश बघेल :- आप देख लीजिए। कल तो बजट आ रहा है। आप इंतजार कर लीजिए। आप कर्ज बढ़ रहा है ऐसा बोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार, आपके समय अनुदान देती थी और हमारे समय में भी अनुदान दे रही है आपके समय में भी भारत से कर का हिस्सा मिलता था और हमारे समय में भी मिलता है। जब यू.पी.ए. की सरकार थी, तब आप देखें कि वर्ष 2005-06 में 90 प्रतिशत, वर्ष 2006-07 में 96 प्रतिशत, फिर 2007-08 में 93 प्रतिशत, वर्ष 2009-10 में 99 प्रतिशत इतना मिलता रहा। अब जब हम सरकार में आये, मोदी जी आये, वह प्रधानमंत्री बने तो आपकी क्या स्थिति है, वर्ष 2019-20 में 68 प्रतिशत और वर्ष 2020-21 में 59 प्रतिशत हो गया यह आपकी केन्द्रीय अनुदान में कमी है और आप कटौती कर रहे हैं, कटौती किसके लिए, तो कर्ज नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा ? आप जो अनुदान बजट में कर रहे हैं, उसमें भी 59 प्रतिशत, 60 प्रतिशत और इस साल तो फरवरी तक केवल 47 प्रतिशत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा, वह अनुदान का हिस्सा था। केन्द्रीय करों में वर्ष 2005-06 में यूपीए की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में डॉ. रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, आप सरकार में थे, 99 प्रतिशत, वर्ष 2006-07 में 106 प्रतिशत, वर्ष 2007-08

में 107 प्रतिशत, वर्ष 2009-10 में 100 प्रतिशत, वर्ष 2010-11 में 105 प्रतिशत लगातार चला आ रहा है। उसके बाद जैसे मोदी जी आए तो कितना हो गया- वर्ष 2014-15 में 89 प्रतिशत, वर्ष 2016-17 में जरूर 107 प्रतिशत लाए लेकिन अब क्या स्थिति है, वर्ष 2019-20 में 78 प्रतिशत और 2020-21 में 76 प्रतिशत, यह छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि यह पैसा देते तो हमारा कर्ज नहीं बढ़ता। हम और लोगों को नौकरी देते, किसानों को और इंटेंसी देते, यहां के आदिवासियों को अनुसूचित जाति के लोगों के हित में और काम करते, यहां की महिलाओं और बच्चों के लिए और ज्यादा काम कर सकते थे। लेकिन केन्द्रीय करों में और अनुदान में लगातार छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव होता रहा है। (शेम-शेम की आवाज) और हम पर आरोप लगा रहे हैं कि कर्ज बढ़ गया। आप बाध्य कर रहे हैं और फिर आप तो लिखित में आदेश देते हैं कि हम जी.एस.टी. का पैसा नहीं दे सकते, इसलिए आप कर्ज ले लीजिए। अभी कर्ज ले ही रहे हैं। इस साल भी लिए, पिछले साल भी लिए। कर्ज ले रहे हैं। जीएसटी का जो पैसा है, हमको मिलना चाहिए, वैट खत्म कर दिया। अब तो जून, 2022 के बाद जो कंपनसेशन का पैसा मिलता था, वह भी बंद हो जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ का शुद्ध 5 हजार करोड़ का नुकसान होने वाला है। छत्तीसगढ़ के हित में कम से कम आप लोग हंटर वाली से न कह सकें तो दिल्ली में पुराने नेता हैं, उनको पकड़कर यह तो करवाईए कि छत्तीसगढ़ के साथ अहित न हो। आप लोग भी छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि हैं, माटी पुत्र हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- गरीबों के लिए यदि आप कर्ज ले रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास के लिए क्यों नहीं ले रहे हैं ?

श्री भूपेश बघेल :- हां, अभी हमने 600-700 करोड़ दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, दो साल का दिया है, तीसरे साल का तो वापस हो गया है। आप तो पहले साल भर के लिए 762 करोड़ के लिए बोल हैं। फिर दूसरे साल 800 करोड़ रूपये लगेगा, उसके लिए भी लीजिए।

श्री भूपेश बघेल :- उसकी चिंता हम कर लेंगे। हम उसकी भी उसकी चिंता कर लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- आज प्रश्न के उत्तर में है। आप कर्ज ले रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं, गरीबों को बांट रहे हैं तो गरीबों को...।(व्यवधान)

श्री भूपेश बघेल :- उसकी लिमिट भी तो है। हमारा सारा पैसा हजारों करोड़ रूपए कोरोना में गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कोरोना की तो बात ही मत करो। कोरोना का सेस आपका धंधा हो गया है। सेस लगाकर बैठे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, प्रधानमंत्री जी, पीएम केयर फंड का छत्तीसगढ़ के जितने भी उद्योगपति से लेकर गये हैं। उसका वेंटिलेटर आया था जो चलता नहीं था। उसका हिसाब कौन देगा ? उसका तो ऑडिट भी नहीं होना है, आपने ऐसा नियम बना दिया है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपने तो फ्री में टीका लगाऊंगा बोले थे, बाकी को वापस कर दीजिए। आप यहीं बोले थे कि फ्री में लगायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां हम देना शुरू कर दिए थे, वह क्या हुआ।

श्री अजय चंद्राकर :- कुछ नहीं-कुछ नहीं।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी, सुनिए तो हमने देना शुरू कर दिया, उसके बाद केबिनेट में डिसीजन लिया, जब हम पैसा दे रहे हैं तो हम अपने मुख्यमंत्री का फोटो लगायेंगे। जैसे ही मोदी जी की जगह मेरा फोटो लगा, झारखंड ने शुरू किया, ममता बनर्जी ने शुरू किया तो तुरंत वह वैक्सीन का पैसा वापस मिल गया। बोले कि फोटो जरूर होना चाहिए। वैसे ही है।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं यह नहीं कह सकता कि आप असत्य कह रहे हैं। मैं तो आपका सम्मान करता हूं लेकिन आप जो कह रहे हैं, वह बातें दूसरी है और हम इसको समय में बतायेंगे।

श्री भूपेश बघेल :- बिल्कुल यही हुआ है। कैबिनेट में डिसीजन लिया कि हम पैसा लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- छत्तीसगढ़ के कोरोना से इनकम का साधन बन गया था। बीमारी में पैसा कमा लिए।

श्री भूपेश बघेल :- सुनिए तो, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान है। राज्यपाल जी के अभिभाषण में भी 7 हजार गौठान निर्माण का उल्लेख है। मैंने पिछले सत्र में आपसे निवेदन किया था कि आप लॉट निकाल करके सारे सदस्यों को 5 गौठान दिखा दो। कितना सदुपयोग हो रहा है, शासकीय राशि का क्या उपयोग हुआ है, जरा लोग समझ लेंगे ? आप चिन्हांकित मत करो, 7 हजार गौठान का लॉट निकाल लो और 5 गौठान सब सदस्यों को दिखा दो। हम लोग आपके साथ जाना चाहते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हां, बिल्कुल चलिए ना। यह बजट सत्र समाप्त होगा, फिर मेरे साथ चलना।

श्री शिवरतन शर्मा :- लॉट निकाल करके।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां चलेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी चरोदा चलो।

श्री शिवरतन शर्मा :- लॉट निकालकर चलो।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी आप यहां से चरोदा चलिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपका स्वागत है।

श्री अजय चंद्राकर :- चरोदा गौठान चलेंगे क्या ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका स्वागत है।

श्री अजय चंद्राकर :- आपका बहुत मॉडल प्राजेक्ट है न।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आपका स्वागत है ।

श्री अजय चंद्राकर :- वह आपका बहुत मॉडल प्रोजेक्ट है न । क्या चरौदा गौठान चलेंगे?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप बोलते हैं कि अभी चलो, क्या रात में दिखायेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आपका स्वागत है लेकिन चश्मा बदलकर जाना । (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- चरौदा चलेंगे क्या ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपका चश्मा पहनकर चले चलेंगे लेकिन दिखाओ तो सही ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी चलो यह क्या बात है भाई ? आप तो अभी चलो बोल रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- चरौदा में उनका चश्मा पहन लेंगे ।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी चलो बोल रहे हो तो क्या सदन से उठकर चले जायेंगे ।

श्री अजय चंद्राकर :- जब अभी चर्चा कर सकते हैं तो अभी जा क्यों नहीं सकते ?

श्री चंद्रदेव प्रसाद राय :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल बना लिये हैं । व्यवस्था को आगे बढ़ाईये ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब क्या है कि अजय जी थोड़ा सा नाराज हो गये हैं और शिवरतन जी उनका साथ दे रहे हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये उत्तेजित होने की दवा खाकर आते हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- अब बृजमोहन जी भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने पिछले सत्र में भी कहा था ।

श्री भूपेश बघेल :- हां-हां चल देंगे । कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक साल पहले भी कहा था ।

श्री भूपेश बघेल :- हमारे पास छिपाने के लिये कुछ नहीं है । हम दिखायेंगे, क्यों नहीं दिखायेंगे ?

श्री अजय चंद्राकर :- हम आपकी पूरी बात सुन रहे हैं लेकिन जहां पर आप कुछ अनुपयुक्त बातें कहेंगे तो वहां पर बोलना ही पड़ेगा ।

श्री भूपेश बघेल :- अब नेता जी ने खाद के बारे में बोला ।

श्री अजय चंद्राकर :- अब आपने कह दिया कि आप लोगों ने हत्या कर दी । मैंने टोका नहीं, आपने अपने भाषण में बोला न कि गांधी जी की हत्या कर दी ।

श्री भूपेश बघेल :- हां, जो शोषक लोग हैं । उनका प्रतिनिधित्व करने वाले गोडसे की चर्चा की ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप ऐसी बात करते हैं, इस तरह की बात आपको शोभा नहीं देती । आप बाकी विषय रखिये, उसमें हमारी कोई नाराजगी नहीं है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

वाणिज्यिक कर मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- जब हमारे नेता बोल रहे हैं तो आप बार-बार खड़े हो रहे हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- हमारे नेता जी बोल रहे हैं तो क्यों नाराज होंगे लेकिन नेता होने के कारण कुछ भी नहीं चलता है न ।

श्री भूपेश बघेल :- हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं । गोडसे ने हत्या इसलिए की कि गांधी जी श्रम का सम्मान कर रहे थे और इस कारण से हत्या की । वे शोषकों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

श्री अजय चंद्राकर :- यह कौन सी चर्चा से कहां से कैसे उद्भुत होता है ?

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा यह क्यों उद्भुत नहीं हो सकता, क्या यह कोई प्रश्नकाल है ?

श्री अजय चंद्राकर :- प्रश्नकाल नहीं है लेकिन अभी आप ही बोल रहे थे न कि उद्भुत नहीं होता है । यदि गवर्नर एड्रेस में बात कर रहे हैं तो या तो उसके लिये अलग से चर्चा कर लीजिये ।

श्री रविन्द्र चौबे :- गांधी के नाम और चर्चा से आपको इतनी आपत्ति क्यों हो जाती है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आपकी तबीयत खराब है, आपको चिल्लाना नहीं है । आज मुख्यमंत्री जी भारी मुस्कुरा रहे हैं, चार्ज उधर दे दीजिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- गांधी जी के चरण में जाते हो और गांधी जी का ही नाम लेते हो ।

श्री अजय चंद्राकर :- तें हा बइठ जा, तोर बात ला हमन गंभीरता से नइ लेवन।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप लोग एक-बार गोडसे का मुर्दाबाद नारा लगा दो।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब अजय जी की जो व्यग्रता है वह चरम पर पहुंच गयी है । अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे तो इसलिए सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने भाग लिया और सदन में जो उपस्थित हैं उन सभी के प्रति धन्यवाद करते हुए माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सदन से यह अनुरोध कि इस कृतज्ञता प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपने जो समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद । (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- आज आपने बहुत मुस्कुरा कर भाषण दिया ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उन पर एक-साथ मत ले लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

**समस्त संशोधन अस्वीकृत हुए ।**

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - "माननीय राज्यपाल महोदया ने जो अभिभाषण दिया उसके लिये छत्तीसगढ़ विधानसभा के इस सत्र में समवेत् सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022 को 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित ।

**(रात्रि 8 बजकर 29 मिनट पर विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 09 मार्च, 2022 (फाल्गुन-18, शक संवत् 1943) के पूर्वाह्न 11.00 बजे दिन तक के लिये स्थगित की गई।)**

**चन्द्र शेखर गंगराड़े**

रायपुर (छत्तीसगढ़) **प्रमुख सचिव**

दिनांक - 08 मार्च, 2022 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं